राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2 दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का पच्चीसवां दिवस संख्या–16

शनिवार,

19 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रतन लाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के ग्राम बादलपुरा निवासी नारायणसिंह की दिनांक 16.1.94 को हुई निर्मम हत्या की निष्पक्ष जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से यातायात विभाग की अकर्मण्यता से निजी बस मालिकों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसों के अवैध संचालन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निम्न आशय की जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के गांव रयोंगा में दिनांक 8 जनवरी, 1994 की रात्रि को विक्रमसिंह नामक व्यक्ति की हत्या के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि दिनांक 8.1.94 की रिपोर्ट पर मर्ज संख्या 1/94 के अन्तर्गत धारा 174 जा. फौ. थाना उद्योग नगर पर दर्ज कर जांच शुरू की गयी। मेडिकल बोर्ड द्वारा किये गये शव परीक्षण रिपोर्ट से मृत्यु गर्दन पर झटका देने से हड्डी टूटने के कारण होना बताया अतः घटना हत्या की होने पर अभियोग संख्या 8 दिनांक 10.1.94 को धारा 302 भा. द. सं. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण थानाधिकारी द्वारा प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक, भरतपुर द्वारा थानाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इस मामले की तुरन्त कार्यवाही करें। आकस्मिक रूप से घटी इस घटना के कारण भरतपुर तहसील व आस-पास के क्षेत्रों में उत्तेजनात्मक एवं उद्वलित वातावरण नहीं है एवं जनता सामान्य रूप से अपने कार्य में व्यस्त है। फिर भी पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तों की तलाश हेतु निरन्तर हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

Page No.2

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट के शिवसिंहपुरा में 33 के.वी. के सब-स्टेशन का ट्रांसफार्मर खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि 33 के.वी. सब-स्टेशन शिवसिंहपुरा पर पूर्व में एक एम.वी.ए. की क्षमता का ट्रांसफार्मर प्रतिष्ठापित था, लेकिन यह ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण उसके स्थान पर 2.5 एम.वी.ए. की क्षमता का ट्रांसफार्मर दिनांक 10.3.94 को लगा कर चालू किया जा चुका है। उस क्षेत्र की मांग को देखते हुए तीन एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर लगाना अभी उपयुक्त नहीं है। भविष्य में यदि मांग के अनुसार आवश्यक होगा तो तीन एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाने पर विचार किया जाएगा।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री अमराराम, सदस्य, विधानसभा की ओर से दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, भूपालसागर को ही गन्ना बेचने के कथित सरकारी आदेश से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री एमामुद्दीन अहमद खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील वस्सी के ग्राम कानोता स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की लगी प्रतिमा को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बारां जिले के किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में सीमेण्ट फैक्ट्रियों द्वारा फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला राजसमन्द की भीम व देवगढ़ तहसीलों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के इटावा में डिग्री कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के चांदपोल बाहर शास्त्री नगर में स्थित कब्रिस्तान पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री पराक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के अप्रशिक्षित पंचायत अध्यापकों को राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा प्रशिक्षण दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय महाविद्यालयों के समस्त अस्थायी व्याख्याताओं

(श्री ग्रध्यक्ष)

की समस्या के समाधान हेतु राजस्थान लोक सेवा ग्रायोग द्वारा ग्रारम्भ की गई स्थायी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के काश्तकारों की भूमि को ग्रमीनों द्वारा सिवाय चक घोषित करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जिला सवाई माधोपुर के पांचना बांध का पानी नादौती तहसील के ग्रामों को देने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सिरोही जिले की पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के मापदण्ड 1971 की जनसंख्या को ग्राधार मानकर करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की ग्रनुमति होगी।

श्री जगदीप धनखड़।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, बात निश्चित रूप से गम्भीर जांच करने की है, साथ ही यह ग्रत्यन्त प्रशंसा का विषय है कि ग्रापने ग्रपने स्तर पर स्क्रिप्ट मंगवा लिया है ग्रौर उसकी सूक्ष्म जांच की जा रही है। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे पास ग्रौर ग्रन्य सदस्यों के पास ग्रखिल भारतीय युवा जाट महासभा के ग्रध्यक्ष विजय पूनिया ने एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें उन्होंने कुछ टिप्पणी की है कि "दी ग्रेट मराठा" सीरियल....(व्यवधान)....मैं कह रहा हूं कि जांच हो रही है, जरा सुनिये तो सही। ग्राप यह कहना चाहते है कि जो मैं कह रहा हूं वह गलत है इसलिए बात इधर-उधर हो जाए, गम्भीर विषय है गम्भीरता से लीजिए....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं तो केवल इतना ही पूछ रहा था कि क्या ग्रापको कोई पर्सनल नालेज भी है इस सम्बन्ध में?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : ग्राप पार्टी के चीफ व्हीप हैं ग्रापकी जिम्मेदारी है कि हाउस ठीक प्रकार से चले। ग्राप ग्रासन को सहयोग दें, परन्तु ग्राप उसमें विघ्न डलवा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) : कम से कम गरिमा तो रखिए।

श्री जगदीप धनखड़ : ग्राप क्यों भूल जाते हैं कि ग्राप सत्ता पक्ष में बैठे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्राप ग्रपने दायित्व ग्रौर जिम्मेदारी को महसूस कीजिए।

श्री जगदीप धनखड़ : बार-बार विपक्ष की भूमिका कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, मैं इतना पूछना....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा है, मामला उठाया जा रहा है, ग्रध्यक्षजी ने

(श्री रामनारायण चौधरी)

अनुमति दी है फिर भी आप चीफ व्हिप हैं....(व्यवधान)....माननीय अध्यक्ष के आदेशों की आप अवहेलना कर रहे हैं, आपको+++आनी चाहिए कि आप गवर्नमेण्ट के चीफ व्हीप हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दलगत राजनीति से ऊपर रखो ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप गवर्नमेण्ट के चीफ व्हीप हैं, अध्यक्ष ने इनको अनुमति दे दी है और आप बीच में खड़े हो रहे हैं, यह कोई बात है क्या है?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं कोई जानकारी नहीं कर सकता क्या?....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप जानकारी करना चाहते हैं या विघ्न डालना चाहते हैं?....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपके मत से सहमत नहीं हूं, ऐसा नहीं है, मैं केवल इतना पूछ रहा था कि क्या आपको इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनको सलाह दीजिए कि इनकी हैसियत हो उसके मुताबिक यह करें ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये । यह तो बाद में करने की बात थी आपने पहले ही कर दी । सब बोल लें, अभी बहुत से लोग बोलने वाले हैं इस पर । बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और अनुरोध करूंगा कि उधर बैठे लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वह सत्ता पक्ष में बैठे हैं आदतवश वह अपने आपको विपक्ष में मानते हैं । अध्यक्ष महोदय, या तो इनको इधर बैठने की आप इजाजत दीजिए....

श्री अध्यक्ष : इसमें तो मेरी मुसीबत है कि दोनों तरफ विपक्ष बैठा है, मेरे पर ही आक्रमण कर रहा है ।....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्षजी, इस बात पर मैं कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता कि "दी ग्रेट मराठा" सीरियल में क्या है, पर मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से इस बात की ओर जरूर आकर्षित करना चाहूंगा कि महाराजा सूरजमल जाट नेता ही नहीं थे, राज्य के नेता ही नहीं थे निश्चित रूप से राष्ट्र की धरोहर है, उनका सही चित्रण किया जाए । यह चिन्ता का विषय हो सकता है और होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को और सदन को इस बात के लिए जागरूक करूंगा कि महाराजा सूरजमल पर जो सीरियल बनाया जा रहा है और जिसके एपीसोड्स की संख्या 5 से ज्यादा बढ़ाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस प्रकार के डिस्टोरशंस हो रहे हैं, अभी उन डिस्टोरशंस की बारीकी में नहीं जाते हुए आप और हमको एक प्रस्ताव पारित

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री जगदीप धनखड़)

करना चाहिए कि महाराजा सूरजमल के सम्बन्ध में जो दूरदर्शन पर सीरियल दिखाया जाने वाला है उसके एपीसोड्स की संख्या, जिसकी मांग 26 के लिए की जा रही है, उसके पक्ष में अपना समर्थन जाहिर करें।

मान्यवर, यह बात महाराजा सूरजमल के लिए नहीं है। भारत के संविधान में 1976 में एक संशोधन हुआ। पहली बार एक नया चैप्टर जोड़ा गया फण्डामेंटल ड्यूटीज का। जब भारत में संविधान बना था तब फण्टामेंटल ड्यूटीज का चेप्टर नहीं था और सेक्शन 51 ए में, मान्यवर, यह कहा गया कि जो भी अपना कल्चर है, जो भी अपनी हेरिटेज है उसको सुरक्षित रखने के लिए हर नागरिक कार्य करेगा। यह उसी प्रकार की बात है जिसके लिए सदन का हर सदस्य अपनी फण्टामेंटल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने की दृष्टि से राजस्थान के हर महानतम व्यक्ति का सही चित्रण हो, इसके लिए प्रयत्नशील रहे। मान्यवर, इस सदन को महाराजा सूरजमल के लिए व राजस्थान के और जो भी महानतम व्यक्ति हैं, उनके लिए इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि भरतपुर घराने का सम्बन्ध है, विश्वेन्द्रजी इस सदन के सदस्य हैं, अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष भी हैं....(व्यवधान)....नहीं, नहीं। मैं बिलिटिल नहीं कर रहा हूं, सदन में टेलेंट है इस मामले के अन्दर। रामनारायणजी कह रहे हैं कि बिलिटिल करने की बात है। रामनारायण जी, बिलिटिल करने की नहीं है। जिसको भी इस बारे में ज्ञान ज्यादा है उनकी एक कमेटी का गठन करके इस सदन को चाहिए कि जो भी राजस्थान के इस प्रकार के ग्रेट परसोनेजेज हैं उनका किसी तरीके से सही चित्रण नहीं किया गया है, उनको नहीं दर्शाया गया है, राष्ट्र के अन्दर जो उनका योगदान होना चाहिए वह नहीं हुआ है, तो उसको क्लेम करने के लिए सदन को सामूहिक रूप से आगे आना चाहिए और सत्ता पक्ष को बिलकुल इस मामले में बाधक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : पहले शिवनाथसिंह जी का है, आप भी बोलेंगे। पहले ये बोलेंगे। बिराजिये। अच्छा, उन्होंने अपना नाम समझ लिया, सनाढ्य समझ लिया।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, काफी सीरियल बन रहे हैं और इन सीरियल में मध्यकालीन इतिहास का दिग्दर्शन किया जा रहा है। संजय खान का नाम बार-बार आता है। अभी दो-तीन रोज पहले महाराणा प्रताप के सम्बन्ध में, क्या उस सिरियल में आया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन लगातार इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है कि इस तरह से हमारे इस देश की आजादी के संग्राम के जो वीर योद्धा हैं उनके चरित्र को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जैसी हमको जानकारी मिली है और जैसा हमें बतलाया गया है, महाराणा प्रताप के चरित्र को एक तरह से बहुत बुरे रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है।

(श्री शिवनाथसिंह)

यही हाल महाराजा सूरजमल के लिए कहा जाता है । अध्यक्ष महोदय, महाराजा सूरजमल इस भारत भूमि के सपूत थे। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अग्रणी भाग लिया और उस समय के सन्दर्भ में जब हम देखते हैं तो इस देश की आजादी के लिए जंग भी करनी पड़ती थी, लड़ाई भी करनी पड़ती थी। उस वक्त जो देश के राजा और बादशाह थे उन्होंने हमारे देश की भूमि पर जिन लोगों ने आक्रमण किया उस शासन को, उस प्रशासन को हटाने के लिए उनके खिलाफ युद्ध किया था उस समय लड़ाइयां लड़ी थीं और एक विजेता के रूप में महाराजा सूरजमल दिल्ली भी गये थे। दिल्ली का कुछ सामान भी लूट के रूप में नहीं, अध्यक्ष जी, विजेता के रूप में वह लाये थे। ऐसे वीर बहादुर के लिए जो देश की आजादी के लिए लड़ा था उनका इस प्रकार का चरित्र उन सिरियल्स में दिखाया जाय, अशोभनीय है। मैं जाट जाति की बात नहीं करता हूं, वह भारत के सपूत थे, हमारी एक धरोहर है और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए, सम्पूर्ण राष्ट्र की जाति के लिए वह लड़े थे।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री धनखड़ साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। महाराजा सूरजमल जी या भरतपुर के जाट राजाओं का इतिहास स्वयं के स्वार्थ के लिए लड़ने वालों का इतिहास नहीं है। लगातार वे इस राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए लड़ते रहे हैं इसलिए उनको राष्ट्रीय हीरो के रूप में देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के बाद बहुत से लेखकों और सीरियल्स बनाने वालों ने कभी शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा, कभी महाराजा सूरजमल को लुटेरे की संज्ञा दी, कहीं राणा प्रताप को ट्रेटर कहा और पाकिस्तान में भी एक पुस्तक छपी है जिसमें गुरू गोविन्दसिंह के बारे में नरसंहारक जैसी टिप्पणियां की गयीं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम राष्ट्रीय हीरोज के प्रति इस प्रकार का असम्मान बरदाश्त कर पाते हैं। जिस प्रकार के सीरियल्स चल रहे हैं महाराजा सूरजमल ने क्या किया, इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि जब अंग्रेजों ने भरतपुर घेरा और नहर के चारों तरफ गोरे आ गये तो उन्होंने कहा दो गोरे एक जाट का छोरा लेकर डूब कर मर गये और स्वतन्त्रता की रक्षा की, मारते-मारते अंग्रेजों को दिल्ली तक पहुंचा दिया था। यह महान कार्य किया था, आजादी का काम था। इतिहासकार कई बार भूल करते हैं। ये साम्प्रदायिक बातें नहीं हैं, ये राजनैतिक बातें नहीं हैं, ये बातें वे हैं कि उनकी पूजा राष्ट्रीय हीरो के रूप में की जानी चाहिए।

अध्यक्ष जी, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस समय मुगलों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, भरतपुर के जाट राजाओं ने फतेहपुर सीकरी में बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी इसके कारण से इतिहासकारों ने जाटों को उदण्ड लिखा है। मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास से उदण्ड शब्द भी हटाया जाए। वे उदण्ड नहीं थे वे स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे थे, उसके लिए

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संघर्ष कर रहे थे। इतिहास में जिक्र आया इस बात का कि अकबर की कब्र को जाटों ने फतेहपुर सीकरी में खोदकर निकाल दी। वह अकबर के प्रति दुर्भावना नहीं थी उस समय लड़ाई चल रही थी मुगलों के प्रति। उन्होंने उखाड़कर फेंक दी तो फेंक दी, उनको उदण्ड नहीं कहा जा सकता और उसके आधार पर अगर इतिहासकार उनको उदण्ड कहते हैं तो इतिहासकार भारत के इतिहास के साथ अन्याय करते हैं। इस प्रकार से अगर महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहे थे तो हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उसको साम्प्रदायिक लड़ाई नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार अगर गुरू गोविन्दसिंह औरंगजेब से लड़ रहे थे तो भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सीरियल में हमारे जो राष्ट्रीय हीरोज हैं उन हीरोज की किसी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी नहीं हो इस आशय का राजस्थान की विधान सभा से प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब एकता यात्रा निकली तो मुझे कहा गया कि राजस्थान के इतिहास के किन-किन लोगों का नाम लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक रथ बनाया था जिस पर राजस्थान का नक्शा लगाया उस रथ पर लौहागढ़ की सीमा पर हमने महाराजा सूरजमल का चित्र लगाया, मेवाड़ की सीमा पर महाराणा प्रताप का चित्र लगाया और इधर दुर्गादास राठौड़ का चित्र लगाया था। हमने महाराणा प्रताप का चित्र लगाया और जाट राजा सूरजमल का चित्र लगाया। ये राजस्थान के हमारे प्रतीक हैं जिन पर हमको स्वाभिमान है, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं और हमारे ऐसे पूर्वजों के प्रति अगर कोई टिप्पणी करता है तो वह राष्ट्रीय अपमान की अवस्था है न किसी जाति का अपमान है, न व्यक्ति का अपमान है और न किसी परिवार का अपमान है, वह हमारे राज्य का अपमान है। मैं आज ही सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जाट राजा सूरजमल केवल विश्वेन्द्रजी और अरुणसिंह जी के पूर्वज ही नहीं थे, वह घनश्याम तिवाड़ी के भी पूर्वज थे और राजस्थान के भी पूर्वज थे और राजस्थान को उन पर गर्व है। उसी प्रकार महाराणा प्रताप हैं और उसी प्रकार दुर्गादास राठौड़ हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी पक्षों के लोगों से बात करके सदन में उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाय, उनके ऊपर गर्व प्रकट किया जाय और इस प्रकार के सीरियल्स न बने इसका सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, जो इस प्रकार के सीरियल्स बन रहे हैं उनकी मैं कठोर शब्दों में निन्दा करता हूं और इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहता हूं कि इतिहास के अक्षरों में उनका नाम अमिट है और जब तक भारत स्वतन्त्र रहेगा, भारत की संतति स्वतन्त्र रहेगी तब तक उनके प्रति श्रद्धानुगत रहेगी और उनको श्रद्धांजलि देती रहेगी। इनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जाति-पांति में कभी

(श्री रामनारायण चौधरी)

विश्वास नहीं करता। राजा और महाराजा, नवाब और बादशाह की कमी कोई जाति नहीं होती, वे सबके होते हैं। महाराणा प्रताप, महाराजा शिवाजी, महाराजा सूरजमल इनको जाति विशेष से आइडेंटीफाई करके इनकी पोजीशन को बिलिटिल नहीं किया जाय।

मान्यवर, ये नेशनल हीरोज थे और आज हम उनका सम्मान करते हैं। वह तत्कालीन समय था जब इन लोगों ने संघर्ष किया था। उन परिस्थितियों को देखिए, उन हालात को देखिए, आज तो जनतन्त्र है, चाहे जैसा बोल सकते हैं, चाहे जहां बैठ सकते हैं, चाहे जो खा सकते हैं, चाहे जो पी सकते हैं, उस जमाने का अन्दाजा लगाइये जब कठिन परिस्थितियों के अन्दर देश गुजर रहा था, तब महाराजा सूरजमल ने भरतपुर रियासत को स्टेब्लिश किया। मुगलों का राज जमा नहीं था, जम भी गया तो कोई बात नहीं, वे देश के बाहर से आये हुए उस समय के शासक थे उनको उखाड़ा जा सकता था, और वह देश भक्ति का काम था। उन्होंने रियासत बनायी थी। मान्यवर, रियासत ही नहीं बनवायी, मैं एडिशनल इफेक्ट देने के लिए और जोड़ूंगा। उन्होंने वह रियासत बनायी कि जो भी उनके सक्सेसर रहे, वह देशभक्त थे। उनके बाद में एक महाराजा किशन सिंह हुए। महाराजा किशनसिंह आपको मालूम है, मान्यवर, गिरफ्तार करके अंग्रेज लंदन में ले गए, वहीं उनकी डेथ हुई और उनके बच्चे वहीं पर पाले गए थे। आज के जो महाराजा हैं उनका पालन-पोषण भी वहीं अंग्रेजों के पास में हुआ था। वह महाराजा किशनसिंह, महाराजा सूरजमल के उत्तराधिकारी थे। मान्यवर, जब महाराजा भरतपुर अंग्रेजों से लड़ रहे थे और उनके गढ़ को अंग्रेज काबू नहीं कर सके, रियासत को काबू में नहीं कर सके थे। गांव-गांव में होली के दिनों में यह गाना जोड़ा गया था कि "अंग्रेज हट जा, भरतपुर का गढ़ बांका", यह गांव-गांव के अन्दर गाये जाते रहे। आज भी गाये जाते हैं। अब मैं नहीं कहता जोधपुर में है कि नहीं। लेकिन मैं जिस जगह से आता हूं सीकर, झुन्झुनूं, और चूरू वगैरह के अन्दर आज भी होली के दिनों में यह गाया जाता है कि "गोरा हट जा, भरतपुर का गढ़ बांका"। इस प्रकार के हमारे नेशनल हीरोज हैं। महाराणा प्रताप का तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। किन परिस्थितियों में वे लड़े थे, घास खाकर और जंगलों में रह कर। हमारे जिन हीरोज ने संघर्ष किया, उनके बारे में आज जो सीरियल बन रहे हैं, वह सीरियल हम देखेंगे। मान्यवर, संघर्ष हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर। उन सीरियल्स को फेंक दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, चौमू से आने वाले माननीय सदस्य के विचारों का समर्थन करता हूं कि तमाम मतभेद भुलाकर नेशनल हीरोज के ऊपर कोई भी डाक्यूमेंटरी फिल्म बने, कोई भी सीरियल बने, उनके सम्बन्ध में हम इस बात से सर्वसम्मत राय दें कि इस प्रकार के सीरियल नहीं बनाए जाने चाहिए। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उन भावनाओं के साथ अपनी भावनाएं मिलाते हुए सदन से, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रकार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ये मसला महाराजा सूरजमल के मान और सम्मान का नहीं है अपितु राष्ट्र के इतिहास के सम्मान का प्रश्न है। राष्ट्र के सम्मान का प्रश्न है। महाराजा सूरजमल का इतिहास केवल राजस्थान का इतिहास नहीं है। महाराजा सूरजमल का नाम भारतवर्ष के इतिहास में एक महान अद्वितीय योद्धा के रूप में लिया जाता है। एक बहुत ही अच्छे प्रशासक के रूप में लिया जाता है। एक बहुत ही रणयोद्धा और रणकुशल के रूप में लिया जाता है। मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता हूं। यदि महाराजा सूरजमल ने बगरू का युद्ध जयपुर के मैदानों पर नहीं लड़ा होता तो आज जयपुर की गद्दी पर कोई दूसरा ही खानदान बिराजा हुआ होता। ऐसा योद्धा जिसके बारे में जयपुर में पेशवा से बात होते समय पेशवा ने पूछा था, तब महाराजा सूरजमल राजकुमार था, क्या सूरजमल का राजतिलक हो गया? उस समय के राज कवि ने कहा था कि "केहर को अब शेख तब तीनों विप्र समाज। केहर को अब शेख तब तीनों विप्र समाज, निज भुज बल के तेज सो विपुल भयो नगराज।" तो ये जो बहादुर लोग होते हैं वो अपने भुजबल से राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं, अपना नाम शासन में पैदा करते हैं। महाराजा सूरजमल को इस प्रकार से ग्रेट मराठा के अन्दर अपमानित किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि संजय खान एक राष्ट्रीय हीरो को अपमानित करके हिन्दुस्तान और राजस्थान के अन्दर एक षड्यंत्र का काम कर रहे हैं। यह आदमी हिन्दुस्तान में एक विद्रोह पैदा करना चाहता है। कभी राजपूतों को भड़काना चाहता है, कभी जाटों को भड़काना चाहता है। महाराजा सूरजमल की फौज के अन्दर तो कोई जाट ही थे क्या? उनकी फौज में सिपहसालार ब्राह्मण थे, उनकी फौज के अन्दर हर कौम के लोग थे। जब देहली पर गए थे वो लड़ने के लिए तब हर कौम का व्यक्ति उनके साथ में था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं महाराजा सूरजमल का इतिहास है, उसमें इस प्रकार से छींटाकशी हो रही है। मैंने खुद ने देखा है आज ग्रेट मराठा आता है सुबह नौ बजे, आप महावीर जी देख लेना उसमें सूरजमल का अच्छी प्रकार से चित्रण नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे करबद्ध सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार के सीरियल, 'ग्रेट मराठा जैसे सीरियल्स चलते रहे तो राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर में एक विप्लव पैदा हो जाएगा। कानून व्यवस्था का प्रश्न राज्य सरकार के सामने उपस्थित हो जाएगा। प्रदेश की सारी कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि इस प्रकार के षड्यंत्रकारी जो सीरियल्स इस राजस्थान में बनाए जा रहे हैं और राजस्थान की सरकार सीरियल्स को बनाने के लिए कन्सेशन दे रही है। ग्रेट मराठा, अकबर द ग्रेट सीरियल्स को बनाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से संजय खान को कन्सेशन दिए जा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में बहुत

Page No.10

(श्री हरिसिंह)

सोच-समझकर काम करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पेशेवर के लिए, किसी भी ऐसे आदमी के लिए जो नौटंकी करता है, इस प्रकार के काम करता है, उसको इस प्रकार से हिन्दुस्तान के इतिहास को, हमारे देश के इतिहास को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को यह चाहिए कि इतिहास के सम्बन्ध में जो भी सीरियल्स बनें, उनको बहुत अच्छी तरीके से देखा जाए, बारीकी से देखा जाए। यह देखा जाए कि यह इतिहास की कसौटी पर खरे उतरते हैं अथवा नहीं उतरते हैं। तब जाकर ऐसे सीरियल्स को अलाउ किया जाए और सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बनाया था संजय खान ने। उसमें भी बहुत एतराज हुए थे। उसमें शुरू में लिखा जाता था कि यह कोई इतिहास से सम्बन्धित सीरियल नहीं है, एक नॉवल के आधार पर सीरियल बनाया गया है। ऐसा लिखा जाता था। उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा था? ग्रेट मराठा के अन्दर तो यह बात भी नहीं लिखी जा रही है। यह तो ऐसा लगता है जैसे कि इतिहास का कोई चित्रण कर रहा हो, बहुत बड़े इतिहासकार संजय खान बन रहे हों। पेशेवर आदमी के सम्बन्ध में यह कहने में कोई संकोच या शर्म नहीं कि यह आदमी हिन्दुस्तान के अन्दर एक षड्यंत्र करके हिन्दुस्तान की तवारीख को बदल कर हिन्दुस्तान के अपने हीरोज हैं, उनका अपमान करके हिन्दुस्तान में कानून-व्यवस्था स्थिति को बिगाड़ना चाहता है। श्रीमन्, यह सदन आज प्रस्ताव पास करे कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के सीरियल्स इतिहास को तोड़-मरोड़कर जिनमें राष्ट्रीय नेताओं का अपमान हो, बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री अरुण सिंह (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वीरभूमि राजस्थान पर महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप का इतिहास में बहुत बड़ा कंट्रिब्यूशन रहा है। मैं चाहूंगा माननीय घनश्याम तिवाड़ी ने जो सुझाव दिया, जो प्रस्ताव रखा, सर्वसम्मति से संजय खान का जो सीरियल है, उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। खास तौर पर इस राजपूताना या राजस्थान पर इसकी शूटिंग नहीं होनी चाहिए। ढाई सौ साल पहले जब उत्तर भारत पर अन्याय हो रहा था, महाराजा सूरजमल जो डीग और सिनसिनी में पैदा हुए, शोषितों को इकट्ठा किया और शोषण करने वालों के खिलाफ जातिगत राजनीति से ऊपर उठ कर, उनके सेनापति ब्राह्मण थे, जाटव खजाने की चाबी रखते थे और गुर्जरों का दूध पिया, शोषण करने वालों के खिलाफ दिल्ली पर चढ़ाई करके दिल्ली के फाटक तोड़ दिये। तो इस वीर भूमि पर सरकार ने जो गलत परमिशन दी है, उसे वह तुरन्त विद ड्रा करे। संजय खान पाकिस्तान में जाकर ऐसी शूटिंग करे।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपत सिंह।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल हीरोज और उनका सही डिपिक्शन आवश्यक नहीं है। लेकिन इतिहास को जिस तरह से ब्रिटिशकाल में और मुगल काल में ट्विस्ट

(श्री नरपतसिंह राजवी)

किया गया और उसी इतिहास को सही मानकर अगर डिपिक्शन किया गया तो आज के आत्म-सम्मान रखने वाले एक नागरिक और एक राष्ट्रभक्त नागरिक के ऊपर क्या गुजरेगी ? यहां पर महाराजा सूरजमल जी के दो वंशज विराजमान भी हैं। उनको चिन्ता होना तो स्वाभाविक था ही लेकिन इस सदन के सभी माननीय सदस्य 199 जो यहां विराजे है, उन सभी को उतनी ही चिन्ता है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका अगर गलत डिपिक्शन हुआ है तो न केवल शूटिंग रुकनी चाहिए बल्कि उन व्यक्तियों को दण्डित भी किया जाना चाहिए।

मुगल बादशाहों के खिलाफ लड़ते-लड़ते आजादी की लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की और स्थिति यह आ गयी थी कि लोग कहते थे कि बादशाही शाह आलम हर दिल्ली का पालम। पालम से आगे शाह आलम की बादशाही ही नहीं थी। उस आजादी की लड़ाई की शुरुआत करने वाले महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल जी का अगर डिपिक्शन होता है तो प्रत्येक राजस्थानी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है और न केवल शूटिंग बन्द होनी चाहिए, अगर स्क्रिप्ट को एग्जामिन नहीं किया गया तो तुरन्त कर लिया जाय और हाउस के अन्दर एश्योरेंस दिया जाय। इसमें इतिहास की बात कही गयी है। राजा सूरजमल जी थे वे राज धर्म निभाते थे और मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्या आज भी दिल्ली सरकार के साथ उसी प्रकार से इस सदन के माननीय सदस्यों को लड़ना पड़ेगा कि सही डिपिक्शन हो। महाराणा प्रताप अगर सक्रिय थे तो उनके भी सेनापति मुसलमान थे और वीर थे। परन्तु अपने धर्म पर आस्था रखने वाले, राजस्थान के रहने वाले, उस राज्य तथा तत्कालीन रियासत में रहने वालों की आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन इतना ही करना चाहता हूं कि स्क्रिप्ट को देखे बिना, स्क्रिप्ट को एग्जामिन किये बिना आगे शूटिंग नहीं होनी चाहिए और सभी माननीय सदस्यों की भावना इसी के अनुरूप है यह सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महाराजा सूरजमलजी जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि खास जाति के राजा नहीं थे बल्कि उनके वंशज एक प्रतीक रहे धर्मनिरपेक्ष के लिए। उनके पूर्वजों ने ही भरतपुर में एक ही साथ मन्दिर और मस्जिद का निर्माण किया और सारे कर्मचारियों की तनख्वाह एक महीने की मन्दिर के लिए देते थे और एक महीने की तनख्वाह मस्जिद के लिए देते थे। इतिहास साक्षी है कि जब मराठा से खाण्डेराव होलकरजी पानीपत का युद्ध करने जा रहे थे तो वे महाराजा सूरजमलजी के यहां रुके और कहा कि मैं तो मुगलों से लड़ने के लिए जा रहा हूं और आपने मन्दिर और मस्जिद बराबर में बना रखे हैं। उन्होंने कहा कि मुगलों के खिलाफ लड़ाई आपसे ज्यादा मेरी है लेकिन जहां तक मन्दिर और मस्जिद है, यह तो ईश्वर और अल्लाह के स्थान हैं। इनके साथ हम कोई

Page No.12

(श्री जुबेर खान)

युद्ध या कोई राजनीति नहीं करना चाहते और खाण्डेराव होलकर जी वापस जब घायल होकर आये तो वे शहीद हो गये और आज भी उनकी कुम्हेर में छतरी बनी हुई है। इसी प्रकार महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा सांगा हो कोई नहीं कह सकता कि किसी समुदाय के या किसी जाति विशेष के लिए लड़े थे। वह इस देश के, राजस्थान के मान-सम्मान, मर्यादा के लिए लड़े थे। जैसे और लोगों ने भी समझौते किये थे उस टाइम के राजा-महाराजाओं ने, वैसे समझौते राणा सांगा और महाराणा प्रताप भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किये चाहे उन्हें जंगल में घास की रोटी खानी पड़ी हो लेकिन अपने देश के साथ, देश भक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया और कोई समझौता नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, किसको राज बुरा लगता है लेकिन यह लोग हमारे प्रतीक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान से जुड़े हुए जितने भी लौह पुरुष रहे हैं, इतिहास पुरुष रहे हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं उन पर अगर कोई सीरियल बनाया जाता है तो हमें कानून बनाने पड़े तो विधान सभा में कानून बनायें कि जब तक राजस्थान सरकार से उसको क्लिअरेंस नहीं मिल जायेगी तब तक उसके ऊपर शूटिंग नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई सीरियल नहीं बना सकते। यह हमें तय करना पड़ेगा। दुःख की बात, अध्यक्ष महोदय, यह है कि आज सारा सदन चिन्तित है और जब ग्रेट मराठा सीरियल की बात होती है उसमें इस प्रदेश का मुख्य मन्त्री भी उद्‌घाटन में जाता है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी को सारे सीरियल की स्क्रिप्ट देखनी चाहिए थी कि हमारे लोगों का इतिहास कहीं तोड़-मरोड़ के तो नहीं पेश किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सदन अगर चिन्तित है तो यह निर्णय ले और सब लोग बैठ कर तय करें कि हम विधान सभा में एक ऐसा कानून पास कर रहे हैं कि, जब भी हमारे राजस्थान के इतिहास पुरुषों से सम्बन्धित कोई भी सीरियल बनेगा, चाहे जरुरत पड़े तो सदन की एक कमेटी पहले बनायी जाय और उस कमेटी से अप्रूवल लेने के बाद ही सीरियल बने। एक बात और है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तो शूटिंग रोक देंगे लेकिन हमारे ही पूर्वजों का इतिहास तोड़-मरोड़ कर अगर कहीं दूसरी जगह शूटिंग होगी तो उसका हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार के सामने भी एक प्रस्ताव रखना पड़े तो रखें कि जब भी कोई सीरियल बने तो राजस्थान सरकार से पूछे बगैर हमारे लोगों के मर्यादा पुरुषों के खिलाफ, इतिहास पुरुषों के खिलाफ, देश भक्तों के खिलाफ कोई सीरियल नहीं बनेगा, उनसे सम्बन्धित कोई सीरियल नहीं बनेगा। यह मैं कहना चाहता हूं आपसे। आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंह।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी मौका दें।

श्री अध्यक्ष : मैं नाम बोल रहा हूं। मेरे सब ध्यान में है। थोड़ी सी शांति रखें तो तसल्ली होगी। उतावले होने से गड़बड़ होती है।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान भारत के इतिहास की तरफ दिलाना चाहता हूं कि वास्तव में लूटेरे अगर भारत में आये तो वह मुगल थे, तुर्क थे, पठान थे और उन्होंने हमारे मन्दिर लूटे, हमारी मर्यादाओं को तोड़ा और फूट के कारण ही यहां पर शासन किया । उन शासकों के विरूद्ध भारत को आजादी दिलाने के लिए महान नेता, राष्ट्र वीर पैदा हुए । आप महाराणा प्रताप को लें, राणा सांगा को लें, गुरु गोविन्द सिंह को लें । जो यह सीरियल बना है उसमें इन दोनों का अपमान किया गया है जिन वीर नेताओं ने हिन्दुत्व की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पण किया था । मैं इस सदन के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि इसके माध्यम से हिन्दु समाज, हिन्दु धर्म को टेस पहुंचायी है । अभी जो यहां कहा गया है मैं उससे आगे निवेदन करना चाहता हूं कि यह धारा 153 (ए) भा.द.सं. का अपराध है । इसके लिए प्रथम इतला रिपोर्ट दर्ज करायी जाय, वह रील जो इन्होंने बनायी है, जिस तरह की बनायी है उसको जब्त किया जाय और जिन्होंने इसको बनाया है उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि आयंदा कोई भी हिम्मत नहीं कर सकें । यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो ग्रेट मराठा सीरियल बनाया जा रहा है । बड़े दुःख की बात है कि हमारे देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने खून दिया, कुर्बानी दी, इस राजस्थान की वीर भूमि पर जहां आन–बान और शान के लिए लोगों ने कुर्बानी की हो उस राजस्थान की वीर भूमि के ऊपर ही उन्होंने राजस्थान का अपमान करने के लिए इस प्रकार का सीरियल बनाया इससे बड़ी +++ की बात और क्या हो सकती है । इसलिए मेरा आज इस सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि हमारे जिन वीरों ने चाहे झांसी वाली रानी रही हो, जिनके बारे में कहा जाता है कि "खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी" । ऐसे ही महाराणा प्रताप और बड़े-बड़े वीर प्रदेश भूमि पर पैदा हुए थे और जिनकी हठ आज भी प्रसिद्ध है "त्रिया तेल हमीर-हठ चढे न दूजी बार" । ऐसे ऐसे महा पुरुष, त्यागी, तपस्वी और वीर पैदा हुए । आज इस राजस्थान के अन्दर आकर के बगैर हमारी किसी की स्वीकृति के जिन लोगों ने इसकी स्वीकृति दी या जिन लोगों ने यह कहा कि राजस्थान में जाकर इस प्रकार की शूटिंग करिये तो ऐसे लोगों के खिलाफ, कार्यवाही की जाय और मैं इस बात में शामिल होता हूं कि राजस्थान का सदन इस बात का सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करें कि जिन लोगों ने इसकी स्वीकृति दी है उन लोगों की जांच की जाय और जांच करने के बाद दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय । साथ ही भविष्य में इस प्रकार का कोई सीरियल बनता है जिससे राष्ट्र और प्रदेश की गरिमा गिरती हो, समाज की गरिमा गिरती हो, वीर भूमि पर वीर पैदा होने वाले वीरों की

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

Page No.14

(श्री रामस्वरूप मीणा)

गरिमा गिरती हो, वीर जाति की गरिमा गिरती हो तो इस प्रकार के सीरियल को नहीं बनने देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारे सीरियल इसलिए बनाये जाते हैं ताकि लोगों को शिक्षा मिले, जिन लोगों ने महान कार्य किये हैं उनको हम याद करें, उनका इतिहास याद करें ताकि हमारे बच्चे भी वीर बने, देश प्रेम की भावना पैदा हो, राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हो लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज उन भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज इन बातों को केवल मनोरंजन का साधन बना दिया गया है। यह मनोरंजन की चीजें नहीं हैं। यह शिक्षा की चीजें हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी शिक्षा के अन्दर नैतिकता जरुर होनी चाहिए। बच्चों को नैतिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर हम नैतिक शिक्षा नहीं दे सकें तो हमारी शिक्षा बेकार है। इस प्रकार हमारे जो भी मनोरंजन के साधन बन रहे हैं उनमें सबसे पहले राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति प्रमुख हो उसके बाद में ही मनोरंजन का ध्यान रखा जाए। इसलिए यह जितने भी सीरियल बनाये जा रहे हैं उनकी पहले स्वीकृति लेनी चाहिए और उसके बाद ही बनाये जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, चर्चा यह है कि महाराजा सुरजमलजी को एक लूटेरे के रूप में चित्रित किया जा रहा है ऐसी कोई बात है। मैं तो विशेष नहीं बोलकर के एक अनुरोध करूंगा कि महाराज सूरजमल एक राजा के रूप में उस समय पदस्थापित हुये और उन्होंने एक राज कायम किया। सवाल यह नहीं है। सवाल इस बात का है कि उस समय इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़कर तथ्यों को पेश किया। हकीकत यह है कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम सही विवेचन करें तो महाराजा सूरजमल दिल्ली की सल्तनत में जो अन्याय वहां आस-पास की पिजेन्टरी पर हो रहा था, उस पिजेन्टरी के नेता थे और वहां पूरे बल्लभगढ़ से फरीदाबाद और भिंड मुरेना तक जितनी भी पिजेन्टरी जिसमें सब जातियां सम्मिलित थीं, उस अन्याय के खिलाफ उन्होंने एक आवाज उठाकर अपना एक नेता तय किया था और जिनका नाम था सूरजमल। उन्होंने उनको अपना राजा घोषित किया। आज अगर आदमी कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी भगतसिंह और चन्द्रशेखर ने कई बैंकों में डकैती डाली और लूटा तो उनको आज डकैत और लूटेरे कहे, यह अन्याय होगा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ यह अन्याय वाली बात है, क्योंकि उस संग्राम को चलाने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी और आजादी की लड़ाई की एक कड़ी थी। महाराजा सूरजमल ने कभी कोई डकैतियां नहीं डालीं। अपनी फौज को संचालित करने के लिए, यहां तक कि उनकी फौज में स्वेच्छा से लोग बिना वेतन के उनके साथ रहते थे। वह पिजेन्टरी के नेता थे और उनके चरित्र हनन की कोई प्रक्रिया अपनायी जाये तो इतिहास के साथ ही अन्याय नहीं है बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जिसमें पूरा आगरा, मथुरा और दिल्ली तक का हिस्सा, भिंड–मुरेना और

(श्री हरिसिंह)

यहां पांचोली, जयपुर की सरहद जहां तक है और भरतपुर की सीमा टच कर रही थी, उस पूरी पिजेन्टरी के वह नेता थे, उन सबके साथ अन्याय है। वह वहां के सर्वमान्य नेता थे। जनता के बनाये हुए शासक थे, उनके चरित्र हनन की प्रक्रिया को रोका जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वेन्द्र सिंह।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं कि महाराजा सूरजमल जी के प्रति सभी ने इतनी श्रद्धा दिखायी है पार्टी लाइन्स को तोड़कर। दो चीजें मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि महाराजा सूरजमल के राज की और महाराजा सूरजमल की खासियत रही है जिसकी वजह से इतिहासकारों ने मुगल जमाना हो, या अंग्रेजों का जमाना हो, या अब चल रहा जमाना हो, मुगल साम्राज्य में कभी भी भरतपुर से मुगलों के लिए डोला नहीं गया जो और राजपूताना की स्टेट्स से गया है। भरतपुर की कोई लड़की या बहन, राज खानदान की या किसी और भी खानदान की सत्ता प्राप्त करने के लिए मुगलों के लिए नहीं दी गयी।

दूसरा, चाहे वह लार्ड लेक हो, चाहे महाराजा सूरजमल हो, चाहे उनके बाद वाली पीढ़ी हो, अंग्रेज 18 बार सफलता प्राप्त नहीं कर पाये और महाराजा बलवंत सिंह की माइनोरिटी में ब्रिटिश को हायर किया गया था कि भरतपुर को कोंकर करें, क्योंकि उनके चाचा दुर्जनसिंह गद्दी पर बैठ गये थे, तब जाकर अंग्रेज भरतपुर में घुसे। आज ज्यादा मैं कहूं तो मुझे शोभा नहीं देगा, क्योंकि माननीय सदस्य मुझसे ज्यादा विद्वान हैं। काफी कुछ चर्चा हो चुकी है तो यही निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि जैसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य सरकार महाराज सूरजमल के प्रति श्रद्धा रखती है, तो जयपुर में एक उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाये जिससे कि उनकी एक आदमकद की प्रतिमा हम यहां स्थापित कर सकें। इतना ही मेरा निवेदन है और साथ में एक यह भी निवेदन है कि स्क्रिप्ट किसी ने नहीं पढ़ी....

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह : स्क्रिप्ट की जब तक कापी सबको उपलब्ध नहीं करायी जाये, मेरे ख्याल से अपना कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र चौधरी (विलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में दी ग्रेट मराठा सीरियल में जो महाराजा सूरजमल के प्रति....

श्री अध्यक्ष : आज सुबह आ रहा था। सीरियल देखा है आपने।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जिस तरह से आपत्तिजनक विवरण दिया गया है....

श्री जुबेर खान : एक टी. वी. यहां लगवा दिया जाये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : वास्तव में जैसा कि नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा स्क्रिप्ट किसी ने नहीं पढ़ी। भैरोंसिंह जी वहां चले गये, दूसरे नेता वहां चले गये, उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि वह

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

जानते नहीं थे कि उसके अन्दर क्या बात है। चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमारी जो विरासत है। हमारे प्रान्त का त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। चाहे वह महाराणा प्रताप थे, चाहे वह महाराजा सूरजमल थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत से हमेशा संघर्ष किया। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने उस भावना को नहीं समझ कर हिन्दु की बात कह दी, जबकि हिन्दु वाली कोई बात है नहीं वहां पर। जिस तरह से रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उदाहरण देकर बताया उस समय सभी इस बात को जानते हैं कि महाराजा सूरजमल की रियासत में किस तरह से मन्दिर-मस्जिद की राज्य की तरफ से समान व्यवस्था की गयी थी। महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान थे। उन्होंने अपनी रियासत में जनता की सेवा के लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। और आज जिस तरह से यह स्क्रिप्ट और सीरियल बनाया जा रहा है, मेरी आपसे गुजारिश और अनुरोध है कि पूरे सदन की भावना इसमें एक है। हम हमारी तरफ से सरकार को सदन का यह प्रस्ताव दें कि इस सीरियल को तत्काल बन्द किया जाये, जो आपत्तिजनक अंश हैं उनको रोका जाये और केन्द्र सरकार को भी हमारी सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाये कि इस सम्बन्ध में तत्काल उसके ऊपर रोक लगायी जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दर लाल।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, महाराजा सूरजमल की जो फिल्म बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक ही बात बताऊं। दिल्ली के किवाड़ हाथियों से नहीं टूटे तो किवाड़ों पर वीर लगाकर हाथियों की टक्करों से किवाड़ों को तोड़ा, उस आदमी को आप +++ बताओ इससे भी और बुरी बात होगी क्या। मैं तो गृह मंत्री को एक बात बताना चाहता हूं कि यह आदमी मैं देखकर आया हूं कि सामोद में शूटिंग कर रहे हैं। एक आदमी के एक बार में तीन नाम बोले हैं। कदे तो वह राणी बण जावे है, वा कदे की बण जावे है, तो 109 की धारा लगती है। सारे 109 में बन्द करवा दो। इनको एक आदमी तीन नाम तीन बार बताये, कदे पिता का नाम बता दे, कदे कोई राजा बण जावे है, कदे कोई बादशाह बण जावे है कदे कुछ बण जाये इसी धारा 109 में बन्द करके थाने में बिठा दो, रात ही इसका फैसला हो जायेगा। हरिजनों का तो कदे–कदे ही मौका लागे है कि मारो बैठकर निभेलो... (व्यवधान) क्या दिक्कत आती है? रोला ही मिटेगा। इसमें जिद करने की जरूरत नहीं, अपने को तो मौका इतना ही मिला है कि कह दो भाई जब्त तो सारे ठाकुर भी राजी हो जायें, जाट भी राजी हो जायें और अपणा भी काम चल जाये। इसलिए ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है। आप एस.पी. को भेजो और उनको बन्द करा दो, हम तो यही कहना चाहते हैं। इस मामले की ज्यादा चर्चा ही नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : तो गृह मंत्रीजी कुछ

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

बोल रहे हैं आप ?....(व्यवधान)....पहले स्क्रिप्ट के बारे में बोल लें....(व्यवधान).... वह स्क्रिप्ट के बारे में बोल रहे हैं....(व्यवधान)....अब यह क्या हो रहा है। अभी सवाल उठा है कि स्क्रिप्ट किसी ने देखी नहीं है, तो आपको मालूम हो जाये। हां, गृह मंत्रीजी बोलिये....(व्यवधान)....प्लीज प्लीज। सिट डाउन प्लीज....(व्यवधान).... बैठिये आप। हां बोलिये।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, टी. वी. सीरियल के बारे में जब से यहां चर्चा चली, पिछली बार अकबर दी ग्रेट को लेकर चर्चा चली थी। कल दी ग्रेट मराठा को लेकर जो चर्चा चली, उसके बाद राज्य सरकार भी इस बारे में बहुत ही गम्भीरता से जुट गयी। क्योंकि सदस्यों की जो भावनाएं हैं वे भावनाएं और हमारी सामान्य जो धारणाएं हैं हमारे महापुरुषों के बारे में, इतिहास में जो उनका स्थान है, उसके बारे में उसकी अभिव्यक्ति थी। मैं तो यहां तक निवेदन कर सकता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में अनेकानेक महापुरुष, अनेकानेक महावीर और योद्धा समय-समय पर बाहर से आने वाले आततायियों और आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़े हैं। हमारा इतिहास उसी का प्रतीक है। अगर इतिहास से महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल जैसे नाम अगर निकाल दिये जायं हिन्दुस्तान के इतिहास से तो मेरा ऐसा ख्याल है कि स्वाभिमान और स्वतन्त्रता यह दो शब्द भी हमको डिक्शनरी से निकालने पड़ेंगे। यह वह योद्धा हैं जिन्होंने देश के स्वाभिमान, देश की स्वतन्त्रता, देश के अस्तित्व के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया जिसको अन्तिम बलिदान कहते हैं उस सीमा तक गये हैं। इस भावना के साथ जुड़ते हुए मैंने त्वरित गति के साथ कार्यवाही की है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरसरी तौर से स्क्रिप्ट को देखने की बात भी कर ली गयी है और....(व्यवधान)....इसलिए मैं व्यवस्था भी बता देता हूं, थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि, बहुत गम्भीर विषय है और इसको हम लाइटली नहीं लें तो अच्छा है।

मुझे अफसोस यह हुआ कि कई बार बिना जानकारी के जब हम बोल लेते हैं, जैसे यहां एक बात कही गयी, मैं क्षमा चाहते हुए, रामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक से कहना चाहता हूं, उन्होंने कह दिया यहां पर "ग्रेट मराठा" के प्रसंग में, सारी चर्चा उठी और सारे सदन की भावनाएं जिस तरह उद्वेलित थीं, उन्होंने जाके कह दिया कि मुख्य मंत्रीजी "ग्रेट मराठा" के उसमें गए थे, समारोह में, उसके प्रारम्भ होने के समय में। यह नितान्त गलत है, मुख्य मंत्री राजस्थान के, "ग्रेट मराठा" के किसी भी सीरियल को न देखने गये न उसको किसी प्रारम्भ कराने में गये। हम ऐसे गम्भीर विषय पर जब बात करते हैं उस समय बिना सोचे समझे मुख्य मंत्री का नाम घसीट लिया कि वह भी वहां जाकर आए हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगा, जिस स्तर की चर्चा थी, जिस गम्भीरता की चर्चा थी और जानकारी नहीं थी, तो मेरे से जानकारी कर लेते। मैं उनको सही जानकारी दे देता। इस तरह यह जिस तरह से असत्य कथन किया गया यह असत्य कथन से मुझको लगा कि हम राजनैतिक

(श्री कैलाश मेघवाल)

धरातल से भी ऊपर नहीं उठ सकते लेकिन यह विषय राजनैतिक धरातल से ऊपर उठने का है और इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले में गम्भीर है। कल ही मुख्य सचिव ने हिन्दुस्तान के दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल को एक पत्र लिखा है और उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि राजस्थान की विधान सभा के सदस्य और राजस्थान की जनता जो कि समाचार पत्रों में आया इस तरह की कुछ चर्चाओं के बारे में उद्वेलित है और आप देखें कि हमारे ये इतिहास पुरुष और ये राष्ट्र पुरुष हैं, उनके बारे में, उनकी छवि को किसी भी तरह की गिराने वाली चीज इस स्क्रिप्ट में नहीं आए। यह कल लिख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा और प्रतिपक्ष के सदस्य तो सीधा अपना सम्बन्ध दिल्ली से रखते भी हैं, राज्य सरकार लिख रही है। मैं अपने स्तर पर सूचना और प्रसारण मंत्री को एक पत्र लिखूंगा इस बारे में, यह मैं विधान सभा में घोषणा करना चाहता हूं। आप भी अपने प्रयत्न कीजिए, यह सबके प्रयत्न का काम है कि हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में, मैं दो पत्र यहां पढ़ना चाहता हूं। दो पत्र इसलिए पढ़ना चाहता हूं....

श्री नाथूराम अहारी : आप हस्ताक्षर करवाकर के....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, दो पत्र यहां पर पढ़ना चाहता हूं। दो पत्र इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि स्थिति, जो अब तक राज्य सरकार ने कार्यवाही की है वह भी सामने आ जाये कि आगे इस बारे में क्या करना चाहती है। एक तो मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स है जो कि "ग्रेट अकबर" सीरियल वह बना रहे हैं, छोटा सा है दो मिनट में पढ़ देता हूं मैं।

"The script of Mega TV serial 'Akbar The Great' was scrutinised by the committee appointed by the Ministry of Information & Broadcasting, Government of India before granting formal permission on 8th April, 1993. Our unit has since then been working for the shooting of this TV serial in Jaipur district for being telecast by Doordarshan. This is not merely a television programme but an humble attempt in the task of national building. This work of mine is dedicated to my motherland. In the manuscript no reference, whatsoever has been made to the great freedom fighter and national hero Maharana Pratap which may have an adverse bearing on his image. On the contrary we are trying to project the historic image of Maharana Pratap as indomitable freedom fighter and a great warrior. Therefore, there arises no question of refering to Maharana Pratap as a traitor etc in the serial. I am, personally, taking care to ensure that while filming this Mega serial

(श्री कैलाश मेघवाल)

for Doordarshan, the historic image of this great warrior of India is shot befittingly."

यह है महाराणा प्रताप के बारे में जो सीरियल कर रहे हैं उसकी जो स्क्रिप्ट है, वह मैंने आपके सामने पढ़कर निवेदन किया है और इस बारे में दूसरा पत्र जो है वह है न्यूमरो यूनो इण्टरनेशनल, जो कि "ग्रेट मराठा" का वह कर रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : यह पहले वाला किसका था, किसका था ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह था मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स जो "द ग्रेट अकबर" का वह कर रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : इस पर आप विश्वास कर रहे हैं....

श्री कैलाश मेघवाल : जो राज्य सरकार के पास जानकारी आयी है और जो उन्होंने पत्र लिखा है, जो स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है । दिल्ली में दूरदर्शन को लिख दिया गया है और लिखेंगे, सदन की सारी भावनाओं से अवगत....

श्री अध्यक्ष : एक बात, एक बात अब मैं निवेदन करूं, जब आप इस मामले को सीरियस ले रहे हैं तो सीरियस लीजिए । जो आपने कहा है राज्य सरकार उसको सपोर्ट कर रही है । राज्य सरकार जो भी उसमें सम्भव कदम उठा सकती है अपने स्तर पर और केन्द्र के स्तर पर, उसके तथ्य और विवरण आपको दे रहे हैं लेकिन इस समय कोई कमेण्ट करें आप तो उचित नहीं है । आप सीरियसली सुनिए । आपने जब मामला उठाया है तो यह कोई नॉन सीरियस नहीं है जब इन माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कर रही है वह आपके सामने तथ्य रख रही है । अभी तो आप शांति से सुन लीजिए....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : वह पत्र की जानकारी थी, किसका था वह....

श्री अध्यक्ष : वह तो पढ़कर बताया न उन्होंने....(व्यवधान)....नहीं, नहीं, आपने कहा न कि आप विश्वास कर रहे हैं ? यह कह रहा हूं मैं विश्वास, अविश्वास नहीं तथ्य आ रहा है आपके सामने ।

श्री कैलाश मेघवाल : अब यह एश्योरेंसेज हैं, आखिर हम कार्यवाही तो उन्हीं पर करेंगे । उनका एश्योरेंस आया । आगे इस पर वॉच रखेंगे । दूसरा पत्र है, माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यूमरो यूनो इण्टरनेशनल **Whomsover It May Concerb. I, Mohafiz Hyder, the script writer of the TV serial "The Great Maratha" hereby confirm that the character of Suraj Mal Jat has not been portrayed as a dacoit in our serial. The said character is presented with all its authencity taken from history. The history line is based on the writing of Mr. Manohar Malgaokar, a historical novelist of international repute, supported by Mr. Garge, former**

(श्री कैलाश मेघवाल)

President, All India History Congress and Dr. Pawar, Head of the History Department Kolhapur, University. I further assure, that nothing derogatory about Suraj Mal Jat will appear in future in our serial which may be derogatory as the theme of this serial is X secularism, national intergration and glorification of our leaders who fought against invaders. I again assert that the role of Suraj Mal Jat has been portrayed according to history and nothing derogatory or unhistorical is presented in our serial." यह दो पत्र तो राज्य सरकार ने मंगाये हैं। स्क्रिप्ट हमने, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरसरी तौर से देख ली गई है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि गम्भीरता से सारी स्क्रिप्ट का परीक्षण किया जाएगा और चूंकि इसमें हम कोई ज्यादा दखल नहीं दे सकते हम इसके लिए अपनी तरफ से केन्द्र सरकार को लिखेंगे कि इस बारे में वह दखल दे अगर हमारे राष्ट्रीय नेताओं की छवि को गिराने का कोई प्रयत्न किया गया है या किसी तरह का कोई रेफरेन्स आता है।

अब, अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मैं आपके और लूंगा कि सरकार का इसमें क्या रोल है। सरकार इसमें क्या सुविधा दे रही है? सरकार इसमें कोई सुविधा नहीं दे रही है। सीरियल करने वाले यहां आए हैं। जयगढ़ पैलेस या सामोद पैलेस में, जहां जहां यह सीरियल हो रही है वहां वह प्राइवेट प्रोपर्टीज हैं वह उन्होंने किराए पर ली है। सरकार का इतना इन्तजाम अवश्य है कि लॉ एण्ड आर्डर मेण्टेन करने, क्योंकि जिस तरह से एक्टर और वह आते हैं वहां भीड़ जमा हो जाती है और उनकी सुरक्षा का इन्तजाम करना, ट्रेफिक रेग्यूलेट करना वह सरकार का अपना जो कर्तव्य है, अपना दायित्व निर्वहन कर रही है। अन्यथा सरकार ने किसी तरह का कोई कन्सेशन या इनको किसी तरह की दूसरी सुविधा नहीं दी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पर्सनली इसको देखूंगा और देखने के बाद में, मैं सदन को भी विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में भी एक सीरियल की तीन स्टेज होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भी क्लीयर कर दूं। पहले प्रपोजल सबमिट किये जाते हैं, उन प्रपोजल के परीक्षण के बाद उस सीरियल को वापस री एडिट करती है कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी जिसका इसमें रेफरेन्स आया और उस कमेटी के बाद जब सीरियल को क्लीयरेंस दी जाती है और क्लीयरेंस के बाद जब शूटिंग होती है। शूटिंग के बाद Again it goes for final screening. और उस फाइनल स्क्रीनिंग के बाद यह टेलीकास्ट पर आती है तो यह तीन-चार स्टेज हैं। मैं आपके द्वारा सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं दिल्ली में जो भी सम्बन्धित लोग हैं उनको इस बारे में लिखूंगा कि फाइनल टेलीकास्ट के बाद वह यह निश्चित कर लें, आश्वस्त हो जाएं कि हमारे इन दो महापुरुषों, इन दो राष्ट्रीय महापुरुषों की छवि को गिराने वाली कोई स्थिति इन सीरियल्स में नहीं आए। सरकार इस बारे में जागरूक है और सदस्यों

Page No.21

(श्री कैलाश मेघवाल)

की भावनाओं के साथ अपने को जोड़ते हुए हर सम्भव प्रयत्न करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों की छवि जैसी है वह कायम रहे।

एक निवेदन और करना चाहता हूं जबकि प्रसंग आ गया, क्योंकि इतिहास का प्रसंग है, मैं जब जनसंघ में काम करता था। तब से हम एक मांग करते आ रहे हैं कि यह जो आज का इतिहास है यह जिस पृष्ठभूमि में और जिनके द्वारा यह लिखाया गया उसमें कई जगह हमारे राष्ट्रीय महा-पुरुषों के चरित्र को गलत ढंग से व्यक्त किया गया है। हिस्ट्री है हमारे फ्रीडम मूवमेण्ट की और उसके पहले के इन्वेडर्स के खिलाफ जो हिन्दुस्तानी लड़े हैं, हिन्दुस्तान का आदमी लड़ा है, उसकी हिस्ट्री का पुनर्लेखन होना चाहिए तभी हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों का वास्तविक चरित्र सामने आ पाएगा।

(12.00)

उसके लिए भी सरकार प्रयत्नशील है, हम प्रयत्नशील हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हिस्ट्री में जो भी तोड़-मरोड़ और एडल्ट्रेशन स्वार्थों के द्वारा उस समय के अंग्रेज रूलर्स के द्वारा या और दूसरे रूलर्स के द्वारा किया गया है वह उससे निकाल करके हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों की धवल छवि सामने आये ऐसे इतिहास के लेखन के बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और कोशिश कर रही है।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, इसमें हाउस की अगर एक कमेटी गठित कर दी जाये जो इसको देख ले तो सभी की भावना आ जायेगी।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। आपने किये मैं भी तो कर रहा हूं।....मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूं....मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, उससे पहले एक मिनट का समय। गृह मन्त्रीजी ने जो पत्र पढ़ा, अध्यक्ष महोदय, कितनी गम्भीर बात है कि कितनी आसानी से गृह मंत्रीजी ने पत्र पढ़ दिया जिसमें महाराजा सूरजमल को सूरजमल जाट कहा गया है। जैसे महाराणा प्रताप को सिर्फ प्रताप कहें, महात्मा गांधी को सिर्फ मोहन-दास कर्मचन्द कहें और दो दफा जिस आसानी से पढ़ दिया। आपके मन में पीड़ा नहीं हुई? आपने महसूस नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी....

श्री अध्यक्ष : Now you all are inte-rwine in to the controversy. इसलिए मैं इस विषय को अब यहीं समाप्त कर रहा हूं....

श्री जगदीप धनखड़ : ....महाराजा सूरजमल को सूरजमल जाट कहना अत्यन्त आपत्तिजनक है....

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरे विचार सुन लीजिए। अब आप बैठिये देखिये अब आपका मूड बदल रहा है। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये....इस सम्बन्ध

(श्री अध्यक्ष)

में दो सीरियल्स पर यहां पर चर्चा हुई और उसमें मैंने माननीय सदस्यों को गम्भीरता से सुना। मुझे जो लगता है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज हमारे देश में इन्टीग्रेशन की सबसे बड़ी आवश्यकता और महत्ता है। जिस तरह की देश में परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं उन परिस्थितियों में हमारा देश संगठित रहे ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम, ऐसे विचार अधिक से अधिक प्रसारित होने चाहिए। आवश्यकता इस बात की है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस आवश्यकता के ठीक विपरीत इस प्रकार के सीरियल्स बनाये जा रहे हैं कि जिनमें कन्ट्रोवर्सी आना अनिवार्य है। उसमें आप दो घोड़ों की सवारी नहीं कर सकते। जब आप किसी इन्टीग्रेशन के हित में जब किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते तो दूसरे का भी नहीं लेना चाहिए और या इस प्रकार के सीरियल कि जो आज की परिस्थिति में फिट-इन नहीं हैं और जो उल्टे इस वातावरण को और बिगाड़ सकते हैं, इस प्रकार के सीरियल्स नहीं आने चाहिए और केन्द्र सरकार को इसके बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे देश में एकता की है। इस एकता पर चोट पहुंचाने वाला कोई भी सीरियल है वह नहीं आयें और इसलिए यह दोनों सीरियल्स जिस तरह से बने हैं इसमें 'आइदर आर' नहीं है क्योंकि इतिहास जिस तरीके का है उसको बदला नहीं गया है, वह है। तो उसको आधार बनाकर आप जो चाहे कह सकते हैं। जब दो आदमी लड़ रहे हों तो आप दोनों में से किसी को तो कहेंगे कि यह ठीक है और यह ठीक नहीं है। दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही ठीक नहीं हैं यह तो कभी दुनिया में होता नहीं है। आखिर देखने वाले निर्णय यह तो करेंगे कि किस ने गलती की और किस ने नहीं की। तो दोनों में से कोई एक फस्ट और दूसरा सैकिण्ड रहने वाले हैं। इस तरह के सवाल उठाना कि जिसमें उन दोनों की तुलना होकर यदि हम दोनों को ही महान मानना चाहते हैं तो दोनों को टकरा कर कैसे महान बनायेंगे मेरी समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में हमारी एकता आवश्यक है। इस दृष्टि से जो सरकार स्टेप्स ले रही है इसके लिए सरकार बहुत धन्यवाद की पात्र है कि सरकार ने अत्यन्त संवेदनशीलता के साथ माननीय सदस्यों के विचारों को लिया है और तुरन्त उन्होंने कार्यवाही शुरू की है। यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह केन्द्र सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाये कि एकता पर चोट पहुंचाने वाले सीरियल्स कि जिनमें हमारे दो महापुरुषों की तुलना होकर उन दोनों में से किसी एक पर भी रिफ्लेक्शन आता है तो उससे निश्चित रूप से एकता पर खतरा होगा। इसलिए इस प्रकार के जो विवादित सीरियल्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाये. उनको बनाने की इजाजत नहीं दी जाये और ऐसे ही सीरियल्स बनाने की इजाजत दी जाये जो हमारी एकता को मजबूत करने वाले हों। मैं समझता हूं कि इसके बाद अब इस पर चर्चा करना उचित नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (व्यवधान) ....आप बैठिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि एक स्वायत्तशासी बोर्ड है उस पर निरन्तर आक्रमण किये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को राष्ट्रपति शासन के अन्दर भंग किया गया। वह लोग हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने इस बात का निर्णय किया कि इस बोर्ड को राष्ट्रपति शासन में जो भंग किया वह गैरकानूनी भंग किया है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। वह जीत कर आ गये। बोर्ड फिर बहाल हो गया है लेकिन उसके चेयरमैन को आज तक तनख्वाह नहीं दी गयी है और उसके अलावा अभी जब माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने सदन को यह आश्वासन दिया कि लड़कों को जो दो प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए जो निर्देश किये हैं उसके बारे में मैं चेयरमैन साहब से बात करके निर्णय करूंगा। तो इन्होंने उस बोर्ड की स्वायत्तता को फिर चैलेन्ज किया है और फिर आदेश दिये शिक्षा विभाग ने जो अखबारों में छपा है कि हमने धारा 28 के अन्दर उसको निरस्त कर दिया है। इस तरह से ह्यूमिलियेशन किया जा रहा है बारबार शिक्षा विभाग द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 131 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी एक लगा रखा है जो अभी तक मेरा नहीं आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग इस तरीके से शिक्षा विभाग के लोगों का ह्यूमिलियेशन नहीं करे। उन लोगों को नीचा दिखाने की कार्यवाही नहीं की जाय। इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य ने बात उठाई है मैं भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन की बात है आज जो स्थिति बोर्ड की हो रही है कि बहाल होने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ध्यान देकर शीघ्र कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को बूंदी तहसील के ठीकरियाचाणा गांव के पास ईंटों के भट्टे खोदते समय चार व्यक्ति दबकर मर गये। मैं उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर ईंटों के भट्टे आजकल बहुत लग रहे हैं उनको एक स्थान अलग से दिया जाये और जहां से मिट्टी लायी जाती है उसका भी एक निश्चित स्थान किया जाये जिससे कि दुर्घटनाएं नहीं हों। पूर्व में भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटी हैं इसलिए आगे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि ईंटों के भट्टे एक स्थान पर लगें और मिट्टी अलग स्थान से आये। उससे गांव वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुटोली ग्राम में एक जिंक स्मैल्टर

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

लगा हुआ है, परन्तु उस जिक स्मैल्टर से आये दिन एसिड युक्त पानी निकलता है जिस पानी में एसिड मिला हुआ है और उस पानी को बेड़च नदी में छोड़ा जाता है। इस एसिड युक्त पानी का असर कम से कम दो-चार दिन तक रहता है। इस अवधि में यदि कोई भी पशु या कोई भी मवेशी इस पानी को पी जाये या उसमें बैठ जायें तो उस पशु की तुरन्त मृत्यु हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिक स्मैल्टर से एसिड युक्त पानी को बेडच नदी में नहीं छोड़ा जाये एवं उसकी व्यवस्था अलग से करायी जाये।

मैं 13.3.1994 को जिक स्मैल्टर के पास ग्राम नगरी का दौरा करने गया था। उसी दिन प्रातः चार बजे जिक स्मैल्टर का एसिड युक्त पानी बेड़च नदी में छोड़ा गया था जिससे तीन मवेशियों की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाने में एक एफ. आई. आर. दर्ज करवायी गयी है जिक स्मैल्टर के विरुद्ध। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि जिक स्मैल्टर का एसिड युक्त पानी बेड़च नदी में नहीं छोड़ा जाए तथा जिक स्मैल्टर के अधिकारियों से मरने वाले मवेशियों के मालिकों को मुआवजा दिलाया जाए। जिस प्रकार से एसिड युक्त पानी बेड़च नदी में मिलाया जाता है उससे गांव में पशुओं की मृत्यु होती है। जो पशु उस पानी के अन्दर पांव दे देता है उसकी चमड़ी जल जाती है और धीरे-धीरे करके वह मर जाता है। इस प्रकार के दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : 295, श्री अमरा राम।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भूपालसागर को गन्ना बेचने से किसानों में व्याप्त असंतोष

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत लोक महत्व के प्रश्न पर निवेदन है कि दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भूपालसागर जो कि एक बीमार मिल बतायी जाती है, इस मिल के पक्ष में राज्य सरकार एक आदेश निकाल कर किसानों को मजबूर कर रही है....

(12.13)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

कि वे अपना गन्ना मिल मालिक की मर्जी के भावों पर इस मिल को ही बेचें। मिल मालिक ने इस वर्ष गन्ने का मूल्य केवल पचास रुपये प्रति क्विण्टल ही देने का निर्णय किया है जब कि गुड़, खाण्डसारी व पेयरस वाले किसान को साठ रुपये से सत्तर रुपये प्रति क्विण्टल तक देने को तैयार हैं। परन्तु इस आदेश से वे किसान गुड़, खाण्डसारी व पेयरस वालों को गन्ना नहीं बेच पा रहे हैं। किसान व उसके संगठनों ने सरकार की इस किसान विरोधी नीति का विरोध समय-समय पर ज्ञापन देकर किया है, परन्तु सरकार ने इस मिल मालिक के प्रभाव में आकर किसान विरोधी रुख अख्तियार किये है। किसान दिनांक 24 जनवरी, 1994 के बाद से इस मिल को गन्ना बावजूद पाबन्दी के नहीं दे रहे हैं और पाबन्दी होने से ऊंचे दामों पर गुड़, खाण्डसारी वालों को भी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे मार्च माह में अत्यधिक गर्मी पड़ने से इस पके-पकाये गन्ने में नुकसान होना प्रारम्भ हो गया है।

(श्री अमराराम)

सरकार के इस अड़ियल रुख के कारण चित्तौड़ जिले के हजारों किसान आज परेशान व जलील हो रहे हैं, अतः यह अति लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए सदन की तमाम कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा की जाए।

श्री सभापति : भाषण नहीं दीजिए, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एमामुद्दीन अहमद खान। (अनुपस्थित)। माननीय श्री हीरालाल सहरिया।

किशनगंज (बारां) में डिग्री कॉलेज

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): सभापति महोदय,. नियम 295 के तहत किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कालेज खोले जाने के क्रम में निवेदन है कि किशनगंज विधान सभा क्षेत्र जिला बारां में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उप खण्ड स्तर पर एक भी डिग्री कालेज नहीं है, जबकि इस क्षेत्र में लगभग 10 माध्यमिक, दो सीनियर व दो छात्रा माध्यमिक विद्यालय हैं। इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति–जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति के बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर बारां या शिवपुरी जाना पड़ता है, जो निर्धन बालकों के लिए महंगा पड़ता है। इसलिए श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इस आदिवासी सहरिया बहुल उप खण्ड क्षेत्र में एक डिग्री कालेज अवश्य खोलने का श्रम करें, जिससे गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सकेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राकेश मेघवाल।

प्रदेश में सीमेण्ट फैक्ट्रियों द्वारा फैल रहा प्रदूषण

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, सीमेण्ट फैक्ट्री द्वारा भयंकर रूप से फैलाये जा रहे प्रदूषण से हो रही जान-माल की हानि के विषय में नियम 295 के तहत निवेदन है कि आज राजस्थान के काफी स्थान प्रदूषण की चपेट में हैं। लगातार धन कमाने की नीयत से गलत तरीके से नयी सीमेण्ट फैक्ट्रीज घनी आबादी के पास लगायी जा रही हैं। उनसे दूषित धुआं, गर्दा व सीमेण्ट का पाउडर हवा में दूर तक फैल जाता है, जिससे बीस किलोमीटर की परिधि में आस-पास फसल, घास, पेड़-पौधे तथा पीने के पोखर, कुएं आदि दूषित हो जाते हैं तथा उक्त क्षेत्र के मनुष्य व पशुधन प्राणघातक बीमारियों टीबी व कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। उक्त उद्योग ट्रीटमैण्ट प्लाण्ट के बिना ही चल रहे हैं तथा बिना प्रदूषण रोकने वाले संयंत्र लगाये ही एन ओ सी प्राप्त कर लेते हैं। इसका भयंकर रूप से प्रकोप गरीब जनता व उक्त उद्योगों में लगे मजदूरों पर होता है। उक्त क्षेत्र की फसल नष्ट हो जाती है, पेड़-पौधों की पत्तियों पर सीमेण्ट जमा हो जाती है जिससे पशुधन के चरने के लिए चारे की भी समस्या हो जाती है।

आज नागौर जिले में कई स्थानों पर उक्त समस्या है तथा सीकर जिले के

(श्री राकेश मेघवाल)

नीमकाथाना क्षेत्र में सीमेण्ट उद्योग से भयंकर रूप से प्रदूषण फैल रहा है, जिससे उक्त क्षेत्रों में टीबी व कैंसर की बीमारी फैल गयी है। इसकी शिकायत बार-बार सम्बन्धित विभागों में की गयी है। सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत मांग करता हूं कि उक्त सभी सीमेण्ट प्लाण्टों पर प्रदूषण रोकने के संयंत्र लगाने पर ही एन. ओ. सी. दी जाये तथा उसकी अवहेलना पर सख्त कार्यवाही की जाये। दर्शायी गयी सीमेण्ट फैक्ट्रियों की जांच कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। यह अति लोक महत्व का प्रस्ताव है, अविलम्ब कार्यवाही करवाएं।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : आई विथड्रा।

श्री सभापति : माननीय श्री रामगोपाल बैरवा। (अनुपस्थित)।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापति जी, कल हम लोगों ने पर्ची दी थी अपने क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं के लिए, लेकिन कल दो डिमाण्ड्स थीं–एक तो अकाल राहत और एक खनिज, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी थी कि आज नहीं इन पर्चियों पर कल बोलेंगे। उसके अन्दर मेरा एक महत्वपूर्ण विषय था उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं दो मिनट।

श्री सभापति : अभी तो 295 चल रहा है, जब बजट पर सामान्य बहस होगी उस वक्त देख लेंगे।

माननीय श्री रामेश्वर भारद्वाज।

कब्रिस्तान (शास्त्री नगर, जयपुर) पर नाजायज कब्जा

श्री रामेश्वर भारद्वाज (मूर्तिकार) (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत, चांदपोल, शास्त्री नगर स्थित कब्रिस्तान पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख है कि चांदपोल बाहर स्थित मुस्लिम समाज के पवित्र कब्रिस्तान पर लगातार कुछ व्यक्तियों द्वारा असीमित निर्माण करवाया जा रहा है और यह प्रक्रिया दिन-प्रतिदिन चालू है। आज के दिन भी वहां निर्माण कार्य अबाध गति से चालू है। इसको रुकवाने के सम्बन्ध में समाज के बन्धुओं ने समय समय पर अनेकानेक शिकायतें भी की हैं, उनका भी कोई असर इन अवैध निर्माणकर्ताओं पर नहीं हो रहा है। आज भी समाज के अनेक बन्धुओं ने आकर इस अवैध निर्माण पर विरोध एवं आक्रोश प्रकट किया। यदि ऐसे पवित्र स्थानों पर भी अवैध निर्माण होने दिया गया, जो कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, तो मजबूर होकर समाज को कोई आन्दोलनात्मक रुख अपनाना पड़ेगा, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस क्षेत्र में शान्ति भंग होने का वातावरण बनेगा जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी।

पूर्व में इसी प्रकार का जन आन्दोलन वास बदनपुरा में समाज के द्वारा हो चुका है, उसी प्रकार का जन आन्दोलन यह भी हो सकता है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर अविलम्ब कार्यवाही

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

कर उन अवैध निर्माणों को हटाकर मुस्लिम समाज की इस पवित्र भूमि को खाली करा दें ताकि समाज इस चिन्ता से मुक्त हो सके।

श्री सभापति : आपने पढ़ दिया। माननीय श्री पराक्रम सिंह। (अनुपस्थित)। माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा।

अस्थायी व्याख्याताओं को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना

श्री कन्हैया लाल मीणा (वस्सी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राजकीय महाविद्यालयों के समस्त अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी किये जाने तथा लोक सेवा आयोग की स्थायी भर्ती प्रक्रिया को अविलम्ब रुकवाने के क्रम में उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, इस राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त अस्थायी व्याख्याताओं की ओर से ध्यान आकर्षित कर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि :-

(1) राज्य में 1982, 1984 तथा 1986 के बाद किसी भी विषय में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन नहीं किये गये हैं। जबकि नियमानुसार प्रतिवर्ष स्थायी चयन करना अनिवार्य था। अतः नियमों की अवहेलना व दुरुपयोग राज्य प्रशासन व लोक सेवा आयोग लगातार करता आ रहा है जिसमें इन अस्थायी व्याख्याताओं का कोई दोष नहीं है। अब अचानक नियमों की दुहाई व आड़ लेकर तथा इतने लम्बे अंतराल के बाद प्रशासन अनेक वर्षों से कार्यरत शिक्षक वर्ग की प्रतिस्पर्धा इनके द्वारा पढ़ाये गये छात्रों के साथ करवा रहा है जो न्यायोचित नहीं है।

(2) राष्ट्रपति शासन में 17 जून, 1993 को थोपी हुई अधिसूचना द्वारा व्याख्याता चयन शैक्षणिक योग्यताओं में परिवर्तन किया गया है जिसमें कार्यरत अस्थायी व्याख्याता अयोग्य घोषित कर दिये गये हैं। जबकि ये सभी नियुक्ति के समय की प्रभावी शैक्षणिक योग्यताओं को पूरी करने के बाद तथा मैरिट सूची में स्थान प्राप्त करने पर हुई है। साथ ही सभी अनेक वर्षों तक मैरिट सूची में प्रतिवर्ष परिवर्तन के बाद भी अपना स्थान बनाये रखकर सेवारत रहे हैं। इसलिए ये व्याख्याता किसी भी प्रकार की बैक डोर एण्ट्री से नियुक्त नहीं हुये हैं। इन नियुक्तियों में नये आशार्थियों तथा रिसर्च स्कालर को भी चयन का मौका 1992 तक प्रतिवर्ष मिलता रहा है।

इसलिए इन पदों पर नये आशार्थियों का कोई अधिकार नहीं है इसके अलावा आज इनको अचानक अयोग्य मानना इनके साथ तो अन्याय है ही साथ ही उन विद्यार्थियों के प्रति भी अन्याय है जिनको इन्होंने पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं। इसलिये इन्हें कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा लागू मैरिट फार्मूले के आधार पर ही स्थायी किया जाना चाहिये।

(3) राज्य सरकार विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों में भेदभाव

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

कर रही है जबकि दोनों तरह के व्याख्याताओं को समान यू.जी.सी. वेतनमान प्राप्त होते हैं इसलिये स्थायीकरण करने की दिशा में महाविद्यालयों के अस्थायी व्याख्याताओं के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाये। यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति व जनजाति के वैधानिक आरक्षण नियम का पालन भी नहीं किया गया है जबकि कॉले अस्थायी व्याख्याताओं की नियुक्ति के संदर्भ में आरक्षण नीति का शत-प्रतिशत पालन किया गया है।

(4) अस्थायी व्याख्याताओं को नियमित करने से सरकार के राजकोष पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ता है, क्योंकि कार्यरत व्याख्याताओं को नियमित व्याख्याताओं के समान सभी लाभ सरकार द्वारा देय हैं।

(5) पड़ौसी राज्य सरकारों, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में अध्यादेश द्वारा अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी किया जाता रहा है यह मात्र राजस्थान के शिक्षक वर्ग के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि एक ओर तो देश के अन्य समस्त राज्यों के प्रत्याशियों की भीड़ व्याख्याताओं के चयन के नाम पर लोक सेवा आयोग द्वारा आमंत्रित कर ली गयी है तो दूसरी ओर इन सभी राज्यों में ऐसे अस्थायी व्याख्याताओं को अध्यादेश द्वारा स्थायी किया गया है जिसमें राजस्थान राज्य के प्रत्याशियों को उपरोक्त राज्यों में चयन का मौका नहीं मिला है। अतः अध्यादेश का विधेयक द्वारा राजस्थान में इन कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी न करना पूर्णतया अन्यायपूर्ण है।

(6) वर्तमान में मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने 1977-78 में राजस्थान विश्वविद्यालय के अस्थायी व्याख्याताओं को अध्यादेश द्वारा स्थायी किया था तथा उनका अनुसरण करते हुये देश के अन्य राज्यों में भी अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी किया जाता रहा है। अतः राज्य के समस्त कॉलेज अस्थायी व्याख्याताओं को भी अध्यादेश या विधेयक द्वारा स्थायी किया जाय। यही नहीं तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने भी 26 फरवरी, 1992 को बजट सत्र के दौरान विधान सभा में यह घोषणा की थी कि सभी अस्थायी व्याख्याताओं को इसी सत्र में स्थायी कर दिया जायेगा। उनकी यह घोषणा वर्तमान में भी कायम है।

(7) व्याख्याताओं का लोक सेवा आयोग का मात्र "साक्षात्कार" द्वारा चयन भी सन्देहास्पद है क्योंकि इसमें लिखित परीक्षा, विभिन्न शैक्षणिक योग्यता व कार्यानुभव का कोई महत्व नहीं है। 1986 में किये गये व्याख्याताओं के चयन भी विवादास्पद रहे थे जिसकी जांच के आदेश तत्कालीन राज्यपाल श्री बसंतदादा पाटिल ने दिये थे। उस समय भी वर्षों से कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं को सड़कों पर बैठा दिया गया था इसलिए यदि इन कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं का चयन लोक सेवा आयोग नहीं करता है तो ये वर्षों के सेवाकाल के बाद कहां जायेंगे।

(8) इतने लम्बे समय तक कार्यरत

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

रहकर आज अनेक व्याख्याता राज्य सेवा में नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा भी पार कर चुके हैं तथा इनके पारिवारिक दायित्व भी बढ़ गये हैं। ऐसी स्थिति में उनके भविष्य तथा जीविका को अनिश्चित बनाकर न केवल उनके वरन् उनके परिवार व समाज के प्रति भी अन्याय किया जा रहा है।

(9) महाविद्यालयों में कार्यरत सभी अस्थायी व्याख्याताओं का अच्छा शैक्षणिक स्तर रहा है तथा इन्होंने सभी कक्षाओं के अध्यापन कार्य व अन्य कर्तव्यों का बड़ी ईमानदारी व लगन के साथ निर्वाह किया है। इनके द्वारा पढ़ाई गयी कक्षाओं के परिणाम भी उत्तम रहे हैं। इन सभी की जांच राज्य सरकार समय-समय पर करती रही है।

(10) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी स्थायी व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया को तुरंत वापस लिया जाये क्योंकि आयोग के चैयरमैन ने स्वयं 14 फरवरी, 94 को आल राजस्थान कॉलेज टेम्परेरी लेक्चरर्स के सदस्यों से भेंटवार्ता के दौरान यह स्वीकार किया है कि विगत शिक्षा सचिव ने आयोग को एक पक्षीय तथ्य रखे जिसमें व्याख्याताओं के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए प्रशासन द्वारा शिक्षक विरोधी तथा जल्दबाजी में प्रेषित स्थायी भर्ती को वापस लेकर निरस्त किया जाय।

(11) इन अस्थायी व्याख्याताओं की पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा उभरते सामाजिक असंतोष तथा कुण्ठाओं को नजर अन्दाज न किया जावे।

अब माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अस्थायी व्याख्याताओं की समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रपति शासन में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरम्भ की गयी स्थायी भर्ती प्रक्रिया को अविलम्ब रद्द करवायें तथा अध्यादेश या विधेयक द्वारा समस्त कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं की सेवाओं को स्थायी करवायें।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीर सिंह। (अनुपस्थित)। माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

पांचना बांध (सवाई माधोपुर) का पानी

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत जिला सवाई माधोपुर के पांचना बांध का पानी नादोती तहसील के ग्रामों को देने के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन है कि सवाई माधोपुर के सबसे बड़े बांध पांचना जिस पर सरकार का करोड़ों रुपया लग गया है और इसका निर्माण तहसील नादोती की बंजर भूमि को सिंचित करने के लिए हुआ था पर बड़े दुःख की बात है कि इस नादोती तहसील के माण एरिया को पानी नहीं दिया जा रहा है। इस क्षेत्र की सीमा पर नहर आ चुकी है। पर उसकी पीलोदा से कूंजेला, लाहद, सोप, सरत, केमा, गुढली, खुड़ा, चैनपुरा, दड़ीबागोर, होदायली, खेमरी, बीला पाड़ा, नादौती, गड़खेरा,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

गुढ़ाचन्द्रजी के लिए नहर का पानी जोड़ कर इस क्षेत्र में सिचाई की व्यवस्था करायी जावे। इस क्षेत्र में वर्षा के अलावा कोई भी पानी का साधन नहीं है। अकाल के कारण बांध सूख रहे हैं। पांचना का पानी बेकार भरा हुआ है। उसको खाली करवाकर रोसी, उजेला, केसला, सुरसेर, केमरी, आदि गांवों के बांधों में डाल दिया जाये तो मनुष्य एवं जानवरों के काम आ सकता है।

अत: मैं सरकार का ध्यान इस प्रक्रिया के द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि पांचना बांध का पानी तहसील नादोती को दिलवाकर पानी की समस्या को हल करेंगे और इस अकाल से ग्रसित क्षेत्र को बचायेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती तारा भण्डारी। (अनुपस्थित)।

नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी जयपुर की पेयजल समस्या के बारे में माननीय जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर की पेयजल और सीवरेज समस्या

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री महोदय का जयपुर नगर की पेयजल और सीवरेज समस्या पर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : माननीय सभापति जी, जयपुर शहर की 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 14.55 लाख एवं वर्तमान में अनुमानित 17.73 लाख है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वर्तमान जनसंख्या को लगभग 695 लाख गैलन पानी प्रति दिन की आवश्यकता है। इस मांग के विरुद्ध वर्तमान में जयपुर शहर में स्थापित 533 नलकूपों से 400 लाख गैलन एवं रामगढ़ बांध से 60 से 70लाख गैलन अर्थात् कुल 470 लाख गैलन पानी प्रति दिन वितरित किया जा रहा है। इस कमी की आंशिक पूर्ति हेतु वर्तमान में 3.80 करोड़ रुपये की एक पेयजल अभिवृद्धि योजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अन्तर्गत शहर में 40 अतिरिक्त नलकूपों का निर्माण, 130 अतिरिक्त हैण्ड पम्पों की स्थापना, पाइप लाइनें डालने व कुछ पम्पिंग मशीनरी बदलने के कार्य प्रस्तावित हैं। योजना के प्रथम चरण में माह मार्च, 1994 के अन्त तक उपरोक्त में से 20 अतिरिक्त नलकूप एवं 80 अतिरिक्त हैण्ड पम्प स्थापित करने के कार्य लक्षित हैं। शेष कार्य द्वितीय चरण में आगामी वित्तीय वर्ष 1994–95 में किये जाने प्रस्तावित हैं। भू-जल के प्रति वर्ष गिरते हुए स्तर को दृष्टिगत रखते हुए एक पूर्व सम्भाव्यत्ता रिपोर्ट तैयार करायी गयी है, जिसमें बीसलपुर बांध से जयपुर शहर की वर्ष की 2021 तक की जनसंख्या की पेयजल की मांग 1850 लाख गैलन प्रति दिन मात्रा की आपूर्ति तीन चरणों में प्रस्तावित है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

विशेषज्ञों द्वारा टोडारायसिंह, लावा, माधोराजपुरा, सांगानेर होते हुए जयपुर तक 110 किमी लम्बी पाइप लाइन प्रस्तावित की गयी है। इस परियोजना के पेयजल से सम्बन्धित भाग की कुल अनुमानित राशि लगभग 1495 करोड़ रुपये है। प्रथम चरण की राशि लगभग 612 करोड़ रुपये आंकी गयी हैं। प्रथम चरण के पूर्ण होने में लगभग 6 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है। इस प्रस्तावित परियोजना रिपोर्ट की प्रति विश्व बैंक को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रेषित की गयी है।

जयपुर शहर में सीवरेज सुविधा आंशिक रूप से उपलब्ध है। चारदीवारी क्षेत्र की लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या को सीवरेज सुविधा उपलब्ध है, जहां निष्कासित जल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में शोधित होकर निस्तारित होता है। बाहरी क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत भाग ही वर्तमान में सीवरेज सुविधायुक्त है, जो कि खुले नाले में प्रवाहित होता है। बाकी आबादी स्वयं द्वारा निर्मित सैप्टी टैंक एवं शाकपिट के माध्यम से मल निस्तारण की व्यवस्था करती है।

भू-जल के गिरते हुए स्तर एवं शहर की सीवरेज सुविधा में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा 442.40 रुपये (360.10 करोड़ रुपये जलप्रदाय हेतु एवं 82.30 करोड़ रुपये सीवरेज व्यवस्था हेतु) की पेयजल एवं सीवरेज योजना शहरी विकास मंत्रालय को माह अप्रेल, 1992 में प्रेषित की गयी थी, जिसको शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक को वित्तीय सहायता सुलभ कराने हेतु प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में यह योजना विश्व बैंक के विचाराधीन है।

उक्त योजना की स्वीकृति एवं आवश्यक धन संसाधन उपलब्ध होने पर ही योजना का क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यह वक्तव्य दिया। लेकिन वक्तव्य के जो तथ्य हैं उसमें एक बात साफ आपके तथ्य से ही प्रमाणित हो गयी है जयपुर को इस समय 695 लाख गैलन पानी की आवश्यकता है, 470 लाख गैलन दे रहे हैं, 225 लाख गैलन पानी की जयपुर में कमी है। मतलब यह तो सरकारी आंकड़ा है, इसी आंकड़े के हिसाब से भी 35 प्रतिशत लोगों को पानी अपन नहीं दे पा रहे हैं या 35 प्रतिशत पानी जयपुर को अपन कम सप्लाई कर रहे हैं लेकिन जो वास्तविकता है वह यह है कि जयपुर नगर की जो सीमा है उसको मंत्री जी क्या मानते हैं, चारदीवारी को मानते हैं, जयपुर का जो म्युनिसिपल एरिया पहले था उसको मानते हैं या जयपुर के कारपोरेशन का इलाका है उसको मानते हैं या जयपुर के जो विकास प्राधिकरण का इलाका है उसको मानते हैं? यदि जयपुर विकास प्राधिकरण के इलाके को छोड़ भी दिया जाय और जयपुर शहर का जो कारपोरेशन का इलाका है उस इलाके को माना जाय तो यहां की जनसंख्या जो 1991 के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आंकड़े के अनुसार 14 लाख 54 हजार 668 जनसंख्या थी, यह जनसंख्या नहीं है। जयपुर की जनसंख्या 1991 में 20 लाख थी और इस समय 1994 है और जयपुर म्युनिसिपल एरिया का आपने विस्तार भी कर दिया है और इस सारे आंकड़ों को देखने के बाद स्पष्ट है कि जयपुर में इस समय 300 एम. एल. डी पानी की रोज आवश्यकता है और इस समय 192 एम. एल.डी. पानी मिल रहा है। अपन जयपुर शहर में 55 पर्सेण्ट लोगों को पानी सप्लाई कर रहे हैं और 45 पर्सेण्ट लोगों को पानी जयपुर में उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। बाकी जो लोग पानी प्राप्त कर रहे हैं वह कहां से प्राप्त कर रहे हैं? कालोनीज बनी हुई हैं वहां पर कुछ आपने हैण्ड पम्प लगा दिये हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी मानसिकता क्या हो गयी है। सन् 1800 में जयपुर के पानी का सर्वे किया गया था शहर के अन्दर का, जैकब नामक एक इन्जीनियर थे उन्होंने उस समय सर्वे करके कहा कि जयपुर शहर की चारदीवारी का पानी जो हैण्ड पम्प और कुओं का है वह पेयजल के लायक नहीं है। आज भी हम यहां पर हैण्ड पम्प खोदते जा रहे हैं। यह जयपुर शहर का सौभाग्य है कि यहां पर दो-तीन बार बरसात हो गयी है, मैं माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा को लक्की आदमी मानता हूं कि वह जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री बने तो रामगढ़ बांध दोनों बार भर गया और जब रामगढ़ बांध दोनों बार भर गया तो चारदीवारी के अन्दर पानी आ गया। अगर यह बरसात थोड़ी सी कम होती तो जयपुर शहर को पानी उपलब्ध नहीं हो सकता था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी दिन भगवान न करे कि एक बरसात फेल हो जाय तो इतनी भयंकर समस्या होगी जितनी पानी की समस्या आज अजमेर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है। इसके लिए सरकार ने प्रयत्न किए हैं, एक सौ और कुछ ट्यूब वैल्स बनाए हैं लेकिन यह तो आग लगने पर कुआं खोदने के समान है। आज भी सरकार जयपुर शहर में आग लगने पर कुआं खोदने की कार्रवाई कर रही है और प्रति साल हमारे यहां पर ट्यूब वैल्स का पानी एक मीटर नीचे जा रहा है, और ज्यों-ज्यों पानी नीचे जा रहा है, फ्लोराइडयुक्त पानी बढ़ता जा रहा है। तो जयपुर शहर आज इस प्रकार के कगार पर पेयजल के लिए बैठा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम बीसलपुर से पानी लाने की योजना बना रहे हैं और विश्व बैंक को भेज रहे हैं। इसी प्रकार से सीवरेज के लिए कहा कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को हमने भेज दी है। वास्तविक स्थिति क्या है? जयपुर शहर में हम क्या करने जा रहे हैं? मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर में पानी के लिए भयंकर युद्ध होगा, दो-तीन साल में हो जायेगा और इसके लिए जिम्मेदार हम लोग होंगे। मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि बांडी-बेसिन के लिए हमने एक योजना बनायी, योजना पर दो करोड़ रुपया हमने खर्च किया लेकिन किसानों ने पानी नहीं लेने दिया। 7.56 करोड़ रुपये की योजना थी, ढाई करोड़ रुपये उस पर खर्च हो गये, ट्यूब वैल बने हुए हैं लेकिन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उनमें पानी नहीं आया और, मैं उस पानी को लाने के पक्ष में नहीं हूं बांडी-बेसिन से....(व्यवधान)....मैं इसलिए पानी लाने के पक्ष में नहीं हूं कि बांडी-बेसिन का पानी भी जयपुर को लम्बे समय तक पानी सप्लाई नहीं कर सकते और वहां पर सारे किसानों के खेत पानी के सूख जायेंगे....(व्यवधान)....आप मेरी बात सुन लें। जयपुर में आप कहीं से नहीं ला सकते। बाण गंगा पर आपने रामगढ़ बांध बना लिया, मानसी से आप पानी ला नहीं सकते, साहबी के पानी पर अब हरियाणा ने अपना काम कर लिया है। आपको पानी मिलना नहीं है। आपके पास दो स्रोत बचे हुए हैं, उन स्रोतों पर कार्यवाही आपने ठीक प्रकार से नहीं की। सभापति महोदय, मैंने इसीलिए कहा कि जयपुर में हानी युद्ध होगा। आप जयपुर में 20लाख लोगों को पानी के बिना प्यासा नहीं मारोगे, बड़ी स्कीम आपके पास नहीं है। आप कभी बांडी-बेसिन में जायेंगे, कभी काणोता-बेसिन में जायेंगे. कभी सांगानेर-बेसिन में जायेंगे, कहीं भी जायेंगे और वहां जाकर ट्यूब वैल खोदोगे और ट्यूब वैल खोदने का परिणाम किसानों को पानी नहीं मिलेगा। इससे तो नुकसान है। किसानों के खेत बरबाद होंगे ही होंगे, लेकिन जयपुर शहर में फल, सब्जी और दूध की सप्लाई भी रुक जायेगी और दूर-दूर से लाना पड़ेगा। जयपुर शहर में पेय-जल के लिए इस प्रकार के जो प्रयत्न किये जाने चाहिये थे, वह कभी भी प्रयत्न नहीं किये गये हैं, वह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर में एक कहावत है, लोग नारे लगाते हैं, लोग नारे लगाते हैं। जयपुर का एक ही लाल, भंवर लाल, भंवर लाल....(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : हमारे माधोपुर का भी एक ही लाल था, किरोड़ी लाल, किरोड़ी लाल। लालों का लाल, किरोड़ी लाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे कई लाल होते हैं, उनमें आप भी एक लाल हो। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आज तो वे नारे लगाते हैं लेकिन अगर इस बरसात में भी रामगढ़ में पानी नहीं आया तो शहर के अन्दर पानी की सप्लाई नहीं हो सकती। जयपुर शहर इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता कि कालीचरण जी को जिताकर भेज दिया, भंवरलालजी को जिता कर भेज दिया, रामेश्वर जी को भेज दिया, राजपालसिंह जी को भेज दिया और उजला जी को भेज दिया। इससे ज्यादा जयपुर शहर से आप क्या चाहते थे लेकिन पिछले ....(व्यवधान)....कृपया सुन लें। पानी का मामला है, आप भी कल बोल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर विशेष रूप से प्रयत्न नहीं किया गया और इसके लिए प्रयत्न करना बहुत ज्यादा जरूरी था। माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमने बीसलपुर से पानी लाने के लिए योजना बनाकर भेजी 620 करोड़ रुपये की प्रथम लागत की, कुल 1450 करोड़ रुपये की, इस योजना का क्या हुआ। इस योजना के बारे में कांग्रेस पार्टी ने और भाजपा की सरकार ने भी व्यवस्थित रूप से प्रयत्न करने की कार्यवाही नहीं की। दुनिया में शायद जयपुर ही 20 लाख की जनसंख्या का ऐसा शहर है जिसको आप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ट्यूब वैल से पानी सप्लाई कर रहे हैं और आप यह मानते हैं कि नाइट्रेट की मात्रा फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके बाद इन ट्यूब वैल पर आप जयपुर शहर को कब तक जिन्दा रखना चाहते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि आने वाले एक-दो साल में जयपुर पानी युद्ध के कगार पर पहुंच जायेगा और उस पानी युद्ध के लिए अगर कोई जिम्मेदार होंगे तो हम होंगे। एक तरफ किसान होंगे, वे कहेंगे कि हम ट्यूब वैल से पानी नहीं ले जाने देंगे और एक तरफ सरकार होगी, वह कहेगी कि 20 लाख लोगों को प्यासा नहीं मार सकते, यह स्थिति हमने जयपुर शहर में पैदा कर दी।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं सीवरेज की, जयपुर शहर में जो सबसे बड़ी समस्या यह है, आपने कहा कि इसमें 20 प्रतिशत लोग बाहर की आबादी वाले हैं वह सीवरेज से और बाकी शहर के लोग 80 प्रतिशत। सभापति महोदय, यहां शॉक-पिट खोदे जा रहे हैं जयपुर में लाखों की संख्या में, 50-50, 60-60 फीट तक ये गहरे चले गये हैं और जल स्तर के बराबर यह जाते जा रहे हैं। आप ट्यूब वैल से पानी लेना चाहते हैं और यह मल-मूत्र विसर्जन वाटर लेवल तक जाता जा रहा है। किसी दिन भयंकर संक्रामक बीमारी से जयपुर शहर ग्रसित होगा। उसका किसी के पास इलाज नहीं, पेयजल का इलाज नहीं। जयपुर को बसाने वाले बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने जयपुर में सबसे पहले नगर नियोजन किया और जयपुर ही ऐसा शहर है जिसने सबसे पहले पेयजल के स्रोतों का विकास किया। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ कि जयपुर शहर के बसते ही 1727 में 100 झालर जयपुर में बनाये गये। झालर कहते थे उनको, वे बनाये गये, उसके बाद में स्कीम की गई। अमानीशाह के नाले से भी की गयी और हरमाड़ा की घाटी को काटकर बांडी-बेसिन से बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ तक पानी लाने की व्यवस्था की गयी और 1900 के प्रारम्भ में जब यह सारी स्थिति हुई तो जयपुर को पानी देने के लिए रामगढ़, उस समय जयपुर में केवल 1200 कनेक्शन प्राइवेट और 300 कनेक्शन सार्वजनिक नलों के थे और उसके लिए उन्होंने 10 लाख गैलन पानी की व्यवस्था की। आज जयपुर शहर में 1.60 लाख कनेक्शन हैं और 1200 सार्वजनिक नल बनाये हुए हैं। उस समय जयपुर शहर के लिए 300 सार्वजनिक नल थे और आज के जयपुर के लिए सिर्फ 1200 सार्वजनिक नल हैं। उस समय जयपुर शहर में 1200 कनेक्शन थे, उनके लिए रामगढ़ से व्यवस्था की गयी, आज के जयपुर शहर में 1.60 लाख कनेक्शन तो हैं, उनके लिए आप इस पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर में जमवा रामगढ़ का बांध सिचाई के लिए बनाया गया था और पेयजल के लिए इसको इसलिए उपयोग में लाया गया कि जैकब ने रिपोर्ट दी कि जयपुर शहर के अन्दर का पानी पीने के योग्य नहीं है, चारदीवारी का पानी। इस प्रकार चारदीवारी में जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन हैण्ड पम्पों के ऊपर नोटिस बोर्ड लगा दिया जाना चाहिये कि ये हैण्ड पम्प पीने के पानी के योग्य नहीं है, केवल कपड़े

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

धोने के लायक है। अगर आपने यह नहीं किया तो जयपुर के साथ अन्याय करेंगे। जयपुर के पानी से पेट की बीमारी जितने लोगों को है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं बीसलपुर की बात पर आ रहा हूं कि बीसलपुर के लिए 620 करोड़ रुपये हम कहां से लायेंगे, इस योजना को कब तक पूरा करेंगे, राज्य सरकार कब तक पूरा कर पायेगी। मैं साफ कहना चाहता हूं, यह राज्य सरकार के बस में नहीं है, न आपका विभाग इस काम को कर सकता है और इसके लिए आवश्यकता है जयपुर के लिए वाटर सप्लाई कार्पोरेशन का गठन किया जाना चाहिये अलग से, अलग से गठन करके उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिये कि वह प्राइवेट लीजिंग एण्ड फाइनेंसिंग कम्पनियों से सब प्रकार से ऋण प्राप्त कर सके और उसको इस बात का भी अधिकार मिलना चाहिये कि जयपुर के पानी पर टैक्स बढ़ा सके। आज जयपुर में एक मजाक है। जयपुर में 9 करोड़ रुपया रेवेन्यू का आता है, 13 करोड़ रुपया बिजली के बिलों पर खर्च हो जाता है। जो जयपुर शहर के निवासी हैं, वे पानी ले रहे हैं और एक गांव का आदमी भी पानी ले रहा है, उसकी रेट आप बराबर करके चल रहे हैं जो अन्यायपूर्ण बात है। जयपुर का अगर आपको काम करना है तो आपको निश्चित होकर जयपुर मे पानी की दर बढ़ानी चाहिये, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार से आपको जयपुर में कार्पोरेशन की स्थापना करनी चाहिये, वह कार्पोरेशन उस प्रकार का नहीं, जैसा आपने कार्पोरेशन बना रखा है लोन लेने के लिए, राजस्थान वाटर एण्ड सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड बना रखा है। चार-पांच एक्स. ईएन. उसमें हो गये, फिर वे कभी बोर्ड में जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं, सात-सात चीफ इंजीनियर्स हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट बने हुए हैं, बाकी बातें तो जलदाय विभाग की मांगों के समय बोलूंगा, लेकिन जयपुर में अगर काम करना है तो 2001 तक आप पानी नहीं ले पायेंगे। आपने जोधपुर की स्कीम शुरू की थी 35 करोड़ रुपये से, वह जाकर 256 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी। जयपुर की आप 620 करोड़ रुपये से शुरू कर रहे हैं, इसके पहले 200 करोड़ की स्कीम बनी थी, 400 करोड़ की बनी थी, 620 करोड़ पर आ गयी, पूरा होते-होते 1400 करोड़ रुपये पर आ गये, जब ये सारी पूरी होगी तो 2000 करोड़ रुपये तक पहुंचेंगे और 2000 करोड़ रुपया तो अब तक सारे राजस्थान में हमने पेयजल पर 46 वर्षो में खर्च किया है। इस बात को गम्भीरता से अगर नहीं लिया गया और जयपुर की जो कहावत है वह चरितार्थ नहीं होगी। जयपुर में लोग कहते हैं कि भंवरलाल जी अमर हैं। मैं भी चाहता हूं कि अमर रहे लेकिन अमर फल जयपुर की जनता को दे जायें कि जयपुर की जनता को पानी मिलता रहे। बीसलपुर से ही नहीं होगा, आपको सेवती-धर्मपुर से 2011 में, आपका विभाग बता रहा है 2021 में, 2021 में नहीं सन् 2010 से आगे बीसलपुर का पानी जयपुर को नहीं दे सकते और मेरी तो मान्यता है कि जिस ढंग से काम किया जा रहा है, उस ढंग से काम किया गया तो 2001 तक जयपुर को पानी बीसलपुर से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किसी भी कीमत में नहीं आयेगा और 2001 तक पानी नहीं आयेगा तो 1996 से 2000 के बीच जो जयपुर आज पिंक सिटी है वह जयपुर डेजर्ट सिटी में बदल जायेगा, जैसे कनाडा के कई शहर बदल गये हैं पानी की कमी के कारण से। जयपुर को बसाने वाले ने इसकी कल्पना नहीं की। इसलिए जयपुर के नागरिकों के लिए, जयपुर के विधायकों के लिए, राजस्थान की संसद के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जयपुर जो गुलाबी शहर है, जो पिंक सिटी है उसको आप निश्चित रूप से कोई न कोई प्रयत्न करके अप्रेल के महीने में आप वाटर सीवरेज मैनेजमेन्ट कार्पोरेशन जयपुर नगर निगम के लिए अलग से बनाये। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर यह नहीं किया गया तो अमर फल की जगह मंत्री महोदय को लोग अमर बेल कहेंगे। मैं नहीं चाहता कि यह अमर बेल बने, मैं चाहता हूं आप अमर फल के रूप में बने और अमर फल के रूप में बीसलपुर का पानी जयपुर के लोगों को दें और जयपुर के लोग इसमे लाभान्वित हों तब तो यह कहावत चरितार्थ होगी कि "जयपुर का एक ही लाल–भंवरलाल", नहीं तो लाल ही लाल है, चेहरा लाल हो जायेगा बिना पानी के। इसलिए माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और मै माननीय मंत्री महोदय से निश्चित रूप से चाहूंगा कि बीसलपुर योजना के बारे में सोचे और आप कहां तक पानी देंगे ट्यूब वैल्स से।

एक माननीय सदस्य : एक लाल गिरधारी लाल भार्गव भी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे आजकल दिल्ली के लाल हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप ट्यूब वैल से कब तक पानी देंगे, हैण्डपम्प कब तक खोदते रहेंगे। बीसलपुर की योजना से निश्चित रूप से आप पानी शुरू करेंगे तो पानी दस वर्ष में पहुंचेगा और दस वर्ष में जयपुर उजड़ जायेगा। इसमें एक दिन, एक घण्टा, एक महीना भी बर्बाद करना जयपुर के साथ अन्याय करना है इसलिए मैं चाहता हूं जयपुर के लिए जिसका सबसे पहले मैनेजमेंट था, लोग कहते हैं कि राजशाही राजस्थान में थी इसके कारण से हमारा स्ट्रक्चर नहीं बना था, मैं आज कहता हूं कि जोधपुर जवाई बांध से पानी ले रहा है, वह राजशाही का काम है। जयपुर रामगढ़ से ले रहा है, यह भी राजशाही का काम है। उदयपुर भी ले रहा है। हमने 50 वर्षों में क्या किया है। अभी तो इन शहरों को पानी उस राजशाही द्वारा बनाये गये बांधों से थोड़ा-बहुत मिल रहा है, हमने तो आग लगने पर कुआं खोदा, ट्यूब वैल खोदा और उससे काम किया है। इस पर गम्भीरता से नहीं सोचेंगे तब तक जयपुर की पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं बाकी बातें पेयजल के बारे में आज जब डिमाण्ड होगी तो रखूंगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको बहुत गम्भीरता से लेकर जयपुर की सीवरेज और पानी की समस्या का समाधान करें। जयपुर के लिए एक हजार करोड़ रुपये की प्राथमिक योजना बनती है। एक हजार करोड़ रुपया राजकोष में नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस तरह से गुजरात में बहुत से शहरों में कार्पोरेशंस बन गये हैं और ये हर बात में विश्व बैंक की रट लगाते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं, मुझे बड़ा दुःख है, हिन्दुस्तान में और भी फाइनेंसियल कम्पनियां हैं। गुजरात में अभी 200 करोड़ रुपया सूरजशहर के लिए बम्बई की प्राइवेट लीजिंग एण्ड फाइनेंसियल कम्पनी से लिया गया है। पांच बैंकों ने मिलकर एक प्राइवेट लीजिंग एण्ड फाइनेंसिंग कम्पनी बनायी है। 200 करोड़ रुपया उन्होंने सूरजशहर की स्कीम के लिए लिया। क्या हम लोग प्राइवेट कार्पोरेशंस बनाकर हिन्दुस्तान में जो प्राइवेट कम्पनियां हैं जो उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं उनसे पैसा नहीं प्राप्त कर सकते। वह पैसा उनसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। या जो ढर्रा बना हुआ है योजनाएं बनाओ, भारत सरकार को भेजो, विश्व बैंक के पास भेजो, विश्व बैंक इनको कागज भेजता है कि तुम्हारे कानूनों में संशोधन करो, तुम कार्पोरेशन बनाओ, तुम इसके लिये वह कानून बनाओ, वह कानून लाओ, फिर राजस्थान सरकार वह कानून लाती है, फिर इनका विभाग चर्चा करता है, विभाग चर्चा करके बोर्ड को जाती है, बोर्ड में मिनिट्स पूरी नहीं होती, मिनिट्स होने के बाद वह बाहर निकलती है, और इस चक्कर में इस विभाग का सारा नाम डूबा हुआ है। आप वरिष्ठतम मंत्री हैं और इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या अवधारणा है, क्या नीति आप बनाने जा रहे हैं या विश्व बैंक पर डिपेण्ड होकर ही रहना चाहते हैं? विश्व बैंक के माध्यम से जयपुर का काम पूरा नहीं होगा, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। इस योजना को बनाने के लिए आप निश्चित घोषणा करें। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि पिछले वर्षों में राजनैतिक कारणों से जयपुर शहर की जितनी विकराल पेयजल की समस्या है उसका समाधान का प्रयास पिछले 40 साल में नहीं किया गया। क्योंकि जयपुर शहर शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और पिछले 40 सालों में तीन सालों को छोड़कर राजस्थान में कांग्रेस का राज रहा। इसलिए इतनी जबर्दस्त समस्या होते हुए भी कांग्रेस के राज ने जयपुर शहर की पेयजल समस्या के बारे में कोई समुचित ध्यान नहीं दिया और यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परन्तु पिछले तीन साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में है और जयपुर के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि पेयजल विभाग के मंत्री जयपुर के हवामहल से चुने हुए आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा हैं। साथ ही जयपुर शहर के पांचों विधायक जयपुर की जनता ने 20-25 हजार वोटों से जिताकर भेज दिए। अब तो जयपुर की जनता इस बात की अपेक्षा करती है और करनी भी चाहिए कि जयपुर की पेयजल समस्या का समाधान निश्चित रूप से जल्दी ही होगा। परन्तु आदरणीय मंत्री जी ने जो जवाब पेयजल समस्या के समाधान के लिए दिया उसको पढ़ कर मुझे तो ठेस लगी ही, जयपुर की जनता को भी निश्चित रूप से ठेस लगी होगी। माननीय मंत्रीजी ने माना है कि वर्तमान में जयपुर शहर की जनसंख्या 15 लाख 73 हजार

(श्री कालीचरण सराफ)

है। मैं इस वाद विवाद में नहीं जाऊंगा कि जयपुर शहर की जनसंख्या 20 लाख, 22 लाख या 25 लाख है लेकिन मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 15 लाख 73 हजार जनसंख्या वर्तमान में है और उसको 695 लाख गैलन पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। मंत्रीजी ने यह भी माना है कि इस समय केवल 470 लाख गैलन पानी जयपुर की जनता को दे रहे हैं। यानि जितना पानी देना चाहिए उसका 70 प्रतिशत पानी हम दे रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जयपुर शहर की 40 प्रतिशत जनसंख्या जो कृषि भूमि पर मकान बना कर रहती है और जो कच्ची बस्तियों में रहती है वहां पानी की जलदाय विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कच्ची बस्तियों में पानी दिया जायेगा यह घोषणा तो हो गयी परन्तु अभी तक कनेक्शन हुए नहीं। उनको यदि इसमें शामिल किया जायेगा तो यह मात्रा और भी कम हो जायेगी।

माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि 380 करोड़ रुपये की एक पेयजल योजना बनायी गई है। मैं पूछना चाहूंगा कि जब 40 ट्यूबवैल आप एक्स्ट्रा लगायेंगे और 130 हैण्ड पम्प आप और खोदेंगे उससे क्या 695 लाख गैलन पानी जो आपके हिसाब से चाहिए, मेरे हिसाब से ज्यादा चाहिए....

श्री सभापति : लीटर होगा, यह गैलन नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ : गैलन है। 695 लाख गैलन पानी जो आपके हिसाब से चाहिए क्या उसकी पूर्ति हो जायेगी ? अभी आप 470 लाख गैलन पानी दे रहे हैं। यह जो 380 करोड़ की योजना बनायी है उससे कितने लाख गैलन पानी मिलेगा। यह इससे पूरा बैकलॉग पूरा हो जायेगा, पूरा 695 लाख गैलन पानी जयपुर शहर को मिल जायेगा ? मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा सोचना है यह जो योजना बनायी है इससे 40 लाख गैलन पानी आप अतिरिक्त और उपलब्ध करायेंगे। 470 लाख अभी मिल रहा है, 40 लाख और इस तरह 510 लाख गैलन पानी आप दे पायेंगे। फिर भी 185 लाख गैलन पानी की कमी रहेगी। अब यह योजनायें टुकड़ों में हैं। 1989 में वाण्डी बेसिन योजना बनी, 7 करोड़ 56 लाख की योजना बनी। 2.5 करोड़ रुपये उसमें खर्च भी कर दिए, 20 ट्यूबवैल भी खोद दिए, पाइप लाइन भी मंगा ली परन्तु क्या हुआ उस योजना का ? ग्रामीणों ने विरोध किया इसलिए हमने उस योजना को बन्द कर दिया। जब योजना बनायी तो उससे पहले ही इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि ग्रामीण इसका विरोध करेंगे क्योंकि जब उनके खेतों में पानी नहीं रहेगा, फल-सब्जी नहीं उगेंगे तो वे विरोध तो करेंगे ही। यह बात पहले सोच लेनी चाहिए थी पर इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया। जैसा घनश्यामजी ने बताया कि जयपुर शहर में पानी लाने का एक ही तरीका है बीसलपुर से हम पानी लायें। कांग्रेस के राज में बीसलपुर योजना पर काम चालू हुआ उस समय बड़े जोर-शोर से कहा गया कि 1992 में बीसलपुर योजना का पहला चरण समाप्त हो जायेगा और 1992 में दूसरे चरण का काम चालू हो जायेगा और जयपुर शहर

(श्री कालीचरण सराफ)

को दूसरे चरण में लिया जायेगा। हम लोगों ने उस समय भी मांग की थी कि जयपुर शहर को प्रथम चरण में जोड़ा जाय। यह बात सही है कि अजमेर में, ब्यावर में, नसीराबाद में पानी का जबर्दस्त संकट था, उनको पानी देना चाहिए था परन्तु आप 1992 में पूरा नहीं कर पाओगे तो जयपुर शहर का क्या होगा? हम उस समय क्योंकि कांग्रेस का राज था और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और कहा कि दूसरे चरण में जयपुर को पानी दिया जायेगा। खैर; हम संतोषी थे, हमने इस बात को मान लिया।

श्री विष्णु मोदी : चार साल में क्या आपकी सरकार ने पहला चरण तो पूरा कर दिया?

श्री कालीचरण सराफ : अब आज स्थिति यह है कि 1992 में जो प्रथम चरण पूरा होना चाहिए था वह 1994 में अब तक पूरा नहीं हुआ तो दूसरा चरण कब चालू करेंगे? अब मंत्रीजी ने केवल इतना सा कह दिया कि विश्व बैंक में योजना भेज रखी है। अब योजना भेजी उस समय 433 करोड़ की भेजी और आज उसकी जो कोस्ट है वह 612 करोड़ तो हो गयी और जब वह योजना विश्व बैंक से स्वीकृत होकर आयेगी तो यह एक हजार करोड़ तक हो जायेगी। मुझे सूचना है कि 14 जनवरी, 1993 को विश्व बैंक ने एक लैटर लिखा था उसमें दो शर्तें मुख्य रूप से आप पर लगायी थीं। हम आपको पैसा तो दे देंगे परन्तु क्या आप टैरिफ को डेढ़ गुना करने को तैयार हैं? यानि शुरू में डेढ़ गुना टैरिफ करिए और फिर दस पर्सेन्ट प्रतिवर्ष बढ़ाइये।

(13.00)

यह पहली शर्त है उनकी। दूसरी शर्त है कि जयपुर के लिए वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए आप अलग से कार्पोरेशन बनाइये। इसके बारे में अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। हम जयपुर के प्रतिनिधि हैं, इसके बारे में हमारे से आज तक कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। तो क्या इन दो शर्तों को राज्य सरकार मानने के लिये तैयार है, क्या इसके बारे में राज्य सरकार ने मानस बना लिया है, क्या इसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है? इसके बारे में भी कोई विचार माननीय मंत्रीजी ने इस काल अन्टेशन के जवाब में नहीं दिये। अब सीवरेज लाइन के लिए मंत्रीजी ने माना है कि जयपुर शहर की चारदीवारी के अन्दर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो सीवरेज की व्यवस्था है पर जयपुर की चारदीवारी के बाहर जितने लोग रहते हैं उसमें से केवल बीस प्रतिशत लोगों को सीवरेज की व्यवस्था अभी तक उपलब्ध करवा रखी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी जयपुर शहर की जनसंख्या है उसका बीस प्रतिशत तो रहती है चारदीवारी के अन्दर और अस्सी प्रतिशत जनता रहती है बाहर। अब अस्सी प्रतिशत जनता का बीस प्रतिशत, यानि कुल जनसंख्या का सोलह प्रतिशत और बीस, इस तरह छत्तीस प्रतिशत लोगों को आप सीवरेज की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। 64 प्रतिशत लोग जयपुर शहर के राजस्थान की राजधानी, पिंक सिटी, पूरे विश्व में विख्यात, उनके लिए सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। आज चाहे जनता कालोनी में चले जाइये, सेठी कालोनी में

(श्री कालीचरण सराफ)

चले जाइये, बर्नीज कालोनी, सिंधी कालोनी, आदर्श नगर, राजापार्क, तिलक नगर, बापू नगर, गांधी नगर, बजाज नगर, बनीपार्क, टोंक फाटक या ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर कोई सीवरेज की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर रखी हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : मानसरोवर भी गिनो, भूलो नहीं।

श्री कालीचरण सराफ : मानसरोवर, मालवीय नगर। मानसरोवर में तो है सीवरेज की व्यवस्था क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सीवरेज की व्यवस्था आपने कर नहीं रखी, अन्डर ग्राउंड वाटर को आप आपात योजना बना-बना कर, नलकूप खोद-खोद कर लेते जा रहे हैं। शॉक पिट्स से लोगों ने अपने सीवरेज की व्यवस्था कर रखी है। किस प्रकार का पोल्यूशन होगा इसके बारे में भी राज्य सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए। आज यह स्थिति है कि सब तरीकों से सब सोर्सेज का दोहन करके जो योजना आप लोग बना रहे हैं, यह चार-पांच साल में सारा अन्डर ग्राउंड पानी खत्म हो जायेगा। जहां पांच-छह साल पहले जयपुर शहर में पानी पचास-साठ फीट पर उपलब्ध होता था, आज 110, 120 और 130 फीट पानी नीचे चला गया है। तो मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि सब बातों को छोड़ कर प्राथमिकता के आधार पर जयपुर शहर की पेयजल योजना, स्थाई पेयजल योजना क्या बन सकती है, इसके बारे में माननीय मंत्रीजी को विचार करना चाहिए। मेरा सुझाव है, जिस प्रकार घनश्यामजी ने कहा कि जयपुर शहर की वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए अलग से कार्पोरेशन बनाया जाना चाहिए, केवल विश्व बैंक पर हमको निर्भर नहीं रह कर, जिस प्रकार घनश्यामजी ने बताया कि दो हजार करोड़ की योजना सूरत की बनी है, जो अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं देश में, उनसे भी बातचीत करके जल्दी से जल्दी जितना ऋण हम उपलब्ध करवा सकें, बीसलपुर योजना के लिए और यह योजना तीन-चार साल में पूरी करने का प्रयास यदि माननीय मंत्री महोदय करेंगे और मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जयपुर में पांचों विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री माननीय भंवरलालजी शर्मा जयपुर शहर के चुने हुए, राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की....

श्री सभापति : रिपीट न करें, यह बात आ चुकी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : तभी + + + हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ : एक सैकण्ड। जयपुर शहर की जनता इस बात की अपेक्षा करती है कि पहले चालीस साल में हमने संतोष कर लिया क्योंकि कांग्रेस का राज था, राजनैतिक पक्षपात से जयपुर के पानी की समस्या के बारे में कोई फैसला नहीं किया, कोई निर्णय नहीं किया, परंतु अब तो अपनी सरकार है, अपने मंत्री हैं, अपने विधायक हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : कहां ले जा रहे हैं आप....

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह कोई तरीका है क्या।

श्री कालीचरण सराफ : निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर बीसलपुर योजना से किस प्रकार से जयपुर शहर में पानी लाया जाय, इस बारे में....

श्री रतनलाल ताम्बी : यह भी कांग्रेस की देन है।

श्री कालीचरण सराफ : मंत्रीजी विचार करेंगे। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि पांचों जयपुर शहर के विधायक और जो टेक्नीकल मेम्बर्स हैं उनकी एक समिति बनायें और वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए अलग से कार्पोरेशन बनायें और केवल विश्व बैंक पर डिपेण्ड न रहकर अन्य वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेने की कोशिश करें और जयपुर में यह काम जल्दी से जल्दी प्रारम्भ करें जिससे जो जयपुर शहर में पांच-छह साल बाद त्राहि-त्राहि मचने वाली है पानी की, उससे निजात पाई जा सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री रामनारायण चौधरी : आप पांचों मिलकर आकाश को फोड़ दो और पाताल को तोड़ दो और जयपुर के पानी की समस्या हल कर दो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जैसे आपको तोड़ा है न।

श्री सभापति : शेखावतजी, प्रारम्भ करें। आर्डर प्लीज।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) : सभापति महोदय, जो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य इसलिए है कि सरकार ने साफ तौर पर माना है कि वर्तमान में जो स्थिति है और वर्तमान के अन्दर साल, दो साल में पूरी होने वाली योजना है उस योजना के अन्दर, उस योजना के द्वारा जयपुर की जनता को पीने का पानी देने की स्थिति में सरकार नहीं है। अब स्थिति आज नहीं आई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह कालीचरणजी कह रहे थे कि जयपुर में चाहे निवास की समस्या जो पैदा हुई थी उस निवास की समस्या के बारे में एक प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग नहीं की। अब निवास की समस्या के साथ जब जनता माइग्रेट होगी, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो पीने के पानी की समस्या भी पैदा होगी और पीने के पानी की समस्या के निदान के बारे में सरकार ने कुछ सोचा नहीं। अब सरकार ने नहीं सोचा, अब इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हम पिछली सरकार के नहीं सोचने की बात कर कर इस जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते....

श्री रामनारायण चौधरी : यह ठीक बात है।

श्री राजपालसिंह शेखावत : इसमें कोई संदेह नहीं है कि भंवरलालजी शर्मा साहब की न तो नीयत पर कोई शंका है, न उनकी क्षमता में कोई शंका है पर माना कि "तगाफुल तुम न करोगे, लेकिन खाक हो जायेंगे तुझको खबर होने तक।"

यह सवाल इस बात का है कि जयपुर में, आपने देखा होगा कि जयपुर में चार-

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

पांच तरह की समस्या है । कुछ वह इलाके हैं जहां सरकार पानी दे रही है । कुछ वह इलाके हैं जहां सरकार पानी दे रही है लेकिन वक्त पर पानी नहीं दे रही, हसनपुरा की जैसे समस्या है । कई इलाकों की समस्या है कि रात को एक बजे पानी दिया जाता है, एक घंटे तक के लिए पानी दिया जाता है । यानि सरकार का नल वहां पहुंचा हुआ है लेकिन नाम मात्र के लिए पहुंचा हुआ है । तीसरा इलाका वह है जिसमें सोसाइटीज ने प्लाट्स काटे लेकिन चाही जमीन थी, जमीन में कुए थे, कुओं से लोगों ने काले रंग के कंड्यूट पाईप से पानी ले रखा है । चौथा इलाका वह है जहां बारानी जमीन थी उस बारानी जमीन के ऊपर प्लाट्स काट दिये गये, इलाके में कोई कुआं भी नहीं है । जयपुर जैसे शहर के अन्दर लोग पीने का पानी लेने के लिए सुबह आठ-नौ बजे डेढ़-डेढ़, दो-दो किलोमीटर दूर जाते हैं । यह चीज, मैं सोचता हूं, निस्संदेह बड़े तकलीफ की चीज है और ऐसी स्थिति के अन्दर हैण्ड पम्प से समाधान नहीं होने वाला । अब बीसलपुर की योजना की तरह, आपने बात कही कि बीसलपुर की योजना हमने शुरू कर दी है । हमने वर्ल्ड बैंक को पैसे के लिए भेज दिया है । अब वह पैसा अगर आ भी गया, मैं सोचता हूं कि बीसलपुर की योजना भी दूसरे इन्दिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के रूप में तैयार होकर आने वाली है । जो 45-50 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज तक पूरा नहीं हो पाया । आज हम 1465 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट, जो वर्ल्ड बैंक को हम आज भेजने की बात सोच रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि वह प्रोजेक्ट आयेगा, पैसा आयेगा, काम शुरू होगा तो महाराज, इस तरह से काम नहीं होगा । बड़ी सीधी-सीधी सी बात है–

आह को एक उम्र चाहिए असर होने तक,
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक ।

सभापति महोदय, इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की बात की गई है कि कितना पैसा है, अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 1465 करोड़ की योजना बना दी और 1465 करोड़ की योजना अगर 1465 करोड़ में पूरी भी हो जाय तो आपने कहा कि 1800 लाख गैलन पानी जयपुर में आयेगा । यानि पर लाख गैलन पानी क्या पड़ेगा, 33 लाख रुपये हम पर खर्च होंगे एक लाख गैलन पानी पर । अब 33 लाख रुपये एक लाख गैलन पानी पर खर्च होते हैं, दूसरी तरफ अगर हम ट्यूब वैल खोदते हैं, नलकूप के द्वारा करीबन 11-12 लाख के अन्दर एक लाख गैलन पानी आता है । यानि नलकूप के द्वारा, ट्यूब वैल के द्वारा करीबन 11-12 लाख के अन्दर एक लाख गैलन पानी ले आते हैं । जो योजना हम बना रहे हैं उस योजना के द्वारा जो एक लाख गैलन पानी आयेगा उसकी कास्ट क्या होगी । क्या उस कास्ट के हिसाब से यहां पर आने का जो पर लाख गैलन पानी का पैसा होगा, वह पैसा क्या फिजीबल होगा, वह क्या कम फिजीबल है । मैं सोचता हूं, आज की तारीख में हम जब पीने के पानी के रूप में लेटेन्ट सब्सीडी दे रहे हैं, गुप्त रूप से सब्सीडी दे रहे हैं, अब इसके बाद सोचना पड़ेगा, यह वक्त आ गया है, जब आपको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह बिजली की दरों के बारे में सोचने की जरूरत है, यह देना

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

पड़ेगा कि लंच फ्री नहीं हो सकता। अगर राजपाल सिंह शेखावत को कालीचरण सराफ ने रात को खाने पर बुलाया है तो राजपाल सिंह का पैसा नहीं लगेगा, कालीचरण सराफ को पैसा खर्च करना पड़ेगा। लंच फ्री कभी नहीं होगा। समबडी विल हैव टू पे फोर इट। जनता के अन्दर, जयपुर की जनता जो पानी पी रही है, पानी की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब पानी की कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको राजी रखना नहीं चाहिए। उसको हम राजी रख कर कीमत नहीं बढ़ायें, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको जनता के साथ सीधा संवाद करना पड़ेगा। जो आपकी तकलीफ है जनता को बतानी पड़ेगी और जनता की तकलीफ है उससे बचने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, क्या आपने जयपुर में कितना अन्डर ग्राउंड वाटर है इसका सर्वे करवाया है और सर्वे करवाया है तो उस अन्डर ग्राउंड वाटर के रिर्सोसेज का कितना प्रतिशत टेप कर रहे हैं, कितना प्रतिशत हम टेप कर सकते हैं। यह सही है, अभी तिवाड़ीजी फरमा रहे थे कि जयपुर में सीवरेज पानी की समस्या होने से वह अन्डर ग्राउंड वाटर टेबल एक दिन पोल्यूट हो जायेगा। तो आज तो ड्रिंकेबल है या नहीं, इसके बारे में तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन वह आज अगर ड्रिंकेबल है भी तो कल ड्रिंकेबल नहीं रहने वाला। तो आज की तारीख में जयपुर के अन्दर अन्डर ग्राउंड पानी कितना है, उसका कितना प्रतिशत हम एक्सपर्ट कर सकते हैं, कितना प्रतिशत हमने एक्सपर्ट कर लिया है क्योंकि बीसलपुर का पानी तो काफी देर बाद में आने वाला है और जिस तरह का आपने अभी प्लान बनाया है, आपने कहा कि चालीस नलकूप और लगेंगे। अब चालीस नलकूप का मतलब है, 75 हजार गैलन पानी एक नलकूप देता है, आप ही के हिसाब से, जो डेटाज आपने दिये, लगभग। इसके हिसाब से जो पानी आपको मिलने वाला है और जो डेफिसियेट आपका बीच में आ रहा है, आपके आंकड़ों के द्वारा, वह डेफिसियेट अब मीट आउट नहीं होने वाला है। तो मैं सोचता हूं कि क्या जो सस्ती चीज है, ट्यूब वैल के द्वारा, जिसमें कम पैसे से, हम एक लाख गैलन पानी, ग्यारह-बारह लाख रुपये में क्रियेट करते हैं तो क्या अभी जयपुर के अन्दर पोटेन्शियल बाकी बची हुई है जिसके द्वारा हम इस कम पैसे के द्वारा इस पानी को जनरेट कर सकें और बीसलपुर की उम्मीद के ऊपर, बीसलपुर का नारा देकर जनता को भ्रम में रखने की कोशिश न करें। बीसलपुर का काम चलना चाहिए, यह इलाका प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ना चाहिए, इसके बारे में एग्जामिनेशन करना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन इस काम में किया जाए, या नहीं किया जाए, क्योंकि जो रकम यहां पर प्रस्तावित की गयी, अगर वर्ल्ड-बैंक से आती है, तो भले ही आ जाए और वर्ल्ड बैंक से नहीं आती तो राज्यों के संसाधन उसको देने की स्थिति में नहीं है। अभी तिवाड़ीजी बोल रहे थे कि आज हमने कितना पैसा पेयजल योजनाओं में खर्च किया है और कितने पैसे की हम अकेले जयपुर की पानी की प्यास बुझाने के लिए, बात कर रहे हैं? क्या हमारी सरकार के पास इतने संसाधन हैं? संसाधन नहीं हैं

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

और संसाधन आपके पास में है नहीं, वर्ल्ड-बैंक की तरफ आप देख रहे हो, वर्ल्ड बैंक आप पर कुछ शर्तें लगायेगा।

श्री सभापति : कृपया रिपीट नहीं करें। बहुत लम्बी कार्य-सूची है, रिपीट नहीं करें जो पहले कह चुके हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : नहीं, आप मुझे मना कर देते, मैं तो बोलता नहीं, जो बात रखनी थी मुझे, रख चुके हैं, तो इस बात का रिपीटेशन नहीं होगा। जब नियम 131 के अन्दर 15, 20 और 25 नाम आते हैं, नियम 131 में कॉल-अटेंशन तो एक ही चीज पर करना है, कॉल-अटेंशन सरकार का जो करना हो वह एक ही लाइन में किया जा सकता है, फिर इतने बड़े एक्सप्लेनेशन की लम्बी प्रक्रिया जो आपने बनाई है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सोचता हूं जो भावना है कानून की उसी के तहत आपको मुझे बोलने से रोकना नहीं चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सीवरेज की भी स्थिति वही वाली है। सीवरेज के लिए भी आपके पास पैसा नहीं। वर्ल्ड-बैंक की योजना आयी है तो मैं पूछना चाहता हूं जयपुर के डवलपमेण्ट के लिए इन्टेग्रेटेड प्लान आपने अगर कोई तैयार किये हैं, तो सीवरेज के बारे में क्या प्लान है? पानी के बारे में क्या योजना है, क्या प्लान है और क्या यह टाइम-बाउंड प्लान है? आप कब तक पूरा कर देंगे और पूरा करने की दिशा के अन्दर आपके कदम क्या शुरू हो चुके हैं, अभी आज की तारीख में मांग पेश होने वाली है। मैं सोचता हूं बीसलपुर के बारे में, जयपुर के पानी की समस्या को भी निदान करने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में बहुत बड़ी रकम की व्यवस्था हमने की नहीं है और चर्चा हम करना चाहते हैं। इस स्थिति में मैं सोचता हूं कि समस्या का समाधान हो, इसकी स्थिति कम नजर आती है। कमिटमेण्ट की उसमें कमी नहीं है, सवाल है कि प्रायोरिटीज को रि-फिक्स करके नयी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य के अन्दर अपने प्लान को रि-ओर्गनाइज करके पूरे कमिटमेण्ट के साथ में काम किया जाये। मैं सोचता हूं कि इस बारे में माननीय मंत्रीजी बताना चाहेंगे कि बदले हुए परिवेश में नई समस्याओं के अनुरूप इस प्रकार से हम जयपुर की पेयजल समस्या के निदान के बारे में कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : माननीय रामेश्वर भारद्वाज।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले दो विधायकों और चौमूं से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने पानी के पूरे इतिहास की कहानी सदन में रखी। 1727 से जयपुर जब से बसा, पानी का क्या इतिहास रहा, उस संबंध में जो चिन्ता व्यक्त की है, यदि थोड़ा सा भी प्रकृति ने बरसात के समय पानी नहीं दिया तो जयपुर की स्थिति क्या होगी, उसका भी चित्र उन्होंने यहां उपस्थित किया है। जयपुर से आये माननीय दो विधायकों ने वर्तमान में जो व्यवस्था हैं, उस संबंध में विस्तार से यहां बात रखी है। मैं भी उसमें कुछ बातें बढ़ाते हुए अपनी बात रख रहा हूं। एक तो जो बीसलपुर की योजना रखी है, जयपुर में पानी है ही नहीं, उस

Page No.45

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

योजना पर शीघ्रातिशीघ्र अमल किया जाए और जिस प्रकार से माननीय घनश्यामजी ने बताया कि अन्य स्त्रोतों से भी आर्थिक साधन जुटा कर और शीघ्रातिशीघ्र इस व्यवस्था को पूरा कराया जाये, तभी जाकर पानी की व्यवस्था हो सकती है। इसी के साथ-साथ कुछ कच्ची-बस्तियों का भी विचार और जो सोसायटीज के द्वारा बसायी गयी बस्तियों का विचार माननीय राजपाल जी शेखावत ने किया, इस सन्दर्भ में मैं भी अपनी कुछ राय प्रकट करना चाहूंगा कि ऐसी लाखों जनसंख्या की बस्तियां हैं जो विधिवत् रूप से बसी हैं और एक बूंद भी सरकार की ओर से पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने स्त्रोतों से, अपने प्रयत्नों से ही अपनी प्राइवेट पाइप लाइन डालकर, जैसी भी है और जो भी उपलब्ध उनके पास कुएं हैं, उनसे पानी लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि लाखों की आबादी है, इसी के साथ-साथ मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो वर्तमान व्यवस्था उन्होंने बना रखी है, उस वर्तमान व्यवस्था को सरकार अपने हाथ में लें, जैसे भी हैं और उसमें कोई न कोई सुधार करे। इसी के साथ-साथ जो माननीय मंत्रीजी प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं परन्तु इन प्रयत्नों में सुधार की आवश्यकता है। यहां नलकूपों की चर्चा की गयी परन्तु नलकूप बनाने से पहले यह विचार नहीं किया जा रहा कि उसका कोई भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं? नलकूप एक लगा, उसके पास में दूसरा भी लगा देते हैं, उसके पास तीसरा भी लगा देते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक व्यवस्था का आपके सामने जिक्र करूंगा। विद्याधर नगर क्षेत्र में पहले 15 ट्यूबवेल थे आज लगभग उसके आस-पास 150 नलकूप हमने बना दिये परन्तु वहां जो टंकी बनी है, जिसकी केपेसिटी 30 फीट की है, आज भी वह 22–23 फीट से ज्यादा नहीं भर पाती तो मैं समझता हूं कि 15 से 150 बना देने के बाद आखिर हम उस पानी का क्या उपयोग कर रहे है, जिसमें पानी का भराव ही नहीं हो रहा है। इस तरह अनेक ऐसी कई न कई, योजना में खामियां हैं, उन खामियों पर विचार जरूर करना चाहिए। यदि एक ट्यूबवेल है तो उससे कितनी दूरी पर दूसरा ट्यूबवेल है, आखिर पानी के स्त्रोत तो वही हैं जो हमारे पास हैं और माननीय घनश्यामजी ने चिन्ता व्यक्त की है, एक मीटर पानी एक वर्ष में नीचे जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो नलकूप बनाये जा रहे हैं, उनकी एक और दुर्दशा है। पता नहीं विभाग के पास ऐसा कोई साधन है या नहीं है, ऐसे यन्त्र होंगे, मैं समझता हूं कि इतनी प्रगति हुई है, बिना देखें शायद खोद दिये जाते हैं। मैं ऐसी कई जगहों के उदाहरण दे सकता हूं जो ट्यूबवेल पूरा का पूरा खोद दिया गया, अन्ततोगत्वा परिणाम निकला कि उसमें पानी नहीं है, पाइप पूरे लगा दिये गये। इसी प्रकार की दुर्दशा जो हैंडपम्प लगा रहे हैं, उनकी भी है। तो ऐसी व्यवस्था की जाये, विभाग में आखिर कोई न कोई बात पहले देख ली जाये, हमारा भू-जल विभाग है, वह किस काम के लिये है? अगर वहां पर पानी है नहीं तो काहे के लिए प्रयत्न करते हैं, इस बात की चिन्ता विभाग को करनी है,

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

अन्यथा हमारा जो पैसा है, वह भी जाया जायेगा। इसी के साथ-साथ एक प्रयोग, जयपुर शहर में माननीय मंत्रीजी ने 91–92 में किया है, जो जयपुर शहर की पुरानी लाइन है, उनका नवीनीकरण करने का और मैं समझता हूं कि पिछले 91–92 के वर्ष में 20–25 लाख रुपये लगाकर हवामहल क्षेत्र में परिवर्तन किये, वह स्वागत योग्य है। उस योजना को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना चाहिए, जितना पैसा विभाग को मिलता है उसका थोड़ा-थोड़ा पैसा इस योजना पर लगाना चाहिए अन्यथा प्रतिदिन कोई न कोई एक बोतल पानी की भरकर ले जाता है कि आज इस क्षेत्र में यह पानी आ रहा है। इसके साथ इसमें सुधार के लिए मेरा एक सुझाव और है कि जो नयी सीवरेज लाइन डाली जा रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मैनहोल बना रहे हैं और किसी परिवार की या सरकार की कोई पाइप लाइन जा रही है, उसको बदलने का कोई प्रयत्न नहीं करता है। वर्तमान समय में, बनते समय भी मैंने विभाग को एक पत्र लिखा परन्तु उस खड्डे में एक पाइप लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी पाइप लाइन ऐसे जा रही है, तीसरी उधर से आ रही है, और उसमें वह सीवरेज का पानी, जिसको मलमूत्र कहते हैं वह भी बहकर जाता है, तो कितने दिन वह पाइप लाइन टिक सकेगी। भौगोलिक क्षेत्र बिना बढ़ाये, यदि यह पाइप लगाये गये तो निश्चित रूप से हमारा पैसा जाया जायेगा, एक तो मेरा यह सुझाव है जो पुरानी सीवरेज लाइन पड़ेगी, माननीय मंत्रीजी ने पिछले वर्षों में किया उसको भी आगे बढ़ाया जाये और जो अब सीवरेज लाइन नयी डाली जा रही है, उनका भी क्षेत्र बढ़ाना चाहिये, अन्यथा जितना भी गन्दा पानी है, वह टैंकों के माध्यम से जमीन में जाता है और हैण्डपम्पों को भी उसके पास खोदा जाता है, वही पानी पीने के लिए मिलता है इसीलिए पचास प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं। जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़ी योजनाओं का सुझाव दिया है, उन सबका समर्थन करते हुए, वर्तमान व्यवस्था के सम्बन्ध में जो एक कार्पोरेशन बनाने का सुझाव दिया है, पानी और सीवरेज के लिये, मैं उस सबका समर्थन करते हुए, वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिए विभाग से अपेक्षा करता हूं। माननीय मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे और जो कच्ची बस्तियों में, जहां एक बूंद भी हम पानी नहीं दे रहे हैं और जो उनकी वर्तमान व्यवस्था है, सरकार अपने हाथ में लेकर इसमें जो कुछ भी सुधार हम वर्तमान में कर सकते हैं, करें। गर्मी शुरू हो गयी है यदि नहीं कर पाये तो लाखों लोगों के साथ अन्याय करेंगे, ऐसा महसूस करते हैं।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी सन् 63 से हमारे नेताओं ने बीसलपुर बांध की योजना पर, जयपुर को पानी दिये जाने की बात की, चर्चा विधानसभा में शुरू की, आज तक पूरी नहीं हुई। प्रथम चरण में जयपुर को पानी मिलने वाला था, मिलना चाहिये था, वह योजना अभी तक भी कागजों में चल रही है, कहीं नजर नहीं आती। खेद की बात है कि जिस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिये, उसको प्राथमि-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कता नहीं दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी कि वह यमुना से जल लाये, गंगा से जल लाये, चम्बल से जल लाये, ईसरदा से जल लाये, बीसलपुर बांध का जल लाये, बांडी योजना से लाये, रामगढ़ का लाये, पानी तो पिलायें। अब दिक्कत यह है कि इस रामगढ़ के स्त्रोत से, जो राजा रामसिंह जी ने बनवाया था उस समय जयपुर की जनसंख्या चालीस हजार थी और आज बढ़कर बीस लाख के करीब हो गयी है, जब मैंने यहां विधानसभा में चर्चा की, रामगढ़ के जल संग्रहण क्षेत्र में 45 एनीकट लिये गये। यह तो राज्य सरकार ने कर दिया कि सारे एनीकटों पर रोक लगा दी और यहां दिया गया आश्वासन पूरा नहीं किया कि हम उन एनीकटों को तुड़वा देंगे जो जल संग्रहण क्षेत्र में हैं। यहां दिया हुआ आश्वासन और मुख्य मंत्रीजी का दिया हुआ आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। मुझे खेद है।

सभापति महोदय, जो पानी का क्षेत्र रामगढ़ के लोग आज भी पानी देने को मना नहीं कर रहे, पानी दे रहे हैं। वह बात मैं बाद में करूंगी जब जयपुर जिले की बात आयेगी जब अपने जलदाय विभाग की मांगों पर चर्चा करेंगे। वहां के लोगों के लिये जिनसे हम पानी ला रहे हैं, उनके लिये हम पानी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ढूंड नदी में कुएं बना लिये और कुएं बनाकर वहां से पानी ले रहे हैं। इससे आगे चलें तो इन्दरगढ़ के इलाके में नलकूप बना लिये वहां से पानी ले रहे हैं और आगे जायेंगे तो जयसिंहपुरा खोर से पानी ला रहे हैं और उस क्षेत्र को बिल्कुल प्यासा रख रहे हैं, कब तक जनता बर्दाश्त करेगी। गोपीराम जी ने तो आन्दोलन करके अपना पानी रोक लिया है लेकिन मैं क्या बताऊं जयपुर भी मेरा है, रामगढ़ बांध भी मेरा है, इलाका भी मेरा है, मेरी सहृदयता पर आपको कुछ काम करना चाहिये कि नहीं, 67 हैण्डपम्प लगाने की एक सूची दी उसमें से एक भी नहीं लगा। अकाल राहत कार्यों में हमने कहा कि हैण्डपम्प लगा दो, कंटीन्जेंसी प्लान में एक हैण्डपम्प, क्या जवाब दें लोगों को जाकर, क्या कहें लोगों से ?

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब तक यहां वित्त सचिव, स्वायत्त शासन मन्त्री खुद, आपके सचिव, विशिष्ट योजना संगठन और जयपुर के पांचों विधायक खुद जिनमें से एक आप, सब मिलकर बैठकर चर्चा जब तक नहीं करेंगे, आप तो किसी महाजन से ही ले लीजिए ब्याज पर, आपको पैसा लेना है तो पैसा लीजिये ब्याज दीजिये। आप विश्व बैंक को भी ब्याज देते हैं कोई मुफ्त में हमारी झोली में डालने वाला नहीं है। तो आप किसी भी प्रकार से ऋण लेकर इस योजना को पूरा करवाइये और जयपुर को जल पिलाइये। आप पानी दे रहे हैं, मैं आपको सच कह रही हूं कि पेयजल सारा जल नहीं है। उसकी जांच ही नहीं होती, जो हम जल पीते हैं वह पूरा पेयजल नहीं है। कहां जाती है इनकी लेबोरेट्री, उसकी क्षमता ही नहीं है कि वह जांच कर लेकि कौनसा पानी पिलायेंगे। लेकिन खेद की बात है। यह बात कहते हुए मुझे अभी भी याद आ जाती है, यहां सुखाड़िया जी मुख्य मन्त्री हुआ करते थे, मैंने एक हजार घड़ों का प्रदर्शन किया बाहर, डेढ़ घण्टे में मन्त्री महोदय ने यहां मीटिंग बुलाई और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जयपुर में 73 टंकियां ओवरहैड टैंक मन्जूर कर दिये। आज हम किसको कहें ? एक हजार औरतों के मटका फोड़ने पर मटका माठ कहीं कहीं तक प्रसारित हुआ और सरकार झुकी, सरकार ने आवश्यकता समझी। हम किस रूप में बात करें जिससे सरकार प्रभावित हो और किस तरह से इस काम को करें।

सभापति महोदय, जमवा रामगढ़ क्षेत्र में बने एनीकट, जो जल संग्रहण क्षेत्र में हैं, वह तोड़े जाने चाहिए। अन्य स्रोतों में पानी भी लाया जाना चाहिए। यह मैं मानती हूं तात्कालिक योजना हो सकती है लेकिन जहां हम हैण्ड पम्प चालू कर रहे हैं, जो हम पानी पिला रहे हैं उसकी कम से कम जांच तो करें। यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कीड़े मारने की दवाई विश्व में सबसे ज्यादा जयपुर में खर्च होती है। इतने खेद की बात है। एक ओर तो जमवा रामगढ़ की स्थिति इतनी खराब करके रख दी और दूसरी ओर वहां डार्क जोन कर दिया। जीवन धारा के जल के रुपये सहायता के उन्हें न मिल जाये, ग्रामीणों को और अगर कुछ कहा जाये तो फिर यह कि हमारे विरोध में बात कही गयी। कितने अफसोस की बात है, क्या कहा जाये इसको ? आवश्यकता जब पानी पीने की है, रोटी खाकर आप भी एक लोटा पानी पीते होंगे, पानी तो सबको चाहिये। पूरे दबाब से जयपुर में पानी नहीं दिया जाता, पूरे टाइम पानी नहीं दिया जाता। रात को 8 बजे खोलेंगे तो 9 बजे टप-टप करके एक-दो बाल्टी भरती है। यह अमानुषता का व्यवहार है जयपुरवासियों के साथ, क्या व्यवहार है कि वह पानी की एक-एक बूंद को तरसे। कहीं से भी व्यवस्था सरकार करे। यह पानी इतनी जरूरी चीज है, निश्चित रूप से मिलना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक आदमी बेटे का ब्याह करता है तो घर में एक कमरा निर्माण करता है, घर के बजट को बढ़ाता है। जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारा बजट इस प्रकार से क्यों नहीं बढ़ता। यह तो पैसा लेकर पानी देने वाला विभाग है, मुफ्त तो जल नहीं आता और आप यह देखिये कि अब तीन केटेगरी में पैसा लिया जाता है। है। इतने हजार गैलन तक इतना पैसा, इतने हजार तक इतना पैसा और इतने हजार गैलन के ऊपर जाने पर इतना पैसा जलदाय विभाग के वितरण के बिलों पर आता है। कोई मुफ्त में पानी नहीं पिलाया जा रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर नगर में तो व्यवसायिक टैक्स और है, तो रही-सही कमी की और पूर्ति कर दो। इसका भी पैसा दो, उसका भी पैसा दो और पानी मत लो, इस प्रकार की वितरण अव्यवस्था है। मेरे इलाके में नई योजना बनी ऋषि गालव नगर और वन विहार। वहां टंकी बननी चाहिये थी, टंकी नहीं बनी। अब पानी ऊपर से जब जलदाय विभाग की टंकी में आता है तो सीधा रामचन्द्र जी की चौकड़ी में नहीं आकर पुरानी बस्ती में जाता है। वहां दें पानी मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन बीच के रास्ते में पड़ते हैं स्थान, पहाड़ी के नीचे की तलाई से लेकर रामचन्द्र जी की चौकड़ी बिल्कुल सूनी है। एक घण्टा भी पानी नहीं दिया जाता। ऋषि गालव नगर के लोग

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तो पता नहीं कहां-कहां से पानी लाते हैं, वन विहार के लोग कहां-कहां से पानी लाते हैं। मुस्लिम सम्प्रदाय की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं, खेद की बात है कि पानी उन्हें दिया जाता नहीं और गूजर घाटी की तरफ अगर चलेंगे तो वहां वायु सेना वालों ने एक टंकी बना ली है, उनको पानी देती है वह लेकिन शेष पूरी जनसंख्या आगे सन्तोष सागर तक प्यासी तड़पती है। कोई एक टी ऐसी जगह मंगला माता मार्ग पर लगा दी कि वह पानी सिर्फ पुरानी बस्ती जाता है। आमेर रोड के लोग त्राहि-त्राहि करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पेयजल पीने योग्य नहीं है। यहां का मेरा इलाका तो ऐसा है कि अगर नाखूनों से आप आधा घण्टा कोई जमीन खोदें तो पानी निकल आता है लेकिन वह पेयजल नहीं है, उसको कैसे पिलायें। वहां आप हैण्ड पम्प लगा नहीं सकते तो वहां आपको पाइप लाइन डालकर जल वितरण करना चाहिये जिससे वहां के लोग जी सकें, सुखी रह सकें, स्वरूप रह सकें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्या बिराजिए, मुझे निवेदन करना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे टोकेंगे नहीं। मेरी पूरी बात कह लेने दीजिये।

श्री सभापति : मुझे निवेदन करना है। आसन की कभी भी किसी भी वक्ता के बीच में व्यवधान डालने की इच्छा नहीं होती है परन्तु मैं प्रक्रिया और नियमों से बंधा हुआ हूं। नियम 131 के अन्तर्गत भाषण देने की प्रक्रिया नहीं है केवल मात्र जब मन्त्री महोदय का वक्तव्य हो जाता है, प्रश्न पूछने का है। हम नियमों के खिलाफ यदि गलत परम्पराएं डालेंगे तो दूसरे लोग उसी प्रकार की बात करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह नियम सब पर लागू होने चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मैं खड़ा हुआ हूं, मेरी बात सुनिये। तीसरा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ रहा है उसमें 25 आदमियों के नाम हैं। सदन में जो भी प्रश्न आता है, एक-दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है और आगे के जो मामले हैं वह रह जायेंगे इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप सीमित समय के अन्दर प्रश्न पूछकर अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगी कि मुझे यह बतायें कि सीवरेज प्लाण्ट के होते हुए आमेर रोड से सीधे नाले गन्दे जलमहल में क्यों जा रहे हैं। तीन-तीन बार उसके उद्घाटन की प्रक्रिया हो चुकी। तो सीवरेज की पूरी व्यवस्था की जाये, ट्रीटमेंट होकर पानी आये। ढाई-तीन करोड़ रुपया उस ट्रीटमेंट पर लगाया है। मंत्री महोदय बतायें कि उस जगह के खुले नाले कब बन्द कर दिये जायेंगे, जो कीचड़ हो करके पानी जायेगा मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि उस क्षेत्र के लोगों को पोल्यूटेड पानी जो पिलाया जा रहा है वह बन्द करके कब पाइप लाइनों के द्वारा पानी दिया जायेगा और यह भी बतायें कि जो समिति का सुझाव बनाने का दिया गया, कार्पोरेशन का सुझाव देने के लिये दिया गया, वह आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मानने के लिये तैयार हैं अथवा नहीं हैं ? जयपुर के लिये आप बीसलपुर बांध या अन्य कोई भी सोर्स से तात्कालिक रूप से 1994 में कोई योजना बना कर लाने वाले हैं जिससे जल की क्षतिपूर्ति हो सके। कृपया इन चारों-पांचों प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपीराम जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सभापति महोदय, जयपुर में पीने के पानी के अभाव में जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मेरे पूर्व में माननीय सदस्यों ने, जो पीने के पानी की स्थिति उत्पन्न होने वाली है और उसके बारे में योजनाएं बना कर पीने के पानी की आपूर्ति करने जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य कालीचरणजी ने बताया कि 40 प्रतिशत आबादी आज भी जयपुर के बाहर और ऐसी कालोनियों में रहती है जो कृषि भूमि पर बनी हुई हैं और आज तक उनका नियमन नहीं हुआ है। वहां पर पीने के पानी की सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है। सरकार यदि उन कालोनियों को अवैध मानती है तो सबसे पहले उसके विस्तार के ऊपर पाबन्दी लगाई जानी चाहिये थी जिससे कि वह लोग वहां नहीं बसते। अब यदि बस गये हैं तो उसके लिये पीने के पानी की योजना बनाना भी अति आवश्यक है। हालांकि वर्तमान में जो किसानों के कुएं बने हुए थे उनसे वह पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन संसाधनों के अभाव में कालोनी में जो अल्प वेतनभोगी लोग रहते हैं उन योजनाओं को चला पाने में वह सक्षम नहीं हैं। इसलिये मेरा आग्रह है कि उनके जो निजी ट्यूबवैल बने हुये हैं और उन ट्यूब वैल्स को बना करके एक साथ ज्वाइण्ट करके कोई टंकी बना करके पानी देकर पानी का वितरण किया जा सकता है। हालांकि जैसे पहले जयपुर में पीने के पानी की जो योजनायें बनाई गई, माननीय घनश्याम जी ने बताया कि बांडी बेसिन योजना बनाई गई और उसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं उसको विस्तार से देखा भी नहीं। बांडी बेसिन योजना मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती है और सबसे पहला ट्यूब वैल लगा तब से मैंने उसका विरोध किया था क्योंकि उससे उत्पन्न होने वाली जो समस्यायें थी उसका मुझे अच्छी तरह ध्यान था, उसका मैंने विरोध किया और सरकार ने माना इसका तो मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि जो पाइप लाइन मेरे क्षेत्र में पड़ी हुई थी इस चुनाव के तुरन्त बाद में इसका उपयोग सरकार ने किया, इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं और मेरे क्षेत्र की जनता की बात आपने रखी; इस का धन्यवाद देता हूं। लेकिन जयपुर में जो पीने के पानी की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है उसके विषय में चिन्ता करना आवश्यक है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि....(व्यवधान) एक तरफ की समस्या बढ़ा दी एक तरफ की घटा दी, बात बराबर है। उधर जो पैदा होने वाली थी उससे बचा दिया, इधर जो होने वाली थी सरकार चिन्ता कर रही है। सरकार को करना पड़ेगा। हमारे किसानों के खेत सूख जाते हैं उसके ऊपर सरकार कोई चिन्ता नहीं

(श्री गोपीराम जाट)

करती वहां तो मात्र मामूली मुआवजे की चर्चा कर रहे थे, 10 हजार बीघा का मुआवजा दे दें, 20 हजार बीघा का मुआवजा देकर उन लोगों को निर्धन बनाने की योजना थी। लेकिन मैं मंत्री महोदय को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि इस योजना पर उन्होंने पुर्नविचार किया और जयपुर के लिये जो दीर्घकालीन योजना बांडी बेसिन की बना रहे हैं उस बांडी बेसिन योजना से सम्भावित उत्पन्न होने वाली जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिये जल्दी से जल्दी बांडी बेसिन योजना का पानी यहां लायें। और जयपुर की जनता को पानी पिला कर, बीसलपुर योजना का पानी लाकर जयपुर की जनता को राहत प्रदान करें। यही मुझे कहना है।

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय रामनारायण साहब।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदय....

श्री बनवारी लाल बैरवा : मुझे एक सवाल पूछने का मौका दें।

श्री सभापति : आपका नाम पुकार दिया मैंने। आपके बाद बोलने का मौका मिलेगा। मैं नाम आपका पुकार चुका। आप विराजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप यहां बैठे हुये हमारा +++ ।

श्री सभापति : आपको समय दूंगा। मैं निवेदन तो कर रहा हूं। मैं इनका नाम पुकार चुका। आपका बाद में कहूंगा मैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी, आप मेरी बात सुन लें।

श्री सभापति : मैं सुनूंगा, सारा सदन सुनेगा। आप बिराजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी दो मिनट।

श्री सभापति : मैं आपकी चार मिनट सुनूंगा। ट्रेन छूटी जा रही है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, जयपुर के जल सप्लाई की समस्या के बारे में माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया वह ठीक है, उस समस्या की तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित भी कर दिया और सब बातें दे दी। इस सारे विवाद में नहीं पड़ कर माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि मैं जिस मानसरोवर योजना में रहता हूं वह भी जयपुर का एक हिस्सा है, एशिया की इस सबसे बड़ी आवासीय योजना, जहां पर पचास हजार मकान एक साथ बनाने का कार्यक्रम था, आज बन गये और बन रहे हैं, उस योजना के लिये हाउसिंग बोर्ड ने स्वयं ने पानी की व्यवस्था का, सीवरेज लाइन का पूरा खर्चा दिया था। कुएं वहां पर सब हाउसिंग बोर्ड के पैसे से खुदे थे, लाइन हाउसिंग बोर्ड के खर्चे से पड़ी थी,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के अन्दर बने हुये कुओं का पानी आपने दूसरी जगह मालवीया नगर, जवाहर नगर और.... (व्यवधान) दूसरी जगह वहां से पानी की सप्लाई करके मानसरोवर योजना, जो अपने आप में सैल्फ सफिशियेन्ट थी कुछ वर्षों के लिये जितना पानी था उधर तो दूसरी जगह पानी को डाइवर्ट करके वहां पर एक समस्या विभाग ने पैदा कर दी। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इसकी जानकारी करवायें। ठीक है सारा जयपुर एक है मान्यवर सभापति महोदय, लेकिन एक योजना, काम्पेक्ट योजना एक-एक बस्ती के लिये बनती है उस बस्ती को भी मुसीबत में डाल दो और दूसरों का भला नहीं होता है कम से कम 10-5 साल, 20 साल वह तो आराम से रहे। आपके जमवा रामगढ़ से, बीसलपुर से, वह उसके मोहताज नहीं थे। 20 साल तक उन कुओं से सफिशियेन्टली काम हो जाता। वह सारी गड़बड़ा गई। आज, सभापति महोदय, मैं वहां पर आठ साल से रहता हूं, सबसे पहला वहां का आवासी, निवासी, रेजीडेन्ट मैं हूं। मैं गया उस समय वहां कुछ नहीं था। आज वह विकसित हुई है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, दो साल पानी न के बराबर मिला उसके बाद में पानी हैण्ड पम्प से हमें लाना पड़ता था। विधान सभा के चुनाव हुए, मैं एम.एल.ए. बन गया तो वह समस्या दूर हो गयी। मेरी तो दूर हो गयी लेकिन बस्ती के अन्दर समस्या वैसी की वैसी कायम है। तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप इसको दिखाइये कि इस योजना में सारा खर्चा हाउसिंग बोर्ड का लगा हुआ है, हमारा लगा हुआ है, हमारे पैसे से, सब हमारा है। उसको आप दिखा कर इसकी व्यवस्था करें। जयपुर के बारे में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा का जो बांध बना है, आप जयपुर, दिल्ली जाते हैं, सभापति महोदय, आप तो स्वयं परिचित है वह सारा पानी आपका जयपुर से गया है। इन जयपुर के पहाड़ों का पानी है। जयपुर के पहाड़ों का पानी हरियाणा की सिंचाई करेगा। वह पानी चला गया। बीसलपुर में हम उलझ रहे हैं। यहां सारा पानी, माननीय गोपीराम जी अभी कह रहे थे, क्या आप उस बात पर गौर करेंगे कि बांडी का पानी बह करके बनास में जाकर गिरता है और बनास का पानी जमुना में जाकर गिरता है, जयपुर का सारा पानी जो बरसात का है वह जा रहा है जमुना में। इधर जयपुर का सारे पहाड़ों का पानी बहकर जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा तो उसका उपयोग करेगा, तो क्या हम इससे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। अपने एक्सपर्ट्स से पूछिये, जो जानकार है, इंजीनियर्स है पैराफरनेलिया सारा आपका है, एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके पास हैं, एक्सपर्ट्स आपके पास में हैं इसलिये आप एक अलग योजना बीसलपुर तो आता रहेगा, आप क्यों इस विवाद में उलझते हो, इतनी दूर से आती है, जब तक बीसलपुर का पानी नहीं आयेगा तब तक क्या समस्या हो जायेगी, वहां टौंक सूख जायेगा तब तक, टौंक में पानी की समस्या पैदा हो जायेगी तो आप इस पर दिमाग लगाइये, यह भी देखिये उसको आप आउटराइड रिजेक्ट मत

(श्री रामनारायण चौधरी)

करिये। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या जयपुर के पानी की समस्या, बांडी का पानी जो बनास में जाकर गिरता है उसको रोकेंगे। जमुवारामगढ़ की तरह से पानी का बन्दोबस्त, जयपुर के पहाड़ों का पानी जाकर सात्री नदी में गिरता है, ढूढ नदी में जाकर गिरता है उस पानी को रोक कर कोई जमुवारामगढ़ जैसा बड़ा बांध बनाकर पीने के पानी की समस्या को सुलझाने में कोई कारगर कदम उठाये जा सकते हैं, कोई योजना बनायी जा सकती है क्या ? इन सब बातों की तरफ, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और खास तौर से मेरा मकसद मानसरोवर की बस्ती में जहां दो लाख की आबादी है उसमें आप पानी की व्यवस्था करने के लिये था, हम बहुत कठिनाई के अन्दर हैं आप महसूस कीजिये, आने-जाने की मुसीबतें तो है ही, पानी भी नहीं है। जयपुर से 20 किलोमीटर दूर बसें हुए हैं, इसकी तरफ ध्यान दीजिये। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, आज जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जयपुर के पेयजल के बारे में प्रश्न उठाया और वह बहुत वाजिब सवाल था उनका और उनको उठाना भी चाहिये था और उन्होंने आज माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी की बहुत तारीफ भी की, हम भी उनकी बुराई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भी मंत्री तो वही हैं और मैं समझता हूं कि बहुत ही न्यायपूर्वक व्यवस्था उनके यहां रहती है और वह ऐसा भी नहीं करेंगे कि हमारे साथ कोई अन्याय कर दें। लेकिन, सभापति महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो रिपोर्ट आज पेश हुई है "प्रगति विवरणिका जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान, जयपुर" यह आपके मंत्रालय से हुई है, हमने इसे छपाया नहीं है। इसका एक पैराग्राफ आप सुन लीजिए – "बीसलपुर पेयजल योजना अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी व सरवाड़ नगरों को नियमित रूप से पेयजल सुलभ कराने हेतु 153.00 करोड़ रुपये की संवर्धन योजना स्वीकृत की गई है। जिसके अन्तर्गत बनास नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा बीसलपुर ग्राम के पास बनवाये जा रहे बांध से उपरोक्त नगरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।" इसमें जयपुर का कोई जिक्र नहीं है। यह मैंने तो प्रकाशित नहीं की न; यह आपके महकमे ने की, आपने की और सही बात भी यही है कि मूल रूप में यह योजना तैयार हुई थी, सभापति महोदय, वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन 1975 के अन्दर जिस समय मैं यहां पर राजस्थान सरकार में मंत्री था उस समय पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर थे बैदजी और सिंचाई मंत्री थे देवपुराजी, दोनों को मैंने निवेदन किया कि आप चल कर हमारे यहां बीसलपुर के मौके को देखिये और वहां पर एक बांध की योजना बनाइये क्योंकि हमारे पास नैचुरल रिसोर्स बनास के अलावा दूसरा कोई है नहीं; तो आप उसको देख कर एक बांध बनाने की योजना बनायें। दोनों मंत्री मेरे साथ गये और मौका देख कर

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

बहुत प्रसन्न हुए और बहुत संतुष्ट हुए कि यह बिल्कुल सही जगह है जहां पर बांध बनाया जाना चाहिये और वह उस समय योजना तैयार हुई। इत्तेफाक की बात है कि 1977 के अन्दर कांग्रेस का शासन जाता रहा, आते जाते रहते हैं शासन, और 77 से 80 के बीच में जनता पार्टी का शासन रहा उसके बाद फिर 1980 के अन्दर कांग्रेस का शासन आ गया और जब कांग्रेस का शासन आया तो दुबारा मैंने मंत्रालय से जाकर यह जानकारी की तो पता लगा कि वह तो योजना ही खत्म हो गयी। जो बीसलपुर डेम की योजना थी उसको खत्म कर दिया गया और उसके चार भागों के अन्दर सिर्फ एनीकट बांध देने की बात हो गयी, भाई, यह क्या गजब कर रहे हो ? हमारे तो एक-मात्र नेचुरल रिसोर्स यही था और इसको भी आप खत्म कर दोगे तो हम क्या जवाब देंगे ? पहाड़ियाजी उस समय मुख्य मंत्री थे, उनसे बात की। बात चलती रही फिर एक मौका ऐसा आया कि माननीय माथुर साहब हमारे टोडारायसिंह आये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यहां जयपुर की पेयजल समस्या के बारे में है यह।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मेरी सुन लें, सभापति महोदय।

श्री सभापति : इसलिए उसकी समस्या के समाधान के बारे में कोई सुझाव हो तो बता दीजिए।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय सभापति महोदय, समस्या से मेरी जान को परेशानी पैदा हो रही है।

श्री सभापति : नहीं, जयपुर की समस्या का समाधान बताइये आप तो, टोंक की समस्या का समाधान नहीं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : वहीं आ रहा हूं, सभापति महोदय। उसके बाद जब टोडारायसिंह वह गये तो मैंने कहा, श्रीमान्, बीसलपुर यहां से बिल्कुल करीब है आप चल कर उसको देखो तो सही, वह योजना इसके लिए हम बनवा रहे हैं और उन्होंने भी जा कर उसको देखा और कहा कि बिल्कुल सही जगह है, यहां बनना चाहिए। प्रोजेक्ट तैयार हुआ और 1983 में माननीय परसरामजी उस समय जलप्रदाय मिनिस्टर थे, वह और मुख्य मंत्रीजी दोनों 1983 में गये और वहां पर जा कर शिलान्यास किया और उन्होंने यह मान लिया कि ठीक है। यह योजना चालू हुई और काम चालू हो गया और आज उसका स्वरूप यह हो गया और हमने यह मान ली थी। उस समय भी टोंक जिले में मान ली कि अजमेर में पानी नहीं है पीने के लिए, निश्चित रूप से वहां पानी दिया जाना चाहिये और पेयजल के लिए हम सबने इसको मान लिया और 66 हजार हेक्टेयर जमीन हमारे टोंक जिले की सिंचित करने के लिए मान ली गयी और यह बात उनको कही, अब इसके बाद में जब दुबारा कांग्रेस का शासन गया तो फिर बात चल पड़ी कि यह तो पेयजल के लिये बीसलपुर का पानी जयपुर के लिये लाया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे वहां आन्दोलन हो रहा है, हमारे यहां काश्तकारों का गला काट कर आप

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

क्या करना चाहते हैं ? जयपुर को पानी मिलना चाहिये, मैं इससे कहां मना कर रहा हूं लेकिन सरकार के बहुत लम्बे हाथ हैं, सरकार के साधन कुछ सीमित भी नहीं हैं और जो आप योजना बता रहे हो वह 615 करोड़ रुपये तो आपने बताये कि बीसलपुर से पानी लाने के लिए आपके 615 करोड़ खर्च होंगे तो, सभापति महोदय, इस समय कालीसिंध का पानी उपयोग कुछ नहीं हो रहा है, पार्वती के पानी का उपयोग कुछ नहीं हो रहा है, चम्बल से जो पानी बह कर जा रहा है उसका उपयोग कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं आप वह पानी ले कर आते और जयपुर के आप 15 लाख के ऊपर निर्धारित कर दें ऐसा नहीं होगा। दिन प्रति दिन जनसंख्या की समस्या भी बढ़ रही है इसलिए आपकी डिमाण्ड भी ज्यादा बढ़ेगी। आप हमारा भी गला काट लोगे और आपको कुछ मजा नहीं आयेगा। हमारे काश्तकारों को हम क्या जवाब देंगे, सभापति महोदय, तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं क्या आपके अधिकारी उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करते ? यह पानी जो बेकार जा रहा है उसको लाया जाये ईशरदा के ऊपर बांध बना दिया जाये और उसके ऊपर आप पार्वती से लाइये, कालीसिंध से लाइये, चम्बल का जो एक्स्ट्रा पानी है वह लाइये और पिलाइये पानी यहां पर....

श्री सभापति : आपका पाइण्ट आ गया। माननीय श्री विजयेन्द्र पाल सिंह।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर मान लीजिये हमारी इच्छाओं के विपरीत अगर जिस प्रकार राज्य सरकार ने कोशिश की, सभापति महोदय, हमारा पानी इधर लेकर आये, हमारे यहां आंदोलन होगा, लोग वहां पानी नहीं लाने देंगे।

श्री सभापति : आपका पाइण्ट आ गया, बिराजिये। श्री विजयेन्द्र पाल सिंह। कृपया, बहुत संक्षिप्त में कहें। आगे बहुत काम लेने हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति : दो मिनट नहीं, आपका प्रश्न पूछ लीजिये। आपका सम्बन्ध नहीं है जयपुर से।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सब को तो कह लेने दिया, मेरे कहने से पहले यह आपने लगा दिया।

श्री सभापति : उनका सम्बन्ध तो है, आपका तो कोई सम्बन्ध है नहीं इससे। नहीं, आपका सम्बन्ध नहीं है न इस प्रश्न से।

श्री कालीचरण सराफ : श्रीमान्, यह जयपुर में रहते हैं 15 साल से।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हां, 15 साल से....(व्यवधान)....

श्री सभापति : अच्छा-अच्छा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदय, इस कॉल अटेन्शन मोशन पर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय यह पूछना चाहता हूं, एक तो मैं कहूंगा कि मैं

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

री-ईट्रेट नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, मैं तो एक जानकारी करना चाहता हूं कि आपको यह जानकारी है क्या कि यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन है उन्होंने काफी बड़े-बड़े सिटीज पर एक स्टडी की है और वह स्टडी निकली है कि कहां पर कैसा पानी है सिटीज के अन्दर और उसके अन्दर जो कुछ और सिटीज के लिए कहा है वही जयपुर के लिए भी कहा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि **Drinking whater of Jaipur is not potable not only for human consumption but also for animal consumption.**

और इसमें जयपुर भी है और यह जयपुर के लिए कहा गया है कि यहां पर यह पानी खाली आपने....

श्री सभापति : कौनसी किताब के कौनसे पृष्ठ पर है यह ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन की स्टडी की है सिटीज के अन्दर, मैं आज तो लाया नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैं सामने रख देता टेबल पर....(व्यवधान)....और उसके अन्दर भी यह लिखा है, यहां पर जयपुर के लिए उन्होंने खास तौर से लिखा है एमीबायसेस कितनी होती है, पर्सेण्टेज उन्होंने दिया है 65 या 68 पर्सेण्ट और तेल बर्न से जो लोग मर जाते हैं वह भी इस पानी के कारण होता है और जो सीवरेज से मिक्सअप की बात कही, दूसरी बातें कहीं ....(व्यवधान).... मैं वह स्टडी ले आऊंगा, तो यह इतनी सीरियस बात है और इसके लिए मैं यही कहूंगा....

श्री सभापति : रियली सीरियस।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने जो यह कोपरेट सैक्टर को लेने की बात कही और आप एक कमेटी बनाकर थिंक टैंक्स जैसे यह हैं उनको बैठाकर इस पर विचार क्यों नहीं करवाते ?

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री विष्णु मोदी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : खाली आप ही क्यों... थिंक टैंक बनते हैं इसके बारे में। यह बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जयपुर में एग्जिस्टिंग हैंड पम्प कितने हैं ?....

श्री कालीचरण सराफ : 1156।

श्री विष्णु मोदी : अच्छा। आपने जो जयपुर में 460, 470 लाख गैलन पानी पर डे देना बताया है उसमें 400 लाख गैलन पानी आपके ट्यूबवैल से आता है तो आपके जयपुर में कितने जोन हैं जिनसे यह आता है और उसमें कितने डार्क जोन हैं, और एक्सपर्ट्स ने आपको डार्क जोन से पानी निकालने के लिए मना किया है कि आप इन डार्क जोन से पानी नहीं लें ? आज एक किसान डार्क जोन में कुआं खोदना चाहता है उसको तो कुआं खोदने नहीं दिया जाता है और आप यहां पर डार्क जोन से पानी निकाल रहे हैं तथा आपके यहां जो बरसात होती है उसका कितना पानी परकूलेट होता है, जो वाटर टेबल गिर रहा है उसका एक मुख्य कारण भी

(श्री विष्णु मोदी)

यह है कि यहां पानी रूकता ही नहीं है और यहां परकूलेट ही नहीं होता। तीसरी बात, यह कितने जोन हैं और उनमें डार्क कितने हैं जिनमें एक्सपर्ट्स ने मना किया है आपको ?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मद्रास शहर में भी वही स्थिति है जो राजस्थान पूरे की है। यहां पीने के पानी की तकलीफ है तो उन्होंने वहां बाई आर्डिनेंस एक कानून पास किया है कि मद्रास शहर के अन्दर बिल्डिंग के ऊपर गिरने वाला पानी सड़क पर बहकर नहीं जायेगा। उसका एक नक्शा बनाकर दिया है कि बिल्डिंग के ऑनर को, उसको जमीन में परकूलेट करना पड़ेगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो यह एक्यूट सिचुएशन है, वाटर टेबल पूरा राजस्थान में नीचे जाता जा रहा है तो कम से कम जयपुर के ड्रिंकिंग वाटर के लिए ट्यूबवेल आपका मेन सोर्स है तो उसमें इस तरह के जो कदम हैं उनकी जानकारी करके क्या आप विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, छोटा सा प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने यह जो पानी के वितरण के आंकड़े दिये हैं तो यह आंकड़े आपने जो पानी के बिलिंग के हैं उसमे दिये हैं या पानी का प्रोडक्शन है उससे दिये हैं ? जहां तक मेरी जानकारी है, आपके पानी की बिलिंग और प्रोडक्शन में अन्तर है। जितना पानी का प्रोडक्शन होता है उसमें सार्वजनिक नल भी शामिल हो जाते हैं उसके बावजूद भी आपकी बिलिंग पानी के प्रोडक्शन से ज्यादा तो नहीं है। आप इस बात की तसल्ली करके मुझे उत्तर दे दीजिये।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, जिस समस्या पर यहां विचार व्यक्त किये गये हैं यह वास्तव में बड़ी गंभीर समस्या है और जो माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है, मेरी भी चिन्ता इससे कम नहीं है लेकिन समस्या न तो आज की है, न छोटी है और इस समस्या का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, क्षेत्र का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, क्षेत्र का विस्तार, पानी का स्तर नीचे जाना, सोर्सेज से पानी कम आना शुरू होना और जो योजनाएं समयबद्ध हर वर्ष की जानी चाहिये थी उनका नहीं करना, इन सबने इस समस्या को इतना बड़ा आकार दे दिया। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पानी कम मैंने बताया है यह 200लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर हम देते हैं, जो नार्मस् हैं उससे कम है। 200 लीटर तो पर्याप्त माना जाता है, 200 गैलन। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए दो-तीन रास्ते हैं। सबसे बड़ा तो बीसलपुर है। आज हम जिन बस्तियों का जिक्र करते हैं वे बस्तियां बिना किसी योजना के, बिना किसी को पूछे कि वहां पानी उपलब्ध होगा या नहीं होगा, इसका विचार किये बिना अपने आप बस जाती

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है, वह एक अलग समस्या है, उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन समस्या सामने दिखायी देती है। एक महीने बाद जब भी कहीं शहर में घूमते हैं तो लगता है कि एक बस्ती और बस गयी और इस प्रकार की बस्तियां बसने के बाद भी पानी उनको मिलना चाहिये, उनकी मांग खड़ी होती है। पानी की उपलब्धता जितनी है उतनी ही रहती है तो ऐसी परिस्थिति में जो तात्कालिक उपाय किये जा सकते हैं जब तक कोई बड़ी योजना न बने, माननीय रामनारायणजी ने कहा कि जयपुर शहर का पानी बहकर नदियों में व्यर्थ चला जाता है इसको रोका जाना चाहिये, यदि इसको रोकें तो जयपुर की पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है। एक अच्छा सुझाव है। इस पर बातचीत मैं अधिकारियों से भी करूंगा लेकिन यह एक दिन में नहीं होगा। यदि यह वायबल भी हो तो इसका लाभ तुरन्त नहीं मिल सकता।

ऐसी स्थिति में, सिवाय इस बात के सरकार के सामने कोई उपाय नहीं बचता कि पहले प्राथमिकता पर फर्स्ट एड के नाते ही सही, जो कुछ पानी उपलब्ध हो सकता है वह किया जावे। यह जनसंख्या एम. एल. एज. के कारण भी बढ़ी है। एम. एल. एज. भी आने लग गये, वह भी संख्या बढ़ गयी तो यह भी दिक्कत हो गयी, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे रामनारायणजी हैण्डपम्प से पानी लाते थे और अब एम. एल. ए. बन गये तो वे वहां से पानी लाना बन्द हो गया। इनको भी पानी देने लग गये तो यह विस्तार भी होता है।

श्री रामनारायण चौधरी : हम तो जयपुर की शोभा बढ़ा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : धन्यवाद है, स्वागत है इसलिए व्यवस्था करते हैं आपकी। दूसरी दिक्कत यह आती है कि....

एक माननीय सदस्य : नहीं, साहब। हम तो चले जायेंगे। हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं आप न जायें। जयपुर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं-नहीं, आपका धन्यवाद है, आप विराजें। आप अपना परिवार बढ़ायें, आपका व्यापार बढ़ायें, यहां रहें आप।

अब प्रश्न यह है कि इन सारी समस्याओं का समाधान एक साथ कैसे हो। जयपुर शहर की लाइन या किसी भी शहर में जब पानी की लाइन पड़ी होगी, आज के कितने बरसों पहले पड़ गयी। अब आखिर में उस पाइप की लाइफ होती है। कुछ दिनों बाद वह काम करना बन्द करते हैं, कनेक्शन ज्यादा हो गये तो उसमें लीकेज होता है तो जो पानी हमको मिलना चाहिये वह छीजत में चला जाता है। यह भी एक समस्या है। अब ऐसी स्थिति में दो ही रास्ते हैं। एक तो बीसलपुर की योजना और एक तात्कालिक योजना जिसमें ट्यूबवेल, हैण्डपम्प यही हो सकते हैं। बीसलपुर की योजना के बारे में यह बात सही है, जैसा आपने कहा, शिलान्यास भी कर दिया। आपने कहा न, शिलान्यास कर

Page No.59

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिया वहां । कोई वहां गये बतायें, उन्होंने शिलान्यास कर दिया इस बीच ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : बीसलपुर डेम बन ही रहा है । बीसलपुर डेम उसी पर आधारित है । बीसलपुर डेम वहीं बन रहा है । मेरा निवेदन करना तो यह था कि वहां से पानी लेकर आयेंगे आप, उसके ऊपर भी आपका खर्च होता तो ईशरदा के बांध का आप सर्वे करा चुके हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी मैं निवेदन करता हूं ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उसका आप सर्वे करा चुके हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिलकुल, मैं निवेदन करता हूं ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उसका सर्वे हो चुका आपका ।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिलकुल हो चुका है, वह मेरे पास उपलब्ध है ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : और उसके ऊपर डेम भी बना लें आप । उस डेम के अन्दर पानी कम पड़े तो उधर से पानी लेते आइये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं निवेदन कर दूंगा ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप कालीसिंध से, पार्वती से, चम्बल से पानी उस ईशरदा में डालते रहिये, यहां बनाते रहिये ।

श्री सभापति : आप बिराजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह भी एक सुझाव है, यह भी पानी उपलब्ध है । कौन सा पानी होना चाहिये कम कीमत पर और लम्बे समय तक जो मिलता रहे । यह तो विचार करना ही पड़ेगा । कर लेंगे वह विचार ।

बीसलपुर योजना के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता की और उसे विलम्ब से बताया । विलम्ब हुआ मैं इससे इन्कार नहीं करता, परन्तु, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूं कि जब पिछली बार हमारी सरकार आयी तो इस बीसलपुर योजना पर दूसरे चरण में जो प्रस्तावित थी, हमने विचार शुरू किया और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अप्रेल, 92 में हमने इसकी सारी प्रक्रिया पूरी करके दिल्ली भेज दिया । इससे जल्दी हम नहीं कर सकते थे । 92 में हमने इसको दिल्ली भेज दिया और वहां से जनवरी, 93 में जब हमारी सरकार नहीं थी तो वहां से कुछ क्वेरीज आयी यहां पर जिसका उत्तर सितम्बर, 93 में गया और आज इसकी प्रगति यह है कि अगले सप्ताह उनकी एक टीम जयपुर में आ रही है और वह यहां पर विचार-विमर्श करके इसको फाइनल करेगी । जहां तक इसके साधनों का सवाल है, माननीय तिवाड़ी जी और बाकी के लोगों ने भी कहा । मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार पन्द्रह दिन या एक महीने पहले जब हमारी पी. पी. सी. की मीटिंग हुई थी उसमें हमने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एक कारपोरेशन बनाने का निर्णय कर लिया है आलरेडी। we have done it. (व्यवधान).... अलग से जो आपके सुझाव हैं उनके लिए....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : उसकी तो अलग से ही बना लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह कारपोरेशन तो बना हुआ है, अलग से बना दिया ताकि जो आपकी चिन्ता है, जो लोनिंग के लिए और सब बातों के लिए सक्षम हो। हम यह कोशिश करेंगे कि उसको अधिकृत कर दें। जहां तक बीसलपुर का सवाल है इसमें तो इतना समय जो लगेगा वह लगेगा और पूर्ण रूप से गति देकर इसको पूरा कराने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक बीसलपुर का पानी नहीं आता तब तक क्या आप यह सलाह देंगे कि जैसा पानी उपलब्ध है वह भी लोगों को न पिलाया जाय? चाहे वह ट्यूबवेल्स हों, चाहे हैण्डपम्प हो, मुझे कई बार आश्चर्य होता है, कई दफा कहते हैं कि हैण्डपम्प बेकार हैं, नहीं करने चाहिये और फिर माननीय सदस्य खड़े होकर मांग करते हैं कि हमारे पांच ही हैण्डपम्प कैसे दिये, दस दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं, यह हमने नहीं कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने नहीं, अभी कहा है किसी ने। आपको जरूरत ही नहीं है, परन्तु है जिनकी बात बता रहा हूं और यह आप मांग करें, चाहे न करें, इसके अलावा हैण्डपम्प के....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पानी मिल नहीं रहा है, यह क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? पानी तो सारा जयपुर में ले आते हो, बन्द कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं खुद ही मान रहा हूं। यही मजबूरी आपकी है, वही मजबूरी हमारी है और इसीलिए हैण्डपम्प से ही जो कुछ व्यवस्था हो सकती है

(14.00)

चाहे उसको तात्कालिक या फर्स्ट-एड के नाते करें। इसके अलावा हम जयपुर को बीसलपुर के इन्तजार में पानी पीने से महरूम नहीं कर सकते। जब तक वो आएगी, तब तक क्या पिये जाएगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि यह जो हैण्डपम्प हैं यह ट्यूबवेल्स हैं यह कोई परमानेण्ट व्यवस्था नहीं है और जयपुर शहर में पानी की व्यवस्था के लिए जैसे और माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया, चम्बल का भी दिया किसी ने (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : वित्तीय साधनों के लिए केवल वर्ल्ड बैंक पर डिपेण्ड रहेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं नहीं। वो कॉरपोरेशन, मैंने निवेदन किया कारपोरेशन बढ़ा दिये और उस कारपोरेशन को इस बात के लिए अधिकृत करेंगे वो चाहे संस्थाओं से लोन ले ले, प्राइवेट लोगों से ले ले, आप लोगों से ले ले, आपकी मदद से किसी से ले ले और धन-साधन जुटाकर इस योजना को किसी भी प्रकार जल्दी पूरा करे। यह हमारी चिन्ता का विषय है। We are doing it. मैं समझता हूं अब जयपुर के मामले में हैण्डपम्प नहीं खोदें और ट्यूबवेल्स नहीं बढ़ाएं, यह तो सम्भव नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : यह किसने कहा है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : किसी ने कहा है। जहां तक बांडी बेसन का सवाल है वो भी निवेदन करूंगा कि बांडी से जो पानी लाना था। वह योजना जब हमारी सरकार नहीं थी उससे पहले बनी थी वहां किसानों ने विरोध किया, किसानों ने कहा कि अगर आप पानी ले जाएंगे तो हमारे खेत सूख जाएंगे। यह बात उनकी उचित थी। यह आप कहते हो बांडी बेसन में इतना रुपया लग गया। पाइप लग गया यह सब कुछ हो गया, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन हम यह करते कि वहां किसानों के खेत सूखा देते, उनको बर्बाद कर देते। इसलिए सरकार ने सोचा कि हम और कहीं से पानी जरूर लाएंगे लेकिन पानी लेकर पीने के नाम पर किसानों को बर्बाद करें, यह सम्भव नहीं होगा। इसलिए बांडी बेसिन की योजना अभी चालू नहीं की गयी और बाकी जो योजनाएं हैं वह हमारे सामने हैं। उनको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और मानसरोवर के लिए जो आपने फरमाया कि आपको पानी कम मिल रहा है तो मैं इसको देखता हूं कि कम क्यों मिल रहा है यदि आपको पूरा पानी मिलने के बाद भी जिन इलाकों को दे रहे हैं अगर वे प्यासे नहीं मरेंगे तब तो आपको पानी मिलेगा और यदि आपको देने के बाद, पूरा देने के बाद वह प्यासे नहीं मरेंगे तो दे देंगे और यदि पूरा देने के बाद उनकी हालत खराब होगी तो आपसे निवेदन करूंगा कुछ दिन इन्तजार करें। भगवान बरसात करेगा। बहुत अच्छा होगा और आप विश्वास करिए। भगवान पर भरोसा करिए। यह हमारा रामगढ़ भी भरेगा, सब काम ठीक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं माननीय मंत्रीजी का धन्यवाद दूंगा। लेकिन मैं निवेदन यह कर रहा हूं यह जो कारपोरेशन बनाया है वो तो विश्व बैंक की एक शर्त थी कि आप टेरिफ रिवाइज करेंगे और कारपोरेशन बनाएंगे। उसके हिसाब से कागज लिख दिया गया। यह कोई कारपोरेशन नहीं है तो उस हिसाब से; लोन लेने के हिसाब से बनाया गया है। इसका जब तक इकट्ठा कर पूरी स्वायत्तशासी कारपोरेशन जयपुर का, जैसा बंगलौर का, मद्रास का, अहमदाबाद का, अन्य सिटीज का नया बना हुआ है, उसी प्रकार का कारपोरेशन बनाएं। माननीय मंत्री महोदय, तब इस समस्या का समाधान होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि कारपोरेशन बनाये हैं। उसमें यदि आपके हिसाब से कोई कमी लगती है तो आप बता दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ : वैसे ही बना दो।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी से पिनपाइंटेडली यह सवाल पूछा था। तीन सवाल पूछे थे एक तो....

श्री सभापति : ठीक है। आप पूछ चुके, उनको पता है। वह जवाब नहीं दे रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप उनको बाध्य करें। माननीय दीवान साहब।

(श्री सभापति)

देना चाहते तो दे देते। अब बाध्य थोड़ी कर सकते हैं।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, तो आप, कुछ जिक्र नहीं है।

श्री सभापति : अब उन्होंने नहीं दिया तो नहीं दिया। अब बाध्य थोड़ी कर सकते हैं। आप बाद में पूछ लेना। माननीय दीवान जी।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक ही बात पूछना चाहता हूं जिस तरह से नई दिल्ली के अंदर बड़े-बड़े बंगलों में बगीचों को पानी पिलाने के लिए सीवरेज वाटर के लिए अलग पाइप लाइन डाली हुई है, ताकि बगीचे में अच्छे पानी का, मीठे पानी का उपयोग न हो और वह वेस्ट वाटर है, उसका उपयोग हो सके। ऐसी कोई योजना यहां पर बड़े-बड़े बंगलों में पानी पिलाने के लिए बनायी जा रही है ताकि जो पानी उपलब्ध है उसका पीने के लिए उपयोग किया जाये और फालतू बगीचों को पिलाने में वेस्ट न हो ?

श्री सभापति : जयपुर की पेयजल पर चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय श्री नरपत सिंह राजवी चित्तौड़गढ़ स्थित घोसुन्डा बांध का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। ....(व्यवधान)....

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं ....(व्यवधान)....

सूचना

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में डा. पाटनी की लापरवाही से मृत्यु

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइंट आफ इनफार्मेशन है साहब।

श्री सभापति : क्या पाइंट आफ आर्डर है आपका ?

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अंदर पाटनी डाक्टर जो चुम्बकीय चिकित्सक थे....

श्री सभापति : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : कल उनकी मौत हो गयी साहब। कल उनकी मौत कर दी गयी डाक्टरों की लापरवाही के कारण और ऐसे व्यक्ति की लापरवाही के कारण, डाक्टरों ने लापरवाही की है....(व्यवधान)..

श्री सभापति : मैं सुन नहीं रहा हूं तीन का। एक आदमी बोलें। क्या हो गया ?

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, डाक्टरों की लापरवाही के कारण जो इमरजेन्सी वार्ड में चुम्बकीय डाक्टर साहब पाटनी जी भर्ती थे उनकी मौत हो गयी और जो सारे भारतवर्ष में....

श्री सभापति : यह पाइण्ट आफ आर्डर है क्या ? इनफार्मेशन है यूं कहिए। पाइण्ट आफ आर्डर थोड़े ही हुआ। पाइण्ट आफ इनफार्मेशन है।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस प्रकार से जो लापरवाही की गयी डाक्टरों द्वारा, उस के कारण मौत हो गयी। उनकी हत्या की गयी, ...(व्यवधान)....

श्री सभापति : हां, पाइण्ट आफ इनफार्मेशन बोलना चाहिए ....(व्यवधान).... पाइण्ट आफ आर्डर बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी इसके बारे में ध्यान दें कि डाक्टरों की लापरवाही से एक डाक्टर मर गया और उसकी जिंदगी चली गयी।

श्री सभापति : हां, इनफार्मेशन है। ठीक है। बहुत सही बात है। इन्होंने पाइण्ट आफ आर्डर कहा।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, पाइण्ट आफ इनफार्मेशन कहा है।

श्री सभापति : अच्छा, सारी। वैरी सारी। इम्पोर्टेण्ट नहीं वैरी इम्पोर्टेण्ट।

श्री रामनारायण मीणा : इम्पोर्टेण्ट है। आप पानी पीने में मशगूल थे।

श्री सभापति : इम्पोर्टेण्ट, वैरी इम्पोर्टेण्ट।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर भारतीय चुबंक चिकित्सक संस्थान के संस्थापक डॉक्टर पाटनी के पुत्र ने आरोप लगाया है कि उनके पिता की मृत्यु में सवाई मानसिंह चिकित्सालय के डाक्टरों की लापरवाही मुख्य भूमिका रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अखबार नहीं पढ़े। आपने बात बता दी। मंत्रीजी ने सुन ली और वह जरूर इस बात पर ध्यान देंगे। माननीय राजवी जी।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा....

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, मंत्री महोदय बता रहे हैं, साहब। डाक्टरों की लापरवाही से एक डाक्टर को मार दिया ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : सुनिये, मंत्रीजी बता रहे हैं कुछ।....(व्यवधान).... सुनिये मंत्रीजी बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : इस बारे में सदन को अवगत करा दूं, सभापति महोदय, 15-3-1994 को डाक्टर सी.एम. पाटनी एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे जिसको प्रोफेसर पी.पी.एस. माथुर ने स्वयं ने देखा उसके तुरन्त बाद उनका सी.टी. स्केन उसी वक्त कर लिया गया था। उनके दाहिने तरफ कोई हिमोटोना बन गया था और गंभीर अवस्था में ही उनको सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। सभापति महोदय इसके पश्चात् भी अगर इस पूरे प्रकरण में किसी भी तरह का लेप्सेज किसी भी स्तर पर हुआ हो, चाहे चिकित्सक स्तर पर हुआ हो, चाहे पेरा-मेडिकल स्टाफ के स्तर पर हो, चाहे आपातकाल में उनके भर्ती करने में विलम्ब के सम्बन्ध में हो, मैं पूरे प्रकरण की जांच कराकर और सदन को भी अवगत करा दूंगा और माननीय सदस्य को भी अवगत करा दूंगा।

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बिलकुल मंशा नहीं है कि जो चिकित्सक अपने कार्य के प्रति लापरवाह हो या किसी इस तरह की बात में उसके लेप्सेज के कारण किसी की जान जाये, उनको बचाया जाये । निश्चित तौर पर इसकी पूरी जांच कराकर मैं सदन को अवगत करा दूंगा ।

श्री सभापति : श्री नरपतसिंह राजवी ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चित्तौड़गढ़ स्थित घोसुन्डा बांध का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़ जिले में, नगर के समीप भी है, एक बांध बना हुआ है, उसको घोसुन्डा बांध के नाम से जाना जाता है ।

श्री सभापति : आप केवल ध्यानाकर्षण कीजिए मंत्रीजी का । वक्तव्य आएगा फिर बोलिए ।

श्री नरपतसिंह राजवी : अगर आप नाम ही लेने देना चाहते तो ध्यानाकर्षण कैसे करूंगा सभापति जी ।

श्री सभापति : अच्छा, सॉरी । मैंने सोचा आप बोलने लग गए ।

श्री नरपतसिंह राजवी : मैं बोल नहीं रहा हूं मैं ध्यानाकर्षण करने के लिए ही मैंने लिखकर दिया था और मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : करिए-करिए ।

श्री नरपतसिंह राजवी : उससे उत्पन्न स्थिति के कारण मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा ।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : घोसुन्डा बांध के निर्माण हेतु....(व्यवधान)..

श्री रामनारायण चौधरी : न कोई राजकुमार है, न कोई महाराजकुमार है, न कोई कंवर साहब । इस सदन में आसन है, आप सभापति हैं, स्पीकर हैं, दूसरे सब माननीय सदस्य हैं । अक्सर सुनने में आता है कभी कोई काको सा कह देते हैं, कभी कोई बाबो सा कह देते हैं तो इस सदन की परम्परा रही है कि सदन में सब माननीय सदस्य हैं और माननीय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है ।

श्री सभापति : कुछ विरोध भी होना चाहिए । माननीय मंत्रीजी ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सदस्य ने बिलकुल वजह फरमाया है लेकिन हम समाज में रहते हैं और सामाजिक रिश्तों के नाते काको सा भी होते हैं, बाबो सा भी होते हैं और कंवर साहब भी होते हैं । आप इन रिश्तों से बचकर जा नहीं सकते ।

श्री रामनारायण चौधरी : वो तो विधान सभा के बाहर है । यहां कोई काको सा नहीं है, न कोई बाबोसा है । यहां सब माननीय सदस्य हैं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । माननीय मंत्रीजी ।

श्री देवीसिंह भाटी : घोसुन्डा बांध के निर्माण हेतु 709.50 लाख रुपये की स्वी-

(श्री देवीसिंह भाटी)

कृति वर्ष 1980 में जारी की गयी। स्वीकृत योजना में बांध की भराव क्षमता 2665 एम.सी.एफ.टी. एवं इससे 24 हजार 700 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1980 में सिंचाई विभाग द्वारा परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। इसी दौरान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर ने, जो भारत सरकार का उपक्रम है, चित्तौड़गढ़ के पास ग्राम चंदेरिया में सुपर स्मैल्टर परियोजना एवं अन्य दूसरे प्लाण्ट बनाने हेतु पानी की मांग प्रस्तुत की। जिस पर विचार कर बांध के निर्माण के विषय में राज्य सरकार एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के मध्य निम्नानुसार सहमति हुई।

(1) बांध की नींव 4000 एम.सी.एफ.टी क्षमता के लिए भरी जायेगी। तथा प्रथम चरण में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 2600 एम.सी.एफ.टी. भराव क्षमता के लिए बांध का निर्माण किया जायेगा।

(2) 2600 से 4000 एम.सी.एफ.टी. भराव क्षमता बढाने हेतु बांध को ऊंचा उठाने का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) 2600 में से 500 एम.सी.एफ.टी. जल राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के लिए आरक्षित रहेगा।

(4) सभी ड्राइंग सिंचाई विभाग द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने बांध की डिजाइन, ड्राइंग का कार्य केन्द्रीय जल आयोग से कराकर बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इसके पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा 86.67 लाख रुपये व्यय किये जा चुके थे। डिजाइन के अनुसार कुल भराव क्षमता 3824 एम.सी.एफ.टी. रखी गई तथा इसी भराव क्षमता के लिए बांध की नींव भरी गई। वर्ष 1990 तक मुख्य बांध का एवं स्पिल वे के लेवल तक 418 मीटर तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया। परन्तु बांध में फाटक का कार्य शेष है। इसके अतिरिक्त स्पिल वे को 2 मीटर अस्थाई रूप से ऊंचा कर बांध में 450 एम.सी.एफ.टी. पानी का संग्रहण करना शुरु कर दिया। बांध स्थल पर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कर पाइप लाइन बिछा कर सुपर स्मैल्टर प्लांट हेतु वर्ष 1990 से पानी का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया। वर्ष 1986 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने चित्तौड़ जिले में थर्मल प्लांट निर्माण हेतु जो सेन्च्युरी टैक्सटाइल एवं इण्डस्ट्री लिमिटेड के माध्यम से प्रस्तावित है, 1700 एम.सी.एफ.टी. जल की मांग की जिसे बाद में 1800 एम.सी.एफ.टी. कर दी गई। 90 पर्सेण्ट विश्वसनीयता पर बांध स्थल पर पानी की आवक 3600 एम.सी.एफ.टी. आंकी गयी जिसके विपरीत हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की सम्मिलित मांग 3900 एम.सी.एफ.टी. होने से वर्ष 1988 में इस बांध से सिंचाई न किये जाने का निर्णय लिया गया एवं बांध से जल को उक्त दोनों इकाइयों के लिए आरक्षित किया गया। यह निर्णय राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने की दृष्टि से किया गया। तत्पश्चात् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

(श्री देवीसिंह भाटी)

विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ शहर के लिए पेयजल हेतु 450 एम.सी.एफ.टी. जल की आवश्यकता दर्शायी गयी एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपनी मांग 2100 एम.सी.एफ.टी. से घटाकर 1900 एम.सी.एफ.टी. कर दी। वर्ष 1992 में पानी का वितरण निम्नानुसार निर्धारित किया गया।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	– 1500 एम.सी.एफ.टी.
सी.टी.आई.एल.	– 1800 एम.सी.एफ.टी.
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	– 300 एम.सी.एफ.टी.
कुल	– 3600 एम.सी.एफ.टी.।

लगभग तीन वर्षों से बांध का निर्माण कार्य बन्द पड़ा हुआ है तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड वर्तमान व्यवस्था से जो पानी उपलब्ध हो रहा है उसका वह उपयोग कर रहा है। राज्य सरकार इस स्थिति से चिन्तित है एवं बांध के निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए सम्बन्धित इकाइयों से विचार-विमर्श कर शीघ्र निर्णय लेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री नरपतसिंह राजवी।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, फेक्चुअल पोजीशन तो मंत्रीजी ने सदन को अवगत करायी लेकिन डेड स्टोरेज लेवल कितना है। डेड स्टोरेज लेवल 419 मीटर पर है और डेड स्टोरेज लेवल के साथ में जितनी अस्थायी व्यवस्था हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने की है उसको उतने ही पानी आवश्यकता है बल्कि मैं कहूंगा उससे कम पानी की आवश्यकता है इसलिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उसको कम्पलीट नहीं करना चाह रहा है। हिन्दुस्तान जिंक के अधिकारी माननीय मंत्रीजी के साथ घोसुन्डा बांध पर पधारे थे। वहां पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री, माननीय भंवरलालजी शर्मा भी वहां पधारे और उन्होंने ऐसी बात कही जो मेरे ख्याल से कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी कह ही नहीं सकता। उन्होंने कहा साहब यह पिलर बाद में इरेक्ट करेंगे, पायर्स, बाद में इरेक्ट करेंगे पहले हम गेट तैयार करवा रहे हैं। गेट की स्टेडी हो चुकी, गेट के लिए टेण्डर निकाले जा चुके लेकिन टेण्डर एक्सेप्ट नहीं हुए। कोई फाइनेंशियल बिड आयी नहीं उनके पास। कम से कम 14-15 करोड़ रुपये इस बांध पर और खर्च होंगे तब जाकर के उस बांध को पूर्ण कराया जा सकता है। प्रथम स्टेज के लिए जब मिस्टर इब्राहीम अली, डाइरेक्टर प्रोजेक्टर हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि फर्स्ट फैज में ढाई करोड़ रुपये लगा कर हम यह निर्माण कार्य पूरा कराना चाह रहे हैं। फर्स्ट फैज में 2600 एम.सी.एफ.टी. का प्रावधान है। अभी तो 450 एम.सी.एफ.टी. रोकने की व्यवस्था उन्होंने नहीं की और वह 2600 एम.सी.एफ.टी. है। कितने और वर्ष लगायेंगे और यह प्रश्न सिर्फ हिन्दुस्तान जिंक का नहीं है। प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान जिंक की अकर्मण्यता के कारण क्या यह राज्य सरकार और इरिगेशन विभाग, सिंचाई विभाग चुपचाप बैठा रहेगा। आज डाउन स्ट्रीम में ग्रेजिंग सिस्टम इरिगेशन विभाग का नहीं

(श्री नरपतसिंह राजवी)

है। इतना रन ग्राफ, फ्लड रन ग्राफ है उसके लिए भी इनको पूछना पड़ता है, सी. डब्ल्यू.सी. को। माननीय सभापति महोदय, इब्राहीम ग्रलीजी ने एक पत्र दिनांक 7-6-1990 को लिखा। उसकी ग्रोर मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। उस पत्र में ग्रलग–ग्रलग उन्होंने लिखा है–

"Government of Rajasthan to consider the provision for infrastructure facilities and locations of new lead, zinc smelter plant for Hindustan Zinc Ltd."

उसमें काफी ग्रधिकारी उपस्थित थे– "Repuirement of water of 70,000 metric ton for Zinc Plant, 35,000 m.t for lead Plant, 3,000 m.t. for Copper Plant, 1,80,000 m t. for Sulfuric Acid Plant and 4 × 5 mega-watt captive power plant, besides other industries like fertilizers." ग्रब यह एन्सीलियरी यूनिट, जो ग्रनफोरसीन फ्यूचर में कभी लगाई जायेगी उसके लिए उन्होंने एक ऐसा फिगर 1900 एम.सी.एफ.टी. का रखकर कर दिया। ग्राज की स्थिति में जितना पानी हिन्दुस्तान जिंक ले रहा है, 400 एम.सी.एफ.टी. से ज्यादा वह ले ही नहीं सकता। उतनी ही उनकी कैपेसिटी है जो पाइप लाइन उन्होंने लगायी है। उससे जितना भी सरप्लस पानी है वह किसानों के यूज में क्यों नहीं ग्राये। ग्रगर ग्रार.एस.ई.बी. उसको उपयोग में लायेगी तो बांध के निर्माण पूर्ण होने से पूर्व आर.एस.ई.बी. के ग्रधिकारी वहां जाकर भी न देखेंगे। वह इसलिए नहीं देखेंगे कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इतना ही नहीं, मैं यह पूछना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से, कि जनरल इम्प्रेसन चित्तौड़गढ़ में ही नहीं आपके विभाग के अधिकारियों का भी यही है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को यह बांध हस्तान्तरित कर दिया गया है। जबकि यहां के मुख्य सचिव ने एक पत्र लिखा है दिनांक 16-3-1983 को उसके ग्राधार पर प्रोजेक्ट डाइरेक्टर ने आगे पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि– the Government of Rajastban and Allotment of water was confirmed by the Chief Secretary, Government of Rajasthan vide D.O. letter No. 80 dated 16.3 1983." यह ग्रलाटमेण्ट ग्रॉफ वाटर है। ग्रगर अलाटमेण्ट ऑफ वाटर है तो उनसे वाटर चार्जेज आप ले लें जितना पानी हिन्दुस्तान जिंक को चाहिए वह ले लेकिन कम से कम घोसुन्डा बांध पर किसानों का और राज्य की जनता का हक है वह फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। पानी उसको चाहिए 1900 एम.सी.एफ.टी. उसको उस टाइम में चाहिए, ग्राज की तारीख में इतने पानी की उसको ग्रावश्यकता नहीं है। बांध का निर्माण भी पूरा करना नहीं चाह रहा है ग्रौर जितना पानी सरप्लस फ्लो हो रहा है तो उतना इनफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेण्डीचर लगाने की ग्रावश्यकता क्या थी फाउण्डेशन तो डिपार्टमेण्ट ने लगायी, थोड़ी सी क्रेस्ट लेवल तक उसको रेज कर वह मालिक बन कर वहां पर बैठ गया। एक वहां पर वर्कचार्ज एम्प्लायी उनका रहता है। इंजीनियर वहां पर रह नहीं सकता, क्योंकि ग्रापकी

(श्री नरपतसिंह राजवी)

मिल्कियत नहीं समझते हैं। फ्लड के टाइम पर क्या स्थिति होगी अगर यह बांध पूरा बन गया और उनका वर्कचार्ज एम्प्लायी को कौन सूचना देगा, उनके क्या नेटवर्क हैं ? सभापति महोदय, भूमि एक्वायर नहीं की गयी। यह भी उन्होंने कहा.... क्रेस्ट लेवल तक जितनी जमीन एक्वायर करनी थी, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने उसका पैसा भी दे दिया और लैण्ड एक्वायर भी हो गयी। तो बेस्ड लेवल से ऊपर जितनी जमीन एक्वायर होनी चाहिये बांध का पूरा निर्माण करने के लिए वह भूमि अभी तक एक्वायर नहीं की गयी लेकिन उसकी मिल्कियत उसको हस्तांतरित कर दी है, अभी तक एग्रीमैण्ट पर मेरे ख्याल से साइन नहीं हुए हैं लेकिन अगर उसकी मिल्कियत उसको हस्तांतरित कर दी है तो यह लैण्ड एक्वायर हिन्दुस्तान जिंक करेगी और बेस्ड लेवल तक जितनी भूमि एक्यावर करनी थी वह भी हिन्दुस्तान जिंक ने ही एक्टिविटी अपनी खुद की तरफ से रिकमंडेशन देकर लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर के माध्यम से करवायी। इरिगेशन विभाग के माध्यम से लैण्ड एक्वीजीशन उस समय भी नहीं हुआ। इसके पश्चात् उन्होंने कहा कि हमने कम्पनसेशन के अलावा रीसेटलमैण्ट भी उनका कर दिया। रीसेटलमैण्ट किया है, जमीन अलॉट की है, उनको एडीशनल जमीन अलॉट की है, कम्पनसेशन के अलावा तो राज्य सरकार ने, सिंचाई विभाग ने, रेवेन्यू विभाग ने हिन्दुस्तान जिंक से पैसा लिया है। प्रश्न यह हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार का नहीं है। प्रश्न यह है कि राजस्थान की सरकार का पैसा जो राजस्थान की जनता का पैसा है, उसका सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ। जो भी ड्यूज हिन्दुस्तान जिंक से इरिगेशन विभाग की थी वह उन्होंने पूरी की या नहीं की। हिन्दुस्तान जिंक ने फाउंडेशन लेबल तक जितना 86 पाइन्ट कुछ लाख का खर्च किया है, वह उन्होंने नहीं दिया अभी तक। बिल्डिंग्स भी उनको हस्तान्तरित की है लेकिन उसका पैसा भी अभी तक नहीं दिया है। जितने काश्तकारों को उठाना था, उसको अन्यत्र बैठा दिया, भूमि उनको आवंटित की है लेकिन सरकार को कम से कम उसका पैसा उसको मिलना चाहिये था। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव श्री एम. एम.के. वली के एक पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फर्स्ट भेज में उन्होंने 2600 एम.सी.एफ.टी. तक हिन्दुस्तान जिंक को पूरा करना था। इरिगेशन विभाग 2600 एम.सी.एफ.टी. के बाद 4 हजार तक उसको रेज करेगा लेकिन 2600 एम.सी.एफ.टी. केपेसिटी भी अभी तक डवलप नहीं हुई है तो आने वाले वर्षों में जितनी प्रोजेक्ट कास्ट थी, उतनी तो बढ़ चुकी है और बढ़ जायेगी। मैं मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम यह तो व्यवस्था दें कि जितना भी पानी सरप्लस, हिन्दुस्तान जिंक की उपयोगिता के अतिरिक्त सरप्लस है, वह पानी वहां के किसानों के लिए रखा जाये। आर. एस. ई.बी. उस पानी को यूज करना चाहती है, बेशक उसको यूज करे लेकिन जितना पानी सरप्लस होकर फ्लो करेगा उसमें पिकअप वीयर बनाकर कम से कम वहां की जो विकट स्थिति है, गंभीर स्थिति बनी हुई है, पानी को पिकअप वीयर के साथ में वहां पर वाटर टेबल तो कम से कम मेनटेन करें। इतना ही नहीं वाटर टेबल मेनटेन

(श्री नरपतसिंह राजवी)

उससे थोड़ा-थोड़ा होगा। थोड़े बहुत आस-पास के किसान हैं, उस नाले में जितना पानी बहेगा उससे लिफ्ट करके पानी लगा लेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से कि वह व्यवस्था दें कि कितने दिन में हिन्दुस्तान जिंक के अधिकारियों से और केन्द्रीय मंत्रालय से वह बात करके चित्तौड़ जिले के काश्तकारों के साथ जो अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिले, इस सम्बन्ध में कितने दिनों में आप कार्यवाही करेंगे और जो किसानों को कम्पनसेशन के अतिरिक्त, भूमि आबंटन के अतिरिक्त भूमि इनको लेनी है, कब तक उनको कम्पनसेशन देकर के गेट्स लगवा देंगे ताकि पानी को रोका जा सके।

श्री सभापति : श्री राजपाल सिंह शेखावत। (अनुपस्थित)। श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, आम तौर से किसी भी क्षेत्र में यदि बांध का निर्माण होता है तो बड़ी प्रसन्नता की लहर फैलती है। लेकिन मैं घोसुन्डा का रहने वाला हूं, वैसे विधायक तो राजसमन्द का हूं लेकिन....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया यह दुकान नहीं खोलें यहां पर।

श्री शांतिलाल खोईवाल : घोसुन्डा बांध वहां की जनता, वहां के किसानों के लिए एक अभिशाप साबित हुआ है। मंत्री महोदय यह बात सुनने लायक है कि किसी क्षेत्र में बांध बने वहां प्रसन्नता की लहर होनी चाहिये लेकिन घोसुन्डा बांध उस क्षेत्र की जनता और किसानों के लिए एक अभिशाप साबित हुआ है। अभी मंत्री महोदय ने जिस तरह के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं कि प्रारम्भ में इरिगेशन डिपार्टमेंट को इस बांध का निर्माण करना था लेकिन बाद में यह सुपर स्मैल्टर की स्थापना की बात चली तो इन्होंने अपना क्लेम सरेंडर कर दिया और उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान जिंक अपने स्तर पर इस बांध का निर्माण कराये लेकिन उसमें तीन-चार कंडीशंस रखी हैं। जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बताया कि 2600 एम.सी.एफ.टी. तक भराव के लिए तो बांध निर्माण पर जितना खर्चा होगा वह हिन्दुस्तान जिंक वहन करेगा और उसके बाद में 2600 से 4000 तक का खर्च राजस्थान का सिंचाई विभाग वहन करेगा। प्रारम्भ में जिस तरह की योजना थी उसका उपयोग सिंचाई के लिए होगा लेकिन बाद में हिन्दुस्तान जिंक के अधिकारियों और हिन्दुस्तान जिंक ने इस बात का विरोध किया कि हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहते। मुझे जिस तरह की सूचना है यहां के तत्कालीन मुख्य सचिव ने लिखित में यह दे दिया है, एक एग्रीमेंट के स्वरूप में कि हम इरिगेशन के लिए इस पानी का उपयोग कभी नहीं करेंगे। आप इस बांध का निर्माण कीजिये। इस बात की चर्चा मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में नहीं की। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि घोसुन्डा बांध के निर्माण के पहले आम तौर से उस नदी में जोहड़ के रूप में पानी भरा रहता था। वहां का वाटर लेबल बहुत ऊंचा था लेकिन यह बांध बनने के बाद पानी का रुकाव हुआ है। आज वह सारे जोहड़ सूख चुके हैं। वहां का वाटर लेबल

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

बहुत नीचे गिर चुका है और इन जोहड़ों के भरोसे जब तक पानी नहीं रोका था उस समय तक उस नदी के किनारे कई ईरिगेशन लिफ्ट स्कीम्स का निर्माण हुआ। वहां के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। आज वहां की स्थिति यह बनी है कि वहां पर एक भी ईरिगेशन लिफ्ट स्कीम चालू नहीं की है। अब ऐसी स्थिति में आप उस क्षेत्र के किसानों को इस तरह क्यों मार रहे हैं? एक तरफ तो बीसलपुर परियोजना के बारे में चर्चा चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि वहां पर यह पेयजल का मूल स्रोत बनाया जा रहा है। अब उसको भी साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर मान कर कैचमेंट एरिया मान लिया है और वहां पर आप छोटे-छोटे एनीकट्स के निर्माण के लिए अवरोध पैदा करा रहे हैं ईरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से। अब एक तरफ तो आप एनीकट नहीं बनाने दे रहे हैं, इधर जिस तरह का घोसुन्डा बांध बना है उससे उस क्षेत्र के किसानों को कोई लाभ नहीं है तो आखिर यह सरकार इस तरह की योजना बनाकर उस क्षेत्र की जनता को क्यों परेशान करना चाहती है। पानी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि पानी की सुविधा भी उस क्षेत्र की जनता को उपलब्ध नहीं करायेंगे, वहां की जनता पानी सिर्फ देख रही है कि इस बांध में पानी भरा हुआ है लेकिन उस क्षेत्र की जनता के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। मैं पेयजल की बात नहीं करता। पेयजल का प्रावधान तीन सौ एम.सी.एफ.टी. रखा है, अच्छी बात है। मिलना चाहिये इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन वहां सिचाई के उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा और सिचाई के लिए जब कोई प्रावधान नहीं रखा है तो मैं समझता हूं वहां के किसानों पर बहुत बड़ा अत्याचार है।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि यदि हिन्दुस्तान जिंक जैसा कि चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि 400 एम.सी.एफ.टी. तक भराव क्षमता के बांध का निर्माण हिन्दुस्तान जिंक ने अभी किया है जबकि वह उपयोग सिर्फ 200 एम.सी.एफ.टी. का ही कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि....220 एम.सी.एफ.टी. कर रहा है।. 220 एम.सी.एफ.टी. से ज्यादा की आवश्यकता हिन्दुस्तान जिंक को हो। अब वह अपना पैसा खर्च क्यों करेगा। क्योंकि आपके टर्म्स एण्ड कंडीशंस के हिसाब से 2600 एम.सी.एफ.टी. भराव क्षमता तक बांध का निर्माण हिन्दुस्तान जिंक को कराना है, वह क्यों करेगा इतना बड़ा खर्चा और इसीलिए वह टालमटोल कर रहा है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार इंटरवीन कर हिन्दुस्तान जिंक पर दबाव डाले कि वह 2600 एम.सी.एफ.टी. भराव क्षमता तक बांध का निर्माण तो वह तत्काल कराये और शेष यदि राजस्थान सरकार अपनी टर्म्स एण्ड कंडीशंस में कोई तब्दीली करने की क्षमता रखती है तो उसमें तब्दीली कराये और उस पानी का उपयोग सिचाई के लिए कराया जाये नहीं तो आज हर दृष्टि से, आपके बीसलपुर परियोजना और घोसुन्डा बांध की दृष्टि से वहां के किसान परेशान हैं और यदि इसके बारे में तत्काल राजस्थान सरकार ने इंटरविन करके कार्यवाही नहीं की तो बहुत परेशानी हो जाएगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल। (अनुपस्थित)। श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान घोसुन्डा बांध की ओर दिलाना चाहूंगा। चित्तौड़गढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र में घोसुन्डा बांध अपूर्ण पड़ा हुआ है। अतः सिंचाई मंत्री जी से विशेष आग्रह करूंगा कि इस बांध को जल्द ही पूरा करवाने की स्वीकृति प्रदान करें जिससे चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र को ही सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा वरन् मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगरार तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। जिसकी भराव क्षमता भी अधिक है। अतः मेरा विशेष निवेदन है कि इस कार्य को अविलम्ब पूरा करवाया जाये तथा साथ ही साथ मेरे क्षेत्र की नहरों का भी सर्वे कराया जाकर उन्हें भी पूरा कराने के आदेश दिलाये जायें। यह मांग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में भी बनास नदी पर मेजा फीडर नाम से एक बांध बना हुआ है उसकी भराव क्षमता 2410 एम.सी.एफ.टी. है लेकिन इसका सारा का सारा पानी भीलवाड़ा स्थित मेजा डेम में 54.2 किलोमीटर लम्बी नहर बनाकर ले जाया गया है। इस नहर की क्षमता तीन सौ क्यूसेक्स पानी पर सैकिण्ड है। अतः श्रीमान् सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर मेजा फीडर जो बांध है उस का सारा का सारा पानी भीलवाड़ा को दिया जाता है जबकि मेरे क्षेत्र की जनता को एक बूंद पानी भी इस डेम से नहीं मिल पाता है। चित्तौड़ का पानी चित्तौड़गढ़ जिले में, जो मातृकुण्डिया बांध स्थित है वह धार्मिक स्थल भी है, परन्तु उसमें वहां की जनता के लिए एक बूंद पानी भी आरक्षित नहीं किया गया है। अतः आप से निवेदन है कि हमारे हिस्से का पानी हमको दिलाया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हरिसिंह सोढ़ा। (अनुपस्थित)। श्री प्रताप सिंह। (अनुपस्थित)। श्री कन्हैयालाल पाटीदार। (अनुपस्थित)। श्री चुन्नीलाल गरासिया। (अनुपस्थित)। श्री अमरचन्द मिढ्ढा। अनुपस्थित)। श्री पूराराम चौधरी (अनुपस्थित) श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (अनुपस्थित)। श्रीमती मीना अग्रवाल। आपका क्या सम्बन्ध है इससे ?

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : बांधों का है साहब। पहाड़ों का जो पानी आता है उसके बारे में थोड़ा बोलना चाह रही हूं मैं मास्टर प्लान के लिए। (व्यवधान)....

श्री सभापति : नहीं, नहीं। यह इसी विषय पर। बिराजिए। श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर)। (अनुपस्थित)।

श्री नरपतसिंह राजवी : इस पर आपके भी हस्ताक्षर हैं।

श्री सभापति : हैं ?

श्री नरपतसिंह राजवी : इस पर आपके भी हस्ताक्षर हैं, सभापति महोदय, इसलिए बोलना चाह रही हैं....

श्री सभापति : हस्ताक्षर तो हैं, लेकिन इस विषय पर नहीं बोल रहीं....

श्रीमती मीना अग्रवाल : सभापति जी, थोड़ा अलवर के बारे में....

श्री सभापति : अच्छा, अच्छा। बोलिए, बोलिए।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय सभापतिजी, अलवर में अरावली पहाड़ी पर बरसात का पानी जो झरने की तरह आता है वह सारा पानी सड़क पर आकर रास्ता जाम करता है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि बड़े बांध की योजना के बदले छोटे बांधों की स्कीम स्वीकार करके, निर्माण का मास्टर प्लान बनाया जाये खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्र में, अलवर में वैसे दो-तीन झील हैं, सिलीसेड है, जयसमन्द है, विजय मन्दिर के पीछे है। इसलिए इनका मास्टर प्लान बनाकर इनका पानी हमारे किसानों और जानवरों के लिए काम आ सके स्कीम बनायी जाय। इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल। (अनुपस्थित)। श्री प्रभुराम गरासिया। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) अच्छा, क्षमा कीजिए। गरासिया जी हैं। (व्यवधान)

श्री प्रभुराम गरासिया : नहीं, मेरा तो मेरे क्षेत्र के लिए है....

श्री सभापति : बोलिए, बोलिए।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में, आबू पिंडवाड़ा में कई ऐसे जो बांध हैं, सर्वे हो चुका है, उनकी स्वीकृति के लिए यहां भेजे गये है लेकिन अभी तक वह सैंक्शन नहीं हुए हैं। अतः आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि यह आदिवासी क्षेत्र है और इस आदिवासी क्षेत्र का सारा पानी गुजरात में जा रहा है इसलिए हमारे आबू पिंडवाड़ा के जो बांधों के सर्वे हुई है वह स्वीकृति के लिए आपके पास आयी है। उनको कम से कम जल्दी सैंक्शन करें और काम चालू करवाएं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, घोसुन्डा बांध के बारे में, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की है, विशेष रूप से पूर्व में इस बांध का निर्माण मात्र सिंचाई के लिए ही किया गया था, इसके बाद में समय-समय पर इसके अन्दर परिवर्तन करके और सिंचाई को तो बिल्कुल ही काट दिया गया। तथा अलग-अलग हिन्दुस्तान जिंक को, आर.एस.ई.बी. को और पेयजल के लिए देना तय कर दिया। एक माह पूर्व मैंने पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर माननीय भंवरलालजी शर्मा और चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य से, इस सम्बन्ध में हमने थोड़ी यहां चर्चा की थी और वास्तव में यह चिन्ता का विषय था कि, हम से हिन्दुस्तान जिंक वालों ने जो बात की थी उस पर न तो वह पूरे उतर रहे हैं, न उनकी ऐसी कोई मंशा लग रही है कि समय पर इसका निर्माण करवा दिया जाये। चित्तौड़ के लिए भी पेयजल की विकट समस्या थी लेकिन सारा मुद्दा इस पर जुड़ा हुआ था कि इसका निर्माण समय पर होना चाहिए था। जिसके लिए हिन्दुस्तान जिंक ने हमें आश्वस्त किया कि इसके अन्दर जैसे क्रेस्ट लेवल के ऊपर हमें जो आगे निर्माण करना है, गेट्स लगाने हैं वह हम समय पर कर देंगे लेकिन जैसा पूर्व में कोरस्पोंडेंस

(श्री देवीसिंह भाटी)

हुई, पत्रावली देखी वह बारबार इस बात को टालते रहे हैं और इसलिए हमने मौके पर जाना उचित समझा और हम लोग वहां मौके पर गये। वहां देखकर वाकई में बड़ा दुःख हुआ कि जो पानी मूल में सिंचाई के लिए काम में आना चाहिए था उससे तो काश्तकारों को बिल्कुल वंचित कर दिया गया है डाउन स्ट्रीम में, पहले हिन्दुस्तान जिंक इसके बीच में आया, उसके बाद में आर. एस. ई. बी. को पानी की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने भी अपनी मांग रख ली और अब पी. एच. ई. डी. की चित्तौड़ के लिए यह मांग थी। कुल मिलाकर हमारे पास इसमें पानी उपलब्ध है, जब यह पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो 3600 एम. सी. एफ. टी. पानी हमें सारा उपलब्ध होगा। वैसे इसकी क्षमता चार हजार एम. सी. एफ. टी. की होगी लेकिन धीरे-धीरे करते-करते 1500 एम.सी.एफ.टी. पानी हिन्दुस्तान जिंक के लिए तय हो गया और सी.टी.आई.एल. के लिए आर.एस.ई.बी. के माध्यम से 1800 एम.सी.एफ.टी. उसके लिए तय हो गया और पी.एच.ई.डी. के लिए 300 एम. सी. एफ. टी. हो गया। हालांकि उसकी मांग अब और बढ़ गयी है तो कुल मिलाकर सारे पानी का वितरण तो हमने कागजों में कर दिया लेकिन मौके के ऊपर यदि हिन्दुस्तान जिंक वालों की इच्छा होती कि हम इसके अन्दर पूरी रुचि रखते हैं तो इसका समय पर निर्माण करें, हम इसके लिए बाउण्ड हैं। वह उन्होंने कतई रुचि ली नहीं, हम मौके पर गये, उनके अधिकारियों से भी बातचीत की। इस सारे मुद्दे के बारे में चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अलग-अलग कुछ बिंदु उठाये लेकिन मैं उनको सार की बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जिंक वालों ने राज्य सरकार को विश्वास दिलाया कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करके इसका समय पर निर्माण करा देंगे, जब गेट्स लग जाएंगे, इसकी क्षमता बहुत बढ़ जायेगी तो इसके पानी का आप दूसरे कामों में उपयोग ले सकते हैं लेकिन इन सारे हालात को देखकर जो भी चर्चा हुई उससे मैं बिलकुल संतुष्ट नहीं हूं। मैं एक ही बात कह देना चाहता हूं स्टील एण्ड माइन्स की सैण्ट्रल मिनिस्ट्री से इसके लिए हम तुरन्त चर्चा करेंगे कि यदि आपकी इसके अन्दर रुचि है और पानी लेना चाहते हैं तो समय पर इसका निर्माण करा दें। समय की भी मैं अभी आपको घोषणा कर देता हूं कि उनको हम बाउण्ड करेंगे कि छह महीने के अन्दर या तो आप निर्माण की कार्यवाही शुरू कर दें वरना इसके लिए हम बाउण्ड नहीं हैं। हम अपने हिसाब से इसका निर्माण करेंगे और मैं यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हमारे पास शेष पानी बचेगा, जिस तरीके से भी हम पानी ला सकेंगे। चाहे आर.एस.ई.बी. का पानी बचे, उसमें मात्रा हालांकि कम होगी या कितनी होगी यह तो सारा डिस्कस करने के ऊपर पता लगेगा लेकिन जितना पानी हम ज्यादा से ज्यादा डाउन स्ट्रीम में ले जाकर काश्तकारों को उपलब्ध करा सकें जिससे थोड़ा कुओं का भी वाटर लेबल बढ़े। इन सारे मुद्दों के बारे में हम कार्यवाही करेंगे और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी प्रगति होगी। अगले विधान सभा के सत्र में जब भी सदन की बैठक होगी, उस समय निश्चित तौर पर मैं

Page No.74

(श्री देवीसिंह भाटी)

आपको जानकारी दूंगा और इसकी कार्यवाही होगी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : कितना समय लगेगा इसमें सभापति महोदय ? कितना समय लगेगा इसमें ?

श्री देवीसिंह भाटी : छह महीने का हम उन्हें समय देंगे या तो इसके अन्दर बैठकर तय करें इसकी कार्यवाही और निर्माण शुरू कर दें वरना हम इसके लिए बाउण्ड नहीं हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वह एग्रीमेंट अगर साइन नहीं हुए हैं तो...

श्री देवीसिंह भाटी : एग्रीमेण्ट नहीं कन्सेंस हैं, सहमति है।

श्री नरपतसिंह राजवी : नहीं, एग्रीमेंट एक पेण्डिग है साइन होने पर तो उस एग्रीमेंट को साइन कृपया इस अवधि में न करें ताकि कोई लीगल काम्प्लीकेशन वहां खड़ा न हो जाये और जहां तक सरप्लस पानी का सवाल है, सवाल यह नहीं है कि कितना पानी सरप्लस किसानों को मिले, पानी जिस जिस एजेंसी को चाहिये उतना लें। आज जो स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से वहां के किसानों को अगर पानी लिफ्ट इरिगेशन से भी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं लेकिन वहां पानी का स्तर जो नीचे चला गया, कम से कम एक हजार करोड़ रुपये की कोस्ट की अभी जो ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री बन रही है वह भी बंद हो जाएगी। यहां पर जितना यह पावर, केपटिव पावर प्लांट पांच सौ मेगावाट का यह लगा रहे हैं यह आने वाले दस वर्ष में भी अभी नहीं होगा। स्टेज आफ इन्फेंसी में पेरेनियल फ्लो जहां पर रिवर्स का है उस स्थान पर नया सर्वेक्षण करवाकर पावर प्लांट लगाने की व्यवस्था करें। यहां पर वह पावर प्लांट भी बंद हो जाएगा और किसानों के घर के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। इसलिए इस पूरे प्रास्पेक्ट को दुबारा एग्जामिन करने के लिए सदन में कोई घोषणा करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस समय हिन्दुस्तान जिंक का प्लांट भारी घाटे में चल रहा है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और आपकी पहली सीढ़ी हिन्दुस्तान जिंक के खाते में बनती है 2600 एम.सी.एफ.टी. तक की, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो संस्थान घाटे में चल रहा हो और उनके कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है वह पहली सीढ़ी बना लेंगे ? अगर वह अपनी पहली सीढ़ी नहीं बना पायेंगे तो दूसरी सीढ़ी क्या हवा में बनायेंगे ? इसलिए मेरा निवेदन यह है मंत्री महोदय कि आप इसके बारे में गहराई से विचार करें, चिन्तन करें हिन्दुस्तान जिंक इस समय वायेबल संस्था नहीं रही है अब इन्टरनेशनल मार्केट को मद्दे नजर रखते हुए इसलिए वह बहुत बड़े घाटे में दिनो दिन बढ़ती जा रही है। मेरा निवेदन यही है कि तत्काल जो टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स यदि हिन्दुस्तान जिंक वायोलेट कर रहा है तो इस

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

वायोलेशन करने पर राजस्थान सरकार आगे आकर अपने स्तर पर निर्णय ले। धन्यवाद,

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार खुद 400 करोड़ के घाटे में चल रही है। कर्मचारियों को देने के लिए उसके पास तनख्वाह के पैसे नहीं है और यह उस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। यहां कौनसी जगह आपको सरप्लस नजर आ रहा है? राजस्थान सरकार 400 करोड़ के घाटे में है, कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है।

श्री सभापति : बिराजिए–बिराजिए। मंत्रीजी।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय श्री रामनारायण जी साहब यह लाइटली नहीं कह रहा हूं और इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मुझे कहना आवश्यक है लेकिन जिस....

श्री रामनारायण चौधरी : उस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का है। वह घाटे में चल रहा है। तो घाटे में आज कौन सा नहीं चल रहा है? देने के लिए तनख्वाह नहीं है और कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं। आप सरप्लस में है और मालदार हैं तो उनको तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं ताकि उनकी भी समस्या हल हो जाये और उनकी स्ट्राइक टूट जाये।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के बारे में आपको यह बात उठानी है तो उचित माध्यम से जरूर उठायें लेकिन इस इश्यू को डाइल्यूट करके किसानों पर आघात नहीं पहुंचायें। यह बात सही है कि अगर उनकी नीयत बनाने की होती और उनके पास पैसा होता तो वह अवश्य बनाते और आज भी बना लें लेकिन वह बनाना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए इसको आप डाइल्यूट नहीं करें। इस पूरे प्रास्पेक्ट में मैं, सदन की अनुमति चाहता हूं, आप सभी लोगों के माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको री-कन्सीडर करें। इसमें स्टेट इन्टरेस्ट सफर करे, किसानों का इन्टरेस्ट सफर करे, उस इश्यू को लाइटली लेकर डाइल्यूट कर देंगे तो अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन चित्तौड़गढ़ की जनता जो पीढ़ियों से संघर्ष करती आई है वह अब और संघर्ष नहीं करे, कम से कम वह स्थिति तो आप पैदा करें।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं किसानों के हक में हूं। उनके पक्ष में हूं। आपके इस प्रस्ताव से किसान को लाभ मिलता है तो हमारी राय आपके साथ में है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए कह रहे हैं वह दिवालिये में चला गया और तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है। मैंने तो सिद्धान्त की बात कही है आज घाटा कहां नहीं हैं, घाटा तो चारों तरफ है। मैंने तो प्रसंगवश बात कही हैं वरना मैं आपके प्रस्ताव के साथ हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, जैसा कि चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की कि कोई इस प्रकार का एग्रीमेंट होकर हम बाउन्ड नहीं हो जायें इसके लिए मैं उनको विश्वास

(श्री देवीसिंह भाटी)

दिलाता हूं कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होगी और यह बात भी सही है कि अभी आर.एस.ई.बी. भी इस स्थिति में नहीं है कि पानी का उपयोग कर सके। तो यह सारे हम मुद्दे ध्यान में रखते हुए मैं राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य को फिर यह विश्वास दिलाता हूं कि हम स्टील एण्ड माइन्स मिनिस्ट्री को इसके लिए मजबूर करेंगे कि या तो 6 महीने के अन्दर चाहे वह घाटे में है यह उनका काम है वह खुद देखें, यदि उन्होंने 6 महीने के अन्दर अपना निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो हम इसके लिए कतई बाउन्ड नहीं होंगे और हम सिंचाई के लिए काश्तकारों को जितना पानी उपलब्ध करा सकते हैं उसके लिए योजना बनायेंगे और बिलकुल वह व्यवस्था की जायेगी।

श्री सभापति : घोसुन्डा बांध पर चर्चा समाप्त हुई, श्री लक्ष्मणसिंह नियम 131 के अन्तर्गत ब्यावर शहर में पेयजल समस्या से आम जनता को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री लक्ष्मणसिंह। (अनुपस्थित)। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री भीमसेन चौधरी।

याचिकाओं का उपस्थापन

नागासर माइनर (कंवर लिफ्ट नहर) के फाल हटाकर सिंचाई क्षेत्र का विस्तार

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, मैं, (1) नागासर माइनर (कंवरसेन लिफ्ट नहर) के फाल हटाकर सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करवाये जाने बाबत 2 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका एवं (2) तहसील लूणकरणसर के ग्राम घेसूरा से रामबाग पंचायत मुख्यालय तक 6 किलोमीटर की सम्पर्क सड़क का निर्माण करवाये जाने बाबत 2 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : श्री महावीर भगोरा।

तहसील कोटडा की पंचायतों को तहसील उपखण्ड एवं जिला मुख्यालयों में सीधी सड़कों से जोड़ना

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, मैं गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र की तहसील कोटड़ा की पंचायतों को तहसील उपखण्ड एवं जिला मुख्यालयों से सीधी सड़कों से जोड़ जाने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अजमेर फाइसागर खरेकड़ी-पुष्कर सड़क का अविलम्ब निर्माण कार्य करवाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय, पुष्कर का धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। वर्तमान में अजमेर से पुष्कर जाने वाली सड़क में कई घाटियां होने के कारण तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस सड़क के मध्य में दुर्घटनाएं होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। अतः अजमेर, फाइसागर, पीसांगन, खरेकड़ी–पुष्कर सड़क का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने का निवेदन करता हूं। अजमेर फाइसागर खरेकड़ी-पुष्कर सड़क पर अकाल राहत के कार्यों के अन्तर्गत काफी काम कराया गया था लेकिन चूंकि इसके लिए कोई नियमित राशि स्वीकृत

(श्री विष्णु मोदी)

नहीं की गयी अतः यह कार्य नियमित रूप से नहीं चल सका। उक्त सड़क मार्ग की स्थिति बहुत खराब है और इसकी देख-रेख नहीं हो पाती है। अतः इस सड़क मार्ग की ओर अधिक ध्यान देने के लिए निवेदन है।

श्री सभापति : आय-व्ययक (बजट) 1994-95 अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव। ....(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापति जी आपने मुझे एश्योर किया था कि कल जो हमने शून्यकाल में प्रस्ताव रखे थे....

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे पहले मांग रख लेने दें फिर आप बोल लेना।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27–पेयजल योजना की प्रस्तुति

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27–पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,78,92,40,000 (पांच अरब, अठहत्तर करोड़, बानवे लाख, चालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

1. झुन्झुनूं जिले के खारे पानी के गांवों को जर्मन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम फेज में शामिल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

2. झुन्झुनूं जिले के खारे पानी के गांवों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. मण्डावा क्षेत्र के गांवों में निर्मित क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना लूट्, कोलिन्डा का संचालन अनियमित तथा अति असंतोष-जनक होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

4. प्रदेश में पीने के पानी के संकट ग्रस्त गांवों के लिये जल योजना बनाकर समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र तथा राजस्थान के अन्य हिस्सों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

6. बीसलपुर परियोजना की क्रियान्विति में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

(श्री विष्णु मोदी)

7. अजमेर जिले में खराब पड़े हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. पुष्कर में पेयजल समस्या के निवारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं करने के के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

9. अजमेर एवं ब्यावर शहर में उत्पन्न पेयजल की विषम स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

10. शहर व गांवों में जल की कमी व व्यवस्था ठीक न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

11. ब्यावर शहर में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. ब्यावर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में भोमादह बांध एवं अन्य स्त्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

13. नौरंगदेसर, रानीसर, बीकानेर व मनाफरसर में पेयजल की पूर्ति हेतु नया ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. ग्राम कालू, पूगल की संशोधित पेयजल योजना स्वीकृत करके कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

15. ग्राम उदासर, बसलू, नौरंगदेसर, रायसर, नापासर, सिंथल के अपर्याप्त भू-जल को मद्देनजर इन गांवों के लिए कवरसेन नहर से दीर्घकालीन योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम):

16. गलत निर्णयों के कारण अजमेर शहर में उत्पन्न पेयजल की समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन) :

17. केशवरायपाटन तहसील (बून्दी) के गांव रेबारपुरा, अरनेठा, रडी, श्रीपुरा, आणन्दा आदि में भारी पेयजल संकट को मध्य नजर रखते हुये शीघ्र योजना स्वीकृत करवाई जाकर वर्षों पूर्व की समस्या का समाधान करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

18. केशवरायपाटन क्षेत्र की लाखेरी कापरेन एवं केशवरायपाटन नगरपालिकाओं की पुरानी पेयजल योजना को जनसंख्या के अनुरूप एवं भविष्य में समाधान को मध्य नजर रखते हुये योजना बनाकर स्वीकृति दिलाने पर चर्चा के लिये।

19. कापरेन (बून्दी) नगरपालिका की ग्रामीण बस्तियों (वार्डो) की एक करोड़ 25 लाख की पूर्व प्रस्तावित योजना की स्वीकृति हुडको द्वारा स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

Page No.79

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

20. सहायक अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लाखेरी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

21. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अनुसूचित जाति जन-जाति का आरक्षित कोटा पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

22. पंचायत समिति नीमकाथाना के ग्राम रामसिंहपुरा में पेयजल टंकी के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. कोटड़ा एवं पुराना बास व सिरोही ग्राम पंचायत नीमकाथाना में पेयजल का गम्भीर संकट होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

24. विभाग में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :

25. निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ में अपर्याप्त पेयजल योजना द्वारा अनियमित रूप से पानी वितरित करने तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

26. भीलवाड़ा जिले में स्वीकृत पेयजल योजनाएं निर्धारित अवधि में पूरी न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) :

27. गंगापुर, सहाड़ा, रायपुर क्षेत्र में पेयजल सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) :

28. पंचायत समिति सांगानेर के गांवों में चालीस हैण्ड पम्पों का पानी स्तर नीचे जाने के कारण नये पाइप नहीं लगाने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

29. पंचायत समिति सांगानेर में पेयजल योजना की 9 टंकियों में पानी नहीं पहुंचाने के कारण उत्पन्न गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

30. पंचायत समिति लालसोट की अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की ढाणियों में हैण्डपम्प नहीं होने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम तलाबगांव बगडी की पेयजल योजनाओं से अनुसूचित जाति की बस्तियों में सार्वजनिक स्थान पर पी.एस.पी. नहीं लगाने के कारण उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

32. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम विलौनाकला सामूहिक पेयजल वितरण योजना से पर्याप्त पानी नहीं मिलने के

(श्री परसादीलाल मीणा)

कारण उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

33. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम रामगढ़-पचवारा में पेयजल टंकी का निर्माण नहीं होने के कारण उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

34. लालपुरा बिहारीपुरा (लालसोट) की पेयजल योजना से पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) एवं **डा. जितेन्द्र सिंह** (खेतड़ी) :

35. पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादोती के ग्रामों में चालू हैण्डपम्पों का जल स्तर नीचे जाने तथा विचाराधीन एवं स्वीकृत योजनाओं को चालू न करने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) :

36. निवाई कस्बे में 2 लाख की दो नई टंकियों के निर्माण न होने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) :

37. माण्डलगढ़ क्षेत्र की अधूरी पड़ी जल प्रदाय योजनाओं के कारण जनता को हो रही पेयजल की दिक्कत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

38. ग्राम पंचायत जाखोद पंचायत समिति सूरजगढ़ चनानीया की ढाणी, हरिजनों की, ग्राम पंचायत फरट मेदा की ढाणी, हरिजनों की, कासनी में हरिजनों के बास में पीने के पानी की विकट समस्या पर चर्चा के लिये ।

39. ग्राम निहालपुरा/कलोठडा ढाणी भालोठ / कालोता / मोई पुरानी पंचायत समिति बुहाल (झुन्झुनू) में पीने के पानी की उत्पन्न भयंकर समस्या पर चर्चा के लिये ।

40. झुन्झुनू जिले में पेयजल के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

41. पंचायत समिति बुहाना (झुन्झुनू) में उत्पन्न पीने के पानी की समस्या पर चर्चा के लिये ।

42. सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री कालूलाल गुजर (मांडल) :

43. भीलवाड़ा जिले में अकाल के कारण पेयजल संकट के सम्बन्ध में तथा माण्डल विधान सभा क्षेत्र की थाना ज्ञानगढ़, कोड़ियाल कटार, पीथास अमरगढ़, दरीबा समोडी, मालाखेड़ा, भांवलास, सबलपुरा योजनाओं व सागवा एकलिंगपुरा योजना को तत्काल चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) :

44. सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र के राजास, बलाल, नैयासर आदि ग्रामों में

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

पेयजल की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. इन्दिरा गांधी नहर के लिए जर्मनी के सहयोग से बनी पेयजल योजना में सरदारशहर क्षेत्र के सभी गांवों व कस्बों को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. सरदारशहर कस्बे में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक कुओं को विभाग के अधीन लेकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. साहवा-गंधीली पेयजल योजना के अन्तर्गत सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) :

49. भीम व देवगढ़ तहसीलों में मदारिया, सारोठ, पारड़ी पंचायत मुख्यालयों पर पनघट पेयजल योजना पर चर्चा के लिये।

50. भीम देवगढ़ तहसीलों में खराब हैण्ड पम्प सुधारने तथा नये हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. ब्यावर नगर तथा भीम व देवगढ़ तहसीलों में पेयजल की गम्भीर समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) :

52. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोटडा पुराना बास की ढाणियों में खारे पानी की वजह से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. पंचायत समिति नीमकाथाना में सूखे व बेकार हैण्ड पम्पों की जगह नये हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. सुभाष मण्डी नीमकाथाना में वाटर टैंक बनाकर पेयजल सप्लाई करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण):
श्री कालीचरण सराफ(जौहरी बाजार):
श्री गोपीराम जाट (आमेर) : एवं
श्री रामेश्वर भारद्वाज (मूर्तिकार) (किशनपोल) :

55. ग्राम साइवाड़ ग्राम वामना के अधूरे कुओं को तत्काल पूरे किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. जयपुर नगर में दोनों समय पूरे दबाव के साथ जल वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. जमवारामगढ़ के जलग्रहण क्षेत्र में बनाये गये 43 एनीकटों को तत्काल वायदे के अनुसार ध्वस्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. जमवारामगढ़ बन्धे को और ऊंचा किये जाने की आवश्यकता पर तथा जयपुर नगर की पेयजल आपूर्ति के लिये

Page No.82

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कानोता बन्ध को तत्काल बांधे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. हैण्ड पम्प के रखरखाव मरम्मत का कार्य राज्य में पंचायत समितियों के बजाय विभाग को सौंपे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

60. प्रदेश में नल योजना द्वारा शहरी क्षेत्र में जनता को पानी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

61. ग्रामीण क्षेत्र में जनता को पानी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

62. बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 की आबादी पर हैण्ड पम्प लगा कर पानी दिलाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

63. कुशलगढ़ शहर में नल योजना द्वारा अनास नदी से पानी लाकर पानी दिलाने में राज्य सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द (दानपुर) :

64. राज्य सरकार दानपुर विधान सभा क्षेत्र में दानपुर, घोड़ी तेजपुर, छोटी-सखन अम्बापुरा, माहीडेम, पीपलखुर, घण्टाली ग्रामीण क्षेत्रों में जनता हाट बाजार करने जाती है वहां पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. दानपुर विधान सभा क्षेत्र में बस स्टेण्डों पर पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. राज्य सरकार की दानपुर व आवापुरा गांवों में ट्यूबवेल खोदकर पानी दिलाने में असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

67. झुन्झुनूं जिले में पंचायतों, पंचायत समिति तथा जलदाय विभाग द्वारा निर्मित पीने के पानी की टंकियों पर विद्युत कनेक्शन करवाकर चालू करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

68. झुन्झुनूं जिले में पूर्व में स्वीकृत पीने के पानी की टंकियों के शीघ्र निर्माण कार्य चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. झुन्झुनूं जिले के गुढ़ा गांव में एक नई पानी की टंकी बनाकर गांव वालों को पेयजल सुलभ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील की बागोली-नेवरी तथा अन्य रीजनल योजना को सुचारू रूप से चालू रखने पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

71. ग्राम बांधोली (रामगढ़, अलवर) को पेयजल आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. नशोपुर ग्राम को पानी के स्रोत से ग्राम खूंटेटा को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) :

73. धौलपुर क्षेत्र के गांवों में पीने का पानी सुलभ करवाने के लिए हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. धौलपुर नगर में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए अलग से नई टंकी बनाई जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

75. धौलपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय योजनाएँ मभरोली, सरानीखेड़ा, अरेली, वरेह-मोरी जो स्वीकृत है उन्हें चालू नहीं करने के कारण उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. धौलपुर नगर में ओगमेन्टेशन करवाकर पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर):

77. सभी नई बनने वाली जल प्रदाय योजनाओं में ऊंची टंकी बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. नई बनी जल प्रदाय योजनाओं को नहरों से पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. चालू जल प्रदाय योजनाओं की डिग्गियों के कच्चे तले को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. पेयजल के घरेलू कनेक्शन प्राथमिकता से देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :

81. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या के लिए अधिक आर्थिक प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी):

82. रामगंज मण्डी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) :

83. क्षेत्र महुवा में जलदाय विभाग द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय जलदाय योजनाओं की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. जलदाय योजना पावटा तहसील महुवा के गत 10 दिन से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र महुवा पंचायत समिति टोडाभीम की स्वीकृत जलदाय योजना फोजीपुर ताजपुर की शीघ्र क्रियान्विति हेतु चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

86. जालौर जिले में पेयजल में फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में डीफ्लोराइडेशन प्लांट लगवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. जालौर जिले में क्षतिग्रस्त गिराने योग्य उच्च जलाशयों को शीघ्र गिराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

88. खूड, बानूडा, मूण्डवाडा ग्रामों की पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान करने

(श्री ग्रमराराम)

की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

89. जैतपुरा पंचायत समिति रोहट में पीने के पानी के लिये तालाब भरवाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

90. विभाग द्वारा लाडनूं क्षेत्र में पूर्व की तरह टेंकरों से पानी सप्लाई ग्रभी तक चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज फर्म से पाइप खरीद कर किये जा रहे घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. नागौर जिले में खारे पानी को मीठा करने के लिये लगाये गये बीस संयंत्रों के लम्बे समय से बन्द पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. कस्बा लाडनूं की पेयजल योजना के सुधार नहीं किये जाने के कारण लोगों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

94. ग्राम देवरा, तीलोकपुरा, बगडीयों की ढाणी तहसील लाडनूं की पेयजल योजना को पी.पी.सी. द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

95. तहसील राजगढ़ (चूरू) के ग्रामों को पेयजल स्थानीय साधनों से उपलब्ध करवाये जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. तहसील राजगढ़ जिला चूरू के ग्राम सुलखनिया छोटा, सुलखनिया बड़ा ग्रादि ग्रामों में दूषित पीने का पानी उपलब्ध करवाने से ग्रामीण जनता का स्वास्थ्य खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. तहसील राजगढ़ जिला चूरू के ग्राम हसियावास, धानोरी बड़ी, धानोरी छोटी, न्यागल छोटी, न्यागल बड़ी, रेजडी, चुम्बकीयागढ़ ग्रादि गांवों को गेन्धेली साहब पेयजल योजना से पीने का पानी उपलब्ध कराने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. तहसील राजगढ़ जिला चूरू के लाभान्वित ग्राम कामाण, बीराण, ढाणी खुडानी, ढाणी जीराम को पिछले एक साल से पीने का पानी नहीं उपलब्ध होने से जनता को हो रही कठिनाई के बारे में चर्चा के लिये।

99. तहसील राजगढ़ जिला चूरू में लगाये गये ग्रार. प्लान्ट गत तीन वर्षों से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

100. कुम्हेर क्षेत्र को उत्तर-प्रदेश की यमुना नदी से चार क्यूसेक पानी जो भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र को मिल रहा है उसमें से पेयजल उपलब्ध कराने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. ग्राम ग्रवार तहसील कुम्हेर में एक गहरा टयूब वेल खोदकर पेयजल

(श्री हरिसिंह)

उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. ग्राम भटावली तहसील कुम्हेर का पानी की टंकी के निर्माण को पूरा कर पेयजल योजना की क्रियान्विति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. कुम्हेर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु गहरे ट्यूब वेल खोदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) :

104. पंचायत समिति कोटकासिम के साबी नदी के पार' हरियाणा सीमा पर स्थित ग्राम पंचायतें जैसे उजोली, लालपुर, आकोली, जाटूवास बीरनवास आदि ग्रामों में पीने का पानी खारा होने के कारण बीरनवास ग्राम (जहां पानी मीठा है) वहां बोरिंग करवा कर ग्राम उजोली में टंकी निर्माण कर समस्या दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) :

105. विभाग द्वारा जल प्रदाय योजनाओं हेतु विद्युत कनेक्शनों के लिए डिमाण्ड राशि जमा नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. अधीक्षण अभियन्ता जलदाय विभाग सीकर की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

107. सीकर जिले की पेयजल समस्या के समाधान हेतु पाइप लाइन की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. ग्राम लोहरवाड़ा (सीकर) में अधूरी पड़ी पानी की टंकी को पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. श्रीमाधोपुर क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर) :

110. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में खराब हैण्डपम्प ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. ग्राम गोलाना-खानपुर में पेयजल की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) एवं **श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (बल्लभनगर):

112. हैण्डपम्पों के रख रखाव की दो विभागों की जिम्मेदारी होने एवं उनमें तालमेल की कमी से अधिकांश हैण्ड पम्पों के खराब पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

113. मीटर द्वारा तथा फ्लेट रेट पर जल प्रदाय करने बाबत कोई मापदंड नहीं होने से बढ़ते भ्रष्टाचार की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

114. पंचायत समिति बांदीकुई के गांव हिंगोटा, गुल्लाना, बसवा, ऐचेंडी, लीलोज में कुओं के जल स्तर में हो रही कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

115. पंचायत समिति बांदीकुई के गांवों में पर्याप्त हैण्ड पम्प नहीं लगाने के कारण पेयजल का गंभीर संकट पैदा होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

116. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के स्कूल डूगरली, दीपरी, इटावा टंकी, ग्रासीध ग्रादि गांव में ग्रामीण क्षेत्र में नई बस्ती में उत्पन्न पेयजल संकट की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री उमगराज मेहता (ब्यावर) :

117. ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद में पेयजल की उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) :

118. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में स्कूलों में हैण्डपम्प लगाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

119. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पेयजल हेतु टंकी व कुग्रों के ग्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

120. राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पनघट के ग्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

121. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पशुग्रों के पीने के पानी के ग्रभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

122. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में ढाणियों में हैण्डपम्प लगाने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (बल्लभनगर):

123. बल्लभनगर तहसील के नगरपालिका क्षेत्र भीण्डर एवं कानोड जल प्रदाय योजना में फिल्टर नहीं होने से गन्दा पानी वितरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

124. बल्लभनगर तहसील के ग्रन्तर्गत पनघट योजनाग्रों में सालेडा चारगदीया, नीमडी, राजपुरा, ग्रमरपुरा विभाग द्वारा बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

125. बल्लभनगर तहसील के ग्रामीण जल प्रदाय योजना के ग्रन्तर्गत कर्णपुर, भटेवर, खेरोदा, लूडेणा, दरोली व हिन्ता योजना से निर्धारित मापदण्ड के ग्रनुसार जल वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

126. भीण्डर तहसील बल्लभनगर में जल प्रदाय योजना के ग्रन्तर्गत गन्दा पानी वितरण करने एवं निर्धारित मापदण्ड के ग्रनुसार पानी नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

127. ग्राम पंचायत मुख्यालय खरेपुरा में ट्यूबवेल टंकी बनाकर गांव खरेपुरा ग्रौर लक्ष्मीपुरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

128. पंचायत मुख्यालय रायता में ट्यूबवेल लगाकर रायता, तुरकड़ी एवं बोरखावड़ी में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

129 रावतभाटा में पेयजल योजना लागू करने पर चर्चा के लिये ।

130. पंचायत मुख्यालय नन्दवाई एवं मेघनिवास में खुदे ट्यूबवेल को चालू कर शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

131. पंचायत बेगू और मैंस रोड-गढ के शेष सभी प्राथमिक विद्यालयों पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्प लगाने पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) :

132. झुंझुनूं जिले के लिये पूर्व में स्वीकृत पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत टंकी आदि का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

133. जहाजपुर क्षेत्र में फ्लोराइड एवं खारे पानी की उत्पन्न गंभीर स्थिति पर राज्य सरकार की उदासीनता, वर्ष 89-90 में स्वीकृत योजनाएं पूरी नहीं करने, हैण्डपम्पों का पानी स्तर नीचे जाने तथा जल की स्थाई एवं सुचारु व्यवस्था के लिए व्यापक सर्वेक्षण एवं मास्टर प्लान न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

134. विभाग द्वारा बैनाड़ा मंदिर श्रीजी महाराज में चल रही पेयजल योजना को ही संचालित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

135. ग्राम गढ व लालगढ़, दूधली, झर, बडवा, पडासोली, कून्थाडा, बैनाडा, मोहनपुरा, हैसमहल, दयालपुरा, नांगल बोहरा, बाबूपुरा की जल योजनाओं को इसी वर्ष चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

136. बूरथल की ढाणी कैण्डया, खुराबियों की व मीणान ढाणी में हैण्ड पम्प लगाने पर चर्चा के लिये ।

137. पेयजल योजना जो विधान सभा क्षेत्र बस्सी हेतु बनाई है को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

138. ग्राम रामसिंहपुरा (रेल्वे स्टेशन) को पानी उपलब्ध कराने हेतु गांव में कुएं का निर्माण पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री फूलचन्द (सलूम्बर) :

139. जयसमन्द झील का पानी पीने के लिए निःशुल्क सलूम्बर तालाब (सोरिंग तालाव) में डालकर जल वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

140. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सलूम्बर में पेयजल योजना की पाईप लाईन डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

141. बरोड़ा थड़ा, गावडापाल ईडाणा आदि गांवों में पेयजल सुविधा मुहैया कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

142. पंचायत समिति सलूम्बर एव गिर्वा की शालाओं में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प

(श्री फूलचन्द)

नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

143. हैण्डपम्पों की सम्पूर्ण देखरेख किसी भी एक संस्था द्वारा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

144. पेयजल की जो योजना गांवों में आरम्भ की जाती है उनमें प्राथमिकता से हरिजन तथा पिछडे वर्ग के मौहल्लों में पहले पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. दांतारामगढ़ क्षेत्र (सीकर) में पीने के पानी के कुओं का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो रही है तथा आने वाली गर्मियों में भयंकर समस्या उत्पन्न होगी अतः समय रहते कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. सीकर जिले में जो हैण्डपम्प ठीक होने योग्य नहीं रहे है इनकी जगह दूसरे हैण्डपम्प स्वीकृत कर पीने के पानी की समस्या का समाधान कराये जाने पर चर्चा के लिये।

147. ग्राम रलावता, जीणमाता आदि ग्रामों में भयंकर पानी की समस्या के सम्बन्ध में राज्य सरकार को भेजी गई रीजनल स्कीम के लम्बे समय से लम्बित पडे रहने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

148. ग्राम डांसरोली पंचायत समिति दांतारामगढ़ (सीकर) में तीन साल पूर्व टंकी व ट्यूबवेल बनने के बाद भी पेयजल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) :

149. निम्बाहेड़ा शहर का हुडको कालोनी में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. छोटी सादडी शहर की पेयजल समस्या के निवारण हेतु बाड़ी मानसरोवर बान्ध से पानी लाने की योजना पर चर्चा के लिये।

151. निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में निर्मित पनघट योजना के अन्तर्गत बने ट्यूबवेल एवं टंकियों को तुरन्त चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सभापति : अब आप फरमायें, क्या कहना चाहते हैं। किस बात का आश्वासन दिया था आपको ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय सभापति महोदय, यह आपने आश्वासन दिया था कि जो हमने कल शून्यकाल के अन्दर पर्ची दी थी हमारे इलाके में जो भी महत्वपूर्ण मसले चल रहे हैं उनके लिए तो अध्यक्ष जी ने यह बात कही थी....

श्री सभापति : आज आपका नाम बोलने वालों में है कि नहीं ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : वह तो है।

श्री सभापति : तो उस समय रख देना। उस समय बता दें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : लेकिन उसमें यह विषय नहीं है।

श्री सभापति : इस विषय को साथ जोड़ देना क्या दिक्कत है । बोलिये,

श्री बनवारीलाल बैरवा : उसको कैसे जोड़ दूंगा । माननीय सभापति जी, हमारे यहां महाविद्यालय निवाई में नहीं है । उसकी वजह से बहुत बैचेनी और परेशानी वहां लोगों को महसूस हो रही है । निवाई एकदम फिटेस्ट जगह है कि जहां महाविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए । उसके कुछ कारण हैं । एक तो वह सुरक्षित सीट है, वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग दोनों मिलाकर कम से कम 40 फीसदी के हिसाब से तो यह उस क्षेत्र में निवास करते हैं और हमारे यहां जो स्कूलें हैं उनकी तादाद भी आप सुन लें । सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, निवाई, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल गर्ल्स, निवाई, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, झिलाई, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, राहोली, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल जो हमसे बहुत करीब पड़ती हैं वह हैं शिवाड़, बौंली और चाकसू और इन सब में जो स्टूडेन्टस की संख्या है वह है निवाई में 390, गर्ल्स की 150, झिलाई की 40, राहोली की 160, शिवाड़ की 200, बौंली की 250 और चाकसू की 250 यह कुल मिलाकर 1640 विद्यार्थी हैं जो अब फर्स्ट ईयर के अन्दर एडमिशन लेने के लिए आतुर रहेंगे । आज की तारीख में कालेज की पोजिशन यह है कि टोंक के अन्दर कोई स्थान हमारे यहां के विद्यार्थी को मुश्किल से मिल पाता है । जयपुर की भी स्थिति यही है और अड़ौस-पड़ौस में दूसरी जगह पर कालेजेज नहीं हैं वहां पर पिछले दिनों हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी निवाई गये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था इस बात का कि हम यहां कालेज खोलेंगे बशर्ते कि.... उन्होंने ऐसा लगा दिया । यहां तक तो पूरी करने के लिए तैयार हैं कि जगह दे दें, बिल्डिंग दे दें, जो भी आवश्यकता है बिल्डिंग की वह पूरी कर दें, पर कालेज हम से थोड़े-ही चलाया जाएगा । सरकार नहीं चलाए तो हमारे जो भी विद्यार्थी हैं उनमें से मुश्किल से दस फीसदी जा पाएंगे बाहर और बाकी सब की एजुकेशन ड्राप आउट हो जाएगी । उन ड्राप आउट होने वाले लोगों में अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग होंगे, अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे, गरीब लोग होंगे और छात्राएं होंगी । इसलिए मेरा आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे यहां महाविद्यालय की स्थापना की जाए ।

श्री सभापति : श्री शीशराम जी ओला ।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मेरे कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहूंगा । आज डिमाण्ड नम्बर 27–जलदाय पर हाउस में चर्चा हो रही है । मैं सबसे पहले मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनूं जिले के लिए 1987 से 1990 तक जो स्वीकृतियां हुई उन पर एक क्वश्चन मैंने पिछली विधान सभा में रखा था । शार्ट नोटिस क्वश्चन था । माननीय मंत्रीजी ने उस पर अपना उत्तर दिया था, वह उत्तर बिलकुल सही नहीं था । हाउस को गुमराह करने वाला उत्तर था । 120 टंकियों के लिए ए आर

(श्री शीशराम ओला)

पी के तहत, उन्होंने अपने जवाब में स्वयं माना है, पैसे भारत सरकार से 1988-89 में स्वीकार हुए। यह राशि थी 1189.45 लाख। इनमें, उन्होंने बताया कि कोई 97 कार्य हो गये और 8 कार्य हो तो गये पूर्ण पर उनमें पानी नहीं दिया जा सका। यह उन्होंने बहुत गलत आधार पर सूचना दी, तथ्यों से दूर हटकर। मैं नहीं समझता कि विभाग ने भी उनको इस प्रकार की सूचना क्यों दी जो नहीं देनी चाहिए थी गलत सूचना। इसमें जसरांपुरा में अभी पानी नहीं डाला गया, टंकी बनी पड़ी हैं। नयासर में टंकी का उद्घाटन भी नहीं हुआ और सिरियासर में उद्घाटन तो हो गया लेकिन उसमें पानी की बूंद नहीं डाली है। सब जगह पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। नानकेवास में भी टंकी खाली पड़ी है, देरवाला में खाली पड़ी है, उदावास में खाली पड़ी है, जईपाड़ी में खाली पड़ी है। माखर-इस्लामपुर में मंत्री महोदय गये तो जरूर थे, उन्होंने कहा कि मार्च तक इन सब टंकियों में पानी डाल दिया जाएगा, टंकियां पानी से भर दी जाएंगी और गांव वालों को पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन आज तक तो झुंझुनू जिले में जो टंकियां बनी हैं जलदाय विभाग के माध्यम से, उनके लिए एक इंच पाइप भी नहीं गया। पाइप क्या, कोई एक टूंटी भी ऐसी नहीं गयी जिसको लगाकर पानी दिया जा सकता हो। यानी कोई सामान बिलकुल गया नहीं। ये स्कीमें मंजूर हुई 1987 से 1990 के बीच में, जिनमें अनेकों टंकी बनी पड़ी हैं–सिरोड़ है, घमोरा है, छावसरी है, टीटणवाण है, धोलाखेड़ा है, जखोड़ा है, डुलानिया है, बजावा है, गोमनसर कलां है, गोमनसर पहाड़ी वाला है, सोलाना है, मुकाना है, मलरमपुर है, किशोरपुरा है, पदमपुरा है, बामनवास है, माण्डीकलवा है। बहुत सारे गांव हैं जहां टंकियां बन गयीं लेकिन पानी नहीं है। उनमें जब भी पानी डालेंगे, ऐसी स्थिति उन टंकियों की बन गयी, वे इतनी जर्जर हो गयीं कि टूट जाएंगी। क्योंकि सीमेण्ट की टंकियां बनी पड़ी हैं और पानी डाला नहीं गया। ऐसा एक काण्ड सीकर में हो चुका है, कोई सात-आठ बरस पहले की बात है कि उस टंकी में जब पानी डाला गया तो वह टंकी फूट गयी थी। इन सब टंकियों की भी वही हालत होगी। यह योजना जब मंजूर हुई है पी पी सी के माध्यम से तो किस दूरी तक, कितने नल की, पाइप की आवश्यकता होगी, कितनी दूसरे सामान की आवश्यकता होगी, वह सारी योजना इसमें स्वीकार हुई है और सम्पूर्ण धन की व्यवस्था की गयी। धन आ भी गया लेकिन यह धन दूसरी जगह खर्च कर दिया गया, इस राशि का दूसरी जगह इस्तेमाल हो गया। जहां के लिए आयी वहां पर हुआ नहीं। अब जब कभी भी इनको पूरा करेंगे तो इतना बड़ा गैप हो जाएगा राशि का वह राशि कहां से लाएंगे? एक स्कीम दस लाख रुपए की थी, एक स्कीम बीस लाख रुपए की थी, आज अगर उसको करेंगे तो शायद वह स्कीम पचास लाख रुपए की होगी। तो इस स्वीकृति का कोई तथ्य नहीं रह जाएगा, आधार नहीं रह जाएगा।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : सभापति महोदय, मैं माफी चाहता हूं। एक सीनियर सदस्य बोल रहे हैं, ठीक है नियमों में

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

सरकार यहां बिराजमान है लेकिन जलदाय विभाग के मंत्री हैं नहीं, उनके डी.एल ओज हैं नहीं। यह विधान सभा के इतिहास में एक बहुत बुरी बात है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह ठीक नहीं है।

श्री सभापति : होम मिनिस्टर बैठे हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आपसे निवेदन किया कि नियमों में है, लेकिन सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री जब यहां बिराजमान हैं, और वह सदन में नहीं आ रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : खुद के विभाग की जानकारी नहीं रहती, पी. एच. ई. डी. की क्या जानकारी रखेंगे ?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मैंने यह पहले ही निवेदन कर दिया कि गृह मंत्री जी बिराजे हुए हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह किसको कह रहे हैं ?

श्री सभापति : अच्छा, हो गयी बात। आ जाएंगे। सुन लिया उन्होंने....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप सरकार के चीफ व्हिप को कहें.... (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप विराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : कौन जवाब देगा इन बातों का ?

श्री सभापति : बोलने दीजिये ओला जी को।....व्यवधान

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, हर रोज यह हो रहा है। सरकार जैसे पानी के प्रति गम्भीर नहीं है। रोज की समस्या है यह।

श्री सभापति : विराजिये।....(व्यवधान)....माननीय ओला जी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपका शायद यह पता नहीं है कि बिराजे हुए मंत्री महोदय इसी विभाग के राज्य मंत्री हैं।....(व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : कोगटा जी मंत्री जी क्या नोट कर रहे हैं आपको मालूम है क्या ? ....(व्यवधान).... शर्म की बात है।....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी बैंचों की तरफ देखो क्या हालत है।....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। चलने दीजिए आप बात को। विराजिये।....(व्यवधान).... राज्य मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी भी आ गये हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : राज्य मंत्री बैठे हैं, मुझे पता है। ओला जी ने जो बोला था एक शब्द भी बता दें।....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये। क्या बात हुई ? आ गये न मंत्रीजी। राज्य मंत्रीजी बैठे थे, दूसरे गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं यहां पर.... (व्यवधान) मंत्रिमण्डल की जिम्मेदारी सबकी शामिल होती है।....(व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : यह कोई नाराजगी कहीं दूसरी जगह की है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, कभी कोई पानी पीने भी जा सकता है। ऐसा क्या हुआ, समझ में नहीं आता ?

श्री सभापति : क्या बात हुई इसके अन्दर इतना व्यवधान करने की ?

श्री रामनारायण वर्मा : क्या सरकार को बहुत देर में पानी मिला पीने को ?.... (व्यवधान).... तो गांवों की क्या हालत होगी ?

श्री शीशराम ओला : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था कि कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी माखर और इसलामपुर गये थे दो जलदाय योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए। वहां पर उन्होंने यह फरमाया था कि मैं झुन्झुनूं जिले की जो टंकियां बनी हैं, जो जलदाय विभाग की योजना स्वीकृत हुई है, जो कार्य हो चुके हैं उनको मार्च तक पानी से जुड़वा दूंगा। पाइप लाइन उनको दे देंगे, सामान आ जाएगा और गांव के लोगों को, कस्बे के लोगों को, शहर के लोगों को, जहां भी ऐसी स्थिति है, उन्हें स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन, मैं आपके माध्यम से पुनः ये शब्द दोहराना चाहता हूं क्योंकि तब मंत्री जी नहीं थे, कि उन्होंने मौके पर जो आदेश दिये उनकी कोई पालना नहीं हुई। एक इंच भी पाइप नहीं पहुंचा है, वहां पर कोई सामान नहीं गया है....

(15.00)

और आज 19 मार्च होने को आयी है। सीकर में एक-दो ट्रक गये हैं लेकिन उससे आगे कोई सामान नहीं गया है इसलिए माननीय मंत्रीजी मेहरबानी से आप जहां कहीं घोषणा करें उसकी पालना करें। यदि आपके, क्या कहूं मैं कहना नहीं चाहता लेकिन अभी इस विभाग पर आपका अगर अधिकार मानते नहीं हैं आप ? या आपकी बात नहीं चलती है तो फिर दूसरे को दीजिये यह विभाग ताकि काम चल सके। मैं यह कहना चाहता था, सभापतिजी, आपके माध्यम से, कि जो काम स्वीकार हो गये और जहां पर पानी की इतनी बड़ी किल्लत थी या जो फ्लोराइड या खारा पानी वहां पर, इस बात की आवश्यकता को महसूस किया सरकार ने और विधिवत तरीके से सारी योनजाएं स्वीकार की गयीं। उन योजनाओं में कहीं 4 वर्ष पहले टंकी बन गयी, कही 5 वर्ष पहले बन गयी, कहीं 3 वर्ष पहले बन गयी। वे आज सारी की सारी सूखी पड़ी है। मंत्रीजी ने केवल एक टंकी को स्वीकृति दी है अपने चार वर्ष के कार्यकाल में 1990 से आज तक बाडां की की ढाणी में और झुन्झनूं जिले में कोई भी पानी की टंकी की स्वीकृति नहीं दी। मैं नहीं समझता कि पिछले समय में जो कार्य हुये उन्हें पूरा नहीं किया जाय, उन्हें संचालित नहीं रखा जाय, पानी की सुविधा गांव के लोगों को उपलब्ध नहीं करायी जाय, नई योजनाएं स्वीकार नहीं करें तो आने वाली गर्मी में पानी का क्या होगा ? और पानी की समस्या मंत्रीजी कैसे करेंगे ? जादू से होगा नहीं, पानी तो जमीन में से टंकी में आयेगा, टंकी में से पाइप के माध्यम से पीने वाले के पास जायेगा उसके घर में, मौहल्ले में तब पानी पीने के लिए प्राप्त हो सकेगा। और मंत्रीजी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक गम्भीर विषय है जहां पर

Page No.93

(श्री शीशराम ओला)

भयंकर पानी की समस्या हो, 11 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं इस प्रान्त में, उनके लिये अलग-अलग योजनाएं बने। 23 मशीनें फ्लोराइड पानी को शुद्ध करके पीने योग्य बनाने के लिए गई झुन्झुनूं में, उनमें एक भी मशीन कार्यरत नहीं है। 16 ऐसी मशीनें गयी जो खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करके पीने योग्य बनाना था, एक भी कार्यरत नहीं है, मशीनें पड़ी हैं, पैसे लग गये, उनका उपयोग नहीं हो रहा है और विभाग कोई ध्यान नहीं देता है। मंत्रीजी कुछ सुनते नहीं, विभाग से पूछते नहीं, क्या हो रहा है? क्यों खराब पड़ी हैं? क्यों इन पर कार्य नहीं हो रहा? इसी प्रकार से चूरू की स्थिति है खारे पानी की। मुझे याद आता है एक गांव है नांगल छोटा, वहां पर खारे पानी को मीठा पानी बनाने के लिए एक मशीन दी गई। तो वहां जब वह पानी खारे से मीठा बना तो हजारों की संख्या में महिलाएं आयीं, उनको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई खारा पानी मीठा भी हो जायेगा। लेकिन जब उस मशीन ने उस खारे पानी को मीठे में बदलकर पीने योग्य बनाया तो वहां वे महिलाएं पानी पीकर गीत गाने लगी इस खुशी में। वे सारी मशीनें चूरू की भी खराब पड़ी हैं, वहां भी यही स्थिति है। स्थिति यह है कि नई कोई भी योजनाएं आप स्वीकार करो नहीं मंत्रीजी, पुरानी को ठीक से संचालित नहीं रख सको तो फिर कैसे पानी दे सकोगे लोगों को पीने के लिए। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि 120 टंकियां तो वे हैं जो 1989 में मन्जूर हुई हैं और भारत सरकार ने इनकी स्वीकृत दी है। उसके लिए 1179.45 करोड़ रुपये स्वीकार है, विधिवत सारी स्वीकृतियां हो चुकी हैं और 80 ऐसी दूसरी हैं। ये सब पी.पी.सी. की मीटिंग में मन्जूर हुई है। कोई मंजूरी हुई है 48वीं मीटिंग में। 1.1.1989 को कुछ की मन्जूरी हुई है 59वीं मीटिंग में, एक दिसम्बर 1989 को। इसमें मलसीसर 15 लाख, बुडाना 22 लाख, बीबासर 7 लाख 70 हजार। ए.आर.पी. के, भारत सरकार के द्वारा 120 टंकियां अलग हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ टंकियां पी.पी.सी. की 43 वीं मीटिंग में दिनांक 18.2.1988 की, जिनमें झुन्झुनूं शहर, चिड़ावा व मण्ड्रेला। मण्ड्रेला की स्थिति यह है कि 13 कि.मी. दूर से काटली नदी के पाट से ट्यूबवैल के माध्यम से, 4 ट्यूबवैल खोदकर और 13 कि.मी. से 14-15 हजार की आबादी के मण्ड्रेला कस्बे में, जहां पर खारा पानी है, अच्छा स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए स्कीम स्वीकृत हुई और स्वीकृति हो गयी, उद्घाटन हो गया लेकिन आज तक वहां पानी नहीं है। इसलिए नहीं है कि 5 लाख रुपये अलग से बिजली का एक फीडर बनाकर जो 13 कि.मी. दूर से मण्ड्रेला को ट्यूबवैल के माध्यम से पानी मिलना था वह नहीं मिल रहा है बिजली के अभाव में। और वे स्वीकृति के पैसे तो पता नहीं कहां खर्च कर लिये होंगे लेकिन वह फीडर नहीं बना इससे जो बिजली आती है, कभी 6 घण्टे, कभी 4 घण्टे तो वह 13 कि.मी. पानी नहीं दे पाती। बिजली के अभाव में वहां पर पानी नहीं मिलता है। इसका अलग फीडर होता तो वह फीडर केवल उन्हीं कुओं के काम आता है, यह पहले स्वीकृत हुई है, तब मन्जूरी

(श्री शीशराम ओला)

हो चुकी थी, वह यों का यों पड़ा है कस्वा, कस्वे को खारा पानी पीने के लिए मिल रहा है। सरकार के पैसे खर्च हो गये। थोड़े से पैसे और व्यवस्था के लिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार के कई हैं, एक नहीं अनेक मिसाल हैं इसलिए मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे कम से कम मुझे नहीं भुला सकते, मुझे वे झुन्झुनूं की तरह से नहीं भुला सकते। यह भाषण दे आये कि 31 मार्च तक काम हो जायेगा। मैं आज भी यह दावा करता हूं कि इस विभाग के बारे में शायद उनको तो विभाग गलतफहमी में रखता है, मुझे नहीं रख सका और आज भी जो मेरी जानकारी है उससे अधिक जानकारी वे नहीं प्राप्त कर सकते।

यह ऐसी गम्भीर समस्या है, इसको यदि गम्भीरता से नहीं लिया तो हमारा विशाल प्रान्त, इसमें पेयजल की गम्भीर समस्या है उसके समाधान के लिए, अब तो सर्दी समाप्त हुई है, गर्मी में इनको सोने नहीं देंगे लोग। जगह-जगह से कलक्टरों के टेलिफोन आयेंगे, जगह-जगह से लोगों की डिमाण्ड आयेंगी, आन्दोलन होंगे, सत्याग्रह होंगे और पानी की एक विकट समस्या है, उसके समाधान के लिए इन्हें बहुत जागरूक रहना पड़ेगा।

मैं कुछ और तथ्य आपके माध्यम से इनको निवेदन करना चाहूंगा, वह इस प्रकार है कि इन्होंने अपने इस प्रतिवेदन में या प्रगति रिपोर्ट में तीन बड़ी योजनाओं का जिक्र किया। उसमें बीसलपुर, उदयपुर और जोधपुर हैं। उदयपुर के लिए इन्होंने 55 कि.मी. जयसमन्द से उदयपुर पानी देने की बात इसमें दर्शायी है। यह 1989 में मजीठियाजी जब पी.एच.ई.डी. के सेक्रेटरी थे और एल. आई. सी. से लोन लेकर साढ़े बारह करोड़ रुपये के पाइप उस वक्त खरीद लिये गये थे, उनके रोगन भी कर दिया था। मुझे खेद है यह कहते हुये कि आज तक वे कार्य नहीं हुये। वे पाइप नहीं लगे। ये स्कीम इनकी थी सारी 16.16 करोड़ की। आज इन्होंने इस पर खर्चा दिखा रखा है 15.82. स्थिति यह है कि जो खर्चा इस पर होना था लगभग उतना ही हो चुका है जो स्वीकृति की और इनकी गवर्नमेण्ट के अधिकारियों की या इनके विभाग की लापरवाही से वे कार्य सम्पन्न नहीं हो सके।.... अब उसको करेंगे तो और कितना खर्चा लगेगा, कहां से वह आएगा और आएगा तो क्या वह जनता का टैक्स नहीं है? इसलिए जो कार्य जिस अवधि में पूरा होना चाहिए था। जैसा माननीय श्री तिवाड़ीजी कह रहे थे जयपुर के बारे में, कि वह उस अवधि में क्यों नहीं होता है और पैसा बढ़ता चला जाता है।

इसी प्रकार से जोधपुर की जो इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट योजना फलोदी से आ रही है वह मेरे ख्याल से 205 किलोमीटर उसकी लम्बाई होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं है इन्होंने अपनी पुस्तक में दिखायी है कि उसकी लम्बाई 189.24 है, इसको भी मैं मान लेता हूं, जब लिखा है तो असत्य कैसे मानूंगा। लेकिन शुरू में इसके बजट की जो स्वीकृति थी योजना की सारी वह 103.14 करोड़ रुपये की थी जबकि आपने दिसम्बर, 1993 तक 143.67 करोड़ रुपये तो खर्च कर दिए हैं और जोधपुर को फिर

(श्री शीशराम ओला)

भी पानी नहीं मिल पा रहा है। कैसे मिलेगा, यह योजना इन्होंने ढाई सौ करोड़ रुपये की कर दी पर ढाई सौ करोड़ रुपये में भी काम नहीं हो पाएगा, हजारों करोड़ों रुपयों में भी नहीं कर पाएंगे, यह योजना बड़ी डिफेक्टिव योजना है। 180, 179 या 205 कुछ भी आप इसकी लम्बाई ले लीजिए, इसमें खुला पानी आएगा, इसके बीच में बहुत सारे गांव है, इसके बीच में बहुत सारे कस्बे हैं उन कस्बों और गांवों से बच भी जाय तो बीच में जिनके खेत हैं वह उस पानी को तोड़ कर पानी ले लेंगे और पानी जोधपुर तक नहीं पहुंचने देंगे। फिर हमारे ऊपर प्रकृति की बड़ी कृपा रहती है, जबर्दस्त आंधियां चलती हैं, आंधियां जब आती हैं तो वह इसको बूर देंगी फिर आप छांटने में लगेंगे जिससे पानी की क्षमता कम हो जाएगी, उस क्षमता से नहर पानी नहीं दे पायेगी फिर कैसे पानी पहुंचेगा ....(व्यवधान).... नहीं आ रहा है जब जगह पाइप लाइन से क्या बात करते हैं। जिस प्रकार से पूना और बम्बई के बीच में पाइप लाइन के द्वारा पानी आ रहा है उसी प्रकार की योजना माननीय मंत्रीजी आपने नहीं बनाई तो आप जोधपुर को कभी भी पानी नहीं दे पाएंगे। जादू तो आपके हाथ में है नहीं जो पानी दे दोगे आप पानी तो पानी है। आप सब जगह खड़े नहीं हो सकते हैं, आपके अधिकारी सब जगह जा नहीं सकते हैं....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : पैसा इतना लग जाएगा।

श्री शीशराम ओला : आप उसको बन्द कर दें। पर मैं एक बात कहता हूं नहीं देना है तो मत दो लेकिन जो पानी दें वह व्यवस्थित तरीके से दें इसलिए पाइप लाइन डालकर पानी दें ताकि जोधपुर को भी पानी मिले और जिन जिन गांवों को देने के बारे में आपने इसमें लिखा है कि इतने गांवों को दे रहे हैं सबको पर्याप्त पानी मिले और आपके पैसे का दुरुपयोग भी न हो और सम्पूर्ण रुपये से पेयजल समस्या का समाधान हो सके।

मैं आपको एक सुझाव और देना चाहता हूं, करना आपके हाथ में है पर मैं इसको अच्छी बात मानता हूं इसलिए निवेदन किया है आपको। अब मैं कुछ दूसरी बातों पर आता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और दूसरे माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं। आपने कहा है कि हैण्ड पम्पों के बारे में कि अब तक 42,734 हैण्ड पम्प आपने फरवरी, 1993 से जुलाई, 1993 तक मरम्मत दिखाए हैं। मंत्रीजी मेरे जिले में और जहां से भी मैं निकलता हूं, हमारे यहां डोंसी से नारनोल, राजस्थान और हरियाणा के बीच में है वहां से जयपुर तक आ जाऊं मैं तो एक भी हैण्ड पम्प चलता हुआ दिखाई नहीं देता है सारे सूखे हुए पड़े हैं, पचेरी में सूखे पड़े हैं, ढाणी में सूखे पड़े हैं यानी सब जगह सूखे पड़े हैं कितनी जगहों के नाम गिनाऊं मैं आपको, नाम गिनाकर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता सारे हैण्ड पम्स खराब पड़े हुए हैं। पिछली बार कुछ हैण्ड पम्प खोदे गए, उन हैण्ड पम्पों को खोदने के बाद जो पार्टी यहां से गई, अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की गई या दूसरी जगह की गई मुझे पता नहीं लेकिन उसने पाइप को तो रोप दिया जमीन

(श्री शीशराम ओला)

में, खड़ा कर दिया मगर पानी की एक बून्द जमीन से ऊपर आई नहीं और हैण्डिल भी लगा दिया और काम पूरा कर दिया, उसका पेमेण्ट हो गया पर पानी मिला नहीं। आपको यकीन नहीं हो तो मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखा दूंगा, आप देखेंगे तो ताज्जुब होगा....

श्री भंवरलाल शर्मा : कौनसी जगह का आपने बताया ?

श्री शीशराम ओला : मैं एक झांझोत, झुन्झुनूं जिले का नाम लेना चाहता हूं। आप चलिए और जांच करवा लें यह बात गलत हो तो मुझे आप कह देना कि आप असत्य बोले, नहीं तो मैं आपको कह दूंगा कि अब काम तो करवा दो। इस प्रकार के सारे हैण्ड पम्पों में, जिनमें पानी नहीं आया, वह तो कुछ मीटर खोद कर आ जाते हैं, उससे नीचे जाते नहीं, गांव के लोग देखते रह जाते हैं।

आपने इसी प्रकार से जहां 10 हार्स पावर की मोटर जहां लगनी चाहिए वहां पर आपने साढ़े 7 हार्स पावर की दे रखी हैं। आपसे मेरा व्यक्तिगत मतलब नहीं है, आप विभाग के मंत्री हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह समझ रहे हैं इस बात को।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो आपके लगाए हुए हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : आपके टाइम में लगे हुए बता रहे हैं वे।

श्री शीशराम ओला : मेरे टाइम में, मैं कहना चाहता हूं आज तो मैं कुछ हूं नहीं लेकिन जो अकाल 1988-89 में पड़ा था वह राजस्थान का सबसे भयंकर दुर्भिक्ष था उस समय एक जगह पर भी पानी की समस्या नहीं होने दी थी मैंने मिस्टर माननीय श्री ताम्बीजी लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करता जिसके पास काम होता है, वह काम करता है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं नहीं कह रहा हूं मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी, साढ़े 7 हार्स पावर की मोटर झुन्झुनूं जिले में कहीं भी जमीन से बाहर पानी नहीं ला सकती है, क्योंकि पानी इतना गहरा चला गया है। श्री शिवनाथसिंहजी, श्री सुन्दरलालजी, श्री रामनारायणजी साहब, व डा. साहब सब लोगों ने मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री ओला साहब, श्री रामनारायणजी साहब कल यह मांग कर रहे थे कि साढ़े 7 हार्स पावर की मोटरें ठीक हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने कल कहा था कि साढ़े 7 हार्स पावर की मोटरें काम नहीं देती हैं इसलिए मैं तो 10 और 15 हार्स पावर की बात कर रहा था। मैं तो यह मांग कर रहा था।

श्री शीशराम ओला : जहां पर साढ़े 7 हार्स पावर की मोटरें आपके विभाग ने दे रखी हैं वह मोटर जमीन का पानी जमीन से बाहर नहीं ला सकती हैं इसलिए आप मेहरबानी से बिना सोचे समझे तत्काल

(श्री शीशराम ओला)

आदेश दे दीजिए कि 10 हार्स पावर की मोटरें वहां देनी चाहिए। इसी प्रकार से जहां 15 हार्स पावर की जरूरत है वहां पर 10 हार्स पावर की दे रखी हैं तो जहां पानी 300 फीट नीचे गहरा चला गया जमीन में वहां 10 हार्स पावर की मोटरें बाहर पानी नहीं ला सकती हैं इसलिए जिस क्षमता की मोटर जमीन से पानी ऊपर ला सकती है उतने ही हार्स पावर की मोटरें मेहरबानी से आप देने के आदेश दीजिए ताकि पानी जमीन से बाहर आ सके और लोगों को पीने के लिए मिल सके।.... (व्यवधान).... पुरानी जलदाय योजनाओं की पाइप लाइनें हैं उनकी या तो पाइप लाइनें ब्लाक हो चुकी हैं या जंग लग कर टूट गई हैं इसलिए उनसे जो पीने का पानी आता है वह बड़ा गन्दा आता है, सीवरेज में मिक्स हो जाता है उससे बड़ी बीमारियां फैलती हैं। जलदाय विभाग का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वच्छ जल पीने के लिए मिले ताकि बीमारियां दूर रहें, बीमारियां हम से दूर भाग जायं। लेकिन इस गन्दे पानी के कारण से बीमारियां बढ़ती हैं। मंत्रीजी इसके दो कारण हैं। एक तो आबादी बहुत बढ़ गई है और जिस पाइप लाइन से पानी आता है वह पूरी क्षमता से नहीं आता है इस कारण सब मोहल्लों के लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए उनको बदलवायें ताकि स्वच्छ जल पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल सके। बहुत लम्बे समय से उसके लिए कहीं प्रावधान नहीं देखा है कि उनके लिए आपने कोई व्यवस्था की है। इसी प्रकार से जो कुएं गहरे चले गए हैं, सूख गए हैं, पानी नहीं है उनको भी कन्टीजेन्सी बजट के तहत तत्काल गहरा कराने के लिए बजट की व्यवस्था की जाय। ताकि लोगों को गर्मियों में पानी उपलब्ध हो सके। हमारे जिले के लिए खासकर मैं बहुत लम्बा बोलूंगा तो समय लग जायेगा। हमारी जो योजनाएं हैं, वे स्वीकृत हो चुकीं, स्वीकृति के बाद कुछ में काम भी हो गया, कुछ में काम होना बाकी है। पैसे की पहली किश्त भारत सरकार से आपके विभाग के पास आ गयी, दूसरी किश्त आपको तब मिलेगी जब आप यू.सी. देंगे। आप यू.सी. नहीं देंगे, दूसरी किश्त आपको मिलेगी नहीं और जो किश्त आ गयी है उससे काम चलेगा नहीं और जो मंजूरी मिली वह 5 वर्ष पहले के भाव से मिली, आज भाव बढ़ गये हैं इसलिए आप इस कार्य को पूरा नहीं करवा पाओगे, यदि तत्काल इसको पूरा करने की विचारधारा नहीं बनायीं तो मेरा आपको निवेदन है कि जो योजनाएं बन गयी, जो योजनाएं स्वीकृत होकर, जिनके कार्य पूरे हो गये उनको तत्काल पानी दिलावे और जो स्वीकृत हो गयी कार्य शुरू नहीं हुआ है जैसे कुलड़ियों की ढाणी, पिलानी, भोमियां ढक्करवाला, कई ऐसी योजनाएं हैं उनको मेहरबानी से आप शुरू करायें ताकि उनको भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके और जो ये मशीने खारे पानी की लगी हुई हैं इनको या तो वापस मंगायें ताकि आपके विभाग की और सरकार की बदनामी तो नहीं हो और वहां पड़ी रहने देना है तो उनको ठीक कराकर काम पर लगायें ताकि वे खारे पानी को मीठा करके पीने को दें। फ्लोराइड पानी को उसमे अलग करके एवं उन्हें अच्छा बनाकर पानी पीने को दे इसलिए मेरे जो सुझाव हैं, उनसे मैं निश्चित तरीके से

(श्री शीशराम ओला)

निश्चित समय आपसे चाहूंगा कि आप इन पर समयबद्ध तरीके से कब तक सारी योजनाओं को शुरू करके अपने हाथ में लेकर पूरा कर देंगे और कब तक स्वच्छ पानी वहां की जनता को पीने के लिए उपलब्ध हो सकेगा। यह पूरा नहीं किया तो हो सकता है भारत सरकार में मिलने वाली राशि में आपको दुविधा आये। दुविधा इसलिए आयेगी कि जो पैसा आया, उस पैसे का आपने उपयोग नहीं किया उनकी निगाहों में, मैं जो आपसे कह रहा हूं, ये मंत्रीजी प्रत्येक कस्बे और गांव के अगेन्स्ट हैं, हर गांव के नाम से आये हैं इसलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने किठाणा को पेयजल से जोड़ दिया है। किठाणा है 120 पर। और किठाणा के लिए 8 लाख 40 हजार रुपये की स्वीकृति है; किठाणा एक बहुत बड़ा गांव है लेकिन वहां न टंकी है और न पानी की व्यवस्था है और आपने दिखा दिया कि हमने दे दिया, टंकी नाम की कोई चीज वहां नहीं है, कोई पाइप नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, मैं एक के बाद एक गिनाऊं तो बहुत समय लगेगा। यह वो डाक्युमेंट है, ये वो कागज है, ये वो पत्र है जिसमें एक-एक गांव को अलग से स्वीकृति मिली, उसको पी.पी.सी. ने मन्जूरी दी। आपके टेक्नीकल मेम्बर, फाइनेन्स सेक्रेटरी, फाइनेन्स, सी.ओ., पी.एच.ई.डी. के चीफ इंजीनियर, भारत सरकार ने सबके देखने के बाद स्वीकृतियां दी हैं और उस समय पी. एच. ई. डी. के सेक्रेटरी मजीठिया थे....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आप कहां से पढ़कर बता रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं वह क्या है आपके पास ?

श्री शीशराम ओला : मेरे पास वह कागज है जो भारत सरकार ने स्वीकृत करके दिया....

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नाम क्या है इसका, नहीं-नहीं, किताब है क्या, क्या है यह ? यह आप पढ़ रहे हैं, यह क्या है ?

श्री शीशराम ओला : ये स्वीकृति है। ये 40 लीटर से 70 लीटर में परिवर्तित किया गया....

श्री भंवरलाल शर्मा : ये मिनिट्स है क्या कहीं के ?

श्री शीशराम ओला : आप कहें तो मैं इसकी कापी दे दूंगा और यह है – **The augmentation scheme – desert districts, Rajasthan, 1988-89, Annexure 1, District Jhunjhunu,** ये सब आपके आफिस में मिल जायेगा। उस समय इसके सेक्रेटरी श्री मजीठिया थे। अब मुझे खुशी है कि आपने या भैरोंसिंह जी ने बहुत सक्षम अधिकारी को पी.एच.ई.डी. का सेक्रेटरी लगाया है। अब इसमें शायद कुछ काम आगे बढ़ेगा, यह मुझे पूरी आशा है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, कई कागज विभाग ने गुम कर दिये हैं तो मैंने सबकी फाइल रख रखी है, मैं देता रहूंगा और आप मेहरबानी से काम करिये। इतना ही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : माननीय सभापति महोदय, इस सदन का सौभाग्य है कि हम सब, जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, उस पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन माननीय शीशराम जी का अभी मैंने भाषण सुना, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा आपको तो कम में कम श्री भंवरलाल जी शर्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिये क्योंकि इस विभाग का नियम बना हुआ था, जिस किसी ने पी.एच.ई.डी. विभाग सम्भाला, सम्भालते ही वह तुरन्त हार गया । बनवारी लालजी शर्मा ने लिया, वे चुनाव हार गये । गुलाब सिंह जी ने लिया....

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप मत लेना कभी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनते जाओ इन्दौरा जी । गुलाबसिंह जी ने लिया वो हार गये, शीशराम जी जो कभी चुनाव नहीं हारते, वह पी.एच.ई.डी. विभाग उनके गले आ पड़ा, वे हार गये, पिछली बार भंवरलाल जी शर्मा ने लिया....

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपको दिया तो क्या आप ले लेंगे ? श्रीमान् भैरोंसिंह जी की मेहरबानी आप पर हो जाय और आपको देना चाहें तो आप लेंगे क्या ?

एक माननीय सदस्य : आप दिलाओ तो सही ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको अभी जवाब दे दूंगा, रूको आप दो मिनट । डाक्टर हरिसिंह जी ने लिया था वे भी हार गये । जब ये हारते ही हारते रहे तो विभाग में एक हवा चल गयी कि जो ये पी. एच. ई. डी. लेगा वह चुनाव हार जायेगा, तब हमने तय किया कि भई, यह ऐसे व्यक्ति को दें जो जीत भी जाय, दुबारा जीत जाय और जीते इस आशा से कि सारे के सारे हारे हुए पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर्स हाउस में दुबारा आ जाय तो, मैं गुलाब सिंह जी को....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : वे हार गये थे, बीच में चले गये थे ।

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्याम जी, गंगानगर का क्या हुआ, वहां पर हार क्यों हुई ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहां, वह अलग बात है । पी.एच.ई.डी. से जोड़ रहा हूं तो पी.एच.ई.डी. विभाग जिस-जिसने सम्भाला वे हार गये । अब भंवरलाल जी ने पी.एच.ई.डी. विभाग लिया, वे खुद जीते और आप सबको सदन में लेकर आ गये । इसके लिए सब भूतपूर्व पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर्स को श्रीमान् भंवरलाल जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिये ।

श्री सुन्दर लाल : बिना पाणी पिये ही धन्यवाद देबो करां के ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब लियाया न थान तो, तो मैं निवेदन कर रहा था, यह जो अपने प्रदेश की स्थिति है, हिन्दुस्तान के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भू-भाग हमारे यहां राजस्थान में है, लेकिन एक प्रतिशत भूगर्भ जल हिन्दुस्तान का अपने यहां है, 5.6 प्रतिशत जनसंख्या है.... (व्यवधान) और इसी प्रकार राजस्थान की आबादी का हिन्दुस्तान की आबादी में 4.9 प्रतिशत हिस्सा था 1981 में और 1991

Page No.100

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गया और साढ़े पांच करोड़ के करीब पशुधन है और आज 10 करोड़ के करीब पशु और मनुष्य मिलकर राजस्थान में पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं, यह हमारे सामने समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी समस्या यही नहीं, राजस्थान में हमने पी. एच. ई डी. पर छठी योजना तक कुल 131 करोड़ रुपया खर्च किया, उसके बाद में हमारा खर्च बढ़ने लगा और इस समय तक हमारे रूरल क्षेत्र में 1100 करोड़ के करीब और शहरी क्षेत्र में 600 करोड़ के करीब, कुल 1700 करोड़ रुपया पेयजल की समस्या पर खर्च किया जो शायद मेरे हिसाब से एजुकेशन को छोड़कर सबसे अधिक खर्चा आपने किया है, अगर बड़े-बड़े बांध और बिजली को छोड़ दें तो एजुकेशन के अलावा सबसे अधिक हमने इस पर किया है। यह करने के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, हमारी समस्या इसके बाद लगातार बढ़ती जा रही है। जिस-जिस जगह हमने समस्या विहीन ग्राम किये थे, वे ग्राम भी वापस समस्याग्रस्त गांव में बदलते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 9400 के अधिक गांव फ्लोराइड युक्त हो गये, 6,500 से अधिक गांव खारे पानी और नाइट्रेट की समस्या से ग्रस्त हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे स्थान नये आ रहे हैं, जो इण्डस्ट्रिलाइजेशन के कारण से पेयजल से रहित होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कल शान्तिलाल जी खोईवाल बोल रहे थे, वे कह रहे थे कि उनके यहां परमानेन्ट अकाल की समस्या बनती जा रही है, ऐसे कारखाने लग गये। जैसे खेतड़ी में कारखाना लगा, लोगों को रोजगार तो मिला लेकिन आसपास के इलाके पेयजल से विहीन हो गये।

इसी प्रकार से उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और राजसमन्द जिले जो कभी पेयजल की समस्या से ग्रसित नहीं होते थे वे बहुत गहरे ट्यूब वैल लगा देने से, भूगर्भ जल का दोहन होने से आज उनमें भी पेयजल की समस्या हो गई है। पहले कभी चर्चा होती थी तो रेगिस्तानी इलाके में पेयजल पर चर्चा होती थी लेकिन आज चर्चा का विषय बदल गया है। आज पहाड़ी इलाके भी समस्याग्रस्त हो गए हैं और रेगिस्तानी इलाकों में भी पानी गहरा होता जा रहा है लेकिन पठारी और पहाड़ी इलाके समस्याग्रस्त हैं उतने रेगिस्तानी इलाके समस्याग्रस्त नहीं रहे। पानी गहरा चला गया यह बात जरूर है। ये सारी समस्यायें मिलकर हमारे सामने बहुत बड़ा संकट पैदा कर रही हैं और सभापति महोदय, हमारी इसके प्रति कोई निश्चित नीति नहीं है। 50 साल से हमने पानी के बारे में कोई नीति नहीं बनायी। हम बराबर यहां पर मांग करते हैं कि 95 पर्सेण्ट जो पेयजल है वह भूगर्भ जल से आता है। सिर्फ 5 प्रतिशत पानी हम नदियों या तालाबों से लाकर पीने के लिए देते हैं। बाकी सारा पानी भूगर्भ जल से निकालते हैं। इसी प्रकार सिंचाई का सारा स्रोत भी भूगर्भ में से हो रहा है। आज कुएं लगातार खुद रहे हैं। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। वह रोजगार कहां से प्राप्त करे, साधन डवलप नहीं हो रहे हैं, जमीन के अलावा कोई चारा नहीं है और जमीन में जब तक पानी नहीं देंगे तब तक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खेती नहीं होगी। आज राजस्थान अगर सबसे विकट समस्या से जूझ रहा है और आगे आने वाले समय में राजस्थान के सामने सबसे बड़ी प्रोब्लम होगी तो वह पानी की आयेगी।

सभापति महोदय, पानी केवल पेयजल के लिए नहीं, सिंचाई के लिए भी चाहिए। जिस ढंग से उद्योग-धंधे लगे हैं और उनको लगाने की आवश्यकता है उनके लिए भी पानी की आवश्यकता है और अगर इसकी समन्वित योजना नहीं बनी तो राजस्थान के लिए यह सबसे बड़ी समस्या बन जायेगी। खेतों का पानी भी नीचे जा रहा है। 50 हजार, 25 हजार या 10 हजार कनेक्शन प्रतिवर्ष हम देते जा रहे हैं। इसी प्रकार इण्डस्ट्रिलाइजेशन होता जा रहा है उसी प्रकार भूगर्भ जल की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन सारी समस्याओं के लिए सिंचाई विभाग अलग ढंग से सोचता है। ऊर्जा विभाग अलग ढंग से सोचता है और पेयजल विभाग अलग ढंग से सोचता है। तो सबसे पहले मैं मांग करता हूं कि राजस्थान में भूगर्भ जल की नीति निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए जो बहुत आवश्यक है। अगर ये कदम नहीं उठाये गये तो यह बात मान लेनी चाहिए कि 5 साल बाद में कितनी बिजली की डिमाण्ड करते रहो जब कुओं में पानी नहीं होगा तो सिंचाई के लिए बिजली लगाकर आप क्या करेंगे। आप कितने ही गहरे कुएं खोदते रहें जब तक पानी नहीं मिलेगा तो पेयजल के लिए क्या करेंगे। आप 500 मीटर खोद लो तो पानी नहीं मिलेगा। खेतड़ी में जाओ तो आपको यही हालत मिलेगी। जब यह हालत बनती जा रही है तो कहां से सरकार पानी लायेगी, कहां से पानी दिलाया जायेगा और कहां से पानी सिंचाई के काम आयेगा। यह बहुत बड़ी समस्या राजस्थान के बारे में है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि भविष्य को देखते हुए सरकार को नीति बनानी पड़ेगी। सरकार को सोचना पड़ेगा कि पेयजल के लिए कौनसे स्रोत लिये जाय, सिंचाई के लिए कौनसे स्रोतों को अपनाया जाय और इण्डस्ट्रीज के पानी के लिए कौनसे स्रोत अपनाये जाय। दूसरी ओर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि पानी का जो रिचार्ज कम हो रहा है उसकी क्या व्यवस्था होनी है। आज सभापति महोदय, हमारे पूर्वजों के लिए यह कहा जाता है कि वे समझदार नहीं थे, लेकिन कोई भी ऐसा गांव नहीं था जहां गांव के बाहर तालाब बेजड़, जोहड़ छोड़कर उसको पानी से भरने की व्यवस्था नहीं थी। कोई भी ऐसा गांव नहीं था जिसके पास में इस तरह की योजना नहीं थी कि जहां पर बण या बणी नहीं हो। कहीं भैरूजी की बणी, कहीं बालाजी की बणी, कहीं माताजी की बणी। गांव गांव में लगायी। उसकी कोई डाली नहीं तोड़ सकता था, कोई पत्ता नहीं तोड़ सकता था और वाटर रिचार्ज का परमानेंट सिस्टम हमारे यहां था। वह वाटर रिचार्ज का सिस्टम हमने तहस-नहस कर दिया। आज पानी के रिचार्ज का कोई साधन नहीं है और यही कारण है कि हैण्ड पम्प लगाया, पानी नीचे चला गया। फिर 20 फीट खोदा, फिर नीचे चला जायेगा। इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि राजस्थान में पानी आयोग का गठन किया जाना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहिए और आयोग का गठन करके राज्य को पानी की नीति तय करनी चाहिए और साफ-साफ तय करना चाहिए कि सिंचाई के लिए कितना पानी होगा और कितने रिचार्ज की व्यवस्था कर सकेंगे और पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था कहां से करेंगे। हो सकता है कि सिंचाई के लिए कुएं सूख जाय तो हम और कोई व्यवस्था करें, पानी नहीं दे सकें लेकिन पीने का पानी देना ही पड़ेगा। पीने का पानी सबसे पहली आवश्यकता है मुझे दुःख है कि जब यहां पर चर्चा होती है, कोई कहता है बीसलपुर से वहां सिंचाई कर दो, कोई कहता रामगढ़ से सिंचाई कर दो। एक बात निश्चित रूप से होनी चाहिए कि पानी पर पहला हक पेयजल के लिए होना चाहिए और पेयजल के लिए इसको रिजर्व करते हुए यह कानून भी बनना चाहिए कि पेयजल के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो प्राइवेट कुएं को किसी भी बावड़ी को, किसी भी तालाब को सरकार एक्वायर कर सके और पानी पर पहला अधिकार पेयजल का होना चाहिए। इस दृष्टि से इस पर निश्चित रूप से कानून सरकार को पास करना चाहिए, जो करे।

साथ ही इस आयोग में इस प्रकार के आदमी होने चाहिए जो भूगर्भ के विशेषज्ञ हों, जो कृषि के विशेषज्ञ हों और वे नीति घोषित करें। सभापति महोदय, पानी आप देंगे कहां से? आपने 24 हजार गांवों को हैण्ड-पम्पों से कमीशंड कर दिया और कह दिया कि समस्याग्रस्त नहीं हैं। आपने रीजनल पाइप लाइन स्कीम बनाई और खारे पानी के गांव में दे दिया और कहा कि गांव समस्या से दूर हो गया है। आपने टी. एस. एस. लगाई और कहा कि पानी की समस्या दूर हो गयी। मैं कहना चाहता हूं सरकार का पैसा भी गया, सरकार ने मेहनत भी की, सरकार ने धन भी लगाया और हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। समस्यायें बढ़ रही हैं। ज्यों-ज्यों जमीन का पानी निकलता जा रहा है फ्लोराइड युक्त पानी बढ़ता जा रहा है। जहां पहले मीठा पानी था वहां पूरा खारा पानी हो गया। आज पूरा भरतपुर जिला खारे पानी से लबालब है। नागौर जिले में खारे पानी की समस्या, चूरू जिले में, झुन्झुनू और सीकर के बहुत से इलाकों में खारे पानी की समस्या है। जोधपुर जिले में खारे पानी की समस्या है।

एक माननीय सदस्य : चौमूं में भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चौमूं में नहीं है। चौमूं के बारे में तो विधान सभा में कभी बोलता ही नहीं, मैं खुद ही निपट लूंगा। मैं निवेदन कर रहा था यह समस्या बढ़ती जा रही है। फ्लोराइड युक्त 9–9।। हजार गांव हैं उनमें भी हमने पानी की स्कीम बनायी लेकिन फ्लोराइड आ गया। 6।। हजार गांवों में हमने स्कीम बनाई नाइट्रेट्स आ गए। इसी प्रकार जो रीजनल पाइप लाइन स्कीम्स बनी हुई हैं उनमें टेल एण्ड के गांवों में पानी नहीं पहुंचता। पानी जब देते हैं तो बिजली बीच में चली जाती है तो पानी वहीं रूक जाता है। जो 38 हजार के करीब आबाद गांव हैं उन गांवों में ज्यों-ज्यों समस्याविहीन करते गए त्यों-त्यों वे समस्याग्रस्त होते जा रहे हैं और 2 हजार करोड़ रुपया खर्च करने के बाद में भी समस्या का समाधान नहीं कर सके। इसलिए मैं मांग करता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हूं, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, पानी तो देना पड़ेगा। आग लग गई तो कुआं खोदना पड़ेगा और मैं कहना चाहूंगा पिछले 40–45 सालों से यह विभाग तो आग लगने पर ही कुआं खोदता रहा है। इस विभाग ने परमानेंट कंटीनजेंसी प्लान नहीं बनाया। ज्यों ही सर्दियों का टाइम समाप्त होने लगता है तो कंटीनजेंसी। इस विभाग को अगर कंटीनजेंसी विभाग कह दिया जाय तो कोई अलग बात नहीं है। कंटीनजेंसी के अन्दर काम करता है यह विभाग या इस विभाग को फेमिन से पैसा चाहिए या कंटिनजेंसी का पैसा, ए. आर. पी. में चाहिए, एम. एन. पी. में चाहिए, कहीं से भी चाहिए लेकिन विभाग को दिशा नहीं है। अगर दिशा मिलती तो विभाग काम करता।

माननीय शीशराम जी ने कई बातें कही हैं। मैं उन बातों से सहमत हूं, वे प्रशासनिक लेप्स थे। टंकी बन गई, टंकी बनी हुई पड़ी है लेकिन पाइप लाइन को जोड़ने के लिए पैसा नहीं है इसी कारण से टंकियां खड़ी नहीं हो सकी। पाइप लाइन डाली गयी जो राइजिंग मेन के पाइप नहीं है जिनके कारण पड़ी रही। वो काम होता तो बिजली का बिल एक लाख रुपये का आ गया और विभाग के पास काम करने के लिए है तो और किसी कारण से पड़ा रह गया। ये सारे काम जो पड़े हुए हैं वे इफेक्टिव प्रशासनिक कंट्रोल नहीं होने के कारण आज तक नहीं हुए। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि माननीय भंवरलाल जी शर्मा जो हमारे वरिष्ठतम मंत्री हैं, इस विभाग के मंत्री हैं, माननीय शीशराम जी मैं आपको कहना चाहूंगा, माननीय हरिदेव जी जोशी जब इधर बैठते थे तो उन्होंने भंवरलाल जी के लिए कहा था कि यह बी. जे. पी. में सर्वोत्तम आदमी हैं। शीशरामजी आप जोशीजी की बात तो मानेंगे ही।

श्री रामपाल उपाध्याय : आपसे श्रेष्ठ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे से भी श्रेष्ठ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप अपने आपको सुधार लें। सर्वोत्तम नहीं कहा था। यह कहा था कि एक मात्र भले आदमी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारे सदन में एक मात्र भले आदमी ये हैं। मुझे तो इनका आशीर्वाद जन्मा जब से प्राप्त है इसलिए आप चिन्ता न करें। वो कह भी नहीं रहा हूं और वह मेरी आदत भी नहीं है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा इस विभाग का सौभाग्य है कि इस विभाग में जो-जो सेक्रेटरी आये उनको भी आप सब जानते हैं। सबसे बड़े आदमियों में गिने जाते हैं, पी. एन. भण्डारी आये और मैं कहना चाहूंगा....

श्री शीशराम ओला : मैंने कह दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं। पी. एन. भण्डारी और उनका दुर्भाग्य है कि वे जिस विभाग में जाते हैं उसके थोड़े दिनों बाद दूसरे विभाग में चले जाते हैं।

श्री शीशराम ओला : यह आपका काम है, हमारा नहीं है। हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छे अधिकारी आये हैं, सक्षम हैं, आप इनको इस विभाग में रखिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे में से सर्वोत्तम आदमी भंवरलालजी इस विभाग को संभाले हुए हैं और प्रशासनिक सेवाओं में भी बहुत बढ़िया आदमी पी. एन. भंडारी इसमें आये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब भंवरलालजी हैं तो अब यह उनका दुर्भाग्य नहीं रहेगा कि उनको किसी दूसरी जगह जाना पड़े। क्योंकि उनका यह हिसाब रहा है कि बिजली में आये तो बिजली से फिर वह चले गये दूसरी जगह....(व्यवधान) आप सुनते जाओ थोड़ा। वहां से गये जे. डी. ए. में, वहां थोड़ी कार्यवाही तोड़फोड़ की शुरू की और रास्ते चौड़े करने लग गये तो वहां से चले गये।

श्री रामपाल उपाध्याय : आप किस भाषा में बोल रहे हैं ? आदमी के लिए बोल रहे हैं या किस तरह बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब यह आप समझिये, आप तो उपाध्याय हैं, मैंने तो प्रवेशिका ही पास नहीं करी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने जे. डी. ए. में ही नहीं रहने दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जे. डी. ए. में तो आपने हटाया था और वह जे. डी. ए. से आये रेवेन्यू। रेवेन्यू में उन्होंने कुछ काम किया कि सैटलमेंट को तोड़-ताड़ कर नष्ट किया जाय। फिर कुछ लोगों ने गैंग बनाई कि सैटलमेंट में नहीं रहने चाहिए। तो बढ़िया से बढ़िया जगह भंवरलालजी के पास आकर वह रूक गये।

श्री सभापति : अब यहां क्या तुड़वा रहे हैं आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यहां पाताल तोड़ कुएं खुदवा रहे हैं उनसे ताकि पेयजल की समस्या का समाधान हो जाय।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यहां जो भ्रष्ट तत्व है उन पर यह हाथ डालेंगे और मंत्रीजी टिकने नहीं देंगे, भगा देंगे उनको।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : यह काम तो आपको सौंपा हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह भ्रष्ट तत्वों पर हाथ डालेंगे और इसीलिए जो निर्विकार और निर्लिप्त आदमी हैं उनके पास लगाया है उनको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब इस विभाग में काम करें वह, नहीं तो इसके लिए एक नाम हो जायेगा जैसे आजकल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी टी. एन. शेषन का नाम पोपुलर हो गया है, उसी प्रकार राजस्थान में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनमें....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मरवाओगे क्या।

श्री शीशराम ओला : नाम तो हो चुका है जब सीकर कलक्टर थे। घनश्यामजी, आपको याद नहीं। तो फेमिन कोड में प्रथम बार तबादला करवाकर उन्होंने कुएं खुदवा कर दिये किसानों के लिए झुंझुनूं और सीकर में, आपके जयपुर में आज भी इनका नाम है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह शेषन का नाम एक प्रशंसा के रूप में ले रहा हूं। लेकिन मुझे याद है उनका वह काम। मैं चूंकि पी. एच. ई. डी. पर चर्चा कर रहा हूं, सीकर में जो शुरू-शुरू में कलक्टर थे, उस समय मैंने राजनीति शुरू ही की थी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और एक भी पैसा लगाये बिना फेमिन में जो पांच हजार कुएं इन्होंने खुदाये थे वह आज तक का एक रिकार्ड है और इस बात को आप भी जानते हैं....

श्री शीशराम ओला : नाम तो कमा लिया न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाम कमाया। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब यह जोड़ी ऐसी मिली है कि यह जोड़ी अगर इसका समाधान करने की कोशिश करें तो इस समस्या का समाधान होगा। सभापति महोदय, हमारी जो कमी है योजनाओं में, सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारी योजनाएं एक के बाद एक विलम्बित होती जा रही है। उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि जोधपुर की योजना बनाई, 38 करोड़ रुपये की योजना 256 करोड़ तक पहुंच गई लेकिन जोधपुर को अभी तक पानी नहीं पहुंचा। यद्यपि माननीय भंवरलालजी के आने के बाद में....

श्री राजेन्द्रसिंह चौधरी : वह बात आप इधर कह रहे हैं पर अब के तो बजट में मुख्य मंत्रीजी ने उसका उल्लेख तक नहीं किया। जोधपुर लिफ्ट कैनाल का कोई उल्लेख नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने यहां बड़ा उल्लेख किया था। अशोकजी गहलोत, जो आपके प्रिय मित्र हैं, वह यहां पर बनते ही आये और आकर कहा कि मैं मार्च में पहुंचा दूंगा, मार्च भी गया और वह भी गये माधवसिंहजी दीवान आये, आते ही वह भी गये काम भी गये। इन्होंने किया या नहीं किया लेकिन इन्होंने स्टील के पाईप, जैसी आपने मांग की थी, स्टील के पाईप चेंज करा दिये हैं और जोधपुर में इस गर्मियों में निश्चित रूप से पानी पहुंचायेंगे, उल्लेख करना अलग बात है लेकिन पानी पहुंचाने का काम है, वह निश्चित रूप से पहुंचा देंगे। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं....

श्री रतनलाल ताम्बी : भंवरलालजी कह रहे हैं। या आप कह रहे हैं।

श्री नारायण सिंह : उनके बिहाफ पर कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब मैं कह रहा हूं और मेरी सुनिये आप। हां, मैं उनके बिहाफ पर ही कह रहा हूं और मैं एक बात आपको याद दिलाता हूं। आप तो कम से कम यह बात नहीं कहें। गुलाबसिंहजी शक्तावत जानते हैं इस बात को कि मानसी वाकल को ले जाकर आपने शिवचरणजी माथुर से पत्थर रूपवा दिया था, उसका कोई प्रोग्राम नहीं था, उसके लिए पैसा अलाट नहीं हुआ था और मैंने विधान सभा में उठाया था और मानसी वाकल का पत्थर उदयपुर का आज तक लगा हुआ है। यह समझ जाइये। उल्लेख करना और पत्थर लगाना, इससे काम नहीं होता। हम काम करने में विश्वास करते हैं और निश्चित रूप से इन कामों को करके रहेंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता था। सभापति महोदय, इसी प्रकार का विलम्ब उदयपुर का हो रहा है। अभी उदयपुर की बात उठाई गई कि उदयपुर में काम क्यों नहीं हुआ। मैं उस समय सदन का मेम्बर था, उदयपुर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में आपने स्कीम बनाई, इसके लिए मैं, शीशरामजी, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने 11 करोड़ रुपये की पाइप खरीदी, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन आपको पता है....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आज 28 करोड़ कास्ट हो गई है उसकी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, 28 करोड़ कास्ट हो गई लेकिन गुलाबसिंहजी, आपको भी पता है, शीशरामजी, आपको भी पता है जब आप यह काम करने लगे थे तो यहां बैठने वाले जोशीजी ने, गिरिजाजी ने और कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने विरोध कर कर उस काम को वहीं रुका दिया था और इसके कारण आज उन पाइपों की पड़े-पड़े कास्ट बढ़ रही है। पानी के चलने के लिए पाईप की कास्ट नहीं बढ़ी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उस वक्त तो पाइप खरीद ली थी, ग्यारह करोड़ रुपये लगे थे। उसकी कास्ट आज तीस करोड़ हो गई है जनाब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो आप उनको बढ़ायें ही बढ़ायें,चालीस करोड़ कर लो।

एक माननीय सदस्य : आपके ही लोगों की राजनैतिक लड़ाई के कारण ही पड़ी रही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह आपने खरीदी थी उसके लिए तो मैंने आपको धन्यवाद दे ही दिया। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि बड़े-बड़े शहर जो हैं, राजस्थान की जनसंख्या का विभाजन करके देखें, आज सारे गांवों को पेयजल देकर गांवों को मान लें तो गांवों की समस्या का समाधान नहीं होगा। राजस्थान में एक करोड़ चार लाख जनसंख्या शहरों में रहती है, दो करोड़ गांवों में रहती है और एक करोड़ जनसंख्या ढाणियों में रहती है जिनकी संख्या 48 हजार है। उनमें पानी नहीं है और उनका 60 प्रतिशत से अधिक पानी पीने योग्य नहीं है। आज तक हम उन ढाणियों के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके। क्या हम यह भेदभाव कर सकते हैं कि जयपुर की पानी की व्यवस्था करें, उदयपुर के पानी की व्यवस्था करें, सीकर के पानी की व्यवस्था करें लेकिन हम ढाणियों में रहने वाले लोगों के पानी की व्यवस्था न करें। राजस्थान में तीस प्रतिशत जनसंख्या ढाणियों में रहती है और 58 हजार ढाणियों में आज हम पेयजल की व्यवस्था नहीं कर सके, यह भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा। तो सभापति महोदय, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पानी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है और इसके लिए हमको कोई योजना बनानी पड़ेगी और मेरा निवेदन है कि इसके लिए हमको भूगर्भ जल को पूर्णतया छोड़ना होगा। यदि भूगर्भ जल पर आधारित रहे तो यह काम अब नहीं कर पायेंगे और इसके लिए राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी लेकिन भारत सरकार के पास भेजने से काम नहीं होगा। राजस्थान में फ्लो पानी, नदी पानी, बांध के पानी से सिंचाई की योजना बनानी पड़ेगी। इसके लिए इन्टर स्टेट का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मामला हो तो वह भी निपटाना पड़ेगा और राजस्थान में मामला हो तो वह उठाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि अलवर, भरतपुर और इधर का जो हिस्सा है उसको जमुना का पानी हर हालत में लेकर जमुना के पेयजल से गांव-गांव तक पानी पहुंचाने की स्कीम बनाई जाय। उसी प्रकार से सवाई माधोपुर, टोंक और धौलपुर जिले को चम्बल लिफ्ट कैनाल बना कर पानी उससे दिया जाय। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में इन्दिरा गांधी कैनाल से पानी दिया जाय और सीकर, झुन्झुनूं और नागौर जिले में गंगा का जो फ्लड वाटर में हमारा हिस्सा बनता है वह लाकर दिया जाय। माही के पानी से डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पानी दिया जाय। और सारे राजस्थान का एक नक्शा बनाया जाय, एक बड़ी प्लानिंग बनाई जाय। एक योजना बनाई जाय और इसीलिए मैंने पहले मांग की कि राजस्थान में पानी की नीति तय करने के लिए एक पानी आयोग का गठन किया जाना चाहिए और उसके आधार पर काम किया जाय। विभाग के द्वारा यह काम सम्भव नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि कार्पोरेशन बनाना पड़ेगा। आज हम दुविधा में जूझ रहे हैं। आज हमारी क्या स्थिति है। हमारी स्थिति यह है, यह विभाग था, इस विभाग को लोन लेने की आवश्यकता हुई तो लोन विभाग को मिलता नहीं, तो विभाग ने एक बोर्ड बना दिया। अब बोर्ड और विभाग। योजनाएं सेंक्शन करता है बोर्ड और काम करता है विभाग। बोर्ड की मीटिंग होना, फिर इसमें पी. पी. सी. की मीटिंग होना और एस. पी. जी. की मीटिंग होना एवं उसके बाद फाइल नहीं निकलना, यह एक विभाग में वीसियस सर्किल बन गया था और आज बना हुआ है। फिर हम मांग कर रहे हैं कि जयपुर जैसे बड़े शहर के लिए अलग से कार्पोरेशन बनाया जाय। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमको टेन्डेंसी बदलनी पड़ेगी। विभाग बिना कार्मशियल हुए नहीं चल सकता। आपको वाणिज्यिक रूप इस विभाग को देना पड़ेगा और यह कहना कि आज के दिन में नौ रुपये में, दस रुपये में पानी दें और हम पेयजल का पैसा बढ़ाते हुए घबरायें, किसी भी कीमत पर नहीं घबराना चाहिए, पेयजल का पैसा निश्चित रूप से बढ़ाने का प्रावधान करना चाहिए और कम से कम जितना एस्टिब्लिशमैंट पर खर्च आता है, जितना तनख्वाह पर खर्च आता है, जितना संधारण पर खर्च आता है वह पैसा पानी पीने वालों से वसूल किया जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी पानी प्राप्त हो सके, निश्चित रूप से मेरी मान्यता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि फ्लो पानी के बिना हम काम नहीं कर पायेंगे। मैं दो बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि इस विभाग का कोई तो एक हैड आफ दी डिपार्टमेंट होना चाहिए। आज इसमें एक तो हैड आफ दी डिपार्टमेंट है फाइनेंस का जो मेम्बर है वह, एक अरबन का चीफ इन्जीनियर है वह अपने आप में हैड आफ दी डिपार्टमेंट है, एक टेक्नीकल का चीफ इन्जीनियर है वह भी अपने आप में हैड आफ दी डिपार्टमेंट है, एक रूरल का चीफ इन्जीनियर है वह अपने आप में हैड आफ दी डिपार्टमेंट है, एक इन्दिरा गांधी कैनाल का, अभी तो हटा दिया, नहीं तो पहले वह भी अपने आप में हैड

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ग्राफ दी डिपार्टमेंट था। ग्रौर फिर इसमें सैक्रेट्री, जो बोर्ड का मेम्बर है उस हिसाब से वह भी हैड आफ दी डिपार्टमेंट है। किसी से भी आप पूछेंगे कि इस विभाग में हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट कौन हैं, तो मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि या तो ग्राप इन्जीनियर इन चीफ की पोस्ट क्रियेट करें, इन्हीं में से एक कम कर दें, एफ. ई. भी उसके अन्तर्गत रहे, ग्ररबन का भी उसके ग्रन्तर्गत रहे, रूरल का भी उसके ग्रन्तर्गत रहे, जब तक इस प्रकार की बात नहीं कर पायेंगे, विभाग पर इफेक्टिव कन्ट्रोल हमारा नहीं हो पायेगा यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं या तो डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट की तरह चलाये या कारपोरेशन की तरह चलाये। इसमें यूं करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से राज्यों में इसको कारपोरेशन के रूप में बदल दिया, ग्रापको कारपोरेशन पसन्द नहीं है तो पूर्णतया इसको डिपार्टमेंट बना दीजिए और डिपार्टमेंट पसन्द नहीं है तो पूर्णतया कारपोरेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको ग्रधरझूल में मत रखें, ताकि इसकी एफीसिएन्सी कम नहीं हो।

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहूंगा, जिसको कहना मैं आवश्यक समझता हूं, उसके मैं तथ्य नहीं बताऊं, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा। इस विभाग की जांच हुई थी, उस जांच में जन लेखा समिति ने कुछ रिपोर्ट्स दी थी और उस जन लेखा समिति ने कुछ नियम और कानून-कायदे बनाये थे। मुझे दुःख है कहते हुए, मैं क्षमापूर्वक मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी और बी.जे.पी. ने धीरे-धीरे करके, एक-एक जो मांगें हैं, जन लेखा समिति ने दी थी, उनको एक-एक करके खड्डे में डाल रहे हैं। आज वह की वह प्रक्रिया विभाग में ग्रापस आ गयी। इसलिए मैं चाहूंगा कि जन लेखा समिति ने जिस प्रकार की सिफारिश की थी, उन पर सरकार कार्यवाही करे ग्रौर उनको लागू करने की कोशिश करे। दो उदाहरण दूंगा जो मैं देना अपना कर्तव्य समझता हूं। एक तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं निश्चित रूप से एक जांच मंत्री महोदय अपने स्तर पर करें, जो व्यक्ति सुपरवाइजरी नेग्लिजेंसी का दोषी हो, उसको दण्ड दें। मैं सारे फैक्ट्स सदन के सामने नहीं रखूंगा। बीसलपुर परियोजना में तीन कम्पनियों को पाइप लाइन डालने का ठेका दिया गया। मैं कम्पनियों का नाम नहीं लेना चाहता, एक कम्पनी ने ग्रपना काम पूरा कर दिया। एक कम्पनी बीच में ही छोड़कर चली गयी और एक कम्पनी काम कर रही थी। ग्रब जो बीच में छोड़कर चली गयी उसका, किस कम्पनी ने काम पूरा किया था, उस कम्पनी ने कहा कि इस कम्पनी का काम भी मैं उन्हीं रेट्स पर करने को तैयार हूं, जिस रेट पर आज से चार वर्ष पहले उस कम्पनी ने शुरू किया था, लेकिन मेरी यह आफर 31 दिसम्बर तक ही है और उसके बाद उस कम्पनी ने लगातार तीन-चार पत्र लिखे राज्य सरकार को ग्रौर राज्य सरकार को और राज्य सरकार को पत्र लिखकर वह मांग करते रहे, उस रेट पर आप देओ 31 दिसम्बर तक और उस कम्पनी को आदेश नहीं दिया उसके बाद उसी कम्पनी को 6 जनवरी को या 10 जनवरी को लेटर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देकर बुलाया गया और बुलाकर उसी कम्पनी को 24 पर्सेण्ट पर, 30% या 12.5 पर्सेण्ट, मुझे पर्सेण्टेज ध्यान नहीं है क्योंकि मैं कागज इस समय सदन में नहीं रखना चाहता, उसको आर्डर दे दिया गया। तो उस काम में चार करोड़ रुपये अधिक दिये गये। अगर 31 दिसम्बर से पहले फैसला करते तो वही कम्पनी जिसका नाम आई. एस. बी. था, वह काम 6 करोड़ में करने को तैयार थी और वहीं 31 दिसम्बर के बाद, 12 जनवरी को, उसको बुलाकर दे दिया गया, उससे विभाग का चार करोड़ रुपया अधिक लगा। इस पानी-ग्रस्त राजस्थान में इस प्रकार से चार करोड़ रुपये अधिक लगाने के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हो उस व्यक्ति के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए यह मेरी मंत्री महोदय से मांग है। फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जिसने सुपरवाइजरी नेग्लिजेंसी की हो, चाहे वह चीफ इन्जीनियर हो, चाहे टेक्नीकल मेम्बर हो, चाहे वह सैक्रेट्री हो, चाहे बोर्ड हो, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए और दूसरी मैं मांग करता हूं....

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : आपके सुझाव तो बहुत अच्छे हैं, मैं डेफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उधर ध्यान बंट जायेगा सबका।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा यह पीरियड ऐसा है कि देखिए या तो तीन साल हम राज में थे या बीच में राष्ट्रपति शासन था, तो या तो मैं दोषी पाया जाऊंगा या राष्ट्रपति शासन में कोई लोग दोषी होंगे, आप क्यों घबरा रहे हो ?

श्री रामनारायण चौधरी : हम तो इसलिए घबरा रहे हैं, व्यवस्था सारी ठप्प हो जायेगी। आप तो जांच करवाओ। मेरी प्रार्थना है मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आपके मार्फत कि इनको भी जांच में साथ ले लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जो भी आप जांच समिति बनाते हो, मुझे रखते हैं। गुलाब सिंहजी ने मेरे पर कृपा की थी, पी. एच. ई. डी. की जांच समिति बनाई, मुझे बना दिया और भंवरलालजी ने कृपा की है हाउसिंग बोर्ड की जांच समिति बना कर मुझे बनाया। कृपया तीसरी मत बनाइये, दो में परिवार नियोजन कर दीजिये ताकि और कोई बन जाये (व्यवधान).... तो सभापति महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बात खत्म करता हूं, माननीय मंत्री महोदय इन सब बातों पर ध्यान देकर काम करेंगे। मुझे दृढ़ विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में पेयजल की समस्या का निश्चित रूप से निदान करेगी और वहां काम होंगे। अगर हम यह कर देंगे, राजस्थान में पेयजल की समस्या का समाधान कर देंगे तो राजस्थान एक स्वर्णिम युग में जायेगा, औद्योगिक विकास होगा और इस काम को करने के लिए हमारे मंत्रीजी सक्षम है। आज सौभाग्य से उनके सैक्रेट्री और उनके चीफ इन्जीनियर भी आज किसी लांछन में नहीं है, वह सब ठीक प्रकार से काम है, इच्छा शक्ति जागृत करके यह विभाग ठीक ढंग से काम करे तो आने वाली गर्मी को हम सब मिलकर ठीक प्रकार से पेश कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस मांग को पारित किया जाए।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़ ।

श्री शीशराम ओला : टीम को डिस्टर्ब नहीं होने दें, इतना ध्यान रखें आप ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भंवरलालजी शर्मा जब तक मंत्री हैं, तब तक टीम डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि परसरामजी ने कहा था स्टोन फेस और मैं कहता हूं स्टोन फेस का अर्थ है स्थिति प्रज्ञ, जिस पर इधर का असर नहीं, उधर का असर नहीं होता, निश्चित होकर बैठिए, कोई चिन्ता नहीं करें ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : विषय पर बोलने से पहले चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, विषय पर बोलने से पहले चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और न कभी थी । मिली-जुली सरकार रही है । पर्यटन मंत्रीजी वहां बैठी हैं, ज्ञानसिंहजी बैठे हैं, सुजानसिंहजी बैठे हैं । बैठे उधर हैं, लेकिन दूसरे हैं ।

(16.00)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

सभापतिजी, एक सदस्या की कमी जो यह सदन काफी महसूस कर रहा है, उन्होंने जब पेयजल पर अपना भाषण शुरू किया, मैं सुमित्रासिंहजी का जिक्र कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा था कि घी ढोल दे म्हारो तो कुछ न जाए, पानी ढुल जाए तो म्हारो जी बल जाए, मेरे जीव जल जाए....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप जयपुर में आकर अपने घर की भाषा ही भूल गये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापतिजी, कुछ समय पूर्व दो बूंद पानी नामक एक फिल्म निर्मित हुई थी और बहुत ही मार्मिक तरीके से पेयजल की समस्या के बारे में जो विवरण दिया गया गया था, वह राजस्थान की स्थिति में कितना लागू होता है । सभापति महोदय, इस बारे में कोई दो विचार नही हो सकते हैं कि पेयजल का गम्भीर संकट है और मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी भी इस मामले में सीरियस हैं । सदस्यों से इस बारे में, विचार-विमर्श किया है पर आवश्यकता है हमको सडन प्लानिंग की । माननीय मंत्रीजी लोंग टर्म और शोर्ट टर्म मैजर्स आप इनीशिएट करें । ऐसा नहीं हो कि समस्या के निराकरण के लिए एक नी-जर्क रिएक्शन दे । आपकी चिन्ता आपने सदस्यों के बीच डिस्कस की है, आपकी काफी दिलचस्पी है परन्तु यदि आपने बहुत ही प्लेड तरीके से इस मामले को आज टेकल नहीं किया तो राजस्थान की समस्या जो पावर के मामले में होने जा रही है, उससे भी ज्यादा गम्भीर समस्या पेयजल के मामले में होगी । सभापति महोदय, राजस्थान की आवश्यकता है आज टेक्नीकल मिशन की और जिस प्रकार के टेक्निकल मिशन की शुरूआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी उनकी सफलता पूरे देश के अन्दर एक नई स्फूर्ति लाई थी । यह निर्विवाद है कि राजस्थान में अण्डर ग्राउण्ड वाटर का एक्सप्लाइटेशन एक तो जरूरत से ज्यादा हो

Page No.111

(श्री जगदीप धनखड़)

चुका है और एक यह इन्टेन्सिव भी हो चुका है। कहने का अर्थ यह है कि एक जगह अण्डर ग्राउण्ड वाटर का एक्सप्लाइटेशन जरूरत से ज्यादा हो चुका है कि अपने आप में एक भयंकर समस्या प्रस्तुत करता है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह एक लोंग टर्म स्कीम बनायें कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर को रीचार्ज कैसे करें, रीप्लेनीश कैसे करें और इसके लिए वह टेक्निकल मिशन जिसका मैंने हवाला दिया है उसमें इतने एक्सपर्टीज रखें कि पूरे इलाके को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान का इस मामले में एक नक्शा बनाया जाए जिसकी जानकारी जनता के समक्ष भी आ सके।

सभापति महोदय, कुछ वर्ष पूर्व चर्चा करते हुए पेयजल की मांगों पर इस सदन के वरिष्ठ सदस्य चन्दनमल जी बैद ने कहा था कि यदि अण्डर ग्राउण्ड वाटर के ओवर एक्सप्लायटेशन को नहीं रोका गया तो जो रेगिस्तान भूमि के ऊपर है वहीं रेगिस्तान जमीन के नीचे भी हमको मिलेगा। तो मेरा सुझाव है कि और समय इस मामले पर बरबाद किये बिना राजस्थान सरकार को यह लोंग टर्म स्ट्रेटेजी तुरन्त अडाप्ट करनी चाहिए। इसको करने के लिए एक आवश्यक उपाय हो सकता है कि आप सरफेस वाटर को मोबिलाइज करें। सरफेस वाटर के मोबिलाइजेशन और उसके कन्जरवेशन के अनेकों फायदे हैं, कई एडवान्टेज हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एक ओर तो अण्डर ग्राउण्ड वाटर रीचार्ज होगा ही उसके अलावा सरफेस वाटर चाहे छोटे-छोटे तालाब हों, एनीकट के द्वारा करें कैसे भी करें वह खेती के भी काम आयेगा, पावर कन्जम्पशन भी कम होगा, वाटर लेवल ऊपर आने से पेयजल की समस्या भी हल होगी। तो जहां एक ओर आपका विभाग सरफेस वाटर के साधारण मोबिलाइजेशन स्कीम्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, उसको महज एक इरिगेशन का मामला मान रहा है।

मेरा सुझाव है कि पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए आप सरफेस वाटर के साधारण मोबिलाइजेशन और कन्जरवेशन स्कीम्स को बढ़ावा दें और इसलिए मैं आपको खास तौर से किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। एक साल पूर्व करीब अराई इलाके के अन्दर बाढ़ आयी। नौ से ज्यादा तालाब नष्ट हो गये उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। नतीजा पेयजल का गम्भीर संकट। वाटर लेवल नीचे चला गया। इन समस्याओं से उभरने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इरिगेशन से कुछ पैसा, पावर जनरेशन का कुछ पैसा आप इस मोबिलाइजेशन में लगाइये क्योंकि इण्डाइरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, अगर सरफेस वाटर का मोबिलाइजेशन आप करेंगे तो इरिगेशन को मदद करेंगे, बिजली की खपत कम होगी, कुए कम खोदने पड़ेंगे। उसके लिए आप कीजिए।

मान्यवर, सरफेस वाटर का एक जबर्दस्त स्रोत इण्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को समाप्त कीजिए। इण्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन से जो अपना हिस्सा

(श्री जगदीप धनखड़)

है वह अपने को जल्दी मिलेगा। इस सदन में काफी दिलचस्प और गहरी डिबेट इस मामले पर हो चुकी है। मैं आपका समय इस मामले पर नहीं लेना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान सरकार अब एक नये कमिटमेंट के साथ, एक नई स्पिरट के साथ, एक नये डिटरमिनेशन के साथ इण्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिये सोचे क्योंकि पेयजल की समस्या भी इससे जुड़ी हुई है। मेरा सुझाव है मन्त्री जी इसकी आप मोनेटरिंग करवाइये। इसके अन्दर सदन की चाहे एक कमेटी बना दीजिए और हर महीने अगर इण्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की मोनिटरिंग होगी तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेटिक परफोरमेंस एट पीक होगा और राजस्थान का हित सुरक्षित रहेगा।

मान्यवर, ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कुछ समस्याएं ऐसी आपने खड़ी कर दी हैं जो सीधी ग्रामीण साइड को टच करती हैं क्योंकि वह गांव के साथ भेदभाव पूर्ण रवैये को उभरती हैं। माननीय मन्त्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शहरों में जहां आप पेयजल की व्यवस्था करते हैं उसका सोर्स आप गांव में रखते हैं। वह कुएं गांव में होते हैं वहां से पाइप शहर तक जाती है और उस पाइप के आस पास जितने गांव और ढाणी हैं वह लोग देखते रहते हैं कि पानी हमारे सामने से जा रहा है पर हमको दो बूंद पानी भी उस पाइप लाइन से नहीं मिल रहा है जिसका सोर्स हमारे रेवेन्यू गांव है, हमारे पास की ग्रामीण भूमि में है। माननीय मन्त्री जी यह समस्या कभी भी जन आन्दोलन का रूप ले सकती है जगह जगह गांवों में हमने लोगों को यह कहा है कि एक समयावधि के पश्चात भी यदि आपको राहत नहीं मिलती है तो कोई हर्ज नहीं है कि आप इस मामले में जन आन्दोलन करें। मेरा अनुरोध है कि आप राज्य स्तर पर इस मामले में नीतिगत निर्णय लीजिए और जहां भी शहर को पानी दिया जा रहा है, रास्ते में जितने गांव, ढाणियां आते हैं उनको भी उसका लाभ दीजिए।

सभापति जी, कुछ वर्ष पूर्व माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में बड़ी मार्मिक अपील की थी इकानामी इन यूज आफ वाटर। इन्होंने कई सुझाव दिये थे। लगता है उन सुझावों का कोई ज्यादा असर नहीं हो पाया है पर उन सुझावों की सार्थकता के बारे में कोई दो विचार नहीं रख सकता, बड़े अच्छे सुझाव दिये। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मन्त्री जी के ध्यान में है पर मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि साइंटिफिक तरीके से करवाइये आपको सुझावों को और यह भी देखिये कि एरिड जोन और सेमी एरिड जोन में किस प्रकार से स्टोरेज हो, किस प्रकार से कन्जरवेशन हो, किस प्रकार से यूटिलाइजेशन हो। इसमें यदि आप साइन्स का उपयोग करें तो निश्चित रूप से समस्या के निराकरण में कुछ मदद मिलेगी। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पशुधन के बारे में कहा था। मनुष्य और पशु का प्रेम सदा चलता रहा है....

श्री टीकम चन्द कान्त : एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : पशुधन तो मनुष्य की खुराक भी है और मनुष्य बिना पशुधन के जी नहीं सकता है ।

श्री सभापति : मनुष्य से तो अच्छा ही है ।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति जी, चौमूं से आने वाले सदस्य के इस सुझाव का मैं पूरी तरह अनुमोदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर पूरी तरह गौर फरमायेगी ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां पूरे देश में एक नई क्रान्ति आ रही है, विश्व एक छोटा गांव बनकर रह रहा है, हैण्ड पम्पस में जो टेक्नालोजी है वह गांव वालों के लिए बड़ी दुखदायी है । पता नहीं क्यों हैण्ड पम्प शुरू के अन्दर जब इनस्टाल करते हैं तो उनका इन्स्टालेशन प्रोपर नहीं होता है, न तो प्रोपर केपेसिटी का होता है और कुछ समय बाद वह डिस यूज में आ जाते हैं । डेप्थ की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं । सभापति जी, जो चौमूं से आने वाले सदस्य थे उनका कुल आधा मिनट समय लूंगा....

श्री सभापति : आपकी पर्ची आई है उसमें समय लिखा हुआ है ।

श्री जगदीप धनखड़ : हैण्ड पम्पस की दूसरी समस्या, माननीय मन्त्री जी मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि.... हैण्ड पम्प्स लगाने के मामले में आप एक बात को दृष्टिगत रखें कि जो भी ढाणियां हैं वहां चाहे 20-30 घर ही हो उनमें पीने के पानी की भारी समस्या है और उनका यह वाजिब हक है कि कम से कम उनको एक हैण्ड पम्प तो उपलब्ध हो । आप एक नीति बनाइये, नीतिगत निर्णय लीजिये ताकि यह नहीं हो कि उनको कितनी राहत देंगे ? मुझे बड़ा झटका लगा किशनगढ़ एस. डी. एम. ने मुझे कहा कि धनखड़जी आपके इलाके में 9 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये । 6 तो शहर में, तीन गांव में तो मैंने कहा कि कहां लगाये जायें इससे....

श्री टीकम चन्द कान्त : आपके इलाके में 9 हुये हैं यहां तो पूरे बाड़मेर जिले के अन्दर 10 हैण्डपम्प हुये हैं । क्या बात कर रहे हो आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा माननीय मंत्रीजी आपसे अनुरोध है कि हैण्ड पम्प्स के मामले में आप तीन काम निश्चित रूप से कीजिये । पहला, जो भी छोटे गांव हैं, ढाणी है छोटी लोकलटीज हैं, उनको आप यह मत कहिये कि 1981 के सेंसस को देखेंगे । आप वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये उनको हैण्ड पम्प दीजिये । दूसरा, आप हैण्ड पम्प इन्स्टोलेशन के अन्दर एकाउन्टेबिलिटी फिक्स कीजिये । ऐसा नहीं हो कि हैण्ड पम्प आप आज इन्स्टोल कर रहे हैं और एक साल दो साल के अन्दर डेप्थ की समस्या के बाद में डिसयूज में आ जाता है और तीसरा, मान्यवर हैण्डपम्प्स की रिपेयरिंग का मानीटरिंग का ऐसा कोई लोकल सिस्टम निकालिये कि गांव-गांव में लोगों को इसके बारे में एक्सपर्टीज हो जाये । इसको एक लोकल क्राफ्ट के रूप में डवलप कीजिये ताकि लोकल लेवल पर लोग रिपेयर कर लें और जो मिडिल मेन इस मामले के अन्दर, हैण्डपम्प्स डिसयूज में रखते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, गांव वालों को दिक्कत रहती है उनको इलेमिनेट कीजिये । लोकल

(श्री जगदीप धनखड़)

लेवल पर जब इस प्रकार इन्स्टालेशन या रिपेयर की व्यवस्था होगी निश्चित रूप से गांव वालों को राहत मिलेगी। सभापतिजी, मेरी बात को समाप्त करते हुये सिर्फ एक बात कहूंगा वह है खारे पानी और फ्लोराइड का, जो हमें विवरण दिया गया है। हजारों गांव इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त है। इस प्रकार की समस्या के निराकरण के लिये माननीय मंत्रीजी विश्व की अनेक संस्थायें हैं जो आपको धन देने के लिये तत्पर है। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। अन्य प्रान्त आपसे कहीं आगे है उनका धन लेने में। मेहरबानी करके आप उनसे धन प्राप्त करके उन लोगों को इस भीषण संकट से बचाइये। मुझे अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : अभी 60 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हमने कटौती प्रस्ताव दिये थे कोशिश इस बात की थी कि सबसे पहले कटौती प्रस्ताव पहुंचे और हमारा जो कटौती प्रस्ताव है वह इस बहस का आधार है। जो लोग फ्रीलान्स बोलते हैं। कटौती प्रस्ताव उनके होते नहीं। ऐसी ऐसी बातें उठाते हैं जिनका मंत्री महोदय जवाब नहीं दे सकेंगे और कायदा यह है कि मंत्री जवाब उसी का देंगे जिस पर कटौती प्रस्ताव होगा और यहां भीषण नीतिगत लग रहे थे। नीतिगत दो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हमने पाइन्टेडली कट मोशन्स दिये हैं। हम उनके जवाब चाहते हैं। सबसे पहले देने की चेष्टा की थी। अब अता-पता ही नहीं है कि नम्बर आयेगा कि नहीं आयेगा। चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर कटमोशन्स का कोई महत्व नहीं है तो यह जो आपकी किताब है इसको आप हटा दीजिये। आपने व्यवस्था कर दी ठीक है। चीफ व्हीप लोग दें वही ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन सामन्जस्य होना चाहिये जिन लोगों ने मेहनत की है, कटमोशन्स दिये हैं, रात-रात खतम किये है। लिखे हैं उनको तो कोई मतलब नहीं रहा। आप टोटली इग्नोर कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जब मैं आसन पर नहीं था, उधर था तो यह प्रश्न उठाया था। माननीय पूनमचन्द जी अध्यक्ष थे उस समय से सदन में व्यवस्था चल रही है कि कटौती प्रस्ताव सीधे प्रस्तुत किये हुये माने जाये। जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं या जिन्होंने ना दिये हैं आपकी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं वह सूची बना कर देते हैं। उसको आसन पुकारेगा और सारे कटौती प्रस्ताव का लिखित में राज्य सरकार जवाब देगी। इसलिये यह मुद्दा बहुत बरसों पहले निर्णित हो चुका है आसन की कई व्यवस्थायें आ चुकी है इसलिये इस व्यवस्था को भी बदलना भी होगा तो आप माननीय अध्यक्ष महोदय जब आयें तो उनके सामने व्यवस्था का प्रश्न उठायें और वह इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें तो कर सकते हैं। मैं तो जिस प्रकार की व्यवस्था है उस प्रकार से माननीय सदस्यों को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री उगमराज मेहता। ....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी जो किताब है उनमें कटौती प्रस्तावों का जिक्र है यह आपके नियमों से अलग नहीं है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

नियमों में यह नहीं लिखा हुआ है कि चीफ व्हीप देगा।

श्री सभापति : आप कृपया अपने सचेतकजी को कहिये कि वह कटौती प्रस्तावों के साथ आपका नाम रखें....(व्यवधान).... वही प्रश्न फिर आ जायेगा, फिर पाइन्ट आफ आर्डर उठायेंगे।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय सभापति महोदय, समय की जो सीमा है। जब सदन समाप्ति की ओर होता है तब समय की सीमा को सख्ती से लागू करते हैं नहीं तो समय की सीमा का कोई मतलब नहीं है कोई कितनी देर बोल लेता है कोई कितनी देर बोल लेता है।

श्री सभापति : पार्टियों से जो पहले वक्ता होते हैं वह पार्टी की नीतियों के बारे में बोलते हैं ऐसी व्यवस्था है। बाकी समय देखते हैं जैसा होता है। फिर आसन यह देखेगा कि कैसे फैक्ट्स आयेंगे जो नहीं आये हैं तो उनको ज्यादा समय मिल जायेगा।

श्रीमती कमला : यह तो आपने कह दिया है कि उनको आया हुआ मान लिया और जवाब भी देंगे। पर उनको प्रायोरिटी में बोलने की व्यवस्था आप कायम करें यह कानून में कहीं बाधा नहीं है।

श्री सभापति : कानून में तो बाधा नहीं है लेकिन आप अपने सचेतक को कहें कि उनको प्रायोरिटी से उस लिस्ट में दिया जाय।

श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, घनश्यामजी तिवाड़ी ने बीसलपुर की पाइप लाइन के घोटाले के बारे में जिक्र किया था मैं उसी से चालू करना चाहता हूं। मंत्री महोदय की अध्यक्षता में बीसलपुर में एक मीटिंग हुई उसमें सारे अजमेर जिले के माननीय सदस्य थे। सारे अधिकारी थे। उसमें भी यह चर्चा चली थी। मैं विस्तार से कहना नहीं चाहता क्योंकि कारण यह है कि एक सदस्य घनश्यामजी तिवाड़ी ने यह बात रख दी है। मैं आगे कहना चाहता हूं कि जिस समय यह बात उठी उस समय बीसलपुर में पाइप लाइन बिछाने का काम अधूरा रह गया था और 110 पाइप बिछाने थे। साढे ग्यारह कि.मी. पाइप लाइन बिछानी थी उसमें भी लिखा है कि साढे ग्यारह कि.मी. पाइप लाइन बिछानी है परन्तु मैंने मालूम किया है कि साढे ग्यारह कि.मी. पाइप लाइन नहीं बिछानी है। तीन कि.मी. साढे तीन कि.मी. अभी भी पाइप लाइन बिछानी अधूरी है। अजमेर के लिये और ब्यावर के लिये जो पानी आ रहा है उसके लिये मैं बात करना चाहता हूं। मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस काम को युद्ध स्तर पर लें। आपने यह वायदा किया था कि ब्यावर, अजमेर, नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी इनको पानी इसी अप्रेल में बीसलपुर से दिया जायेगा। अब तो आपका कोई है ही नहीं। आपके सामने शासन सचिव माननीय भण्डारी साहब बिराजे हुये हैं और उनके हाथ में है यह काम। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस काम को युद्ध स्तर पर लिया जाये। ब्यावर में आज स्थिति यह है कि 5-5 दिन में पानी मिल रहा है। बीच में स्थिति सुधर गई थी 72 घंटे हो गया था। अब चार या पांच दिन से लगातार मांग आ रही है कि

(श्री उगमराज मेहता)

120 घंटे में पानी मिल रहा है और ज्योंहि ब्यावर में जायेंगे। तीन दिन के अन्दर दो दिन छुट्टी में हमें रहने का मौका मिला वापस 72 घण्टे हो जायेगा और वापस जयपुर आयेंगे फिर 120 घण्टा हो जायेगा। इस स्थिति को सुधारिये। नसीराबाद में जो पानी मिलना चाहिये उसको पानी दिलवाइये। अजमेर की स्थिति ऐसी हो गई है कि पिछले दिनों 48 घंटों में पानी मिल रहा था वहां भी 90–96 घंटे में पानी हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपने इसमें लिखा है कि आने वाले बीसलपुर से 140 लाख लीटर प्रतिदिन किशनगढ़ को और 160 लाख लीटर प्रति दिन ब्यावर को पानी दिया जायेगा। 160 लाख लीटर पानी सिर्फ ब्यावर को मिले। इससे होगा क्या 140 लाख लीटर प्रति दिन पानी हमने सप्लाई किया है। मतलब 30 लाख गैलन। जुलाई में वह भी। उससे होगा क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, हाई कोर्ट का फैसला हुआ है। जिस दिन बीसलपुर का ब्यावर में पानी मिलेगा, हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार श्री सीमेंट को भी पानी देना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस आंकड़े को जो 160 लाख लीटर प्रति दिन है इसको बढ़ा कर करीबन 360 लाख लीटर प्रति दिन पानी ब्यावर को दिया जाना चाहिए जुलाई से, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको दुगुना कर दीजिए और ब्यावर के लिए जो पाइप लाइन बिछनी है उसके पांच करोड़ रुपये दिये हैं इसके लिए 15 करोड़ रुपये अतिशीघ्र स्वीकृति किए जाएं ताकि वहां से पाइप लाइन बिछानी चालू हो जाए और बिठूर में जो हमारा सब-स्टेशन बन गया है और 88 लाख रुपये पी. एच. ई. डी. ने आर. एस. ई. बी. विभाग में जमा करा दिए हैं और लामाना की लाइन अभी तक पूरी नहीं हुई है, मैं पी. एच. ई. डी. मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आर. एस. ई. बी. विभाग को कहिये कि कार्य युद्ध स्तर पर करें। आपको भलीभांति मालूम होगा कि पेयजल के मामले में मथाणिया से जोधपुर जब पाइप लाइन डाली गयी थी तो युद्ध स्तर पर पाइप लाइन डाली गयी थी और जोधपुर में कितने ही गांवों में पानी पहुंच गया था। उसी प्रकार से अभी नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्रीजी बहुत सीनियर हैं और वह अभी यह जवाब देंगे कि पानी या तो ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, ग्राउण्ड वाटर से, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं सही बात है कि इन्द्र भगवान की हमारे पर मेहरबानी होगी तो हमको हमेशा पानी मिलेगा और इस बार आपको पानी मिलेगा इन्द्र भगवान भी देंगे क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज है। जब भी भारतीय जनता पार्टी का राज आया है तो कभी अकाल नहीं पड़ा है। यह कांग्रेस का राज आता है तो अकाल पड़ने चालू हुए और पानी की समस्या भी उनके कारण से हुई है। अब आने वाले समय में अकाल नहीं पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जवाजा पंचायत समिति के अन्दर 25 पंचायतें हैं मेरी, वहां पर पूरा फ्लोराइड युक्त पानी है, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि लोटियाणा, सूरजपुरा और खेड़ा कलां जिसको बड़ा खेड़ा

(श्री उगम राज मेहता)

कहते हैं यह बहुत ऊंचाई पर हैं और आस-पास भी पंचायतें हैं, मैंने ट्यूबवैल के लिए मांग की थी और यह भी मुझे मालूम हुआ है कि इन तीन पाइण्ट के लिए पैसे भी उनको जमा करा दिए गए हैं और अभी तक मशीन नहीं पहुंची है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह तीनों पाइण्ट जल्दी से खुदाए जाएं और वहां पर ट्यूबवैल अतिशीघ्र खोदे जाएं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भोमाला सागर जो भोमाला बांध है उसमें आज भी 38 फीट पानी है उसकी क्षमता 40 फीट की है, यह सिंचाई का नहीं है, 20 फीट इसकी ऊंचाई बढ़ा दीजिए और तत्काल पाइप लाइन से पानी आप ले जाएं तारागढ़ की तरफ, दो या तीन कुएं खोद दीजिए चौड़ी मात्रा में और वहां से पाइप लाइन द्वारा पानी गांवों को दीजिए। सारे गांवों को मीठा पानी मिलेगा और आपकी वाह-वाही होगी कि इस भारतीय जनता पार्टी के राज में हमें मीठा पानी पीने के लिए मिला है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र से इस विधान सभा में आया है....

श्री सभापति : दूसरी बार आया है, माननीय सदस्य।

श्री उगम राज मेहता : पहले जनता पार्टी के राज में आया था भारतीय जनता पार्टी का पहली बार एक प्रतिनिधि चुन कर इस क्षेत्र से आया है....

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री उगम राज मेहता : तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी ओर ध्यान दें। हमारे चीफ इन्जीनियर भी हमारे उधर के ही हैं और पी. एन. भण्डारी साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप स्पेशली ब्यावर का ध्यान रखें।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें, माननीय सदस्य।

श्री उगम राज मेहता : एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि शहर के अन्दर पाइप लाइन जो बिछी हुई है वह 40 साल पुरानी है। आज मोहल्लों में प्रेशर नहीं हो रहा है, यह बात तो है कि सारे कम्प्यूटराइजेशन हो गया और जहां भी पाइप लाइन चैन्ज करानी है वहां चैन्ज कराई जाए। मोती नगर, गणपति नगर, नरसिंहपुरा, फतेहपुरा, सेदरिया, रोडाजी का बाड़िया, सावड़ी, फाटक के बाहर आदि यह कॉलोनी है इसमें पानी की कमी है पानी की लाइन नहीं है वहां नयी पानी की लाइन बिछाई जाए और वहां रहने वाले निवासियों को पानी दिया जाए।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री उगम राज मेहता : एक सैकिण्ड। मैं एक मांग करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि ग्रामीण क्षेत्रों में....

श्री सभापति : कृपया शांत रहे।

श्री उगम राज मेहता : ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए बीस-बीस हैण्ड पम्प की मांग करना चाहता हूं। बीस शहर के लिए और पचास हैण्ड पम्प ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी तत्काल हमें दिलाए जाएं,

(श्री उगम राज मेहता)

उसकी स्वीकृति दिलाई जाये ताकि कार्य चालू हो जाये। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति : श्री रिछपाल मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, मनुष्य के जीवन के लिए हवा के बाद जरूरी चीज है तो वह है स्वस्थ पेयजल। यों तो राजस्थान के अधिकांश जिलों में पेयजल की भयंकर समस्या है। मैं नागौर जिले से आता हूं और पूरे नागौर जिले में फ्लोराइड-युक्त पानी है, नागौर, डीडवाना, मेड़ता, डेगाना, मूंडवा, जायल, परबतसर, पूरे जिले में फ्लोराइड-युक्त पानी है। सभापति महोदय, आप कभी नागौर आओगे या मंत्रीजी कभी पधारेंगे तो जिस पानी को पीने से मनुष्यों की हालत खराब हुई है उसका नमूना आपको पेश करेंगे....

श्री सभापति : वह तो विधान सभा में बोल ही रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कुबड़े हो जाते हैं मनुष्य, उस पानी को पीने से दांत पीले हो जाते हैं, लोगों के घुटने दुखने लग जाते हैं और बीस साल पहले वह बूढ़े हो जाते हैं। हां, बीस साल पहले....

श्री सभापति : आपको देखकर ऐसा नहीं लगता, रिछपालजी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, मैं तो वह पानी पीता ही नहीं हूं।....(व्यवधान).... नागौर जिले में पेयजल का गम्भीर संकट बना हुआ है अगर उस जिले को उबारना है तो सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर का पानी नागौर जिले में पहुंचाया जाए और उस जिले की जनता को इस भयंकर संकट से उबारा जाए। अब मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना की ओर ले जाना चाहता हूं, डेगाना में 218 गांवों में से करीब 70 गांवों में पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है, अकाल भी पड़ा हुआ है, अकाल की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सभापति महोदय, कल सदन में अकाल पर चर्चा हुई थी और मैं चला गया था उसमें मेरा भी नाम था, तो 218 गांवों में से 193 गांव मेरे क्षेत्र के अभावग्रस्त घोषित हुए हैं। 194 गांवों में अकाल के कार्य खुले हुए हैं लेकिन वह नहीं के बराबर हैं और उसी से सम्बन्धित यह पेयजल समस्या है। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की तरफ दिलाना चाहूंगा कि पिछली विधान सभा में भी माननीय मंत्रीजी ने वहां के विधायक और वहां के अधिकारियों के साथ में यहां पर विधान सभा में मीटिंग की थी, अब भी की परन्तु उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं निकला।

श्री सभापति : कृपया बोलें।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीब 70 गांव जो इस पेयजल की समस्या से ग्रसित हैं इसमें प्रमुख गांव राजोत, गोठड़ा जिसका, माननीय मंत्रीजी मेरे को आपके विभाग ने जवाब दिया कि गोठड़ा गांव पारम्परिक योजनाओं द्वारा लाभान्वित है। आज तक किसी योजना से

(श्री रिछपाल सिंह)

जुड़ा हुआ नहीं है यह गांव। यह जवाब मिलता है हमको विधान सभा में। आज आप जाकर वहां दिखवा लो अगर यह गाव किसी योजना से जुड़ा हुआ हो तो मैं सदन की समस्या से त्याग पत्र दे सकता हूं। यह जवाब मिला है कि गोठड़ा गांव पारस्परिक स्रोत से लाभान्वित है। यह गांव कोई योजना से जुड़ा हुआ नहीं है। आज इस गांव में न तो कोई पीने का पानी है और कहीं से पानी लाते हैं तो बाहर के कुओं से पानी लाते हैं तो बाहर के कुओं से लेकर आते हैं, पानी पीते हैं लोग। विधान सभा क्षेत्र के गांव राजोद, बिचपुड़ी, बिखरनियां खुर्द, धोलियास, बेड़ास कलां, किलां, लाखीणा, किरोदा, आच्छोजाई, खूड़ी खुर्द, पंडवाला, पंचरंडा खुर्द, सूरजगढ़, इनमें पानी की भयंकर समस्या है। मेरे से पूर्व जो भी माननीय सदस्य बोले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अण्डर ग्राउण्ड जल का जिस मात्रा में दोहन अभी हो रहा है, इसी तरह होता रहा तो आगे आने वाले 5-10 वर्षों में सरकार के पास भी इसका कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस बारे में सरकार को नीति तय करनी पड़ेगी और नीति के अनुसार चलना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी का टी.एस.एस. की जो योजनायें हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। टी.एस.एस. की योजनायें पहले पंचायतें चलाती थी, सरपंच थे जब तक तो उनकी मोटर भी रिपेयर हो जाती थी, सामान भी दिलवा देते थे। अब ग्रामसेवक हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कीम्स हैं नागौर जिले में, तो न तो वे पैसा देते हैं, न मोटर रिपेयर होती है, न उनको कोई खर्चा देते हैं। यह हाल है आपकी टी.एस.एस. योजना का।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें क्या सुझाव हैं आपके?

श्री रिछपाल सिंह : सुझाव तो यह है साहब, अभी ग्रामसेवकों को पैसा देते नहीं हैं। चलाये कौन उन योजनाओं को?

श्री रामनारायण चौधरी : पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट वाले खुद जायं। चीफ इंजीनियर साहब को आदेश दीजिए।

श्री रिछपाल सिंह : अभी माननीय सेक्रेटरी साहब वहां आये थे नागौर।

श्री रामनारायण चौधरी : भण्डारी साहब को आदेश दीजिए कि सरकारी खर्चों पर सब ठीक हों। ग्रामसेवकों से काम नहीं चलेगा, वहां मर जायेंगे लोग प्यासे।

श्री रिछपाल सिंह : कहां गांव में पैसे हैं लोगों के पास? खुजली मिटाने के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास। उस पानी से खुजली हो रही है। उनके पास खुजली की दवा के पैसे नहीं हैं तो वे मोटर रिपेयर कैसे करायेंगे और क्या चलायेंगे कुए? तो माननीय मंत्री जी अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दें कि टी.एस.एस. योजनायें सुचारू रूप से चल सकें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री रिछपाल सिंह : यह तो मेरा सहयोग दे रहे हैं साहब, माननीय सदस्य। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान

(श्री रिछपाल सिंह)

सभा क्षेत्र की सिचाई विभाग से सम्बन्धित बात इसलिए बता रहा हूं कि उससे पेयजल को सहारा मिलेगा। सहारा इस तरह मिलेगा कि कई बांध हैं छोटे-मोटे मेरे क्षेत्र में, जिनकी पालें ऊंची कर दी जायं, उन बांधों को ठीक करवा दिया जाय। उनके नाम भी मैं यहां ले लूंगा। पंचायत समिति रियां में भैरूण्डा का बांध, असोर का बांध....

श्री सभापति : सिचाई विभाग वाले उसका नहीं करा सकेंगे।

श्री रिछपाल सिंह : क्या साहब।

श्री सभापति : यह नहीं करा सकेंगे सिचाई विभाग वाले।

श्री रिछपाल सिंह : कुओं के पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा उससे शम्भूदयाल जी।

श्री सभापति। परन्तु यह इनके बस की बात नहीं है रिछपाल जी।

श्री रिछपाल सिंह : हम हमारी बात कह तो दें यहां पर।

श्री रामनारायण चौधरी : आप अपनी जबान को क्यों खोवो इनके सामने, ये कुछ नहीं करेंगे।

श्री रिछपाल सिंह : ठीक है साहब।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री रिछपाल सिंह : अच्छा, माननीय सभापति महोदय, एक विशेष बात और बताना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को आप-के माध्यम से कि जितने भी गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्र आपके लगाये हुए थे, पूर्णतया फैल हैं। मेरे क्षेत्र में भी ऐसे चार गांव थे उदियास, देणास, डूंगरावास, चार गांव थे जिनमें सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हुए थे और वह पूर्णतया फैल हैं। वहां भी पीने के पानी की व्यवस्था करवा दी जाय और मेरा तो सभापति महोदय के माध्यम से आपसे निवेदन है कि एक दफे आप नागौर पधारें तो हम आपको वहां पूरे जिले की स्थिति से अवगत करा देंगे। आपने मुझे समय, दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल वर्मा।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में पेयजल के बारे में चर्चा हो रही है इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से डग विधान सभा क्षेत्र की जो पेयजल की समस्या उपलब्ध है, विद्यमान है, उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या बड़ी गम्भीर रूप से उपलब्ध हैं। गर्मी के समय में गांवों में रहने वाले लोगों को एक-एक, दो-दो किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता है, कुओं में जो पानी का स्तर है वह काफी नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि वह आगामी आने वाले समय में तत्काल ही कोई ऐसा ठोस उपाय करें जिससे कि इस गम्भीर समस्या से निपटा जा सके।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में भवानीमण्डी कस्बे के बारे में बताना चाहूंगा। भवानीमण्डी कस्बे की आबादी

(श्री बाबूलाल वर्मा)

लगभग 40–50 हजार है। गर्मी से पीने का पानी उनको बराबर मिलता नहीं है। अभी जनवरी, फरवरी में जब मैं क्षेत्र में गया था तो पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट पूरे भवानीमण्डी कस्बे में मात्र 15–20 मिनट में सप्लाई देकर अपनी सप्लाई बन्द कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि कई जगह तो पीने का पानी नलों में पहुंचता भी नहीं था। लोग-बाग रात को सोते हैं तो सवेरे यह उम्मीद करते हैं कि सवेरे पानी आयेगा लेकिन जब सवेरे 15–20 मिनट की मात्र सप्लाई होने के बाद में उनके नलों में पानी नहीं पहुंचता तो उनको वैकल्पिक रूप से क्या व्यवस्था करनी पड़ती है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इसके बारे में मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा। भवानी मण्डी में दूसरी कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं जहां से पानी उपलब्ध किया जा सके। साल भर पहले हुड़को की एक साढ़े 3 करोड़ की योजना भवानीमण्डी कस्बे के लिए सागड़िया देह से स्वीकृत हुई थी। उस योजना को स्वीकृत हुए लगभग सालभर से ज्यादा हो गया लेकिन उस योजना का कार्य अभी तक भी डिपार्टमेंट द्वारा शुरू नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि पीने के पानी की इतनी गम्भीर समस्या बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस योजना का कार्य शीघ्र चालू किया जाय जिससे कि एक परमानेंट, स्थायी रूप से पीने के पानी का समाधान किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। मैं आज आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी दो-दो, तीन-तीन हजार से ज्यादा है और उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ गांवों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कुराडियाजोगा, करावन, आवर, दुवालिया, रोजानाग्वालत, कूंडला। यह ऐसे बड़े-बड़े गांव हैं जिनकी आबादी लगभग दो-तीन हजार से ज्यादा है और वहां अभी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इतने बड़े गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होना, हैण्ड पम्प वहां सक्सेज नहीं हैं। जिन गांवों में हैण्ड पम्प हैं सक्सेस है, सफल है, उस जगह वह खराब पड़े हुए हैं। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इतने बड़े गांवों में जिनकी आबादी दो-तीन हजार से ज्यादा है, उन गांवों में पीने का पानी, पेयजल योजना बना कर जल्दी से जल्दी गांवों में रहने वाले नागरिकों को पहुंचाया जाए। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से एक बात और माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि डग विधान सभा क्षेत्र की, जो गांव की स्थिति है, उसकी भौगोलिक स्थिति, बड़ी विषम स्थिति है। कुछ गांव पहाड़ियों पर बसे हुए हैं पथरीले स्थानों पर गांव हैं, जहां पीने का पानी किसी भी रूप में उनको उपलब्ध होता नहीं है। एक एक, दो-दो किलोमीटर से उनके जो टेम्प्रेरी सोर्स हैं, गड्ढे हैं, साफ पानी वहां से उनको लाना पड़ता है। परिणामस्वरूप कितनी तरह की उनको मुसीबत भुगतनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में ऐसे गांवों के बारे में, जिन गांवों में पीने का पानी न हैण्डपम्प से, न कुएं से उपलब्ध हो सकता है तो इन गांवों के बारे में मैं आपके माध्यम से यह

(श्री बाबूलाल वर्मा)

सुझाव देना चाहूंगा कि इन गांवों के पास आधा किलोमीटर दूर या एक किलोमीटर की दूरी पर ऐसे गहरे स्रोत विद्यमान हैं, जहां से इन गांवों की सप्लाई की जा सकती है। मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि ऐसे स्रोतों से उन गांवों को पीने के पानी की सप्लाई की जाए जिससे कि उनको पीने का पानी पूरा मिल सके। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले में इस तरह की कोई स्थायी रूप से पेयजल की योजना बनायी नहीं गयी है। परिणाम-स्वरूप पूरा झालावाड़ जिला पेयजल से वंचित रहा है। कई तरह की योजनायें बनाने के लिए कहा जाता है। जब विभाग मे जाकर बात करते हैं एक्स. ईएन. से, ए. ईएन. से इस सम्बन्ध में। मैं आपके यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि अभी मैंने डेढ़-दो महीने पहले माननीय राज्य मंत्री महोदय को एक आवेदन दिया था जिसमें लगभग सात-आठ गांवों के बारे में मैंने उनसे निवेदन किया था। जब मैंने उस पत्र के बारे में वहां एक्स. ईएन. साहब से, ए. ईएन. साहब से बात की तो न तो उन पत्रों पर कोई गौर किया न उन्होंने उन गांवों की योजनाएं बनाने के लिए कोई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य मंत्री महोदय को मैंने कहा हुआ है। आठ गांवों के नाम दिए हुए हैं और उन गांवों के बारे में न तो मेरे से अभी तक कोई बात हुई है और यह इनकी नालिज में भी है और इन चीजों को वह ध्यान देकर, नाम मैं नोट करा देता हूं....

श्री रामनारायण चौधरी : ये कुछ नहीं करेंगे।

श्री बाबूलाल वर्मा : नाम नोट कर लें माननीय मंत्री महोदय कुराडियाजोगा, करावन, आवर, दुधालिया, रोजानाग्वालत, कुण्डला। इन सब गांवों के बारे में मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया था। लेकिन उन गांवों के बारे में अभी तक डिपार्टमेण्ट द्वारा ऐसी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। इसके साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि झालावाड़ जिले से कनवाड़ा गांव, मण्डावर गांव और रोजानाग्वालत, इन तीनों गांवों की स्कीम्स आपके यहां डिपार्टमेण्ट को भेजी जा चुकी है। काफी टाइम से इन गांवों की योजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं। इन गांवों की योजनाओं को मंजूरी देकर शीघ्रातिशीघ्र इनकी स्वीकृति दिलवाए। इसके साथ ही मैं झालावाड़ शहर के लिए एक स्कीम रि-ओर्गेनाइज स्कीम लगभग तीन साल से बनी हुई यहां पड़ी हुयी है। और वो स्कीम स्वीकृति हेतु आयी थी लेकिन तीन साल से वो स्कीम अभी तक स्वीकृत होकर वहां पहुंची नहीं।

श्री सभापति : जल्दी करें।

श्री बाबूलाल वर्मा : इस स्कीम के बारे में भी आपके माध्यम से कहूंगा कि इन स्कीमों को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति देकर गांवों के लोगों को लाभान्वित करवाएं इसके साथ ही आपके माध्यम से सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हैण्डपम्प, एक तो डग विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपम्प बहुत कम जगह सक्सेस हैं और जिस जगह सक्सेस हैं तो उस जगह 80–90 प्रतिशत खराब पड़े हुए हैं....

श्री सभापति : संक्षेप में कहें ।

श्री बाबूलाल : खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने के लिए जल्दी से जल्दी कोई ऐसा प्रभावी कदम उठाएं जिससे कि आगामी गर्मी के टाईम में उनको राहत मिल सके । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति : धन्यवाद । देखिये मैं यह कहना चाहता हूं जो सूची माननीय सचेतकों से मुझे प्राप्त हुयी है उनके अलावा मैं बुलाने में असमर्थ रहूंगा । दूसरी, मेरे पास स्लिप आ रही हैं कि मुझे गाड़ी में जाना है, गाड़ी में जाना है माननीय सभी सदस्यों को । अब गाड़ी में सबको जाना ही जाना है तो जिस क्रम से आए हैं उसी क्रम से मैं पुकार पाऊंगा । इसलिए पहले नारायणसिंहजी आप बोलें फिर नरेन्द्रसिंहजी ।

श्री शिवनाथ सिंह : उनको गाड़ी में जाने दें, पहले हम बोल लेते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : चीफ व्हीप ने सूची दे दी आप उसी से बोलेंगे तो हाउस की क्या गरिमा, आपका क्या अधिकार और क्या आपकी शोभा ।

श्री सभापति : मेरी शोभा इसी में है ।

नारायणसिंह जी बोलेंगे । बोलिए ।

श्री नारायण सिंह : वह है उसी परम्परा को निभाएं । सभापति महोदय, मैं मेरे कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करूं इसमें पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर जिला जहां इस साल अकाल....

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सभापति जी, मेरा नाम है लिस्ट में ।

श्री नारायण सिंह : अकाल नहीं है । कहीं आप यह मानकर रहे कि वहां अकाल नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मान्यवर को स्लिप भेजी है ।

श्री सभापति : बिराजिए ।

श्री नारायण सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां सीकर में हालांकि पिछले वर्ष जब रबी की फसल हुई उस समय कुछ बारिश दो-तीन टाइम पर होने के कारण फसल तो हो गयी लेकिन कुओं में पानी चाहे हैण्ड पम्प, चाहे बांध जो भी पानी था उसमें लेश मात्र भी पानी कोई इकट्ठा नहीं हुआ इसके कारण से पीने के पानी की सबसे ज्यादा समस्या हमारे यहां है । मैं समझता हूं कि दूसरे जिलों में भी यह समस्या हो सकती है, होगी लेकिन हमारे यहां भी दूसरे जिलों से कोई कम समस्या नहीं है । हमारे यहां हर साल पानी का जो जल स्तर है वह नीचे जाता जा रहा है ।

श्री सभापति : कान्फ्रेंस नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री नारायण सिंह : वह सिंचाई के कुए हों चाहे पीने का पानी हो, चाहे हैण्ड पम्प हो इनमें पानी की कमी होती जा रही है उसके कारण से एक भयंकर समस्या आपके सामने उत्पन्न होने वाली है । माननीय मंत्री महो-

(श्री नारायण सिंह)

दय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने समय रहते हुए जून और मई के महीने से पहले यदि व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था नहीं की तो हमारे यहां की हालत यह होगी कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, लोगों को पलायन करना पड़ेगा और लोगों को आन्दोलन करना पड़ेगा यहां तक कि आपको इस बात के लिए विवश करना पड़ेगा कि आप पानी की व्यवस्था ठीक तरह से वहां कराएं। इसलिए आप समय रहते हुए यह मान कर नहीं चलें कि सीकर जिला चूंकि अकालग्रस्त जिला नहीं है इसलिए वहां कोई पानी की समस्या नहीं है। पानी की समस्या बहुत भयंकर है। आज भी आपके जो हैण्ड पम्प हैं वह ड्राई हो गये हैं। कुओं के अन्दर आपका जो स्रोत हैं चाहे जी. एल. आर. में जाने का, चाहे आपके पी. एण्ड टी. की स्कीम हो उनमें पानी जाने का, उनके कुओं का पानी सूख गया है, नीचे जाता जा रहा है और उसके कारण भयंकर समस्या उस जिले के अन्दर है। आप व्यवस्था कुओं को गहरा कराने की, हैण्ड पम्प जो आपके हैं उनकी हालत यह है कि आपके 160 मीटर गहरे हैण्ड पम्प हैं इससे नीचे आपका हैण्ड पम्प काम नहीं करता है। यह आपकी जो तकनीक है वह फेल हो गयी है। आज पानी का जल स्तर नीचे जाने के कारण 160 मीटर गहरा उसको बोर करवाते हैं, आपके जो ठेकेदार हैं वह 160 के बजाए 140-135 पर उसको गहरा करता है और इसके कारण जब हैण्ड पम्प इंस्ट्रोल होता है उसके पूर्व महीने दो महीने के बाद में पानी उस हैण्ड पम्प में आता नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से हैण्ड पम्प की 160 मीटर जो गहराई उसके बजाय 200 मीटर की आप करेंगे तब जाकर के आपके हैण्ड पम्प सफल होंगे। हमारे एक जिले के अन्दर पिछले समय में जब शायद आप मंत्री नहीं थे उस समय हजारों की संख्या में हैण्ड पम्प लगे और उन हैण्ड पम्पों के लगने के कारण से हमारे जिले की पानी की जो प्राब्लम थी वह सोल्व हो रही थी। सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमको 12 हैण्ड पम्प दिये। पूरे जिले में 12 हैण्ड पम्प दिये। आज आठ कान्स्टिट्यूएंसी है। आठ में डेढ़ डेढ़, दो दो लेंगे क्या? एक-एक कान्स्टिट्यूएंसी में डेढ़-डेढ़ हैण्ड पम्प आयेगा क्या? तो आप कम से कम मेहरबानी करके 16 हैण्ड पम्प तो देते ताकि 2-2 तो हो जाते। आप कुछ दिन पहले श्रीमाधोपुर पधारे और श्रीमाधोपुर में आपने जिस स्कीम का उद्घाटन किया, लांडवाड़ा के अन्दर पानी की एक स्कीम थी, चाहे छोटा सा वह गांव है परन्तु उसके अन्दर आपने 6 हैण्ड पम्प की घोषणा कर दी जबकि मेरे जिले को सिर्फ आपने 12 हैण्ड पम्प दिये और आपने वहां घोषणा कर दी। शायद घोषणा के लिए ही घोषणा है तब तो हमको कोई एतराज नहीं है लेकिन यदि यह घोषणा नहीं है और सही बात है कि आपने एक गांव को 6 हैण्ड पम्प दिये हैं और सारे जिले को आपने 12 हैण्ड पम्प दिये। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगी? इससे बड़ी नाराजगी प्रकट की है लोगों ने। आपने तो उनको राजी करने के लिए बात कही होगी। इससे लोग बड़े नाराज हुए हैं। इसलिए मेहरबानी करके हैण्ड पम्प 12 एक जिले में जो हैंण्ड पम्प दे रहे हैं, इसको बढ़ाइये।

(श्री नारायण सिंह)

आप कुओं को गहरा करने की व्यवस्था करिये, पैसा अधिक दीजिये। इस तरह यदि आप व्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो मैं तो यह कहता हूं कि आने वाली गर्मियों के समय में बड़ी परेशानी होगी और लोगों के सामने पीने के पानी की परेशानी आने वाली है। मैं इस संबंध में एक-दो बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपका ज्यादा समय नहीं लेकर यह कहना चाहता हूं कि एक तो सभापति महोदय, शायद आपको जानकारी होगी कि जीणमाता के इर्द-गिर्द 5-6 गांव हैं और उनमें खारा पानी है। एक बूंद पानी उनको पीने के लिए नहीं मिल रहा है। आपने अभी रेवास से स्कीम बनायी और अभी एक गाण्डोली से स्कीम बनायी। तो इस स्कीम को बनते-बनते तीन साल तो हो गये और लोग आज इतने दुःखी है पानी के बिना। अब इदुलफितर के बाद में वहां जीणमाता का मेला लगेगा जिसमें लाखों आदमी इकट्ठे होंगे। वहां पानी पीने के लिए....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, उन गांवों की वास्तव में ही बहुत गम्भीर समस्या है जो जीणमाता के आस-पास गांव हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेयजल की मांग स्वीकृत होने तक समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री नारायण सिंह : मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय वह स्कीम बना कर आपके पास भी पी. पी.सी. के अन्दर आ गई है। अगर आयी नहीं है तो शायद आपके चीफ इन्जीनियर के पास हो सकती है। आप मेहरबानी करके उस स्कीम को मन्जूर करवाये जिसके कारण से लोग वहां पर रह सकें। आज लोग पलायन करने की स्थिति में है। जीणमाता एक छोटा सा गांव होते हुए उसके इर्द-गिर्द दूसरे गांव भी हैं उनकी जोइंट स्कीम है और इस मेले के कारण से वहां पर लोगों को बहुत परेशानी होगी। मेहरबानी करके आप यह व्यवस्था करिये।

इसी तरह एक झासोली मेरे क्षेत्र में गांव है। तीन साल पहले आपने ट्यूब वैल बनवाया और दो साल के बाद में आपने ट्यूब वैल से पाइप के द्वारा टंकी से जोड़ा और उसके बीच में जो ट्यूब वैल था उसमें कहते हैं कि किसी तरह के पत्थर डाल दिये जिसके कारण से उसमें बहुत ही खर्चा हो गया, बिजली का कनेक्शन हो गया, लाइन ट्यूब वैल से टंकी तक जुड़ गयी लेकिन आज तक उस गांव को पानी

(श्री नारायणसिंह)

नहीं मिल रहा है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने डिपार्टमेण्ट पर थोड़ी सी नजर रखिये। खाली आपने अभी एक ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा था कि आप भगवान पर भरोसा रखिये बरसात हो जायेगी। उस पर तो सबका भरोसा है, वह तो सब कुछ करने वाला है। यदि आपने उस पर ही, भगवान के भरोसे इस सरकार को छोड़ दिया तो फिर भगवान ही मालिक है इस सरकार का और इस प्रदेश का। इसलिए मेहरबानी करके भगवान के भरोसे मत छोड़िये आपकी सरकार के भरोसे पर रखिये और लोगों को विश्वास दिलायें कि आने वाली गर्मियों के अन्दर पानी की व्यवस्था यह सरकार करायेगी। चाहे किसी भी कीमत पर करना पड़े, सबसे आवश्यक यदि पानी की व्यवस्था सरकार नहीं करायेगी तो मैं समझता हूं सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप बहुत योग्य और होशियार आदमी हैं। सभापति महोदय, क्या क्या किस तरह की उपमाएं दी हैं। तो मैं समझता हूं कि उन उपमाओं के अनुरूप आप काम करें। इतना ही मुझे कहना है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नरपतसिंह राजवी। (अनुपस्थित) श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने राज्य के आर्थिक स्रोत को ध्यान में रखते हुए जितना अधिक से अधिक इस प्रांत को पेयजल की समस्या से निपटने के लिए प्रयास किये हैं। साथ ही साथ उदयपुर की हमारी काफी वर्षों से जयसमंद की योजना इन्तजार में है। सामने प्रतिपक्ष में बैठे माननीय सदस्य उस समय सरकार में थे। इस योजना को राजनैतिक रंग देकर के काफी लम्बा किया। लेकिन माननीय भंवरलालजी शर्मा, पेयजल मंत्रीजी के काल में इस योजना को पूरा करने का श्रेय उनको जाता है। इसलिए मैं उदयपुर का विधायक होने के नाते अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : इसमें थोड़ा गुलाबसिंह जी को भी है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अब मैं साथ ही गुलाबसिंहजी शक्तावत को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर क्षेत्र अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। माननीय सभापति महोदय, मैं पेयजल समस्या पर आना चाहूंगा। राजस्थान सरकार विगत तीन वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की रही है और तब ही मानसून की मेहरबानी रही और अच्छी बरसात होने के कारण उस समय राजस्थान में पेयजल की समस्या नहीं आयी लेकिन इस वर्ष सत्ता सम्भालते ही राजस्थान में अकाल की हालत रही और उसी कारण से पेयजल की समस्या पूरे प्रांत को झेलनी पड़ रही है। राजस्थान का पश्चिमी भाग उदयपुर डिवीजन पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र है। आदिवासी जो बस्तियां हैं या वे बसे हुए हैं वे बिखरे हुए हैं। वहां पर सरकार की एक निश्चित आबादी के अनुपात में जल आपूर्ति की

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

व्यवस्था है वह वहां पर लागू नहीं होती क्योंकि छितरी हुई आबादी होने के कारण वहां पर जो जनसंख्या का आधार बनाया गया है वह वहां लागू नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से अपनी तरफ से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि छितरी हुई आबादी के लिए आपको अलग से योजना बनानी चाहिए। इस सरकार ने 100 की आबादी मानते हुए हैण्ड पम्प का नया आधार बनाया है उसके लिए मैं तो धन्यवाद देता हूं लेकिन उससे अधिक से अधिक गांव जुड़ जाय ताकि वहां का आदिवासी पेयजल की समस्या से जूझ रहा है उसको अधिक से अधिक लाभ मिलें। मैं सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे उदयपुर क्षेत्र में, उदयपुर शहर के लिए, उदयपुर जिले के लिए एक बहुत बड़ी योजना की तैयारी हो रही है और वह है मानसी वाकल। मानसी वाकल योजना को पिछले समय लगभग सरकार बनाने का मानस बना लिया था और हिन्दुस्तान जिंक के साथ समझौता हो गया था लेकिन पता नहीं किस कारण से यह योजना शुरू नहीं हो पायी। जहां तक मुझे ज्ञान है, हो सकता है उसमें सरकार के पास नयी जानकारी हो लेकिन हिन्दुस्तान जिंक यदि एग्री हो गया बनाने को। पानी का 30 पर्सेण्ट सरकार ने इतना कहा था कि हिन्दुस्तान जिंक को देगी। हिन्दुस्तान जिंक इस बांध को बनाये और रेस्ट जो 70 पर्सेण्ट है सरकार उसका उपयोग करेगी लेकिन रायल्टी के बारे में झगड़ रहे हैं....

(17.00)

सरकार चाहती थी कि रायल्टी हिन्दुस्तान जिंक दे और हिन्दुस्तान जिंक का कहना था कि पूरा पैसा हम खर्च करें और बांध बनायें और उस पैसे को रायल्टी में सरकार एडजस्ट कर ले। लेकिन सरकार शायद उसको आय का सोर्स मानकर इस बात पर अड़ी रही और इस कारण से योजना आगे नहीं बढ़ी। मैं सरकार को आग्रह करना चाहूंगा चूंकि पैसा खर्च सरकार को नहीं करना पड़ रहा है, हिन्दुस्तान जिंक खर्च कर रही है और ऐसी परिस्थिति में अगर नया सोर्स हमारी सरकार को मिलता है तो इससे उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्र को लाभ मिलेगा, उदयपुर की जनता को लाभ मिलेगा, ऐसी स्थिति में अगर सरकार उस योजना को मान लेती है, एग्रीमैंट कर लेती है तो मैं समझता हूं आने वाले समय में, उदयपुर जो राजस्थान का कश्मीर है, जिसको ऐतिहासिक नगरी कहते हैं कई विदेशी पर्यटक आते हैं, को पेयजल समस्या से पूरी तरह निराकरण मिलेगा। तो उस योजना को मानकर हिन्दुस्तान जिंक से बनवायेंगे तो हमको एक सोर्स भी मिलेगा और साथ ही साथ पेयजल की समस्या का समाधान होगा। यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब, इस मांग पर बोलें तो इस बात का भी आश्वासन दें, यह मेरा व्यक्तिगत निवेदन है....

श्री सभापति : कोई कटमोशन दिया है क्या आपने ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : नहीं दिया हुआ है, दे दूंगा। जयसमन्द जनजाति क्षेत्र में स्थित है। वास्तव में जनजाति क्षेत्र के काफी लम्बे क्षेत्र में सिंचाई होती है। बीच में एक नयी समस्या या वहां के लोगों की मांग थी कि हमारे सिंचाई के पानी को कम करके उदयपुर को यह पानी दिया जायेगा।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

वैसे जहां तक टैक्निकल बात है या इंजीनियरों से मैंने जानकारी ली कि डैड वाटर उसमें से उदयपुर को भी दिया जायेगा। तो यह अकस्मात् योजना है। अकस्मात् जब जरूरत पड़ेगी उस समय ही यह पानी दिया जायेगा। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उदयपुर के साथ-साथ

(17.02)

(श्री रमाकान्त शर्मा,सभापति, पदासीन।)

जयसमन्द से उदयपुर जो पाइप लाइन लायी गयी है, उसके बीच में जो जनजाति क्षेत्र के जो गांव पड़ते हैं, या जो भी गांव पड़ते हैं उनको भी इस योजना से लाभ मिलना चाहिये, इस पाइप लाइन से जोड़ना चाहिये ताकि जो पाइप लाइन जिन गांवों से आती है वहां के लोगों को भी इस पाइप लाइन का, जयसमन्द के जल का लाभ मिले। यह भी मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा। उदयपुर में सीवरेज पाइप लाइन काफी समय से वहां सरकार ने बिछायी लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह भी प्रारम्भ नहीं हो पायी। मैंने और मेरे साथी माननीय सनाढ्य जी ने विधान सभा में प्रश्न उठाया लेकिन यह योजना ठंडे बस्ते में बंधी रही। पता नहीं किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण से, क्या उसमें टेक्निकल कमियां रहीं और आज भी उदयपुर के लिए सीवरेज योजना एक अभिशाप है और आज भी पाइप लाइन अन्दर दबी हुई है और उस योजना को हम प्रारम्भ नहीं कर पाये। लाखों रुपये उसमें खर्च हुए लेकिन आज तक उदयपुर की जनता को जो लाभ होना चाहिये, वह नहीं हुआ। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस योजना को, इस पाइप लाइन को बिछाने में जिन-जिन अधिकारियों का हाथ था उसकी उच्च स्तरीय अधिकारियों से जांच करायें और इसमें जो भी दोषी पाये जायें, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। यह भी मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा मेरा विधान सभा क्षेत्र अपनी दृष्टि से अलग क्षेत्र है। शहरी भी है, पहाड़ी भी है और कस्बों के रूप में भी है। जब उदयपुर से हवाई अड्डे की तरफ निकलते हैं वह व्यापारिक क्षेत्र है, वहां हिन्दुस्तान जिंक का प्लाण्ट है और कई छोटे-मोटे प्लाण्ट हैं। लेकिन वहां प्रदूषण के कारण जमीन के नीचे का सारा पानी प्रदूषित हो चुका है। उसमें एसिड घुल चुका है। वहां की जनता उस पानी को पी नहीं सकती, पशु भी नहीं पी सकते हैं इतना भयंकर प्रदूषण हो गया है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि बेबारी, सांकरोदा और आस पास के जो गांव हैं वहां सरकार एक अलग से योजना बनाये और पास में जो भोपालसागर बांध है वहां से पानी लाकर वहां के लोगों को, पशुओं को पानी पिलाने की व्यवस्था करे यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा क्योंकि वास्तव में यह समस्या बहुत जटिल है। सुप्रीम कोर्ट तक वहां के लोग गये थे लेकिन वहां के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र है वहां की पेयजल समस्या को निपटाने के लिए अलग से स्पेशल योजना बनायें। उदयपुर के आस पास

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जनजाति क्षेत्र है। 20-25 किलोमीटर के

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

एरिये में रहते हुए भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां का जल स्तर नीचा जाने के कारण हैण्ड पम्प सूखे हुये हैं। सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि अकाल राहत में छोटी छोटी ढाणियों, गांवों में हैण्ड पम्प खुदवाकर इस समय की जल समस्या का निराकरण करे। मानसी वाकल के बारे में मैं अपने सजेशन, एडवाइज देना भूल गया था। इसका पानी गुजरात में जाता है। अगर मानसी वाकल को अगले दो, तीन साल में नहीं बनाया गया तो इस नदी पर गुजरात सरकार कोई योजना बनायेगी और अगर गुजरात सरकार ने कोई योजना बनायी उसके बाद में सरकार कोई योजना बनायेगी तो यह अन्तर्राज्यीय विवाद का नया रूप धारण कर लेगी। इस समय बिना किसी कठिनाई के हम इस बांध को बना सकते हैं। आने वाले समय में अन्तर्राज्यीय विवाद या जल के बंटवारे, के अन्य कई कारण बन सकते हैं। इस समय इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वहां के लोग चाहते हैं कि इस योजना को अतिशीघ्र क्रियान्वित करायें तो सरकार को लाभ मिलेगा, उदयपुर की जनता को लाभ मिलेगा और वहां की जनता को विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र के जो लोग विस्थापित होंगे उनको लाभ होगा जिनको मुआवजा देने वाले हैं उनकी शंका है कि उनको सही मुआवजा नहीं मिलने वाला है, सरकार उनको भी न्यायोचित मुआवजा दे। सही जगह पर उनको बसाये। जो उनको खेती के लायक जमान मिले उसमें उनको पूरी सिंचाई की सुविधा, यह सारी सुविधाएं मुहैय्या करायें, यही मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र है. मैं पुनः आग्रह करता हूं कि इस योजना को प्रारम्भ करे वहां के जो लोग विस्थापित हों, उनको सही जगह पर बसाया जाये, पूरा मुआवजा दिलाया जाये। सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदार शहर) : सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग के कुछ कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। सदन में बहुत अच्छे सुझाव माननीय सदस्यों के द्वारा आये हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन मेरे दिल में यह बात है कि आज हमारे राजस्थान के अन्दर पीने के पानी का भयंकर संकट मंडराया हुआ है। अकाल प्रभावित गांव हैं, तहसील हैं, जिले हैं, या नहीं हैं। दोनों ही स्थिति में आज लोग पीने के पानी के लिये संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान में आजादी के बाद बहुत कोशिश की गयी। बहुत से गांवों को पेयजल योजना से जोड़ा गया। लेकिन मंत्री महोदय, मेरा यह सुझाव है कि आप एक जिले में सर्वे करवा लीजिये। आप यह कहते हैं कि हमने 80, 90 प्रतिशत गांवों को पानी से जोड़ दिया और मेरा यह दावा है कि आपको मुश्किल से दस गांवों में सुनने को मिलेगा कि हमारे गांव में पानी आ रहा है। मेरा दावा है यह। आप राजस्थान के अन्दर चूरू जिले को ले लीजिये। पीने के पानी का सारा का सारा सिस्टम वहां पर कोलैप्स हो गया है और पीने के पानी के स्थान पर लोगों की आंखों में पानी है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। पिछले दिनों आपने एक

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

मीटिंग बुलायी थी। बहुत बड़ा विश्वास हमें आपके ऊपर बना कि आप कुछ एक्शन लेंगे। आप अधिकारियों को ताकत के साथ निर्देश देंगे और आपने दिये भी हैं। हमें बहुत खुशी हुई और आपने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि आने वाली 27 तारीख को मुझे याद है 6 तारीख को मीटिंग थी। 27 तारीख को जब आप दुबारा यहां आयेंगे मीटिंग में या मीटिंग नहीं हुई तो 27 तारीख को आप मुझे रिपोर्ट देंगे कि उन गांवों में क्या हुआ? आप इन बातों को ठीक-ठीक मानेंगे। मैं बताऊंगा। एक-एक गांव के बारे में बताऊंगा लेकिन इन सब बातों के साथ मेरा यह सुझाव है आपको कि मंत्री महोदय इस पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। आप सर्वे करवा लीजिए कि आपके 80% गांव जो आज पीने के पानी से जुड़े हुए हैं लेकिन उन गांवों के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं कि पानी उनके पास पहुंच नहीं रहा है। लाखों रुपये सरकार के नष्ट हो गए उस योजना को ढोने में। आप पूछिए अपने अधिकारियों से कि वहां पानी क्यों नहीं जाता जब पानी की स्कीम बनी हुई है और आप यह भी पूछिए अपने अधिकारियों से कि राजस्थान के अन्दर कितनी बार आपने पाइप योजना बनाकर गांवों को जोड़ा और फिर आपने वापिस उन पाइपों को निकाला? पाइप खरीद का पैसा, पाइप जोड़ने का पैसा और फिर उनको निकालने का पैसा। कितना सरकार का यह पैसा नष्ट हुआ है, आप इसकी इंक्वायरी बैठाइये। एक इस पानी के ऊपर आप एक हाऊस की कमेटी बैठाइये कि किस प्रकार की धोखाधड़ी, गड़बड़ी और बदमाशियां उन लोगों के साथ हुई हैं। आज हम देखते हैं गांवों के अन्दर गांवों में हम जाते हैं, मंत्री महोदय, बहुत ईमानदारी से बताता हूं आपको, सारे सदन को बताना चाहता हूं लोग इस तरह से, हाथ करके पानी का इशारा कर दिया, आंखों में पानी आ जाता है देखकर के उनको उन गरीब लोगों को जब पीने के लिए पानी नहीं। सौ-सौ रुपये एक-एक टंकी का देकर के वह पीने का पानी पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर, बीस-बीस किलोमीटर दूर से वह लेकर आते हैं। यह हालात हैं। उस दिन मैंने आपके सामने जिक्र किया था बलाल गांव के लिए। याद होगा आपको, बलाल गांव के लिए मैंने निवेदन किया। राजास गांव के लिए मैंने आपको निवेदन किया, छेजड़ा गांव, जिसकी आबादी तीन हजार की आबादी है उस गांव के लिए निवेदन किया। आपने कहा कि गांव का नाम मत बताइए। मैं अधिकारी भेजूंगा आपके पास बड़ा अधिकारी भेजूंगा आपके साथ जाकर के वह खुद समस्या का निपटारा करेगा लेकिन कहां अधिकारी गए? कोई पता नहीं और इन गांवों के बारे में आपने कहा था 27 तक अधिकारी मुझे रिपोर्ट देंगे। आप पूछ लीजिये, चार महीने की बात हो गई। यह तो मैंने बहुत छोटी सी बात बताई है आपको। लेकिन आपको कठोर कदम उठा करके स्थाई समाधान करना होगा और जो आज पाइप लाइनें, जो सड़क के ऊपर पड़ी हैं, पैसा तो उन्होंने, एक-एक, दो-दो, मीटर का पैसा उठाया है लेकिन आधा-आधा फुट पर पानी की लाइन डाल दी।

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

आंधी में वह पाइप लाइन बाहर आ गई और ऐसे वैसे पड़ी हैं कहीं ग्वाले तोड़ देते हैं, कहीं प्यासा आदमी लाइन को तोड़ देता है। एक-एक महीने तक वह ठीक नहीं होती। यह हालत आज बनी हुई है। मैं समझता हूं कि आप तत्परता से मेरे इन सुझावों के ऊपर गौर करेंगे।

चूरू जिले की सात तहसीलें हैं, सातों की सातों इस वक्त पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है और इन सातों तहसीलों में, विशेष तौर से जहां से मैं चुनकर आया हूं वह सरदार शहर जहां 185 गांव अकाल के अन्दर हैं, एक भी गांव ऐसा नहीं है जो अकाल के अन्दर नहीं है। सारे के सारे गांव अकाल में हैं और मंत्रीजी मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि पानी का सारा सिस्टम गांव में कोपलेप्स हो रहा है। भण्डारीजी यहां बिराजे हुए हैं। सक्षम अधिकारी हैं, सक्षम मंत्री हैं और फिर लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हम लोग क्या मुंह लेकर जाएं उनके पास में? सरदार शहर तहसील के जो गांव पानी से जुड़े हुए हैं वह भी और जो गांव पानी से नहीं जुड़े हुए हैं वह भी, सारे के सारे गांव मुश्किल से दस गांव ऐसे होंगे पूरे क्षेत्र में जहां लोकल सोर्स हैं, जहां पानी यदाकदा कर्मचारियों की मेहरबानी से आ जाता है। यह स्थिति है, मैं एक योजना जो हमारे जिले के लिए बनी थी, चूरू जिले के लिए साहवा-गंधेली पेयजल योजना। साहवा-गंधेली पेयजल योजना के अन्तर्गत सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र के 74 गांव थे। माननीय मंत्री महोदय, इस पेयजल योजना के प्रथम चरण, द्वितीय चरण दो चरण बने, तारानगर तहसील जो इसी जिले की है, उसका प्रथम चरण भी पूरा हो गया, उसका द्वितीय चरण भी पूरा हो गया। इसी जिले की राजगढ़ तहसील है उसका प्रथम चरण भी पूरा हो गया और द्वितीय चरण भी पूरा हो गया और चूरू जिला मुख्यालय के भी कुछ गांव इसमें जुड़े हुए हैं द्वितीय चरण के अन्दर वह भी पाइप लाइनों से जुड़ गए। सरदार शहर तहसील के प्रथम चरण के 74 गांवों में से 14 गांवों को पाइप लाइन से जोड़ा गया है। मंत्री महोदय यह क्यों? वह क्षेत्र जो सबसे ज्यादा प्यासा है, सबसे ज्यादा तकलीफ में है, सबसे ज्यादा अकाल पीड़ित है और सबसे ज्यादा गरीब लोग वहां रहते हैं और सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है चूरू जिले का। वहां चौदह गांव ही क्यों प्रथम चरण के, आप जवाब लीजिए अपने अधिकारियों से, प्रथम चरण में 76 गांव मंजूर हुए, सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र के, उसमें से 76 गांव क्यों नहीं पूरे हुए आज तक मुझे याद आ रहा है उस दिन आपने कहा था 20 दिन के अन्दर-अन्दर यह योजना बनकर मेरे पास आनी चाहिए कि इस योजना की स्थिति क्या है? मैं बड़ा खुश हुआ कि मंत्रीजी ने 20 दिन का नाम लिया है। सारे क्षेत्र में मैंने ढिंढोरे पीटे आपके, आपके नाम के ढिंढोरे पीटे कि मीटिंग बुलाई है 20 दिन के अन्दर और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ताकत के साथ में पूरा करने की कोशिश करूंगा। मंत्री महोदय, मैंने पता किया विभाग से वह कहते हैं कि बीस करोड़ रुपये इस योजना में और लगेंगे क्यों नहीं लगेंगे? लगेंगे जब वह पूरी नहीं करेंगे, समय आगे से आगे जाएगा

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

तो योजना में राशि तो बढ़ती जाएगी। आज वह कहते हैं बीस करोड़ रुपये लगेंगे और आप इस साल इसको नहीं मंजूर करेंगे, नहीं बनाएंगे तो अगले साल चालीस करोड़ बताएंगे और बढ़ते-बढ़ते एक स्थिति यह आएगी कि आप इन गांवों को कैंसिल कर देंगे और फिर जो आन्दोलन और यह सब बात करनी पड़ेगी क्योंकि प्यासे क्या करेंगे, करना पड़ेगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है आपसे, आपसे भी और आपके..

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस विभाग के सेक्रेटरी महोदय से भी कि आप इस प्यासी तहसील को, प्यासे गांव को, यह जो साहवा-गंधेली पेयजल योजना बनी है इसके 76 गांवों को आप इसी साल में पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे एक साथी ने आरोह प्लाण्ट के बारे में बात कही, खारे पानी को मीठा करने की बात कही। यह कुछ गांव हैं विधान सभा क्षेत्र सरदार शहर के जिसके नाम मैंने पहले भी पुकारे, राजास बिलाला, पिछलाई ताल और नैनासर। यहां चार आरोह प्लाण्ट लगे हुए हैं और इन चारों गांवों में पीने के पानी की आज तारीख में कोई व्यवस्था नहीं है। और यह चारों प्लाण्ट बन्द पड़े हैं और चारों प्लाण्ट सही स्थिति में हैं लेकिन सुना है कि राज्य सरकार का कोई कॉण्ट्रेक्ट है और वह कॉण्ट्रेट पूरा हो गया उसकी वजह से नहीं हो रहा है लेकिन आपको मेरा यह कहना है, मंत्री महोदय कि जब जनता प्यासी मर रही है वहां पर और वह आरोह प्लाण्ट सही पड़े हैं और उन आरोह प्लाण्ट को जिन्होंने चार-चार साल तक चलाया वह कर्मचारी भी गांव के रहने वाले हैं, वह कब तक बैठे रहेंगे, उनकी तरफ कब तक देखेंगे? वह देखेंगे नहीं मंत्री महोदय, आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या एक्शन लेते हैं उनके ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं, नहीं तो गांव वाले चलाएंगे ही चलाएंगे उनको।

इसके साथ ही मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में बताना चाहता हूं, अभी जर्मनी के सहयोग से एक पेयजल योजना बनी है और मुझे जहां तक विश्वास है, मैंने पता किया है दिल्ली में कि इस योजना की स्वीकृति भी हो गई है और जो भी सरकारों के बीच में काण्ट्रेक्ट होता है वह पूरा हो गया है। इस योजना के माध्यम से सरदार शहर तहसील के गांवों को और शहर को लिया गया है। आप इस योजना को तत्परता से लागू करें तो इस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सकता है। अब बात करते हैं गांव की, जब गांव में घूमकर आते हैं। शहर में आते ही सोचते हैं कि यहां तो पानी की समस्या नहीं होगी लेकिन सरदार शहर में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर पानी की समस्या न हो चूरू जिले, के अन्दर कोई ऐसा शहर नहीं है जिसकी वहां पर समस्या न हो। कोशिश की है, निश्चित रूप से सरकार ने कोशिश की है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले चार महीने में चार कुओं की बोरिंग हुई सरदार शहर में नाम नोट कर लें मंत्री महोदय, जमड़ा वेल, छापावेल और मूंदती कुई, राज वेल, मीणा वेल और बादरजी वेल। यह छह कुओं पर बोरिंग हुई और चार महीने में यह बोरिंग फैल हो गई। वह क्यों

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

फैल हो गई ? लाखों रुपये सरकार के वहां क्यों व्यय हो गये ? आप जांच करवाइये इसकी । आप जांच करवायें कि 4 महीने के अन्दर ही यह बोरिंग क्यों फैल हो गए । जमड़ावेल, शायद आपके पास भी नोटिस आया होगा भूख हड़ताल पर बैठे हैं लोग वहां पर । वह कहते हैं कि प्यासे मरेंगे इस लिए पहले भूख में ही मर जायें । एक शहर के अन्दर जहां पानी के सोर्स की कमी नहीं है, बहुत से सार्वजनिक कुएं वहां पर हैं आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं । 3 दिन हो गए उनको भूख हड़ताल पर बैठे । सारे शहर के अन्दर ऐसी कोई पाइप लाइन नहीं है कि जो फूटी हुई नहीं हो । भण्डारी साहब सुन लें आप । पूरे सरदार शहर के अन्दर जो पाइप लाइन डली हुई है वह गली-गली के अन्दर टूटी हुई है और वहां पूरे सरदार शहर के अन्दर कीचड़ भरा हुआ है ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : माननीय मंत्री महोदय, मैंने सरदारशहर तहसील के कुछ गांव जो बहुत समस्याग्रस्त हैं उनकी सूची मैंने आपको भेजी हुई है और मैंने कटौती प्रस्ताव में भी दिया है 11 गांव हैं जहां पर बोरिंग करने का प्रस्ताव है । आप कहें तो मैं दो मिनट में पढ़कर सुना दूं । गिड़-किचिया, मेदासर छन्ना, हिरासर, कमलासर, बोदूसर, गोमटिया, चारणवासी, मित्तासर, घानूसर, ढाणी कालेरा, रंगाईसर, जोवनदेसर, गुदासर चाणना, अजीतसर, सारासर, कालड़वास, पम्पालिया, बिपासर, सांमासर आदि । ऐसे ही मेरे 20 गांव हैं जहां एक स्कीम है एम.एन.पी. की जहां हरिजन बस्तियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । तो हमारी तहसील के अन्दर 25 मोहल्ले ऐसे हैं कि जहां हरिजनों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं नाम नहीं पढ़ूंगा । अलग से मैं आपको स्लिप दे दूंगा । मुझे पूरा विश्वास है कि आप चूरू जिले की पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान देंगे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं । यह समस्या आप अस्थाई रूप से मिटाने के साथ-साथ स्थाई रूप से मिटाने की भी व्यवस्था करें । जो सिस्टम आपका कोलैप्स हो गया है, कर्मचारी काम करना नहीं चाहते हैं । माफ करना मुझे कहते हुए बहुत शर्म आती है कि आपके एस. ईएन. लेवल का जो अधिकारी है उसका एक्स. ईएन. कहना नहीं मानता है, एक्स. ईएन. का कहना ए. ईएन. नहीं मानता है, ए. ईएन. का कहना जे. ईएन. नहीं मानता है और जे. ईएन. का कहना नीचे के कर्मचारी नहीं मानते हैं । यह स्थिति आप की बनी हुई है इसलिये आप जिस भावना से काम करना चाहते हैं वह तभी अच्छी साबित होगी जब आप तुरत-फुरत एक्शन लेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री किशन गोपाल कोगटा ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीन सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 पर चर्चा चल रही है और इसमें मैं भी सम्मिलित होते हुये कुछ मेरे विचार रखूंगा । वर्तमान में पूरे राजस्थान की पेयजल के सम्बन्ध में जो स्थिति है वह

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

सम्माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक ही बात करीब-करीब सभी सदस्यों ने कही है और वह है पीने के पानी की समस्या। और यह जो समस्या आज इस व्यापक रूप में प्रकट हुई है अगर उसके लिये समयबद्ध और योजनाबद्ध अगर योजनायें बनायी जातीं और जिस प्रकार से जनसंख्या का विस्तार हो रहा है और पानी का जिस रफ्तार से दोहन हो रहा है, उपयोग हो रहा है उसको देखते हुए यह स्थिति आने वाली थी। एक तो वर्षा कम हुई और पिछले 8-10 सालों से लगातार वर्षा का कम होना और दूसरे भूतल में जो जल-स्तर है उसका जिस रफ्तार से दोहन हो रहा है और जिस प्रकार से पानी का स्तर नीचे जा रहा है यह समस्या आने वाले समय में बहुत भयंकर रूप से राजस्थान में आने वाली है और इसके लिये जो योजना-बद्ध दोहन होना चाहिये था। अनाप-शनाप ट्यूबवैल खुद रहे हैं, अनाप-शनाप हैण्डपम्प लग रहे हैं और जैसा माननीय सदस्य श्री घनश्याम जी तिवाड़ी ने बताया था जल संसाधन आयोग बनना चाहिये और योजना-बद्ध तरीके से जल का उपयोग हो। इसके बारे में सोचना चाहिये। पानी जितना है उसका जितना उपयोग हम जिस रफ्तार से लेंगे आने वाले समय में पानी की क्षमता हमारे सामने है इसलिये मेरा यह कहना है कि एक योजनाबद्ध तरीके से पानी का उपयोग हो तो यह समस्या जो विकराल रूप ले रही है उसमें कुछ सहयोग मिलेगा। खास कर अजमेर जिले की जो समस्या है वह मैं आपके सामने रखूंगा।

अजमेर जिला राजस्थान का सेण्टर है और कई दृष्टि से वहां की जो पापुलेशन है, वहां का जो नागरिक बन्धु है और उनके साथ-साथ बाहर के लोग भी आते हैं पुष्कर-राज तीर्थ और ख्वाजा साहब गरीबनवाज का वहां तीर्थस्थल है और वहां आना-जाना इतना रहता है तीर्थ यात्रियों का, जायरीनों का और सबसे ज्यादा स्थिति वहीं खराब है। अजमेर में 3 दिन में पानी आता है। ब्यावर, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़ और विजयनगर यह जो बड़े-बड़े टाउन्स हैं उनमें 3 से 5 दिन में पानी आ रहा है और पानी भी स्थानीय लेबल से नहीं बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। बनास की योजना है, अब बीसलपुर योजना समाप्त होने को आ रही है। जल्दी ही पानी मिलेगा पर वास्तव में राजस्थान में अगर कहीं स्थिति खराब है पानी की तो वह अजमेर जिले में है और मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी बीसलपुर योजना पूर्ण होकर सारे एरिये में पानी पहुंचे और पानी की समस्या का समाधान हो और साथ ही अजमेर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है, शहरों की तरफ तो सबका ध्यान जाता है। वहां तो कहीं से भी पानी बीसलपुर से, या बनास से पानी सभी शहरों को मिल रहा है लेकिन पूरे अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो पानी की समस्या है वह बहुत दयनीय है। हैण्डपम्प खोदे जाते हैं एकमात्र ही साधन है हैंडपम्प का लेकिन साल-दो साल में वह ड्राई हो जाते हैं। पानी का स्तर इतना नीचे जा रहा है कि पानी लोगों को पीने के लिये दो-दो किलोमीटर जाना पड़ता है और हैंडपम्प जहां कहीं हैं वहां उनकी ऐसी हालत है कि वह खराब पड़े हैं और जो उनके ठीक कराने की व्यवस्था है वह भी

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

सन्तोषजनक नहीं है। मेरा एक ही कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना बने और जिस प्रकार से शहरों में अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, केकड़ी और सरवाड़ म्युनिसिपल एरिये में पानी बीसलपुर से मिल रहा है जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी बीसलपुर की योजना बने और उनको पानी उस योजना से मिले तभी समस्या दूर हो सकती है.... समस्या इतनी भयावह है कि इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। योजना बनी हुई है पर मेरा यह कहना है कि सारे जिले के लिए जो योजना बनी है उस पर विशेष तौर से ध्यान दें, युद्ध स्तर पर काम हो और पैसा भी स्वीकृत हो। योजना बन गयी, पैसा स्वीकृत होना आवश्यक है। और कार्य प्रारम्भ हो, तब जाकर जिले की स्थिति बनेगी।

मेरा मसूदा विधान सभा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पेयजल की समस्या है, दो-दो किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। कुछ गांव तो ऐसे हैं– नंदवाड़ा, बरल आसन, कानपुरा, बेगलियावास, शेरगढ़, मुहायना, सरमालिया और दौलतपुरा कि वहां हर साल टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ता है और दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर से पानी आता है। मेरा एक ही कहना है कि इन स्थानों पर कोई स्थायी योजना बनायी जाए। हैण्ड पम्प पर्याप्त नहीं हैं। हैण्ड पम्प जितने भी खोदे जाते हैं, स्थिति ऐसी है कि साल-छह महीने में सूख जाते हैं। बहुत से हैण्ड पम्प तो ऐसे हैं, खोदने के बाद जब उनको कमीशन करते हैं उससे पहले ही पानी नीचे चला जाता है। ऐसा एरिया है इसलिए विशेष तौर से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

ब्यावर के आसपास चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है। ब्यावर में पानी ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। उसके चारों तरफ, खासकर मसूदा क्षेत्र के चारों तरफ पंचायतें हैं, पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जिनको पैसा मिलता है वे अपने कुएं और गहरे करा लेते हैं और फिर पानी बेचते हैं। लेकिन जो किसान बंधु हैं, गांव के नागरिक हैं, पीने के पानी के लिए और खेती के लिए उनके स्रोत सूखते जा रहे हैं। वे लोग गरीब हैं, दुबारा उनको खुदवा नहीं सकते, गहरा करा नहीं सकते। इसलिए मेरा आग्रह है कि विभाग या तो वहां से पानी लेना बन्द करे, 15 किलोमीटर दूर से लाये या फिर उन गांवों में रहने वाली जो आबादी है उसके लिए भी पानी की व्यवस्था करे। उन सबके कुएं सूख गये, हैण्ड पम्प सूख गये और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो इस ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में लगे हैं वे अपने कुएं गहरे कराते जा रहे हैं, पैसा आता है फिर गहरा करा लेते हैं और पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। यह एक बहुत भयंकर समस्या है। नरबदाखेड़ा, गुहाना, देलवाड़ा, बलाड, सुहावा, अन्नदेवरी, सरमालिया, ब्यावरखास, रूपनगर और जूंदड़ी मेदरताल ये बड़ी-बड़ी पंचायतें ब्यावर के चारों तरफ हैं। इनमें पैसे वालों के जो कुएं हैं वे गहरे कराके पानी बेच रहे हैं ब्यावर को और वहां के नागरिकों के लिए पानी की भयंकर समस्या है। इसका हल हो, यह नितान्त आवश्यक है। इसके लिये माननीय मंत्री महोदय को भी निवेदन कर रहा हूं कि इस ओर ध्यान दें।

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

जहां तक हैण्ड पम्प का सवाल है और कार्य-प्रणाली का सवाल है, केवल आठ हैण्ड पम्प अभी मिले हैं– 5 विजयनगर के लिए और तीन ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अभी स्थिति यह है कि दो हैण्ड पम्प खुदे हैं, बाकी 6 कहां खुदेंगे, कब खुदेंगे यह विभाग भी नहीं बता रहा और न उसकी कोई व्यवस्था है। जो मशीन आयी वह एक हैण्ड पम्प ग्रामीण क्षेत्र में खोद गयी, एक विजयनगर में खोद गयी और वापस चली गयी। अलाट ही इतने कम किये। किये वे भी अगर समय पर नहीं करेंगे तो? स्थिति का मुकाबला करने में विभाग थोड़ा ध्यान देगा तो निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत तो समस्या ठीक होगी।

मेरे क्षेत्र में फ्लोराइड की भी समस्या है। केशवपुरा पहाड़ी गांव में फ्लोराइड के लिए कितनी बार कहा, सैम्पल भी गये। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए, मीठा पानी एरिया को देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी। मेरा इसमें एक ही आग्रह है कि फ्लोराइड वाटर का जो सिस्टम है उसको थोड़ा आसान बनाएं और जल्दी काम हो ताकि उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ विजयनगर मेरा एकमात्र म्यूनिसिपल एरिया है, उसके लिए मंत्री महोदय ने पिछली बार 37 लाख रुपए की एक स्कीम पास की थी। उसका काम भी पूर्ण हो गया, ट्यूबवैल भी खुद गया, टंकी भी बन गयी लेकिन ट्यूबवैल में कनेक्शन नहीं हुआ, ट्यूबवैल टंकी से जुड़ा नहीं। अभी जो इतनी समस्या है पानी की, विभाग अगर तत्परता से काम करे तो एक महीने में विजयनगर में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। राजस्थान में एक ही पंचायत ऐसी है मसूदा, जिसमें पानी की भयंकर समस्या थी लेकिन माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा कि विभाग ने इसको टेकओवर किया और वहां काम हुआ। उस एरिया वालों ने पहली बार इस विभाग की और माननीय मंत्री महोदय की कार्य-शैली का आकलन किया और पूरा एरिया धन्यवाद दे रहा है कि 15-20 साल से पंचायत से टेकओयर करने के लिए संघर्ष चल रहा था, भंवरलालजी शर्मा, माननीय मंत्री महोदय वहां पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया और काम पूरा हुआ। लेकिन आपने जो बजट अलाट किया है उसका उपयोग अगर समय पर हो जाता है तो निश्चित रूप से पंचायतों और पंचायत समितियों को उसका फायदा मिलेगा।

श्री सभापति : अब मेरा आपको धन्यवाद, विराजिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा : मेरा एक सुझाव और है कि कुछ समस्या स्टाफ की वजह से है। स्टाफ अप-डाउन करता है और गांवों में टिकता नहीं है।

श्री सभापति : बहुत बोलने वाले हैं, विराजिये अब आप।

श्री किशनगोपाल कोगटा : मेरा यह कहना है कि अगर विभाग यह निर्देश दे कि ए ईएन और जे ईएन अपने स्थान पर रहें, तो निश्चित तौर से समस्या का हल होगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाबसिंह शक्तावत ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : माननीय सभापति जी, आज हम राजस्थान की अहम् समस्या पेयजल पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मैंने यद्यपि अपने निर्वाचन क्षेत्र और एक सैद्धान्तिक बात के लिए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं लेकिन कुछ बातें यहां उठायी गयी हैं प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ से और चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ से। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि राजस्थान में जल नीति बननी चाहिए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने नेशनल वाटर पॉलिसी बना रखी है। उस नेशनल वाटर पॉलिसी में सिद्धान्ततः यह तय किया हुआ है कि पानी पर पहला हक पीने का रहेगा। अब राजस्थान और क्या नीति बनाना चाहता है ? जब राष्ट्रीय नीति बन गयी, उस राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में पीने के पानी का सर्वोच्च अधिकार, चाहे जलाशय हों या कोई भी स्रोत हों, स्वीकार किया गया है। जब प्राकृतिक आपदा पैदा होती है तब राज्य सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह जनता को पानी पहुंचाए येन केन प्रकारेण ।

प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया कि जो जयसमन्द का पानी उदयपुर लाया जा रहा है उस से आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। राजस्थान सरकार ने उस वक्त योजना बनायी थी, एक इमरजेंसी के तौर से वह योजना बनायी गयी थी। स्थायी रूप से योजना नहीं बनायी गयी थी। उस वक्त उदयपुर में पानी का संकट इतना गहरा गया था कि हमने दो योजनाएं बनायी थीं इमरजेंसी की। एक बड़ी की योजना बनायी थी जिसको हमारे अधिकारियों ने रिकार्ड टाइम एक महीने में पूरा किया और दूसरी जयसमन्द से पानी लाकर उदयपुर की पानी की कमी को दूर करने की योजना बनायी गयी थी। उसके लिए पाइप खरीद लिये गये थे। सौभाग्य से कुछ वर्षा अच्छी हो गयी, आने वाले वर्षों में पानी की कमी नहीं रही। यह सोचा गया कि मानसी वाकल का पानी जो बहकर गुजरात में चला जाता है, जिसकी देवास स्टेज बन गयी है उस मानसी वाकल के पानी को रोक कर स्टेज एक में देवास में लाकर उदयसागर में डालकर उदयपुर की पानी की समस्या दूर की जाएगी और साथ साथ इण्डस्ट्रियल उत्पादन के लिए जितने पानी की आवश्यकता होगी वह भी पूरी की जाएगी। माननीय शिवचरण माथुर जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने इस योजना का शिलान्यास किया। माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने उस वर्ष बजट में एक करोड़ रुपए का प्रोविजन किया। उस योजना को आपकी सरकार आने के बाद, जो दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना थी, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, ठण्डे बस्ते में, खामोशी के बस्ते में डाल दिया गया। कभी आप कहते हैं कि इस योजना को हिन्दुस्तान जिंक बनाएगा, कभी कहते हैं कोई और बनाएगा। मैंने माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण पढ़ा, मैंने वित्त मंत्रीजी का भाषण पढ़ा, मुझे बहुत निराशा हुई, कहीं भी उस योजना का जिक्र तक नहीं किया गया। लेकिन आज जरूर उस योजना का जिक्र किया गया है। क्या यह दक्षिणी राजस्थान के लोगों के

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

साथ उस सरकार की भेदभावपूर्ण नीति है या नहीं है ? जिस योजना को प्रारम्भ कर दिया गया था उस योजना को बस्ता-ए-खामोशी में डाल दिया गया ।

(17.40)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

आज मैं कहना चाहता हूं, हम इण्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में कई राज्यों के साथ उलझे हुए हैं । एक तरफ हमारा झगड़ा चल रहा है । मध्य प्रदेश से, एक तरफ हमारा झगड़ा चल रहा है हिमाचल प्रदेश से, एक तरफ हमारा झगड़ा चल रहा है यू.पी. से, आप इस मानसी वाकल के पानी को रोक कर, समय पर पानी का उपयोग नहीं करके फिर गुजरात के साथ इण्टर स्टेट वाटर के झगड़े में क्यों फंसना चाहते है ? इस योजना को समय पर प्रारम्भ नहीं करके इस योजना की क्रियान्विति क्यों नहीं करना चाहते हैं ? क्या फिर इराडी कमीशन बनवाना चाहेंगे ? फिर भारत सरकार को रेफरेंस भेजना चाहेंगे, किसी और को जज बनाएंगे जिससे यह तय हो सके कि हमारा पानी का हिस्सा है या नहीं है ? आखिर क्या नीति है ? आप क्या चाहते हैं ? क्या दक्षिणी राजस्थान के साथ भेदभाव करना चाहते हैं ? हमारी बहती हुई नदी का पानी रोक कर के हमारे पीने के पानी को आप लोगों को मुहैया नहीं कराते । औद्योगिकरण के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसको पानी आप नहीं देना चाहते हैं । गांवों की आवश्यकता की पूर्ति आप नहीं करते । और जैसा प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आप सरकार में बैठे हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं, मानसी वाकल की योजना बना लीजिये और जयसमन्द का पानी किसानों को दे दीजिये किसको आपत्ति है । वह पानी किसी काम में नहीं आ रहा है । लेकिन आप बनी बनाई सरकार की योजना को ठप्प कर देते हैं । हिन्दुस्तान जिंक रायल्टी का रुपया देती है आपको । उस रायल्टी में वह बनाये या नहीं बनाये । आप पांच साल से केवल चर्चा कर रहे हो । 89 से 94 हो गया क्या भविष्य है ऐसी योजना का ? मैं जानना चाहता हूं । इसलिए माननीय मंत्री महोदय यह स्पष्ट घोषणा करें कि मानसी वाकल योजना की क्रियान्विति कब से शुरू की जायेगी और इसका कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा । नम्बर दो....

श्री सभापति : इससे पहले यह तो पूछिये कि स्वीकार हुई या नहीं हुई ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : स्वीकार हो गयी । उस योजना को स्वीकार कर लिया गया । टेक्निकल दृष्टि से ये सारी चीजें स्वीकार कर ली गयी । माननीय मंत्रीजी मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपकी हैण्डपम्प की दुरुस्ती की दोहरी नीति है । पंचायत समितियों के पास मिस्त्री हैं वह माइनर खराबी हो तो वह दुरूस्त करेंगे और मेजर खराबी होगी तो डिपार्टमेंट करेगा । डिपार्टमेंट मेजर रिपेयर के लिए चाहिये आर्टिकल वह खरीदेगा और वह पंचायत समितियों को सप्लाई करेगा । पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पास लोग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारा हैण्ड पम्प खराब पड़ा है तो वह कहते हैं कि यह तो मेजर रिपेयर

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

का काम है, हमारे मिस्त्री इसको नहीं कर सकते। इनके विभाग के लोग उस काम को करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक महीने से माननीय मंत्रीजी आपने हैण्डपम्प दुरुस्ती का अभियान शुरू किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में जो खराब हैण्डपम्प पड़े हुये हैं उनमें से कितने दुरुस्त हो गये। आप आंकड़े देने की स्थिति में हो क्या? यह जीप का किराया क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, क्यों गाड़ी तुड़वा रहे हो, क्यों पैट्रोल बर्बाद कर रहे हो। मेरी तहसील की जानकारी और मेरी कांस्टीट्यूएंसी की जानकारी है। केवल दो हैण्ड पम्प एक महीने में दुरुस्त हुये हैं। क्या नीति है आखिर। क्या चाहते हैं आप? लोगों को पानी के बिना तरसते-तरसते मार देना चाहते हैं? मेरे वल्लभनगर निर्वाचन क्षेत्र में आपके विभाग ने 54 हैण्डपम्प नकारा घोषित किये हैं। उसके बजाय आपने दो नये हैण्डपम्प खोदने की मन्जूरी दी। यही नीति है सरकार की पानी पिलाने की। यही हमारी संवेदनशील सरकार का नमूना है कि जहां 54 हैण्ड पम्प नकारा हैं वहां केवल दो हैण्ड पम्प दिये हैं। अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे 8 कांस्टीट्यूएंसी हैं और हैण्ड पम्प कितने हैं, डेढ़-डेढ़ हिस्से में आता है। आप क्या चाहते हैं राजस्थान में? दिसम्बर के महीने में बड़ा उत्साह दिखाया, सब विधायकों की आपने मीटिंग बुलाई, मैंने एक समस्या का जिक्र किया आपके सामने कि यह जो आपकी पम्प एण्ड टैंक स्कीम है जिस पर राजस्थान सरकार का दो-दो लाख रुपया खर्च हुआ है। मैंने उदाहरण दिया, उस योजना को आपने बन्द कर दिया। लोग एक-एक साल से उस योजना के पानी से वंचित हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने उस वक्त चीफ इंजीनियर को निर्देश दिये थे कि यह काम एक महीने में हो जायेगा। दिसम्बर चला गया, जनवरी चली गई, मार्च भी जाने वाला है। मंत्री महोदय क्या चाहते हैं आप? वहां के निवासियों को बिना पानी के रखना चाहते हैं.... (व्यवधान) जुलाई में तो ईश्वर दे देगा। सरकार की कृपा पर पानी की समस्या जुलाई में नहीं पड़ेगी। वह तो ईश्वर की कृपा से जुलाई में पानी पड़ जायेगा। अगर भगवान का भरोसा है तो इस संवेदनशील सरकार के साथ क्या करना चाहते हैं आप?, आपको....

श्री सभापति : भगवान पर तो आपका भी भरोसा है माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सभापति महोदय, मैं आपको भी डिस्टर्ब नहीं करता हूं। मैं कुछ नीतिगत बातें कर रहा हूं, मैं फालतू बातें नहीं कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि पर केपिटा कितना गैलन पानी दे रहे हैं आप बता दीजिये उदयपुर जिले की अलग-अलग योजनाओं में आपकी नीति कितनी है, 40 गैलन पानी देने की है उसके मुकाबले में आप पर केपिटा कितना पानी दे रहे हैं? 10 गैलन दे रहे हैं, 5 गैलन दे रहे हैं। दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तीन दिन में दे रहे हैं या एक दिन में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आपका कांटीजेंसी प्लान कहां है? एक वल्लभनगर तहसील में एक स्कीम के लिए एक ट्यूबवैल दिया है जहां कि मेरी 12 स्कीमें आज पानी के अभाव में बन्द पड़ी हैं। माननीय

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

मंत्रीजी को मैंने उस वक्त भी कहा था और आज फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप फैसला कीजिये, यह जो पनघट योजना है। यह पम्प एण्ड टैंक की स्कीम है जिस पर आपका एक कर्मचारी काम करता था, उस कर्मचारी को हटा दिया उससे वहां के निवासी आज पीने के पानी के अभाव से पीड़ित हो रहे हैं। मैंने यह कहा कि आज भिण्डर जैसा मेरा कस्बा जिसकी 18 हजार की जनसंख्या है। गन्दा पानी पी रहा है जिससे बीमारी फैलने का अन्देशा है। मैंने आपका ध्यान पहले भी आकर्षित किया। आज वहां एक एनीकट बना हुआ था, उस एनीकट का पानी इतना गन्दा पिलाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लोग बीमार पड़ जायेंगे। यह सरकार का दायित्व हो जायेगा कि अगर शुद्ध पानी आपने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा है, किताब छपवाई है कि शुद्ध पानी पिलाने की जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार की हैं। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कथनी और करनी में यह अन्तर क्यों कर रहे हैं माननीय मंत्रीजी ? मुझे यह बताइये कि भिण्डर और कानोर में फिल्टर प्लान लगाने की क्या व्यवस्था है। किताब तो बहुत कीमती छपाई है, अच्छा कलर है, पैसे भी खूब लगाये हैं। पर पानी के लिए पैसे की कंजूसी है। किताब के कलर में कंजूसी नहीं है। मंत्रीजी मैंने 4-5 स्पेसिफिक मेरे कटमोशन के जरिये आपको जो बातें कही हैं पनघट योजना में अच्छा रख दिया, नीमड़ी, राजपुरा, अमरापुरा मैंने अभी एक क्वश्चन के जरिये आपसे पूछा था 16 और 17 तारीख को मेरे उस क्वश्चन का जवाब मिला है। अमरापुरा की योजना 5 साल पहले मन्जूर हुई थी और आज आपका विभाग कहता है कि कुआं खोदने की प्रक्रिया प्रारम्भ है। पांच साल में कुआ नहीं खुदेगा ? आखिर इन योजनाओं से मतलब क्या निकलेगा ? आखिर इन योजनाओं की स्वीकृति का उद्देश्य क्या है यह समझा दीजिये मुझे कि यह उद्देश्य है। इसी तरह से मैंने आपसे निवेदन किया कि निर्धारित मापदण्ड की मात्रा में जो पानी दिया जाना चाहिये वह पानी आज नहीं मिल रहा है लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। उदयपुर जिला पानी की वजह से तड़फ रहा है। मेरी बात छोड़ दीजिये। मावली से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ लीजिये। अगर टैंकर से पानी नहीं पिलाया गया तो वहां के लोगों की हालत खराब हो जायेगी। कांसा और कुछ ऐसे गांव वहां मौजूद हैं। यही हालत उदयपुर जिले की है। एक तरफ आपने यह नीति बनाई है कि एनीकट बनाकर पानी को जगह-जगह नहीं रोकेंगे। अगर जगह-जगह पानी को नहीं रोका तो आपका जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है वह वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। जब वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा तो कुओं में रिचार्जिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी ? आप फैसला करिये कि आज पीने के पानी के आस-पास जो कुएं है, जो स्रोत हैं उसके लिए रिचार्जिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एनीकट को बनाने का काम अगर सिंचाई विभाग हाथ में नहीं लेता है तो पी.एच.ई.डी. विभाग लेगा और उस आवश्यकता को पूरा करेगा या नहीं करेगा। ऐसे कई एनीकट बने हैं। वेस्टर्न राजस्थान में जहां आपका जल स्रोत था, पिछले अकालों के वक्त में ट्रेंच खोदकर के काली

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

मिट्टी उसमें भरी गई और उससे वहां पानी का रिटेंशन होना शुरू हुआ और उसका वाटर चार्जेज बढ़ना शुरू हुआ। आप पता लगा लीजिये वेस्टर्न राजस्थान में यह प्रयोग हुआ या नहीं हुआ और यह प्रयोग सफलता पूर्वक चला या नहीं चला। आज क्या हालत हो गयी है। भारत सरकार प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपको 93 करोड़ रुपये देती है, 31 करोड़ रुपये राज्य का शेयर होता है। 124 करोड़ रुपये का आपका फण्ड आपके पास पांच साल का जमा हुआ है। आपके विभाग में पैसा नहीं है यह प्राकृतिक आपदाओं का सवाल है नेचुरल केमेलिटी फण्ड आपको 50 करोड़ रुपये दे और आप इन योजनाओं को पूरा करें। आज हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, पुराने कुएं बेकार हो गये हैं, गांवों के जो सार्वजनिक कुएं थे वे बेकार हो गये। उन बेकार कुओं को सुधारने के लिए आज दिन तक अकाल सहायता विभाग ने एक पैसा नहीं दिया। गहरा कराने के लिए नहीं दिया, उनका मलबा निकालने के लिए नहीं दिया फिर पानी लावेंगे कहां से। हैण्डपम्प नहीं, सार्वजनिक कुएं नहीं, जल स्रोत बढ़ाने के लिए एनीकट नहीं, आखिर सरकार चाहती क्या है ? यह तो बता दें कि यह चाहते हैं। किस तरह से इस पेयजल समस्या का हल करना चाहते हैं। यह तो हमको कम से कम बता दें कि आपकी योजनाएं क्या है। क्या करना चाहते हैं मुझे कहते हुए क्षमा करें और किस तरह से पूरा करना चाहते हैं, सैण्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने कई ट्यूब वैल्स खोद रखे हैं और वहां पर पीने के पानी की समस्या है आपका विभाग उस योजना को बिजली के कनेक्शन से जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज पचासों ट्यूब वैल्स सैण्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने खोद करके डाल रखे हैं जिसके पानी का उपयोग आपका विभाग नहीं करता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे 6 ट्यूब वैल्स सैण्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की तरफ से खुदे हुए हैं, खेरुंदा में, बल्लभनगर में, बटेवर में, करणपुर में और बौड़ी में आपका विभाग उसका उपयोग नहीं कर रहा है। क्या नीति है, वाटर एवं पम्पिंग स्कीम नहीं चलाएंगे, जो सैण्ट्रल अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने ट्यूब वैल खोद रखे हैं तो उनके अन्दर कनेक्शन हम नहीं देंगे, पानी सूख गया तो हम कन्टीजेंसी प्लान के तहत पैसा नहीं देंगे और केवल नकारात्मक हैण्ड पम्प की बजाय 2 हैण्ड पम्प देकर मंत्री महोदय आप पानी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं ? आप ही बता दीजिये कि यह कोई कल्याणकारी राज का नमूना है, यह संवेदनशील सरकार का नमूना है क्या ? इसी तरह से कल्याणकारी राज की कल्पना और इसी तरह से लोगों को पीने के पानी की समस्या का समाधान करने की आपकी नीति है क्या ? स्पष्ट बता दीजिये। मैंने जो स्पेसिफिक कटमोशन दिए हैं मैं चाहूंगा कि उनके उत्तर आज सदन में दिए जायं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति जी, व्यवस्था का प्रश्न है। यह व्यवस्था आपकी बनाई हुई है, व्यवस्था आपकी ही दी हुई है कि एक उधर से और एक इधर से बोलने के बाद बीच में से बुलवाएंगे।

(श्री शिवनाथ सिंह)

आज सुबह से हम इन्तजार करके बैठे हुए हैं या तो आप हमें कह दीजिए मैं आपको नहीं बुलवाएंगे हम चले जायंगे, क्या करें ? यह व्यवस्था हम आपसे चाहते हैं।

श्री सभापति : बिराजिए माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : यह आसन से पहले व्यवस्था आपने ही दी थी।

श्री सभापति : विराजिए माननीय सदस्य। माननीय सदस्य मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दलों की संख्या के हिसाब से समय तय किया जाता है और कल मैंने आप अधिकांश निर्दलीय माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया था और आज भी अवसर मिलेगा लेकिन वैसे 5 मिनट 4 मिनट का अवसर आता है। आप लोगों को पहले भी अवसर दिया गया है और कल भी मैंने सब माननीय सदस्यों को बुलवाया था, जितने भी माननीय सदस्य बोलने वाले थे परसों भी मैंने पहले अवसर दिया था, तो हो सकता है कि कई बार पहले अवसर आ जाय और कई बार बाद में आए, पर मैं आपको अवसर दूंगा। आप विराज जायं। आपका पूरा ध्यान आसन रख रहा है। श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : आज की बात कर रहे हैं पहले असेम्बली में बुलवाया यह क्या बात हुई ?

श्री सभापति : आपकी सूची मेरे पास नहीं है कि कौन-कौन बोलेंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह : सबसे पहले दी हुई है।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय आज पेयजल की समस्या पर वाद-विवाद चल रहा है.... (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : पाटीदार साहब आप बिराजें।

श्री भीमसेन चौधरी : सभापतिजी, जिन्होंने कटमोशन दिए हैं उनको बोलने का अवसर पहले देना चाहिए और जिन्होंने नहीं दिए हैं उनको बाद में समय मिलना चाहिए। जिन्होंने कटमोशन दिए हैं पहले उनका हक है।

श्री सभापति : माननीय चौधरी साहब अपनी व्यवस्था के हिसाब से माननीय सचेतकों ने जो नाम दिए हैं उनको बुलवा रहा हूं और उसके बाद में भी जिन माननीय सदस्यों ने कटमोशन दिए हैं और माननीय सचेतकों की सूची में कटमोशन देने वाले माननीय सदस्यों को भी और नहीं दिए हैं उनको भी अवसर दूंगा। श्री कन्हैयालाल पाटीदार।....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सभापतिजी, यह तो चर्चा है ना, वाद-विवाद थोड़े ही है, वाद-विवाद किस बात का, सभी दुःखी हैं इस बात से तो वाद-विवाद क्या हुआ, कोई है ही नहीं।

श्री सभापति : विवाद है ही नहीं, चर्चा चल रही है उस पर बोलिए। माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : आदरणीय सभापतिजी, आज सदन में जो पेयजल की समस्या पर वाद-विवाद चल रहा है मैं सोचता हूं कि इसका सीधा सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों से है। पेयजल समस्या से ग्रस्त जितना ग्रामीण जीवन है मैं सोचता हूं कि शहरी क्षेत्र में यह समस्या उतने विकट रूप से व्याप्त नहीं है। हम जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं उनमें से बहुत कम को अनुभव होगा कि जब मई-जून की तपती दोपहर में हमारी ग्रामीण महिलाएं एक-एक, दो-दो किलोमीटर दूर से अपने सिर पर 20-25 लीटर पानी रख कर लाती हैं और अपने बच्चों को, परिवार को और जानवरों को पिलाती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एवं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या से जूझने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाय। यदि समय रहते यह कार्रवाई सुनिश्चित ढंग से नहीं की गई तो जन हानि हो सकती है, पशुओं की मौत हो सकती है और उनके साथ-साथ निश्चित रूप से हम सारे विधायकों की राजनीतिक मौत होना निश्चित सम्भव है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र से आया हूं और मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि वह क्षेत्र डार्क जोन में घोषित किया गया है। डार्क जोन में होने से मेरे क्षेत्र मे पेयजल समस्या का होना स्वयं सिद्ध है। इस क्षेत्र के दो बड़े कस्बे–सुनेल जिसकी आबादी लगभग 12-15 हजार की है। 2-3 वर्षों से सुनेल में पेयजल आपूर्ति हेतु मैंने एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर एक टंकी का निर्माण कराने और पास ही बहती हुई आहू नदी से पाइप लाइन डालकर टंकी में पानी देकर सुनेल के नगरवासियों को पानी की आपूर्ति करने हेतु विभाग से निवेदन किया। लेकिन 72 लाख रुपये का प्रपोजल एक्स.ईएन. झालावाड़ के विभाग से बन कर जयपुर भेज दिए जाने के बावजूद अभी तक उस योजना की स्वीकृति नहीं दी गई है। जयपुर से कोई तकनीकी मिस्टेक निकाल कर वापस झालावाड भेज दी जाती है, झालावाड़ से वापस जयपुर आती है और जयपुर से पुनः झालावाड़ भेज दी जाती है। इसी तरह की आवाजाही में 3–4 वर्ष गुजर चुके हैं और हमारे सुनेल नगर में अभी तक पेयजल समस्या चली आ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सुनेल की लम्बित पड़ी टंकी की योजना को निश्चित रूप से शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर वहां की पेयजल समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें।

इसी तरह से झालावाड़ रोड जो मेरे ही क्षेत्र का गांव है उसमें पूर्व में एक लोहे की टंकी से पेयजल आपूर्ति होती थी लेकिन लोहे की टंकी पूर्ण रूप से जर्जरित हो चुकी है, उसमें पानी ठहरता नहीं है और वहां के लोग पानी के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में काफी पहाड़ी इलाका है और लगभग 10–12 ग्राम पंचायतें पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं, उन पहाड़ी क्षेत्र के कुछ गांवों नकलंग, खटकड़, झीकड़ी, रमाय खेड़ा, सामत खेड़ा, धामनिया, सेमली खाय, हनोत्या कोटड़ी, कल्याणपुरा, शेरपुर, हरनावदा, गजारपुरा,

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

गेलाना ये वह गांव हैं जिनमें अभी से विकट समस्या है और लगभग एक-एक, दो-दो किलोमीटर से वहां पानी लाना पड़ता है। किसी भी तरह से, किसी भी विकल्प से इन गांवों में पेयजल समस्या का समाधान करवायें। ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में कनवाड़ा–कनवाड़ी की एक सम्मिलित पेयजल आपूर्ति योजना बनी हुई है पर उसके ऊपर भी कोई कार्य नहीं हुआ है। इसी प्रकार से मगीसपुरा में भी जलदाय विभाग द्वारा एक कुआं खुदवाया हुआ है लेकिन न तो उसके लिए टंकी का निर्माण हुआ है और न डाइरेक्ट गांवों को पानी दिया जा रहा है। कुएं का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें ठेकेदार का दोष विभाग द्वारा बताया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय विभाग मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ठेकेदारी प्रथा में परिवर्तन किया जाय। एक बार जलदाय विभाग टेंडर जारी कर देता है, ठेका जारी कर देता है और ठेकेदार ठेके लेकर बैठ जाते हैं और 3–3, 4–4 साल तक उसके ऊपर कार्य नहीं करते हैं और हमारी समस्या ज्यों की त्यों अटकी पड़ी रहती है। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाय और उन्हें लम्बा समय नहीं देकर 2–3 महीने का समय दिया जाय और यदि 2–3 महीने में ठेकेदार अपना कार्य वहां शुरू नहीं करते हैं पूर्ण नहीं करते हैं तो उनका ठेका निरस्त किया जाय। यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में घानखेड़ी और बंजारी में भी ट्यूब वैल स्वीकृत है और एक सम्मिलित पेयजल योजना 3-4 गांवों की बनाई गई है लेकिन उसमें भी केवल ट्यूब वैल खोद कर छोड़ दिया है आगे की कोई कार्रवाई वहां नहीं हो रही है....

(18.00)

माननीय सभापति महोदय, मैंने एक श्रेष्ठ योजना माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन की, 2–3 बार सदन में रखी कि जिन-जिन गांवों में जी.एल.आर. के टैंक बने हुए हैं, उन गांवों को पाइप लाइन से जोड़ा जाकर 3–4–5 जगह सार्वजनिक टूंटियां लगा दी जायं तो निश्चित रूप से इन गांवों की समस्या हल हो जायेगी। इस सम्बन्ध में विभाग के कर्मचारी बताते हैं कि यह इस स्कीम में नहीं आता है और हम करने में असमर्थ हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी एवं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हर स्कीम सरकार बनाती है, हर कायदे नियम सरकार बनाती है तो क्या इस स्कीम के स्वरूप को सरकार चेंज नहीं कर सकती है? मेरा आपसे अनुरोध है कि स्कीम में चेंज कर जहां जी.एल.आर. के टैंक बने हुए हैं, उन गांवों में पाइप लाइन बिछाकर, गांव के विभिन्न मोहल्लों में टूंटियां लगायी जाय ताकि उन गांवों की समस्या निश्चित रूप से हल हो सके।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ग्राम्य जीवन के बारे में उदारता पूर्वक सोचते हुए अधिकाधिक मात्रा में पेयजल आपूर्ति कराये। मैं एक बात और हैण्ड पम्पों के बारे में बता दूं कि हैण्ड पम्पों का अभियान अभी चल रहा है लेकिन इससे

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

हमें पर्याप्त संतुष्टि नहीं है। यदि इसी क्रम से, इसी गति से हैण्ड पम्प अभियान चलता रहा तो मेरे ख्याल से बरसात आ जायेगी, तब तक भी सारे गांवों के हैण्ड पम्पों को वह अभियान सफल नहीं कर पायेगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हैण्ड पम्पों के लिए 2 यूनिट बनाई जाय। एक यूनिट रिजर्व रखी जाय। एक यूनिट गांव में क्रमश- गांव वाइज हैण्ड पम्पों को दुरुस्त करे और जो रिजर्व यूनिट है, उसका कार्य यह रहे कि तत्काल समस्या जिस गांव से लिखित में विभाग के पास आये, वह यूनिट उस गांव में जाय और उस गांव की समस्या का हल करे। यदि दो यूनिट हमारे पास उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से हम निश्चित समय में ही सारे हैण्ड पम्पों को दुरुस्त कर पायेंगे। मेरा यही निवेदन है, यहां बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, विराजिये। माननीय सदस्य समय सीमा का ध्यान रखें। अभी 45 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। श्री हीरालाल सहरिया।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में जल के बारे में चर्चा चल रही है। उसमें मैं अपने आपको....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब मैं समय सीमा लागू करूंगा।

श्री हीरालाल सहरिया : ....सम्मिलित करते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद के पेयजल की समस्या के बारे में बताना चाहता हूं, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारी सन् 1980 में हलावनी और बिडोरा की पेयजल की स्कीम चल रही है; उसकी अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, इसे पूर्ण करा कर पेयजल की समस्या का समाधान कराने की कृपा करावें।

दूसरी, इसी तरह की योजना के लिये मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मुडियर, मामोनी, जाखोनी और गणेशपुर और महोदरा, जहां गांवों में हैण्ड पम्प का जल स्तर नीचे इतना चला गया है कि वहां पर हैण्डपम्प सक्सेस नहीं है और हैण्डपम्प की बजाय वहां अन्य पेयजल योजना लागू करके इन गांवों में पेयजल समस्या समाप्त करने की कोशिश करें। साथ ही हैण्ड पम्पों के रख-रखाव की समस्या है; रख-रखाव में माइनर और मेजर डिफेक्ट बताकर उनको सुधारने में काफी टाइम लगा देते हैं, वे सुधर नहीं पाते हैं और इन हैण्ड पम्पों से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि....

(18.05)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

इन हैण्ड पम्पों को एक ही विभाग, या तो पी.एच.ई.डी. ठीक करे या पंचायत समिति ठीक करे और जब तक दोनों विभागों के बीच में रहेंगे तो माइनर और मेजर डिफेक्ट बताकर उनको नकार दिया जाता है। पी.एच.ई.डी. के कर्मचारी वहां जाते हैं तो वे कहते हैं पंचायत समिति का है और पंचायत समिति के कर्मचारी वहां जाते हैं तो वे कहते हैं कि पी.एच.ई.डी. का है, इसलिए

(श्री हीरालाल सहरिया)

वे हैण्ड पम्प ठीक नहीं हो रहे हैं और गांव वाले उस समस्या से ग्रस्त रहते हैं। इसी तरह से मेरा एक और सुझाव है कि एग्रीकल्चर ट्यूब वैल खुदने की वजह से हैण्ड पम्पों के पानी का स्तर नीचे चला गया है, इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां-जहां 4-4 हैण्ड पम्प लगाकर एक गांव की समस्या हल की जाती है, उसकी बजाय एक ट्यूब वैल लगाकर उस गांव की समस्या हल कर दी जाय तो अतिउत्तम रहेगा। वहां की समस्या का समाधान भी हो जायेगा और हैण्ड पम्पों के पाइप गल गये हैं, सड़ गये हैं, उनको सुधारने में भी सुविधा रहेगी।

मेरा एक निवेदन और है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि एक पंचायत समिति को आपने इन हैण्ड पम्पों को सुधारने के लिए 60–60 पाइप दिये हैं। जिस पंचायत समिति में 300-400 गांव हैं और उस पंचायत समिति को आपके विभाग द्वारा केवल 60 पाइप हैण्ड पम्प सुधारने के लिए दिये जायं तो कैसे आशा की जा सकती है कि सारे हैण्ड पम्प, प्रत्येक गांव के हैण्ड पम्प सुधारे जा सकते हैं जबकि एक-एक गांव में 4–4 हैण्ड पम्प लगे हुए हैं तो 60 पाइप से तो हैण्ड पम्प सुधरेंगे नहीं और वहां की समस्या हल होगी नहीं। इसी तरह मोहतरा गांव में एक सरकारी कुआ है उसमें ब्लास्टिंग करने की जो योजना थी, या तो उसमें ब्लास्टिंग करा दिया जाय ताकि पीने के पानी की समस्या हल हो सके क्योंकि वह सरकारी कुआ होते हुए भी एक प्राइवेट ग्रामीण ने उस पर कब्जा कर लिया है और वहां हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं। आज स्थिति ऐसी हो रही है कि वहां के लोग कीड़े पड़ा हुआ पानी, ट्यूब वैल दूर लगे हुए हैं, उसमें से लाकर पी रहे हैं, उससे बीमारियां होने का अंदेशा है, इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करता हूं कि वहां पर हैण्ड पम्प नहीं लग सकता है तो ट्यूब वैल लगाकर उनका निदान किया जाय ताकि पीने के पानी की सुविधा हो सके....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसी तरह, सभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया और उसमें आपने बीच में ही घंटी बजा दी। इसी तरह किशनगंज के विधान सभा....

श्री सभापति : देखिये, 50 जने और बोलने वाले हैं। समय-सीमा में रहेंगे तो सबको मौका मिलेगा।

श्री हीरालाल सहरिया : दो मिनट और चाहूंगा। किशनगंज विधान सभा क्षेत्र की किशनगंज तहसील के एक गांव खेड़ली की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें अभी ट्यूब वैल खुदने की वजह से पानी का जल स्तर नीचे चला गया है, इसलिए इस गांव में पानी सप्लाई के लिए टैंकर लगाने की व्यवस्था की जाय और टैंकर की सुविधा दी जायेगी तो गर्मी के दिनों में उनको पीने का पानी मुहैया हो जायेगा। मेरा इतना ही कहना आपके माध्यम से है। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदया, मांग

(श्री कालीचरण सराफ)

संख्या 27 पेयजल योजना पर चर्चा चल रही है। चूंकि मैं जयपुर शहर से विधायक चुनकर आया हूं इसलिए पूरे प्रदेश की बात नहीं करके केवल जयपुर शहर तक अपने आपको सीमित रखूंगा।

जयपुर शहर में जिस प्रकार से पेयजल की गम्भीर समस्या है, उसका स्थायी समाधान तो बीसलपुर परियोजना से पानी जयपुर में जब आयेगा उसके बाद ही संभव होगा परन्तु क्योंकि आज नियम 131 के अन्तर्गत बीसलपुर परियोजना पर बड़ी विस्तार से चर्चा हो चुकी है इसलिए समय सीमा को देखते हुए उस पर चर्चा नहीं करके, जयपुर में पानी से सम्बन्धित अन्य समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा। आज वह वास्तविकता है कि जयपुर को जहां 695 लाख गैलन पानी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिदिन सप्लाई होना चाहिये, उसकी जगह 470 लाख गैलन पानी जयपुर की जनता को अभी मुहैय्या करवाया जा रहा है। आगामी गर्मी में, यह सर्दी का समय था, 470 लाख गैलन पानी से काम चल गया, परन्तु जैसे-2 गर्मी का मौसम आयेगा, पानी की समस्या निश्चित रूप से बढ़ेगी. और 470 लाख गैलन से जयपुर की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्रीजी को कि उन्होंने पानी की समस्या को ध्यान में रख कर, इसी गम्भीरता को देखकर 3 करोड़ 80 लाख की एक आपात योजना जयपुर शहर के लिए बनाई है जिसके अन्तर्गत 40 ट्यूब वैल्स जयपुर में और खोदे जायं और 130 हैण्ड पम्प जयपुर में लगाये जायं। इस प्रकार की योजना विभाग ने बनाई है परन्तु इससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि जो योजना बनायी गयी है उससे केवल 40 लाख गैलन पानी जयपुर को और उपलब्ध होगा जबकि जयपुर में. 225 लाख गैलन पानी की कमी है। परन्तु निश्चित रूप से इससे जनता को राहत मिलेगी। 1159 हैण्ड पम्प जयपुर शहर में अभी इस समय कार्यरत है। परन्तु माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में जितने हैण्ड पम्प लगे हुए हैं उनमें लगभग 300–350 हैण्ड पम्प इस प्रकार के है कि जो खराब हो रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा इनमें से अधिकांश हैण्ड पम्प केवल इसलिए खराब हैं कि वहां का जल स्तर नीचे चला गया है। यदि एक या दो पाइप और डाल दिये जायं तो ये हैण्ड पम्प ठीक हो सकते हैं। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि गर्मियों से पहले-पहले, जितने भी हैण्ड पम्प जयपुर में खराब हैं उसके लिए एक ऐक्स. ईएन. लेवल का अधिकारी अलग से लगाकर सर्वे करे और जहां एक या दो पाइप डालने से यदि हैण्ड पम्प पुनः चालू हो सकते हैं तो निश्चित रूप से इस ओर विभाग को ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, जयपुर नगर निगम क्षेत्र में कई इस प्रकार के गांव हैं जो नाम के तो गांव है परन्तु अब वे कॉलोनीज में परिवर्तित हो गए परन्तु क्योंकि वे जयपुर से 5-7-8 किलोमीटर दूर हैं तो उनके लिए कोई पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं है। केवल कुओं से उनको पानी उपलब्ध होता है और कुओं का जिस तरह से जल स्तर नीचे गया है वह बताने की आवश्यकता नहीं। इससे कई गांवों में इस तरह की स्थिति हो गई कि उनको दो-

(श्री कालीचरण सराफ)

दो तीन-तीन किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। हमने वहां हैण्ड पम्प भी खुदवाये किन्तु चूंकि जल स्तर नीचे चला गया इसलिए हैण्ड पम्प भी काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार के इलाके हैं – पारली मीणा जामडोली, खोरा गोडियान, झालाना गांव गेटौर गांव और खानिया गांव। इन 6 गांवों में यदि पानी की टंकी बनाकर और नीचे से पानी की टंकी भर कर वहीं यदि पाइप लाइन बिछा दी जाय और वहीं से पानी की सप्लाई की जाय तो निश्चित रूप से इनमें रहने वाले लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सकती है और मैं यह चाहूंगा कि इसी वर्ष इन योजना पर यदि प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाय तो इन 6 गांवों की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में लगभग 2.5 लाख लोग कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। आज तक यह नियम था कि कच्ची बस्तियों में जो अनधिकृत रूप से रह रहे हैं जो अनधिकृत कच्ची बस्तियां हैं, जिनका सर्वे नहीं हुआ उनमें पानी की सप्लाई पर प्रतिबन्ध था। मैं इस बात के लिए माननीय मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि कच्ची बस्तियों में चाहे वे अनधिकृत हों या अधिकृत, उनमें पानी की सप्लाई देने के आदेश तो कर दिये हैं, कनेक्शन देने के आदेश कर दिये हैं परन्तु अभी तक काम चालू नहीं हुआ है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि पी. एन. भण्डारी साहब जब आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन थे तो पहले लाइट के कनेक्शन पर भी बेन था परन्तु जब पी.एन. भण्डारी साहब आर.एस.ई.बी. के चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा कि नहीं यह बिजली की चोरी होती है, सरकार को रेवेन्यू मिलेगी। एक आदेश में एक लाख लोगों को बिजली के कनेक्शन दे दिये और उन्होंने हर कच्ची बस्ती में कैम्प लगाया और एक स्पेसिफिक अमाउंट तय कर दिया कि इतना पैसा जमा कराओ और बिजली का कनेक्शन लेओ। सौभाग्य से अब पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट के सैक्रेट्री भण्डारी साहब बन गये हैं और यह निर्णय भी सरकार ने ले लिया है कि इनको कनेक्शन देना है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसी बस्तियों में कैम्प लगाकर एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करके उनको कनेक्शन दें ताकि कच्ची बस्ती के लोग ठेकेदारों के चक्कर से बच सकें। हर कच्ची बस्ती में कैम्प लगाकर एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करके सबको पानी के कनेक्शंस मिल जायं इस तरह की व्यवस्था निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, आप यह परम्परा मत डालिए कि जो ऑफिसर्स गैलरी में लोग बैठे हैं, अफसरों की अगर हम यहां पर तारीफ करेंगे. यह पहले कभी नहीं हुआ करता था। मिनिस्टर एनसरेबल है। चाहे वो भण्डारी हो, चाहे वो मेहता हो। वे मिनिस्टर को एसिस्ट करते हैं Your Minister is very competent. He is adjoining to your Constituency also....

श्री कालीचरण सराफ : नहीं, नहीं मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं....

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मिनिस्टर ही यह सब व्यवस्था कर देंगे। भण्डारीजी को उसमें क्या करना था? उनको क्या तकलीफ हुई, उसमें करंट ही लगाना था। यहां तो पानी ग्रैविटी से आता है।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदया, यह नियमों में है कि माननीय सदस्य आपको एड्रेस करेंगे और ऑफिसर्स लॉबी या प्रेस इन दोनों को एड्रेस नहीं करेंगे।....(व्यवधान) आज सुबह से ही ऐसा चल रहा है। इस सदन के प्रति रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का प्रतिनिधि मिनिस्टर होता है वह रेस्पोंसिबल है। उसको यहां की मंशा को, डिसीजन को एक्जीक्यूट करवाने की जिम्मेदारी मिनिस्टर की है। मिनिस्टर इसको एक्ज्यूकेटिव से करेगा It is his responsibility. Minister, P H E D. is responsible.

श्री सभापति : इन्होंने संयोग से नाम लिया है पर एड्रेस तो आसन को ही किया है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर किसी भी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कोई चार्ज लगते हैं तो वह थर्ड पार्टी है। उसको हाउस में अपना कंडक्ट एक्सप्लेन करने का अधिकार नहीं है। जिस अधिकारी की आप बात कर रहे थे इनके खिलाफ, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तो 1977 के वक्त चार्जेज लगे थे, मैंने इनको डिफेण्ड किया था। लेकिन यहां अफसरों की हम ज्यादा +++ तो इनकी +++ खराब हो जायेगी।

श्री सभापति : अब आप भी कन्क्लूड करें।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, जिस प्रकार से कच्ची बस्तियों में कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। आज जयपुर में लगभग 4 लाख लोग कृषि भूमि पर बने मकानों में रहते हैं पर क्योंकि अभी तक उनके नियमन की घोषणा नहीं हुई थी। उन्होंने पानी की सप्लाई के लिए निजी रूप से व्यवस्था कर रखी है। हर कॉलोनीज में जैसे एग्रीकल्चर लैण्ड पर बनी हुई कॉलोनी है, उन्होंने अपने यहां कुएं खोदकर पाइप ले रखे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब कच्ची बस्तियों में आपने कनेक्शन अलाउ कर दिए तो उसी प्रकार से कृषि भूमि पर बनी हुई जो कॉलोनीज हैं उनमें भी यदि आप पाइप लाइन बिछाकर जलदाय विभाग की तरफ से पानी के कनेक्शन देंगे तो 4 लाख लोगों को इससे राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदया, जयपुर शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि पानी की पाइप लाइन और सीवरेज लाइन कई जगह बिलकुल पैरेलल चल रही हैं। अब उनमें कहीं भी लीकेज हो गया तो कई जगह इस प्रकार की समस्या आती है कि गटर का पानी पीने के पानी में मिल जाता है और गन्दा पानी आता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की शिकायत जहां से आती है उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना चाहिए। माननीय सभापति महोदया, पानी का दबाव कम है, पानी लिमिटेड

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

समय के लिए आता है तो कई इस प्रकार के लोग हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट तो इन्होंने खराब कर दिए ऐसे तो अन्याय मत करिये, प्लीज....

श्री सभापति : खराब की बात नहीं है। देखिए, पानी का मामला है, गर्मी आने वाली है और सभी माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : मैं दो मिनट और बोलूंगा। कई लोग बूस्टर्स लगाकर पानी की सप्लाई लेते हैं। इससे और लोगों के लिए दबाव कम कर देते हैं। इस तरह के लोगों की चैकिंग होनी चाहिए और जहां बूस्टर से पानी लेते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, मैं सीवरेज लाइन के बारे में भी दो मिनट बोलना चाहूंगा। मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली बार इन्होंने 355 लाख और एक जगह और 171 लाख मेरे इलाके में सीवरेज लाइन के लिए स्वीकृत कर दिए जिससे जनता कालोनी से गांधी नगर तक मैन सीवरेज लाइन तो बनी परन्तु कालोनीवाइज जो सब-लाइन बननी चाहिए वो अभी नहीं बनी।

श्री सभापति : आप धन्यवाद तो देते हैं पर "परन्तु" लगा देते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : परन्तु तो लगाना पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि मैन सीवरेज लाइन तो बनी परन्तु कालोनी के लोगों को उसका फायदा हो सके, एक-एक कालोनी को लेकर सब-लाइन डालकर....

श्रीमती कमला : यह परन्तु, पर, लेकिन, किन्तु तो शब्दावली में बहुत ही जरूरी शब्द हैं।

श्री कालीचरण सराफ : इसलिए बोल रहा हूं। ऐसी जो कॉलोनीज हैं उनके लिए 8 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया है जयपुर की लाइट, सड़कें और सीवरेज लाइन के लिए। निश्चित रूप से 4–5 करोड़ रुपये सीवरेज के लिये मिलेंगे तो इनको प्राथमिकता के आधार पर कॉलोनीज को लेकर जैसे जनता कालोनी, सेठी कालोनी, वर्गीज कालोनी, तिलक नगर, सिंधी कालोनी, आदर्श नगर, राजापार्क, गांधी नगर, बापू नगर, बजाज नगर आदि इस प्रकार की कालोनीज को प्राथमिकता के आधार पर सीवरेज की व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जलदाय विभाग सीवरेज टैक्स के रूप में जयपुर शहर में लगभग 70-75 लाख रुपये प्रतिवर्ष जनता से वसूल करता है। परन्तु सीवरेज लाइन डालने का काम जे.डी.ए. और नगर निगम करती है। यह पैसा नगर निगम और जे.डी.ए. में समय पर ट्रांसफर नहीं होता। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस बात पर ध्यान दें क्योंकि नगरीय विकास मंत्री भी यही हैं, और जलदाय विभाग के मंत्री भी यही हैं। जो 70-75 लाख रुपये आप हर वर्ष जनता से वसूल करते हैं वह यदि समय पर नगर

(श्री कालीचरण सराफ)

निगम और जे.डी.ए. को ट्रांसफर कर दें तो निश्चित रूप से जो सीवरेज लाइन डालने का काम है उसमें गति आयेगी और सीवरेज लाइन जल्दी डलेगी। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल अहारी (अनुपस्थित)। श्री दयाराम परमार (अनुपस्थित)। श्री राकेश मेघवाल।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इधर से दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, लिस्ट में जैसे चला आ रहा है.... (व्यवधान) अब नाम लिस्ट से चल रहे हैं तो दो मिनट बोलने वाले हैं, ज्यादा लम्बा समय नहीं लेंगे। (व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, लिस्ट में यदि कांग्रेस का अनुपस्थित है तो कांग्रेस का दूसरा नाम आना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : हां।

श्री सभापति : दूसरा भी अनुपस्थित है।

श्री रामनारायण चौधरी : एबसेंट में भी हमारी तरफ से लेना पड़ेगा। एबसेंट के बाद....

श्री सभापति : वह तो दो-पांच मिनट लेंगे। अभी दे देते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह भी पांच मिनट ही बोलेंगे, हम कोई एक घंटे बोलने वाले थोड़े ही हैं।

एक माननीय सदस्य : इनके बाद में दो हमारे लेने पड़ेंगे....(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र रावत। थोड़ा सा बड़ा दिल रख लेते।

श्री रामचन्द रावत (कोटपूतली) : सभापति महोदया, आज पेयजल की जो चर्चा हो रही है उसके अन्दर मैं भी अपने आपको शरीक करता हूं। यह पेयजल की जो समस्या है यह कोई एक तहसील या एक जिले की समस्या नहीं है, यह पूरे राजस्थान की समस्या है और बहुत गम्भीर समस्या है। पेयजल की समस्या के लिए सरकार को गम्भीर होना पड़ेगा और इस का मुकाबला भी गम्भीरता से करना पड़ेगा। सरकार का एक दायित्व बनता है, सरकार का यह अधिकार है कि प्रत्येक नागरिक को पानी पीने के लिए उपलब्ध कराये और उसकी व्यवस्था करें। मैं मेरे क्षेत्र कोटपूतली के बारे में अर्ज करूं। कोटपूतली के अन्दर करीब-करीब हैण्ड पम्प सारे खराब हैं और उन हैण्ड पम्पों का जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि उनके अन्दर पानी नहीं आता और सरकार ने यह घोषणा की है कि हैण्ड पम्पों को ठीक करवायेंगे मगर ठीक नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ वहां कर्मचारी लोग गाड़ी लेकर चले जाते हैं और मुश्किल से गांव में एक या दो हैण्ड पम्प ठीक करके वापस चले आते हैं। मेरा क्षेत्र कोटपूतली भौगोलिक स्थिति में इस तरह से है कि ढाणियों में बसा हुआ है। मंत्रीजी, मैं आपसे अर्ज करूं कि राजनुता गांव ऐसा गांव है जिसमें 307 ढाणियां हैं और एक भूरी भड़ाच पंचायत ऐसी है जिसमें 200 ढाणिया हैं और तीस-तीस, चालीस-चालीस घरों की

(श्री रामचन्द्र रावत)

ढाणियां है। वहां ग्राज तक एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया। इसलिए नहीं लगाया गया कि वहां गांव नहीं है, वह ढाणियों में बसा हुआ है और भूरी भड़ाच गांव, गांव नहीं है, खाली ढाणियों से बस करके पंचायत बन गई है। मेरा इस सरकार से निवेदन है और यह सुझाव भी है कि ढाणियों के अन्दर भी हैण्ड पम्प चाहिए। हैण्ड पम्प इसलिए नहीं लगाते हैं कि उसमें ग्राबादी ज्यादा नहीं होती है। मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक ढाणी के अन्दर, जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर निवास करते हैं, उनमें हैण्ड पम्प लगाये जायं। मेरा सरकार से यह भी एक निवेदन है, मेरा सुझाव है, परमानेंट इलाज करने के लिए कि हैण्ड पम्प एक साल में, दो साल में, छह महीने में खराब हो जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रत्येक गांव के अन्दर या प्रत्येक ढाणी के अन्दर एक ट्यूब वैल बना दिया जाय जिससे खुला पानी मिलेगा और वहां पर पशुग्रों की ज्यादा तादाद रहती है, गांव के लोग पशुग्रों को ज्यादा पालते हैं, इससे पशुग्रों के लिए भी पानी की समस्या भी निवट सकती है। एक-एक गांव में, एक-एक ढाणी में एक ट्यूब वैल, कुग्रां खुदवा दिया जाय।

दूसरा, मैं ग्रापको ग्रर्ज करू, मंत्रीजी, मैंने कल भी कहा था और पहले भी कहा था, मेरे क्षेत्र में एक बनार गांव है, सात हैण्ड पम्प लगे हुए थे, ग्रौज की तारीख में सातों खराब हैं ग्रौर दो-तीन मील से पानी लाया जाता है। वह पानी खरीद कर ग्राज की तारीख में भी पिया जाता है। वहां ग्रधिकारियों ने एक टंकी बनाने के लिए योजना बना दी है, उसका एस्टीमेट ग्रा गया है, प्रपोजल आ गया है मगर ग्रधिकारी लोग उसके पास नहीं करते हैं, कुछ न कुछ उसमें घोचा लगाकर फाइल को वापस कोटपूतली भेज देते हैं। यह फाइल कम से कम एक साल से चल रही है, मैं ग्रापसे पर्सनली भी मिल चुका हूं। मैंने सदन में कल भी यह चर्चा की थी और उससे पहले भी की थी। मंत्रीजी, ग्रब ग्राज ग्रापसे यह ग्राश्वासन चाहता हूं, ग्राप खड़े होकर थोड़ा सा यह कह दें कि यह टंकी मंजूर कर देंगे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। यह ऐसा संकट है कि गांव के अन्दर....

श्री भंवरलाल शर्मा : कर देंगे।

श्री रामचन्द्र रावत : मुझे बहुत खुशी हुई, इसके लिए मैं ग्रापको धन्यवाद देता हूं, बहुत ग्राभारी हूं मैं ग्रापका कि ग्रापने कम से कम एक गांव को तो टंकी के लिए मंजूर किया। मुझे एक ग्रर्ज ग्रौर करना है सरकार के सामने कि हमारे कोटपूतली शहर के अन्दर कम से कम दस ऐसे बड़े-बड़े गांव हैं जहां पांच हजार, चार हजार की ग्राबादी है। उनके अन्दर पानी की टंकी बनना जरूरी है जैसे चिमनपुरा, टोरडा, बाला का नांगल, परषोत्तमपुरा ग्रौर दूसरे गांव ऐसे गांव हैं जहां पानी की टंकी बनना बहुत जरूरी है ग्रौर वहां इतनी ग्राबादी है कि हैण्ड पम्प से काम चलता नहीं ग्रौर वहां इतने पशु हैं कि पशुग्रों को पीने के लिए पानी नहीं है। हैण्ड पम्प से पानी की पूर्ति मनुष्य की तो हो सकती है, पशुग्रों की नहीं। इसलिए पानी की टंकी वहां बनवाई जाय ग्रौर साथ ही कम से कम पांच गांव ऐसे हैं जिनके अन्दर टंकियां बनी हुई हैं मगर हरिजन बस्तियों में उन टंकियों से पानी जाता नहीं है। इसलिए नहीं जाता

(श्री रामचन्द्र रावत)

कि पाइप लाइन आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। जैसे एक राकिनपुरा गांव है, एक सुखन्ना गांव है और एक बनेठी गांव है, इन गांवों के अन्दर टंकियां बन चुकी हैं मगर पाइप लाइन इतनी छोटी है, आगे नहीं जा रही हैं, हरिजन बस्तियों के अन्दर पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और न ही वहां हैण्ड पम्प है। कहने को तो यह कह दिया कि बनेठी गांव में टंकी बनी हुई है मगर उस टंकी का फायदा सिर्फ एक चौथाई हिस्से को ही हो रहा है, बाकी को नहीं हो रहा है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जैसे अभी तिवाड़ीजी ने एक प्रस्ताव रखा था और एक सुझाव दिया था, मेरा भी वह सुझाव है कि पानी आयोग का गठन किया जाय और उस गठन से इस पानी की समस्या, जो राजस्थान में है वह स्थाई रूप से मिट जायेगी। इसी तरह से अगर यह चलता रहा तो यह गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी के मौसम में पानी की पूर्ति यह सरकार कर नहीं पायेगी। आपने अकाल राहत के मद से हमको सात करोड़ रुपये पूरे राजस्थान के हैण्ड पम्पों को ठीक करने के लिए या हैण्ड पम्प लगाने के लिए दिये हैं। यह राशि बहुत कम है। पूरे राजस्थान के लिए सात करोड़ रुपये अकाल राहत के मद से? कम से कम पचास करोड़ रुपये पानी के लिए खर्च करने चाहिए थे। आपके बजट के अन्दर जो आपका बजट था, कम से कम इस बजट के अन्दर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रकम आपको इस पेयजल के अन्दर देनी चाहिए थी। आपने सारे का सारा बजट शिक्षा में दे दिया, दूसरी मदों में दे दिया, दूसरों में भी देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है मगर फिर भी इस पेयजल पर ज्यादा देना चाहिए था और देना ही चाहिए। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय....

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, हमारी पार्टी की जो सूची है उसमें अगर मेरा नाम दर्ज नहीं है तो आखिर में मेरा भी नाम दर्ज कर लें।

श्री सभापति : देख लेते हैं, आपको क्या आवश्यकता पड़ गई।

श्रीमती कमला : मेरे यहां भी पानी की बहुत किल्लत है।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का मेरे क्षेत्र की पानी की समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या के लिए पूरा प्रयास किया, मगर जितना किया वह उपयुक्त नहीं है। जितना करना चाहिए वह अभी कम है। क्योंकि मेरे क्षेत्र में चार लाख पचास हजार रुपये आपने सैंक्शन किये थे, लेकिन ई.एम. परबतसर ने कन्टींजेंसी का जो फण्ड है, वह अभी तक खर्च नहीं किया, वह पैसा वैसा का वैसा ही अभी तक पड़ा है कोई भी काम आज तक नहीं हुआ इस-

(श्री राकेश मेघवाल)

लिए आज भी पानी की भयंकर समस्या है। अब गांव तो आपको गिनवाऊंगा तो गांवों की लिस्ट तो लम्बी है, इसलिए मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करता हूं कि लिस्ट मैं आपको अभी दे दूंगा। क्योंकि अभी घंटी बजेगी, सुबह से घंटी के लिए इन्तजार कर रहे हैं फिर भी बीच में नाम कट हो गया था। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर मुख्य बात पर मेरा विचार व्यक्त करता हूं।

ग्राम भयाखुर्द में मीठे पानी की बेरी है। उस पर एक मामूली मोटर लगाने की वजह से आज पूरा गांव त्राहि-त्राहि कर रहा है। काफी गांवों में कुएं खुदे हुए हैं, उनको खाली गहरा करवाना है। खाली गहरा करवाने से भी पानी की समस्या हल हो सकती है। सरकार का इतना पैसा लगता है, लेकिन उस पैसा का सदुपयोग नहीं होता है। हम लोग वहां मीटिंग में गये थे नागौर में और इस समस्या के बारे में चर्चा की, लेकिन यह बातें मीटिंग तक ही सीमित हो जाती हैं, मीटिंग से बाहर कोई भी अधिकारी उस मीटिंग की बात पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी पुरानी आदत पर काम करने लग जाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं यह गुजारिश करता हूं कि मीटिंग में जो प्रस्ताव पास होते हैं. वह तुरन्त लागू किये जाने चाहिए। काफी गांवों में ट्यूब वैल खुदे हुए हैं, टंकियां बनी हुई हैं, लेकिन पाइप लाइन की कमी से पानी की समस्या हल नहीं हो पायी, क्योंकि कहीं पानी खारा है, गांव के अन्दर ट्यूब वैल अगर खुदवाया गया है तो गांव के अन्दर पाइप लाइन लाने के लिए पाइप नहीं है, इसलिए, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जहां पर टंकियां बनी हुई हैं, पाइप लाइन की वजह से आज गांवों में पानी नहीं है, ट्यूब वैल खुदे हुए हैं, टंकियां बनी हुई हैं, लेकिन एक छोटी-सी पाइप लाइन अगर डाल दी जाये तो समस्या का हल हो सकता है। मेरे क्षेत्र में काफी गांव ऐसे हैं, एक-एक गांव में दो-दो टंकियां बनी हुई हैं, लेकिन पाइप लाइन नहीं है। इसलिये हर जगह यह पाइप लाइन की समस्या है, तो मंत्री महोदय इस पाइप लाइन की समस्या पर पूरा ध्यान दिलाओ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक मुख्य बात, जो पूरे नागौर जिले की बात है, उसके लिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी, यह बात मेरी गौर से सुनिये। नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना लायी जाये। माननीय मंत्री महोदय, आप इस जिले में इन्दिरा गांधी नहर पहुंचा देंगे तो नागौर जिले की जनता यह समझेगी कि नागौर में ना हटाकर आपने इस पर गौर किया है। इसलिये इस बात को आप ध्यान में रखते हुए नागौर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना लाने का आश्वासन दीजिये और

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

इस पर गौर फरमायें। मुझे हमारी सरकार पर पूरा भरोसा है, आप पर भी पूरा भरोसा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी पर भी पूरा भरोसा है। यह पूरे नागौर जिले की समस्या है, इसलिए आप इस पर शीघ्र ध्यान दें।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम

(श्री राकेश मेघवाल)

से, नागौर जिले में जगह-जगह हैण्ड पम्प खुदे हुये हैं, इतने हैण्ड पम्प खुदे हुये हैं, शायद किसी क्षेत्र में भी नहीं होंगे, लेकिन इतने खराब पड़े हुये हैं कि शायद किसी भी क्षेत्र में खराब नहीं होंगे। जगह-जगह खराब पड़े हैं। एक दिन एक गांव में मैं गया था, मेरी मीटिंग हुई थी तो मैने कहा पानी तो पिला दो, इस गांव में पानी की समस्या है क्या? बोले, पानी की कोई समस्या नहीं है, एक हैण्ड पम्प है उस पर 50 की लाइन लगी हुई है, जब तक वह 50 की लाइन खत्म नहीं होगी, तब तक आपको पानी नहीं मिलेगा। लाइन ऐसी लगी कि दो आदमी आपस में लड़ने लग गये। लड़ने से वह हैंडिल हाथ में रह गया, और पम्प अन्दर गिर गया। इसलिये इस बात का भी एक मुख्य मुद्दा है कि हैण्ड पम्प खोदे, लेकिन सभी खराब पड़े हुये हैं, उनकी तरफ आप मुख्य रूप से ध्यान दीजिये, ताकि वह हैंडल अलग नहीं हो और पम्प अन्दर नहीं गिरे। आपने अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं की है, हैण्ड पम्प जगह-जगह खराब हैं, आप एक टीम बनाइये और पूरे क्षेत्र में भिजवाइये कि जहां भी हैण्ड पम्प खराब हैं, उनको तुरन्त ठीक किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

बिना टीम के कोई ठीक नहीं करता है। सभापति महोदया, मैं सुबह 11 बजे से मेरे नाम का इन्तजार कर रहा था, अभी लोग मस्ती से बोल रहे थे, अभी मेरा नम्बर आया तो आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं। समयावधि अगर लागू करें तो सुबह से लागू करें, हमारे लास्ट में समयावधि लागू नहीं की जाये।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से आने वाली भयंकर गर्मी की तरफ और मेरे क्षेत्र को चारों ओर से पहाड़ी इलाके ने घेर रखा है, इतना पहाड़ी इलाका शायद किसी क्षेत्र में नहीं है....

श्री सभापति : आप तो सुझाव दे दो, क्या-क्या चाहिये। सबका नम्बर आ जायेगा।

श्री राकेश मेघवाल : वह सुझाव दे रहा हूं। मैं बात बताऊंगा, उसी के बारे में सुझाव देऊंगा, डायरेक्ट सुझाव मंत्री महोदय नहीं सुनते हैं, इसलिए सुझाव भी देने का कोई तरीका है। सभापति महोदया, पानी ऊपर से बरसता है और पहाड़ पर से पानी गिर कर, जैसे छत से नीचे आ जाता है, वैसे पहाड़ से नीचे आ जाता है और सीधे दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। हम सूखे के सूखे रह जाते हैं, इसलिये हमारे क्षेत्र में उस पानी को रोकने के लिये एनीकट बनाया जाये, ताकि पानी का स्रोत बढ़े। इसलिये सभापति महोदया, इस मुख्य बात पर भी मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने जो समय दिया, हालांकि समय को मद्देनजर रखते हुए, मैं मेरी बात को कम करता हूं, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : आपको भी धन्यवाद।

श्री राकेश मेघवाल : एक बार माननीय मंत्री महोदय का मैं मेरे क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि नागौर जिले के पानी में फ्लोराइड की मात्रा है, उसको कोई योजना बना कर दूर किया जाये और इन्दिरा गांधी नहर लाने की कार्यवाही की

(श्री राकेश मेघवाल)

जाये और नागौर जिले पर गौर किया जाये, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री सुन्दर-लाल जी।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : आदरणीय सभापति महोदया, हमने तीन-चार बार कहा हमारे गांवों में भी ढाणी बालोठ, कलोठड़ा, नहालपुरा, बालोता, कादला, कादला का बास, सहामोई, ताल की मोई, इनमें पानी की भयंकर समस्या है। किसी प्रकार की आज तक इसमें कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये मेरे से पीछे बैठे हुए एम.एल.ए. ने मुझ से कहा आपके और गुलाब-सिंह जी के यहां पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यूं, के बात हुई ? आप दोनों जोर से बोलते हो, जोर से बोलने वाले की पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो इसलिये आहिस्ता तो हमसे नहीं बोला जायेगा और जोर से बोलेंगे तो व्यवस्था पंडितजी करेंगे नहीं, तो मामला चाहे खराब ही हो मैं बोलूंगा जरूर। इसलिये आप यह तो जरूर करो, कि हिसाब से लोगों को पानी की जिन गांवों में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हाथ में तो रह गयो उसके हैण्ड और तला नीचे चला गया, इस तरह का, हमारे तो हैण्ड पम्प ही नहीं लगता, जो हरियाणा बोर्डर पर गहरा पानी है, 70-90 हाथ तले पानी है, तो वहां हैण्ड पम्प कामयाब होते नहीं हैं।

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में चार गांव ऐसे हैं, जिनके पानी हरियाणा से कुओं से मोल आता है, या तो उनके आदमी आप जाकर के, किसी को भी भेज कर देख लो और वह कह देंगे हम पानी मोल लाते हैं। कीमत का मतलब यह है कि तीन-चार रुपये दे दिया, काम करवा ले सारे दिन, चाहे दो दिन काम कर दें, फिर एक महीने पानी चाहे कितना ही वसूल जाओ, वह दे देंगे मजदूर रख लेंगे। यह बात सही है। उसके बाद में कहते हो हमारी सरकार, यां किताब मैंने देखी सवेरे, इतनी स्वच्छ छापी है और पानी की कहीं घूट नहीं बताई, आखिर किताब से पानी नहीं मिलेगा। पानी व्यवस्था करवाने से मिलेगा और पानी की व्यवस्था इस तरह की करो, जिस गांव में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आपको एक बात बताऊं, हरियाणा में गांव में सड़क, उन गांवों में बिजली है, उनके अन्दर सब गांवों में पानी की व्यवस्था हैं और हम वहां से पानी लाते हैं, बड़ी शर्म की बात है। इसलिये आप एक ही बात कह दो कि जिन गांवों में हरियाणा से पानी आता है, उन गांवों में ट्यूबवैल बनाकर पानी की व्यवस्था करेंगे। हमारे यहां तो खारा पानी भी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : एक मिनट सुन्दर-लाल जी। सभापति महोदया, यह तो बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे आदमियों को पानी के पेटे हरियाणा बंधक रख रहा है, इससे ज्यादा तो कोई भी बुरी बात नहीं हो सकती, इसको तो तत्काल बन्द करवाइये।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदया, क्या यह पानी अभी से लाया जाने लगा है, हरियाणा से या बहुत पहले

(श्री नरपत सिंह राजवी)

से लाया जाता है ? यह दर्द पहले भी हो सकता था ।.... (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल : आप चाहते हो ना, नहीं छोड़ो, मैं सक्षम हूं इस बात में, आप यही कहलवाना चाहते हो ना कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था करती तो आज कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं हुई उस वक्त व्यवस्था मगर यह तर्क खराब है आपका कि आपने नहीं किया तो हम भी क्यों करें। कोई यह टीस दिखा रहे हो क्या कि कांग्रेस वालों ने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे, यह बात नहीं है आपकी । नहीं हो सका उस समय । आज यह सरकार है, इस सरकार से हम व्यवस्था चाहते हैं पानी की आप यह मत कहो कि कांग्रेस हाला कोनी कर्‌यो तो कांग्रेस हाला तो कई गांव में कोई काम कोनी कर्‌यो उस वक्त तो वो कोनी होवेगो के, तो उने रगड़ कर मारोगा आज आप, यह क्या व्यवस्था है आपकी । इसलिये हम यह चाहते हैं आप लोगों से....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री सुन्दरलाल : आपने नहीं कहा तो मैं आपका नाम भी नहीं ले रहा हूं । मैं तो आपसे यह आशा करता हूं कि आप व्यवस्था करोगे क्या ? एक गांव, पुरानी मोही में तो किसी प्रकार का कुआ ही नहीं है । दो ग्राम बताये, वहां ट्यूब वैल मन्जूर हो रहा है और आज तक खुदा नहीं है फिर सौली से पानी दिया कुछ दिन हरियाणा से जब कांग्रेस की सरकार थी वह भी बन्द कर दिया । आप चैक करवाओ चीफ इन्जीनियर को भेजो कि तीन साल से पानी निहालपुरा और कलोटडा को मिलता है क्या ? पानी मिलता है तो बताओ और या बात कोनी कि अमृतसर जाकर पंजाब में बेच आऊंगा । पानी तो चाहिये हमको पीने को । यह तो बिकता भी नहीं फिर वह तो हरियाणा से ही राजस्थान में आने पर बिकता है और कोई पानी को पैसे में नहीं देता । इसलिए हमने जिन गांवों का नाम लिया पालोता की स्कीम चार साल से पड़ी हुई है बुहाणा से जोड़ने की, वह अब तक नहीं जुड़ी । इसलिये ज्यादा नहीं कह कर आपके जरिये मैं यह चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के पानी की व्यवस्था करें । धन्यवाद । जयहिन्द ।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी । (अनुपस्थित) । श्रीमती कमला ।

श्रीमती कमला : और कोई रह तो नहीं गये फिर कह दें कि मैंने पहले ले लिया । मैंने यह कहा था कि मेरा लास्ट में रखना क्योंकि आपत्ति हो जाती है । आप समय और मैम्बर्स को दे दें मैं फिर बोल लूंगी ।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं अभी तक किसी भी डिमाण्ड पर नहीं बोला हूं । मैंने इसलिये रिजर्व रखा है कि पानी के बारे में बोलना है मेरे को ।

श्री सभापति : मेरे पास सूची है उसी अनुसार बोल रही हूं । विष्णु जी नहीं थे तो इनका नाम लिया है ।

श्री मोहन लाल मोदी : कृपया यह बता दें कि मेरा नाम है या नहीं है । मैं बैठा रहूं, इन्तजार करूं या चला जाऊं ?

Page No.158

श्री सभापति : अभी मैं देख लेती हूं। डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री बनवारीलाल शर्मा : सभापति जी जो लिस्ट दी थी उसमें मेरा चौथा नम्बर था।

श्री सभापति : आप आकर चले गये होंगे.... (व्यवधान).... नाम सबके हैं, अगर आप अनुपस्थित थे तो आकर चले गये होंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : मेरा नाम कहां है, किस जगह है। एक घण्टे बाद आयेगा, आधा घण्टे बाद आयेगा?

श्री सभापति : अब यह किस जगह है बताने का काम मेरा नहीं है। मेरे सामने सूची है और सूची के अनुसार बोल रही हूं और आपके नेता महोदय की दी हुई सूची है। किस जगह है इसका क्या मतलब है?

श्री मोहन लाल मोदी : जिनका नाम नहीं था वह सदस्य भी बोल कर गये हैं यहां।

श्री सभापति : आपका नाम भिजवा दें तो मैं जांच कर लेती हूं।

श्री मोहन लाल मोदी : मोहन लाल मोदी मेरा नाम है। आप देख लीजिये लिस्ट में।

श्रीमती कमला : अगर नहीं है तो जोड़ दीजिये.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : देखिये अगर एक-एक पूछते रहेंगे तो बोलने वाले बोल नहीं पायेंगे। सबके नाम आ रहे हैं अगर आप अनुपस्थित होंगे तो मैं क्या कर सकती हूं.... (व्यवधान).... मेरे सामने जिस प्रकार की सूची है वही बोलूंगी। कम से कम मुझ पर शक नहीं करें मैं किसी का नाम हेरा-फेरी नहीं करूंगी।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह गुजारिश करूंगा कि पानी की जो विकट समस्या है मैं मेरे क्षेत्र की ही आपको बताऊं, राजस्थान की समस्या से आप तो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। राणा जी ने तो मीरा बाई को विष का प्याला एक ही दिन भेजा था लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे क्षेत्र खेतड़ी के लोगों को विष का प्याला रोज यह सरकार पिला रही है। आप तशरीफ लाइये हुजूर, आपको मैं पानी पिलाऊंगा.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका परिवर्तन हो रहा है क्या मीरा बाई की तरह?

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं तो उसकी डैप्थ बता रहा हूं माननीय सदस्य। सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र की पानी की समस्या हुडको के माध्यम से मन्जूर होने को इस सियासत के अन्दर पड़ी है लेकिन वह सरकारी घूंघट में इस तरह से छिप गई है कि मैं नहीं जानता कि घूंघट के पट कब खुलेंगे। सभापति महोदया, क्या खेतड़ी की जनता उस दूषित पानी को पी-पी कर इसी तरह से परेशान होती रहेगी। मेरी इल्तजा है सरकार से कि उनकी बात सुनें।

महोदया, मेरे क्षेत्र में पानी की दो तरह की समस्या है। एक तरफ दूषित पानी है, स्थिति यह है कि अजीत सागर

(डा. जितेन्द्र सिंह)

बांध है, वहां पर गाय-भैंस, बकरी और मनुष्य सब एक ही घाट पानी पीते हैं। कोई उनके पास सुविधा नहीं है। वह जो बांध का जल है उसको सीधे ही मुंह लगा कर पीते हैं। यह स्थिति है। पानी की जो आज से चार-पांच साल पहले बनी हुई करीबन बीस टंकियां पड़ी थीं और उतने ही करीबन पचास ट्यूब वैल खुदे हुये थे। वह अभी तक उसी हालत में पड़े हुए हैं। कभी यह समाचार आता है कि बीच की कनेक्टिंग पाइप लाइन नहीं है। सभापति महोदया, मैं चन्द पानी की टंकियों के नाम आपको सुनाता हूं तो कृपया मंत्रीजी के माध्यम से उनको अतिशीघ्र शुरू किया जाये। उनके नाम हैं सिहोडा, मेहाडा, गुजरवास, मेहाणा, जाटवास, बेंसरडा, शिमला और दो-तीन ऐसे गांव हैं जहां माननीय सुन्दरलाल जी बता रहे थे उसी तरह से हरियाणा से पानी आता है। बड़े अफसोस की बात है। रावां, माणौता, रसूलपुर, कांकरिया ऐसी पंचायतें हैं जिनकी हालत इस्तमबूल जैसी हो रही है बीच में नदी है और दोनों तरफ की आबादी को काउण्ट नहीं किया जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि कांकरिया और नवरंगपुरा, सुनारी गांवों को जोड़ करें एक योजना बनाई जाये जो आपके मापदण्ड पर हो कि यहां जलदाय योजना बनेगी।

सभापति महोदया, यह हैण्ड पम्प सुधार कार्यक्रम पंचायत समिति और पी. एच.ई.डी. विभाग के बीच में एक अजीब सा जंजाल है। सरकार तय नहीं कर पा रही कि कौन ठीक करेगा। यह सरकार का मामला है, मन्त्री महोदय का मामला है कि यह एक विभाग को समझा दें। बी.डी. ओ. के भरोसे कभी हैण्ड पम्प ठीक नहीं हो पायेंगे। मेरी गुजारिश है कि सिर्फ पी.एच.ई.डी. विभाग ही इसको ठीक कर सकता है। उनके पास एक्सपर्ट्स की टीम है। आप उनको यह निर्देश दीजिये कि हैण्ड पम्प उन्हीं के माध्यम से ठीक हों। नये हैण्ड पम्प तो पता नहीं कब लगेंगे लेकिन जो पुराने हैण्ड पम्प हैं उनके आप ट्यूबवैल बदल दीजिये। बीच में इस तरह का स्टेटा है जिस जगह हैण्डपम्प नहीं खुद सकते। आप के विभाग के पास सिर्फ एक रोटा में या दो रोटा में मशीनें हैं जहां पर नीचे मोल्डर्स आ जाते हैं, वहां मोटर फेल हो जाती है आर्डिनरी मोटर। इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है माननीय मन्त्री जी से कि आपके विभाग में रोटा में एक रोटर मशीन और मंगवाइये और जो इस तरह के क्षेत्र हैं जहां पर मोल्डर्स हैं और जहां कोलेप्स होते हैं, ट्यूब वैल हो जाते हैं वहां पर इनको विशेष तौर से भेजिये....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जहां पर नदी की बैल्ट है वहां पर रोटर मशीनें कार्य करें। मन्त्री महोदय, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एक बार मैं पुनः खेतड़ी की जनता की ओर से आपके दरबार में यह गुजारिश पेश करता हूं कि हुडको की. जो योजना पड़ी हुई है उसको पास करवायें। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझे समय मिलेगा या नहीं मैं इतना ही पूछना चाहता हूं?

श्री सभापति : हां, नाम है आपका ।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : सभापति महोदया, मेरे पानी के बारे में कुछ सुझाव हैं और सुझाव इस बात के हैं कि आखिर हमने बीस साल का क्या कोई मास्टर प्लान बनाया है? बीस साल के बाद आज जैसी स्थिति 10 साल में आयी है । पानी नीचे से नीचे जाता जा रहा है । हर जगह पानी की त्राहि-त्राहि हो रही है क्या सरकार ने इस बात की कोई जानकारी हांसिल कर ली है कि बीस साल में पांच हजार तक की आबादी के गांव का कोई मास्टर प्लान बनाकर पानी किस प्रकार से उनको मुहैया कराया जायेगा ? माननीय सभापति महोदया, यह एक गम्भीर विषय है इस पर चिन्तन किया जाना चाहिये कि आखिर हर साल बरसात बरसती नहीं, पानी पूरा होता नहीं अकाल बिलकुल फिनो मिना हो गया इस प्रान्त का । तो क्या हम बार-बार अकाल के माध्यम से इस प्रकार की चर्चा करते रहेंगे या बीस साल में इस प्रकार की स्कीम बनायेंगे कि यहां पर पानी इतना हो जायेगा । और इसके लिए हम अमुक प्रकार का इन्तजाम करेंगे । यदि यह नहीं हुआ तो, सभापति महोदया, राजस्थान को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ेगा । हमारे पास पेयजल के स्रोतों के रख-रखाव का क्या इन्तजाम है ? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि पेयजल का संकट, आज तो बरसात नहीं हुई, कल भी नहीं हुई, अगले साल भी नहीं हुई तो उसके बारे में हमें किस प्रकार की व्यवस्था पानी को सिंचित करने के लिये करनी पड़ेगी । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो चालीस-चालीस घर के गांव हैं उनमें नहीं है तो टांके बनाये जायं । टांकों से पानी संचय किया जाय और जब अप्रेल-मई-जून के कठिन समय आते हैं तो उन टांकों से पानी जनता को उपलब्ध कराया जाय ।

माननीय सभापति महोदया, पेयजल के बारे में अधिकांश राजस्थान भर में फ्लोराइड का पानी आता है हमारे क्षेत्र में भी फ्लोराइड का काफी पानी आता है । लोग कुबड़े हो जाते हैं उसकी क्या व्यवस्था हमारे पास है ? इसके बारे में कोई एनेलिसिस हमारे पास हुआ है कि जितने पेयजल स्रोत हैं उनमें कहां-कहां फ्लोराइड का पानी आ रहा है । इसके बारे में कोई एनेलिसिस करके क्या कोई व्यवहारिक हल हमने करने की चेष्टा की है ? इसके साथ-साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि एनीकट के काम हमने बन्द कराये हैं उस एनीकट के काम को चालू रखा जाय जिससे जल स्रोत कम से कम कुओं में बढ़े । मेरा यह भी मानना है कि बड़े-बड़े कुएं और गहरे किये गये और कुछ कुएं खोदे गये । इस फेमिन में 124 करोड़ रुपया हमारा मिलता है, केन्द्र और राज्य सरकार से मिला कर क्यों नहीं नेचुरल केलेमिटीज फण्ड का पैसा आधा पानी के लिये हर साल के लिए रखें । कम से कम 60-62 करोड़ रुपया हमको एक्स्ट्रा मिल जायेगा । माननीय सभापति महोदया, मैं जानता हूं इस साल का पानी का कुल मिला कर खर्च इस मद में 474 करोड़ रुपये हैं । 18 करोड़ रुपये हमको कन्टीजेंसी का अकाल राहत से भी मिल जाएगा । कुल मिला करके पांच सौ करोड़ रुपये हो जायेंगे पर इसके बारे में कभी हम प्लान बनाकर यदि नहीं सोचेंगे तो मैं समझता हूं

(श्री शांतिलाल चपलोत)

उस पैसे का सदुपयोग होना मुश्किल हो जायेगा ।

माननीय सभापति महोदया, हमारे इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना मानसी वाकल की आयी थी और 131 करोड़ रु. हिन्दुस्तान जिंक से लेकर मानसी वाकल की योजना को पूरी किया जाना था । पर बड़ा खेद है कि वह योजना अभी तक पूरी नहीं हो पायी। मानसी वाकल की योजना इस मेवाड़ के लिये उदयपुर क्षेत्र के लिये अति आवश्यक है । कई जल स्रोत उसके आ जाने से सारे के सारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का पानी का जो संकट है, पेयजल का जो संकट है वह दूर किया जा सके ।

माननीय सभापति महोदया, इसके साथ-साथ जयसमंद से भी उदयपुर में पानी लाने की एक योजना है । मैं समझता हूं अभी तक उसमें काम पूरा नहीं हुआ या पानी लाने का एक बार भी परीक्षण शायद नहीं किया गया है । माननीय सभापति महोदया, मंत्री महोदय ने कृपा करके 10-12 योजनायें स्वीकार की थीं आज की तारीख में दो साल पहले जिसमें 15-15 लाख रुपये लगाकर काम किये हैं वह जल-स्रोत आज सूख गये हैं । मावली, नासा, नासा में टैंकर से पहले पानी पिलाना पड़ा है । जिस मेवाड़ को हम सरसब्ज समझते हैं वहां पर टैंकर से पानी पिलाना पड़ा है । माननीय शक्तावत साहब जो बल्लभनगर से आते हैं उन्होंने सही बात उठाई है । मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि किस प्रकार का पेयजल संकट है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में । मावली, नासा, खेमली, डबोक, फतेहनगर, गुडली, फलाना कला, फलाना खुर्द, कुण्डिया, हिलुड, मोरठ, लडपचा, कुण्डिया में पानी है । बांध है, किन्तु लोगों को फ्लोराइड का पानी पीना पड़ता है । water water everywhere but not a drop to drink. पानी तो सब जगह है पर पीने का नहीं है । बरसात का पानी चारों तरफ हो जाये और हमें प्यास लग रही हो तो हम बरसात का पानी पी नहीं सकते । पानी तो है लेकिन फ्लोराइड से युक्त है इसलिये लोग कुबड़े हो जाते हैं कुण्डिया की हालत ऐसी है । चारों तरफ पानी है किन्तु फ्लोराइड की वजह से वहां पानी पीना सम्भव नहीं है । माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस बिन्दु पर विचार करें ।

हमारी कुछ योजनाएं – भरताना, साकरिया खेड़ी, मोयना, लदानी इस प्रकार की योजनाएं हैं जो यहां लम्बित हैं पर कई वर्षों से उस पर काम नहीं चल पा रहा है । सभापति महोदया, मेरा एक निवेदन है कि हर पंचायत हैड क्वार्टर को कम से कम नल की स्कीम से, पानी की स्कीम से अवश्य जोड़ा जाना चाहिये । एक-एक पंचायत में 5-5 लाख रुपये भी यदि देना प्रारम्भ किया तो छोटी टी.एस.एस. की योजना ही सही पर पीने के पानी की समस्या उससे हल हो पायेगी । टी.एस.एस. की योजना के बारे में मैंने पूछा तो यह कहा गया कि गांव वाले ही कर सकते हैं । बहुत अच्छी बात है हम वहां लोगों को लगा भी देंगे, पानी के लिये भी कह देंगे पर कम से कम आप हमें धन तो मुहैया करायें कि हम टी. एस. एस. की योजना हर पंचायत तक बना सकें ।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

माननीय सभापति महोदया, जिस तरीके से पानी का स्तर कम होता जा रहा है, राष्ट्रीय स्रोत जितना पानी का है उसका एक प्रतिशत मात्र राजस्थान में है जिसमें पेयजल भी है और सिंचाई का पानी भी है। 100 प्रतिशत पानी जहां सारे हिन्दुस्तान का है उसमें से एक प्रतिशत पानी सारे राजस्थान में है। किस तरीके से हम इस संकट का मुकाबला करेंगे। कैसे पांच करोड़ या चार करोड़ जनता को जिन्दा रखेंगे और आगे आने वाले समय में बीस साल के लिए किस तरीके से हम लोगों को ठीक ढंग से पानी मुहैया करा सकेंगे। इसके बारे में कोई न कोई विशेष प्लान अवश्य बनाया जाना चाहिये। कंटीजेंसी के माध्यम से और कुछ नहीं तो नेचुरल केलेमिटीज का जितना पैसा आता है, आधा तो केवल पानी के संकट में ही बात होती है। जहां जाओ पानी के संकट की ही बात होती है। तो उस 124 करोड़ में यदि हमने 62 करोड़ रुपये भी हमने लिया तो मैं समझता हूं कि हमारा काम काफी हल्का हो सकेगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना): सभापति महोदया, आज पी.एच.ई.डी. के बारे में डिमांड चल रही है, मैं भी अपने आपको उसमें शामिल करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल संकट सारे राजस्थान में है। यह नहीं कहता कि दूसरे जिलों में नहीं है लेकिन हमारी भी बहुत बड़ी समस्या है। सीकर जिला जो फेमिन में डिक्लेयर नहीं हुआ वैसे फेमिन तो था वहां लेकिन किन्हीं कारणों से वहां फेमिन डिक्लेयर नहीं हुआ इसलिए उससे तो हम वंचित रह गये लेकिन पानी की वजह से हम वंचित रहे यह उचित नहीं लगता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने विशेष उल्लेख के अन्दर पानी की समस्या रखी थी और उसका विभाग के द्वारा मेरे को जवाब मिला है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। विभाग ने यह बताया है मेरे यहां 1 हजार 46 हैंड पम्प मेरी पंचायत समिति में हैं। 851 उन्होंने ठीक मंजूर किये हैं कि 851 सही हैं। 160 सूखे हैं और 88 बिलकुल खराब हो गये, बेकार हो गये हैं। अब इन 851 के अन्दर से उनकी मान्यता है कि 367 मरम्मत योग्य पाये गये हैं।

(19.00)

1046 में 851 रहे और उसमें 367 मरम्मत के लायक इनका विभाग मानता है, और 151 में वह कहते हैं कि हमने उनमें मरम्मत कर दी अब मरम्मत कि हालत उनकी ऐसी है कि आपके आदमी जाते हैं चार हैण्डपम्प हैं तो उनमें एक-आध हैण्ड पम्पों को ठीक किया और दो तीन दिन बाद गांव से शिकायत आती है कि वह हैण्डपम्प खराब हो गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किस तरह से इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे? आपने एक गांव को यह दिखा दिया कि इस गांव को हमने पानी की योजना से लाभान्वित कर दिया, अब वह आंशिक कर दिया या किसी भी तरीके से उस गांव की आबादी 6 हजार की है और आपने एक हजार की आबादी के लिए इस कस्बे में

(श्री मोहन लाल मोदी)

पानी का कोई सोर्स कर दिया तो उन एक हजार लोगों को तो पानी मिला और बाकी जो पांच-छह हजार लोग ढाणियों में रहते हैं उनकी आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं, आपने कभी यह सोचा है। शहर के लिए तो बहुत-बड़ी तकलीफ हो रही है आपको, छह-छह सौ करोड़ रुपये लेकर आप लम्बी-लम्बी लाइनें लेकर आते हैं और जहां गांव में, कस्बे में एक-दो किलोमीटर पर पानी की व्यवस्था उस गांव के आदमी को मिलती है और ढाणियों में उस आदमी को पानी नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके बारे में व्यवस्था करिये और आप देखिए कि वह ही ढाणी अगर राजस्व गांव डिक्लेयर हो गया, यानि उन्हीं ढाणियों का मिलाकर एक गांव डिक्लेयर कर दिया आपने तो उसके लिए तो पानी की अलग से व्यवस्था करेंगे लेकिन उन ढाणियों के लिए आपके पास व्यवस्था करने के लिए कोई तरीका नहीं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में पूरी तरह से व्यवस्था करें।

मैं मेरे यहां के बारे में आप से निवेदन करना चाहता हूं, सिरोही मेरे ग्राम पंचायत है उसकी जनसंख्या छह हजार की है और उसके अन्दर गांव में तो आपने टंकी बना दी लेकिन वह ढाणियां जो एक-एक, दो-दो मिलीमीटर पर हैं उनको अगर आप पाइप लाइन दे दें तो उनको पानी मिल सकता है। देखिये, गर्मी का मौसम आ रहा है, आपकी स्कीमें तो धरी रहेंगी लेकिन इस वक्त जल्दी पानी की व्यवस्था हो सके वह काम आपको करना चाहिये। सिरोही में सोर्स हैं, पानी की टंकी बनी हुई है अगर आप पाइप लाइन दे दें तो उन पाइप लाइनों से पानी पहुंच सकता है। टटेरा है मेरे यहां उसकी आधी से ज्यादा आबादी में ज्यादा एस. सी के लोग हैं वहां आपने एक छोटी-सी टंकी बना दी लेकिन आज उन हरिजनों के यहां न तो पाइप लाइन है, उन हैण्ड पम्पों की हालत तो मैंने आपको बता दी आधे से ज्यादा हैण्ड पम्प खराब हैं। आपने तो अपने गांवों को लाभान्वितों में ले लिया लेकिन दो हैण्ड पम्प लगे और दोनों खराब हो गये अब क्या मानेंगे उस गांव को कि वह लाभान्वित में हैं, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं इस वक्त आप ऐसी व्यवस्था कराइये कि लोगों को पीने का पानी मिले। यह राजनैतिक भाषण देने की बात नहीं है, घनश्यामजी ने बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दे दिया कि इतने करोड़ रुपये हमने लगा दिये, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों को पीने का पानी दीजिए और यह सरकार की जिम्मेदारी है, आपने प्रगति विवरण में लिखा भी है कि हम स्वच्छ जल लोगों को सप्लाई करेंगे, तो आपकी क्या योजना है? किस तरह आप देंगे? माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां टंकियां बनी हुई हैं, सोर्स भी हैं लेकिन वह टंकी पाइप लाइन से नहीं जुड़ने के कारण उस गांव में पानी नहीं मिल पा रहा है। यह ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं....

[समय-समाप्ति-सूचक घण्टी]

सभापति महोदया, पानी के बारे में मेरे को बोलना है....

श्री सभापति: पानी सब को चाहिए न।

श्री मोहनलाल मोदी: हां, सब को चाहिए लेकिन मेरे यहां हालत बहुत खराब है। मेरा पहाड़ी एरिया है उसकी वजह से बहुत-बड़ी परेशानी है। एक मावंडा खुर्द मेरे यहां गांव है उसके अन्दर क्या सिस्टम है कि एक दिन खारा पानी और एक दिन मीठा पानी देते हैं, पानी तो वहां मीठा है लेकिन इसका कारण क्या है, कारण यह है कि आठ घण्टे आपको बिजली मिलती है आप उसको 16 घण्टे लें तो उस पूरे गांव को मीठा पानी मिल सकता है। यानि कहीं आपके पास कोई तकलीफ नहीं है लेकिन इसकी व्यवस्था कौन करे ? वहां आपके अधिकारी तो ऐसे बैठे हुए हैं कि उनको कहीं कोई चिन्ता नहीं है कि कहीं कोई शिकायत करे कि हैण्ड पम्प खराब है, न कोई उसकी सुनने की बात है हैण्ड पम्प ठीक करने के बारे में। अभी सीकर में एक मीटिंग हुई थी कलक्टर साहब के सामने, सैक्रेटरी महोदय भी पधारे थे वहां यह कहा गया था कि 31 मार्च तक सारे हैण्ड पम्प ठीक हो जायेंगे। आप ठीक होने की स्थिति देख लीजिये कि जो ठीक हो रहे हैं उनकी भी शिकायतें आ रही हैं और वह न किसी में पाइप डाल रहे हैं न किसी में राड डाल रहे हैं, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो-तीन पाइण्ट ऐसे हैं जिन से आप व्यवस्था कर सकते हैं एक तो इन हैण्ड पम्पों को इस हालत से ठीक कराइये, वहां आप इसकी ड्यूटी लगाइये कि तीन महीने जब तक गर्मी का सीजन रहे कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो तुरन्त उस हैण्ड पम्प को ठीक किया जाये, उसकी पाइप डालना हो, उसकी राड बदलनी हो, यानि इस व्यवस्था से आप पानी ले सकेंगे इस गर्मी में। आगे योजनाएं आप बनाते रहिये लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त तुरन्त पानी की व्यवस्था इस तरीके से हो सकती है। मेरे राजपुरा और धांधेला दो गांव पड़ता है, दो किलोमीटर का फासला है धांधेला में पूरा सोर्स पानी है, पानी वहां बेकार जाता है। आपके यहां राजपुरा तक लाइन डाल रखी है लेकिन बीच-बीच में वह लाइन लिकेज है और पानी पहुंच नहीं पाता इसलिए इतनी संभाल हो कि वह पाइप जो लीकेज है उनको संभाल कर के हम बदल दें तो उस पूरे गांव को पानी मिल सकता है, इतना पानी है। कहीं तो दिक्कत है कि पानी नहीं है और जहां पानी है तो आपकी व्यवस्था नहीं है, तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से मैंने सुझाव दिए हैं इन पर ध्यान दें।

एक आप आर.एस.ई.बी. से बात कीजिए। आपके यहां आर.एस.ई.बी. वाले 90 हजार....

[समय-समाप्ति-सूचक घण्टी]

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सभी को बुलवाना है।

श्री मोहन लाल मोदी: सभापति महोदय, मैं बहुत इम्पोर्टेन्ट बात बता रहा हूं आपको। 90 हजार रुपये का डिमाण्ड नोटिस दे दिया और स्कीम में कहीं कनेक्शन मैं लेना चाहूं तो वह पांच हजार का डिमाण्ड नोटिस आये, लेकिन वह देखते हैं कि पी.एच.ई.डी. का मामला है, यहां तो जितना पैसा लिया जा सकता है उतना

(श्री मोहन लाल मोदी)

पैसा ले लो। आपस में इन विभागों को मिल कर, बात कर के और इस तरह से ठीक करिये । 90 हजार डिमाण्ड नोटिस दे दिया वह जमा नहीं हुआ और वहां पानी नहीं मिल रहा है। स्कीम आपकी एक डेढ लाख रुपये की है उसमें 90 हजार डिमाण्ड में चला जाएगा तो कैसे काम होगा ? तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन विभागों को आपस में एकजुट कर के और आप इस पानी की व्यवस्था में लगाइये जिससे पानी की लोगों को सहूलियत मिले। मेरे यहां पर खेल-कोठे बने हुए हैं, पंचायत समिति में बनाए हैं, 40 खेल कोठे बने हुए हैं, कई जगह तो आपने पानी का सोर्स भी कर दिया लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं ले रहे हैं तो बिजली के कनेक्शन ले कर उन लोगों को पानी मिले यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह दो चीजें करिए, जो हैण्ड पम्प खराब हैं उनको आप दूसरे दीजिए। अभी आपने 12 हैण्ड पम्प जिले में दे दिए, क्या करना चाहते हैं ? फिर आप कैसे, क्यों सरकार में बैठे हैं ? अगर आप से यह पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती है तो आप छोड़ दीजिए, कह दीजिए कि हमारे बस की बात नहीं है। अपने आप ही लोग जायेंगे, चिल्लायेंगे जैसे भी होगा लेकिन आपको यह करना चाहिये चाहे जितना भी बजट में दीजिए, कहां से भी लाइये यह आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को पीने का पानी मिले, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, एक-दो बातें और कहनी हैं- मेरे यहां नगर पालिका में डाइरेक्ट पानी मिलता है, वहां टंकी की व्यवस्था नहीं है। एक ही तो नगर पालिका है उसमें बहुत पुरानी टंकी बनी हुई है, छावणी के अन्दर, मण्डी अलग बसी हुई है, वहां की आबादी ज्यादा है वहां डाइरेक्ट पानी मिलता है और वह डायरेक्ट पानी अगर बिजली आती है, मंत्री महोदय, ध्यान से सुनें इसको...

श्री सभापति : मंत्री महोदय का ध्यान है, आप भी सब का ध्यान रखें तो अच्छा है, सब का नम्बर आना चाहिए।

श्री मोहन लाल मोदी : एक मिनिट में समाप्त कर देता हूं। बिजली आती है उस वक्त तो उनको पानी मिल जाता है और बिजली नहीं आये उस वक्त उनकी क्या हालत होती है ? न तो वह कुए से पानी ले सकता है, आजकल कुओं में न रस्सी है न बाल्टी, कुछ नहीं है इसलिए आप वहां भी एक टंकी की योजना बना कर टंकी की व्यवस्था कराएं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हैण्ड पम्प दें। मेरे यहां तो यह हैण्ड पम्प भी कामयाब हैं। पहाड़ी इलाका है, सही तरीके से आप इनकी व्यवस्था कराएं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन ढाणियों के अन्दर पांच-पांच, चार-चार ढाणियों का एक ब्लॉक बना कर के, जैसे रेवेन्यू विलेज बना दिया उसी तरीके से रेवेन्यू विलेज मानकर ही उनकी व्यवस्था कराएं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बड़ी तकलीफ है मेरे इलाके में और आप इसकी पूरी व्यवस्था करें। धन्यवाद।

(19.10)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगी कि एक साल पहले हमारा जमवा रामगढ़ बांध बिलकुल सूख गया। राज के जमाने से कभी जमवा रामगढ़ बांध कभी सूखा नहीं था लेकिन उसका तला तक दिखायी देने लगा। अभी जब हम यहां पर पानी उपस्थिति के बारे में अनुमान लगाते हैं तो उसमें 65 फीट पानी मानकर लगाते हैं। पिछली बार भी बहुत कम पानी आया। हमने सोचा था 50 फीट तक तो आ जायेगा लेकिन नहीं आया। मेरा निवेदन यह है कि इस बांध के रास्ते में आने वाले अवरोधों को हटाया जाना चाहिए जिससे जयपुर में पानी की जो समस्या है, उसमें जो योगदान जमवा रामगढ़ का बांध कर रहा है, वह पूरा कर सके। मेरा निवेदन है कि कानोता बांध पेयजल योजना के लिए स्वीकृत हुआ उसमें काफी पैसा लगा। जयपुर नगर की बहुत बड़ी समस्या का समाधान कानोता बांध कर सकता था लेकिन उस पर आजकल कोई काम होता दिखायी नहीं देता। योजना फेल हो गयी या योजना अभी आगे हाथ में ली जायेगी ? मंत्री महोदय बतायें।

मेरा निवेदन यह है कि जैसे 1980 में मेरे इलाके में बाढ़ आने से 110 बांध फूटे थे। अब बन्धे का नाम लेते ही सिंचाई का बड़ा बांध नजर आ जाता है लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि तालतलैया या ग्रामीण पोण्डस जो भी हैं अगर हम उनको ठीक करा लेते हैं, मरम्मत करा लेते हैं जिसमें किसी में 40 हजार, 50 हजार और किसी में एक लाख रुपया लगेगा तो वह बांध भर जाने से एक तो पशुओं के लिए पेयजल हमको मिलेगा और एक आसपास के कुओं में पानी रिचार्ज होकर जायेगा। तो पानी की समस्या का समाधान गांवों में बहुत बड़ी हद तक हो सकता है। मन्त्री महोदय स्वयं जिम्मेदारी से और अपने साथियों से मिलकर के इस काम को अपने हाथ में लेकर गांवों की समस्या समाधान के लिए काम करेंगे। मेरा निवेदन है कि हैण्डपम्प जो हमने लगाये हैं उनके रख-रखाव हमने पंचायत समितियों को सौंप दिया है वह उसको पूरा कर पाने में अक्षम हैं। अगर डिपार्टमेंट को ही यह काम दे दिया जाय तो खराब होते ही डिपार्टमेंट हैंड पम्प ठीक करेगा या उसकी जगह दूसरा लगायेगा। इस प्रकार की योजना अगर बनायी जाय तो निश्चित रूप से गांवों को परेशानी नहीं होगी। एक मेरा निवेदन यह है कि जो हैंड पम्प सूख गये हैं, एक कारण यह भी है कि उनके नीचे जल नहीं है तो उनमें पाइप और डालकर उन्हें गहरा कराया जा सकता है और जो हैंड पम्प बिलकुल बेकार हो गये हैं उन हैंड पम्पों को उस जगह से उखाड़ कर लगाया जाकर दूसरी जगह पर स्थापित किया जा सकता है उसका पाइप तो नहीं निकलेगा लेकिन ऊपर का सारा सिस्टम जो है वह दूसरे हैंड पम्प में काम आ सकता है। इस प्रकार भी हमारे यहां का यह जो रख रखाव है इसमें काम लिया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर लगभग-लगभग जो हैंड पम्प लगे हैं वह नीचे से सूख गये हैं, और कुए भी सूख गये है, आसपास में कहीं भी जमवा रामगढ़ का जो इलाका है पंचायत समितियों और झोटवाड़ा पंचायत समिति में पड़ने वाले गांव हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कुए

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सूख गये हैं, हैंड पम्प नीचे से सूख गये। अब स्रोत कहां से आये? कुछ टंकियां, जो 54 टंकियां हमने काम के बदले अनाज योजना में जयपुर जिले में बनायी थी उन टंकियों के नीचे कुए हैं। अगर उनमें थोड़ा पाइप डालकर उन गांवों में सप्लाई किया जाय तो उन टंकियों का उपयोग भी होगा और पानी भी मिल पाये। उन टंकियों से एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे यहां हो सकेगी।

[समय-समाप्ति-सूचक घन्टी]

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में मैंने आपको सुझाव दिया जयपुर नगर में भी कुछ ओवर हैड टैंक उन कुओं पर लगाकर जहां पर पानी की सप्लाई ली जा सकती है हाथ में, ली जानी चाहिये और कच्ची बस्तियों और कृषि भूमि में अब मकान तोड़े नहीं जा सकते, वे कभी न कभी तो बसेंगे ही। उन कृषि भूमि की कालोनीज में भी पानी उपलब्ध कराने का अगर सरकार निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से नागरिकों को सुविधा होगी, पानी मिलेगा और पानी की चोरी रुकेगी। पानी की इस समय चोरी होती है। पानी तो वहां पर है लेकिन पाइप लाइन तोड़कर लोग पानी ले रहे हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं है।

एक मेरा सुझाव यह है कि जो हमारी पुरानी पाइप लाइन हैं वे जंग लगने से जगह जगह से गल गयी हैं, बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में लीकेज है उन पाइप लाइनों का आप सर्वे कराकर बदलवायें और उन गटर की लाइनों को भी जिनमें लीकेज है और जिनमें से पीने के पानी में आकर गंदा पानी मिलता है। इस प्रकार दोनों तरफ की लाइनें अगर आपने चेंज की, लीकेज भी रुकेगा, गंदगी भी रुकेगी और लोगों को स्वच्छ पानी भी मिलेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री भीमसेन चौधरी।

श्रीमती कमला (वैराठ): माननीय सभापति महोदय, मेरा भी नाम था, मैंने अपना नाम वापस ले लिया था।

श्री सभापति: वापस ले लिया।

श्रीमती कमला: नहीं, उस वक्त दो तीन हमारे सदस्यों के लिए मैंने विथड्रा कर लिया था।

श्री सभापति: अच्छा किया। अब तो मैंने इनका नाम ले लिया है।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की कंवरसेन लिफ्ट नहर की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं और इन्दिरा गांधी नहर से डिग्गियों के द्वारा चक-आबादियों को पानी की सप्लाई की जाती है। मैं राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस वर्ष नहर में पानी की कमी के कारण मेरा जो सिंचित क्षेत्र है जहां डिग्गियों से पानी आता वहां पर पीने के पानी की समस्या गर्मी के दिनों में बड़ी गम्भीर होने वाली है। नहरों में 33 दिन से पानी की बारी आती है और जो चक-आबादियां हैं उन आबादियों में जो डिग्गियां बनी हुई हैं उन डिग्गियों में पूरा पानी भरा नहीं जाता इसलिए सरकार को गर्मियों के दिनों में जो समस्या आने

(श्री भीमसेन चौधरी)

वाली है इसकी तरफ अभी से ही सावचेत रहकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। चक-आबादियों में जो डिग्गियां हैं उन डिग्गियों का पूरी तरह से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है इतने वर्षों से। कहीं उनके वाटर चैनल हैं वे टूटे हुए हैं और कहीं डिग्गियां टूटी हुई हैं उनका सुधार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, जो रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं वहां पर नहर से जहां पानी जाता है वहां पर सोर्स वाले गांव के लोगों को तो पानी मिल जाता है लेकिन जो अन्तिम छोर के गांव हैं उन गांवों के सामने हमेशा समस्या बनी रहती है, कर्मचारी अपना पूरा काम नहीं करते और जो पाइप लाइन लगायी हुई है वह पाइप लाइन जमीन के ऊपर हैं, वो जगह-जगह से तोड़ ली जाती हैं या ट्रैफिक की वजह से टूट जाती हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पाइप लाइन जो डाली जाती हैं वह एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर की वह जिम्मेदारी रहे कि पाइप लाइन कम से कम 3 फुट 4 फुट नीचे जमीन में गाड़ी जाय। यह सुव्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बार-बार इस तरह से समस्या पैदा नहीं हो।

इसके अलावा जो रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनमें जहां से पानी जाता है और अन्तिम छोर के जो गांव हैं उनका निरीक्षण किया जाना चाहिये। वहां एक निरीक्षण पुस्तिका रखी जानी चाहिये ताकि जो भी अधिकारी, कर्मचारी मौके पर जायं, दौरे करें तो उन पुस्तिकाओं में दर्ज हो और जो भी वहां के पंच, सरपंच या जो मुखिया लोग हैं वे भी उनका निरीक्षण पुस्तिका में देखकर पानी जहां नहीं आता है उनकी उनमें एन्ट्री कर सके, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारियों पर कुछ कन्ट्रोल होगा।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्कीम्स जहां बनाई जाती हैं, हरिजन बस्तियों में अवश्यमेव वहां पर पानी की व्यवस्था की जाय, सरकार को इसके बारे में निश्चित रूप से पालिसी के रूप में करना चाहिये। दूसरा मेरा, मण्डी खाजूवाला और मण्डी लूणकरणसर दोनों कस्बों के अन्दर पानी की जो व्यवस्था है सुचारू रूप में ठीक नहीं है। रॉ-वाटर नहर का कच्चा पानी सप्लाई किया जाता है जो अनहाइजनिक और अनहेल्दी पानी है इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मैं यह समझता हूं कि जहां भी निरीक्षण पुस्तिका रखकर और एण्ड के गांवों को उनको सुचारू रूप से व्यवस्था कर सकेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा मेरा, नापासर, सिशल ये गांव है जहां वाटर सोर्सेज नीचे जा है, पर्याप्त पानी नहीं है। और कई गांव ऐसे हैं जिनमें हमेशा पानी की कमी रहती है तो कंवरसेन लिफ्ट नहर से इनके

(श्री भीमसेन चौधरी)

लिए पाइप लाइन की स्कीम दीर्घकालीन योजना बनायी जानी चाहिए जिससे कि आने वाले वर्षों में जो समस्या पैदा होगी, उसके लिए हम अभी से व्यवस्था कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सुरेन्द्र गोयल (अनुपस्थित)। माननीय श्री भंवर सिंह जी।

श्री भंवर सिंह (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, पेयजल का संकट इतना गम्भीर है यह तो जो प्रगति विवरणिका दी है, उसमें भी अंकित है। दो तरह की व्यवस्था होनी चाहिये। स्थायी व अस्थाई। पहले मैं निवेदन कर दूं अस्थाई के लिए। मेरे क्षेत्र में आधा संकट तो इस बात का है कि पेयजल के कुओं पर जो बिजली के कनेक्शन दिये हुए हैं वह काश्तकारों के कुओं के साथ में हैं। इस कारण से बिजली विभाग उन कुओं को पूरी बिजली नहीं दे पाता। यद्यपि बिजली विभाग को जलदाय विभाग ने पूरा पैसा जमा करा रखा है तदापि उन्होंने कृषि कनेक्शन देकर यह संकट उत्पन्न किया है। पहला तो यह होना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा बिजली पेयजल कुओं को दी जाये। दूसरा निवेदन है कि वाटर टैंकर की सप्लाई बहुत आवश्यक है। मैंने कलक्टर को भी निवेदन किया था कि यहां पर आवश्यकतानुसार आप वाटर टैंकर बनायें। लेकिन जब मैं वहां से रवाना हुआ और वापस एक दफा गया तब तक यह सप्लाई पूरी नहीं हो रही। स्थायी समाधान है उसके लिये इस विवरणिका में लिखा है कि राजस्थान कैनाल से नागौर में पानी लाने के लिये स्वीडिश के सहयोग से योजना बनायी है। मंत्री महोदय ने मुझे अभी बताया मैं कोशिश करूंगा कि उस टीम से जाकर मिलूं और जाकर के नागौर जिले का केस पूरा रखूं। परन्तु मैं निवेदन करूं इन बाहर के देशों पर निर्भर न रहकर अगर हमें एल. आई. सी. से या अन्य फाइनेन्शियल कारपोरेशन से जो ऋण देती हैं, वहां से पैसा लिया जाये तो वह हमें शीघ्र उपलब्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब से यह जलदाय विभाग बना, हमारी खुद की आदत ख़राब पड़ गयी है। पहले पानी को हम रोकते थे। एक विशेषज्ञ कहते हैं मिस्टर बोहरा, जोधपुर में उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा एवेपोरेशन मिटाने के लिये जो साधन हैं, वह टांके है और मैंने कलक्टर को भी निवेदन किया कि आप टांकों के ऊपर अधिक से अधिक धन खर्च करें। और हमारी पुरानी पद्धति थी कि हर मकान के अन्दर नीचे तहखानों में पानी का टांके बनाते थे और बरसात का पानी हम संग्रह करते थे। वह व्यवस्था खत्म सी हो गयी है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे टांके बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये और कम से कम 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार से दी जाये। जल स्तर ज्यों-ज्यों नीचे जा रहा है उसमें फ्लोराइड है, सरकार भी मानती है इस विवरणिका में लिखा है फ्लोराइड मिट नहीं सकता कितने ही उपाय करके पैसे खर्च करेंगे व्यर्थ जायेंगे,

(श्री भंवरसिंह)

बेकार जायेंगे। मैं तो यही आग्रह करता हूं कि हमारे इलाके में जैसे नदी-नालों से पानी इकट्ठा होता है और लूणी नदी में जो गिरता है, उस पर एनीकट बनाये जाकर उस पानी का संग्रहण किया जाये। इससे आस-पास के गांवों में पेयजल समस्या स्वतः ही कुछ अच्छी हो जायेगी समाप्त की तो मैं नहीं कह सकता, वर्षा पर निर्भर है। यही बताना चाहता हूं। सुझाव के अलावा दूसरा भाषण देने की आदत नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती कमला जी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत डरते हैं कि आप बहुत लम्बे बोलते हो। मैं बहुत संक्षेप में बोलने की चेष्टा करूंगी।

श्री सभापति : करीब-करीब एक घन्टा लग जाता है आपको सदा ही।

श्रीमती कमला : नहीं, वह तो दूसरा वक्त होता है साहब आज थोड़ी ही है। मैं तीन हिस्सों के अन्दर अपनी बात कहूंगी। पहला हिस्सा यह है कि हमें स्थायी हल के लिये क्या करना चाहिये ? दूसरा, यह वर्तमान में जो संकट हमारे प्रदेश में है, उसके लिये हमें क्या करना चाहिये ? और तीसरा मेरे इलाके की जो स्थिति है उसके बारे में बताना चाहूंगी।

सबसे पहला मेरा निवेदन यह है कि हमने बहुत लम्बे समय से इस बात की परवाह नहीं की कि आने वाले वक्त में इस तरह का संकट जल का होगा चाहे वह पीने का हो, चाहे सिंचाई का हो। इसलिए हमने बहुत सारे इम्पोर्टेण्ट जो मुद्दे हाथ में होने चाहिये थे, जिनको उसी वक्त लेना चाहिये था, वह नहीं लिये। सबसे पहले मेरा कहना है कि जल संरक्षण के लिए हमारे स्टेट की किसी भी सरकार ने चाहे वह कांग्रेस की थी, चाहे गैर कांग्रेसी थी। उसने कभी आगे तक की सोच-विचार कर उसकी कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए जल संरक्षण करने के लिए

(19.25)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा अध्यक्ष, पदासीन)

छोटे-छोटे नदी-नाले हैं, उनके ऊपर जितना फ्लो उसके अन्दर आ रहा है, उस फ्लो को दृष्टिगत रखते हुए कितनी जगह पर, कितनी ऊंचाई के कितने एनीकट बनाये जा सकते हैं एक तो इस बात के बारे में हमें ध्यान करना चाहिए और उसकी एक योजना बनानी चाहिये। उसका एक आधारभूत काम मैंने अपने समय में किया था। एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान वाटर रिर्सोसिज आफ राजस्थान, उसको अपडेटिंग करके माननीय मंत्री जी उसे बेसिक आधार मानकर उसे और आप अच्छा, बढ़िया और परफेक्ट बनाकर, उसको आधार मानकर और कहां-कहां पर किस प्रकार से आने वाले समय के लिये हम जल संरक्षण का और जल संरक्षण द्वारा इस समस्या को हल करने का काम कर सकते हैं, वो करना चाहिये। एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमारा जो सिंचाई विभाग है वह मेजर एण्ड

(श्रीमती कमला)

मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लेता है जहां तक मेजर का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जितना पैसा लगाते हैं और जो उसमें पानी आयेगा, उससे जो सिंचाई होगी, उसका जो खर्चा होगा, उसका सब रेशों निकालकर जो काम करते हैं वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें मैं आप से दावे के साथ कह सकती हूं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सिंचाई कम होती है, करोड़ों करोड़ों रुपये का खर्च होता है, उसके बावजूद उसका उपयोग नहीं हो पाता है, और वह आगे तक के पानी का फ्लो रोक देता है। इसलिये मीडियम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से जिनको हम माइनर मानते हैं, उनमें माइनर प्रोजेक्ट्स हमें इरिगेशन में से निकालकर एक भू-संरक्षण, जल संरक्षण विभाग अलग से बनाना चाहिये जिसमें माइनर इरिगेशन वाटर कन्जर्वेशन और फ्लड प्रोटेक्शन, यह सारे काम एक साथ रखकर उस विभाग की संरचना की जानी चाहिये अलग से जो इस सारे काम को देखें। आज हालत यह है कि एनीकट बनाने के लिये न इरिगेशन का जिम्मा है, न हमारे जलदाय विभाग का जिम्मा है, न डी.आर.डी.ए. या और किसी महकमे का जिम्मा है। यह सारा का सारा काम जो इतना इम्पोर्टेन्ट है वह यों ही बिना मालिक के हवाले छोड़ा हुआ है। और उससे हमको काफी कुछ नुकसान हुआ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : डी.आर.डी.ए. का भी है।

श्रीमती कमला : डी. आर. डी. ए. के पास कोई इन्फ्रास्ट्रेक्चर नहीं है, क्योंकि उनका जो माध्यम है, जो नोडल एजेन्सी हैं, वह इरिगेशन है। इरिगेशन वाले फौरन हाथ खींच लेते है कि हमारा यह काम नहीं है। हम तो केवल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और आपको विश्वास नहीं हो तो पता कर लीजिए। क्योंकि अभी जब अकाल के तहत यह आया कि हम एनीकट बनाने का काम करेंगे तो उन्होंने कह दिया यह हमारा काम नहीं हैं। कोई मन्दिर का काम होगा तो करेंगे Anicut is not our business. इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सब तीनों चीजों को मिलाकर एक अलग विभाग बनाया जाये और आने वाले समय तक के लिये जल संरक्षण के एक महत्वपूर्ण काम को पूरी गम्भीरता से लिया जाना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि भू-जल विभाग ने कई वर्षों से और अभी भी कर रहे हैं कि जो भी ग्राउण्ड वाटर जहां पर जिस लेवल तक का जिस तरह का है, उसकी सेमी डिटेल सर्वे और डिटेल सर्वे की हुई है और आज और आप कराते रहिये उसके मुताबिक आप वह पाइण्ट आईडेंटीफाइड है, उनको आप टेकअप करिए और नलकूप लगाकर आप ग्रुप आफ विलेजेज की योजना के साथ में ट्यूबवैल का, वाटर का इन्तजाम करिए। उससे अगर सरप्लस वाटर बहुत आ रहा है तो आप आसपास के गांवों को, किसानों को इरिगेशन के लिए दे दीजिये। लेकिन प्रायोरिटी में आप उस पानी को जलदाय के लिये काम लीजिये। आपके पास सारा बेसिक डाटा तैयार है, सारा आधार

(श्रीमती कमला)

तैयार है, सारी इन्फोर्मेशन तैयार है। लेकिन हमने उसके ऊपर कुछ भी काम करने का कभी सोचा नहीं। इसलिए रीजनल पाइप लाइन कहिए, चाहे ग्रुप आफ विलेजेज की योजनाएं कहिए। आप ट्यूबवैल का एक सिस्टम अपने यहां पर लगाइए। जिससे कि आने वाले समय में जो भयंकर पानी की समस्या उत्पन्न होने वाली है, उसको आप मीट-आउट कर सकें। तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जो आप हैण्डपम्प्स लगा रहे हैं, इन हैण्ड-पम्पों को पहले भी लगाया और आगे भी लगायेंगे। तो इसमें कुछ लोहा खोटा और कुछ लुहार खोटा, दोनों ही काम है। एक तो लगाने वालों ने जिस लापरवाही से और जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से लगाये हैं, न तो पूरी डेप्थ ली, न फाउण्डेशन सही बनाया हैं, न उसको इस हिसाब से बनाया कि लम्बे समय तक काम दे सकेंगे। इसमें बहुत सारे घोटाले भी हुए हैं, जो पहले हाउस में भी आये हैं। आज भी स्थिति यह है कि जो नये हैण्ड पम्प लगाये जाये और सुधारे जा रहे हैं उन हैण्ड पम्पों को इस हिसाब से सुधाराया जाय कि वह दरअसल में आने वाले समय में काम दे सकें। यह नहीं कि वह 15 दिन बाद में यह लगे कि एक बार चला कर छोड़ दिया फिर वह आये-गये हो गये।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि दोनों बातें, तीनों बातें जो इसके परमानेण्ट सोल्युशन की है वह तो हमको करनी है। तीसरी बात यह है कि आप पैसा लाइये, बिना पैसे के यह सब काम कैसे होंगे। आपने खूब सारी बातें सुन ली हैं और उसके बाद आपने नोट भी कर लिया है, जवाब भी दे देंगे लेकिन पैसा आप कहां से ला रहे हैं इसका आप जवाब दीजियेगा। इतनी बड़ी समस्या आ रही है उससे झुझने के लिए कहां-कहां से, किन किन योजनाओं से, किन एजेन्सीज से कितना-कितना पैसा कब तक ले आयेंगे और उसके तहत में आप किस तरह से लोगों को राहत दे पायेंगे इस बात को आप अपने जवाब में जरूर बतायें। अन्यथा इतने सारे सदस्य बोलें हैं और भी बोलेंगे उसका कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि अभी तक तो आप कह ही कह रहे हो कि भई मैं तो सुधरा भी कैसे सकता हूं, मेरे पास पाइप ही नहीं है। तो जब पाइप नहीं होने की स्थिति हो रही है तो फिर आगे क्या स्थिति होगी। इसलिए व्यवस्था करिये और इस व्यवस्था के लिए आप टीम के साथ स्टाफ को लगाइये। एस. ई. के साथ में एक्स. ईएन., ए. ईएन., जे. ईएन. और वहां पर दौरा करें, हम लोगों को भी इतला हो कि फलां वक्त में आपके इलाके में दौरा करेंगे। टीम बना कर आप इनके साथ में जाइये आपको पता लगेगा कि वेस्टर्न राजस्थान और सदर्न राजस्थान चाहे पहाड़ी हो, चाहे रेतीला हो उनकी तो समस्या है ही लेकिन जयपुर जैसे इलाके में भी आज इतनी हाय तोबा मची हुई है कि गांव में जाते हैं तो सिवाय एक पानी के और कोई चीख चिल्लाहट नहीं है। इसलिए आप एक टीम की ड्यूटी लगाइये, उनकी तारीखें तय करिये कि वे इलाके में जाकर के सब बातों को देखें, समस्या का निराकरण करें, आपको फीड बेक करें और उसके मुताबिक प्रस्ताव बना कर आप काम करें।

(श्रीमती कमला)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने अपने इलाके में कितने वर्षों से अलग-अलग तरीके से कहीं सोर्स नहीं है, कहीं पर पाइप लाइन मौहल्लों में डाली हुई नहीं है, कहीं टंकी अधूरी पड़ी, कहीं योजनाएं ही 4-4, 5-5 वर्ष से मन्जूरी के लिए सरकार को गई हुई है। इस तरह की कम से कम 20-30 प्रस्ताव मेरे पिछले कई साल से पड़े हुए हैं और मैं आपको नाम बताना चाहती हूं, क्योंकि उसके बिना शायद उनका महत्व इतना नहीं बनता है। मेरे जाजमकलां की योजना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, भामरुका, इसमें सोर्स और बना रहे हैं, ढाणी गैसकान–टंकी बनी हुई है पाइप नहीं लगी है, जवानपुरा, मैं सारी बातों को नहीं कहूंगी लेकिन यह बागावास चौरासी, झाकड़ी, कुहाड़ा, ढाणी जयसिंहपुरा, सूरजपुरा, लुहाकना कलां, सौढयाणा, निठारा, रामपुरा, अमरपुरा, थानोता, नायन, बिलादपुर, धवली, आमलादा। यह इतनी सारी योजनाएं हैं, इनमें कहीं कुछ समस्याएं हैं, कहीं कुछ समस्याएं हैं और कई वर्षों से हैं। यह नहीं कि अभी की हैं। इसलिए इनकी समस्या के निराकरण के लिए धीरे-धीरे आना–दो आना, कुछ कहीं सरक गये तो सरक गये बाकी पैसा नहीं है। इसलिए वहीं की वहीं पड़ी है और जब गांवों में जाते हैं तो हम भी तसल्ली कर आते हैं। हां, भाई आपके काम करेंगे, हां, भाई लिखा-पढ़ी करी हुई है, हां, भई अफसरों को कहा, मिनिस्टर साहब को भी मैंने एक पूरा पोथा दिया है वह उसमें से कुछ करेंगे। इसमें से भी निकाल कर के जो बहुत जरूरी है वह भी दे दी तो भी उसके अन्दर कुछ नहीं हुआ। इसलिए पैसे के बिना और काम के बिना लोगों की तकलीफ मिटेगी नहीं। इसके अलावा तीन बड़े कस्बे हैं। पहले बैराठ कस्बे के अन्दर सोर्स आफ वाटर सूख गया था, बड़ी हालत खराब हो गयी, बड़ी मुश्किल से उसको बनाया, टंकी नीचे खत्म हो गयी, डेमेज हो गयी, क्रेक होकर गिर गयी। अब उसके लिए और समस्या है कब तक उसका निराकरण होगा। मौहल्लों के अन्दर पाइप लाइन डालने में समस्या हो रही है। डाल दी तो छोटी पाइप लाइन डाल दी पानी आगे तक नहीं पहुंच रहा है। चाहे बैराठ ले ले, चाहे शाहपुरा, चाहे मनोहरपुर ले लें बाबा आदम के जमाने की टंकियां बनी थीं और उसके बाद चौगुनी आबादी हो गयी। आज उसी टंकी से हम पानी देना चाह रहे हैं। मौहल्लों में पानी नहीं पहुंच रहा है लोग चीख-चिल्लाहट करें, नयी-नयी बस्तियां बस गयी हैं उनके अन्दर कहीं पानी का लेना-देना नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी 450 हैण्ड पम्पों की सूची है। 10-10 ढाणियां एक साथ ऐसी हैं, जिनके बीच में एक भी हैण्ड पम्प नहीं है और ऐसे गांव हैं जिनमें पहले हैण्ड पम्प थे आज एक भी हैण्ड पम्प वर्किंग आर्डर में नहीं है और नये हैण्ड पम्प लगाने की सवाल ही नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मैं अगर अलवर रोड गिनाना शुरू करूं चाहे कुहाड़ा आ जाइये, चाहे इस्लामपुर आ जाइये, चाहे माधो का बास आ जाइये, चाहे विराटनगर आ जाइये और चाहे सांगोद की तरफ से गिनाऊं, धवेली

(श्रीमती कमला)

है, आमलादा है, म्हार है, फरमानपुरा है, हनुतपुरा, बिलान्दपुर है, करीरी है, यह सारे के सारे गांवों में यह अगर टीम जायेगी तो इनको पता लगेगा कि दरअसल में हालत कितनी खराब है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इन तमाम समस्याओं का निराकरण पानी लाने के लिए उसकी व्यवस्था करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार चाहे फोरेन एजेन्सी से ले, चाहे भारत सरकार से ले, चाहे कहीं से भी करें लेकिन पानी की समस्या को हल करने के लिए आपको यह कार्यवाही करनी जरूरी है। मैं समझती हूं आप इसकी गम्भीरता के मुताबिक काम करेंगे। अब हमको यूं ही कह कर नहीं टरकायेंगे कि भई अभी-हमने टेण्डर मांगा है, कुछ कर रहे हैं। इस हिसाब से मैं समझती हूं कार्यवाही होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अभी माननीय 32 सदस्यों के नाम और है मैं समझता हूं कि सभी बोले तो अच्छा रहेगा इसलिए आप कृपया समय का थोड़ा ध्यान रखें।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष जी, जब लिस्ट तैयार हुई थी उसमें मेरा नाम पांचवें नम्बर पर था बनवारीलाल बैरवा। पता नहीं, आज सुबह से बैठे हुए हैं। वह लिस्ट ही गायब है, कहां नाम चला गया, क्या हो गया।

श्री अध्यक्ष : देखिये, लिस्ट कोई गायब नहीं हुई है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : कम से कम यह जानकारी तो मिल जाय, अध्यक्ष महोदय, न इस बनवारीलाल का न इस बनवारीलाल का। यह जानकारी तो मिल जाय कि किस-किस का नाम है।

श्री अध्यक्ष : सारी लिस्टें यहां पड़ी हुई हैं। लिस्टें कोई गायब नहीं हुई हैं और आप सबके नाम इसमें है। बात यह है कि जो शुरू में, यह तो लिस्ट मैंने बना दी थी शुरू में जो मेरे पास लिस्ट आयी उसके हिसाब से। पहले वाली लिस्ट में आपका नाम पांचवें नम्बर पर नहीं था। होता तो निश्चित रूप से आ जाता। पांचवां भी हो तो पांचवां का मतलब होता है दसवां यानी यदि आपकी लिस्ट में पांचवां नम्बर है तो आपका नम्बर आयेगा दसवां।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, श्री रिछपालसिंह जी मिर्धा के साथ ही मेरा नाम लिखा हुआ था।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता, आप जरा देखिये, सचेतकों की भी, उनकी भी परेशानी को समझिये। उन पर दबाव पड़ता है, बार-बार दबाव पड़ता है, जो आपने दबाव डाला फिर चिट भेज देते हैं, फिर दबाव डाला फिर चिट भेज देते हैं।

एक माननीय सदस्य : मेरा नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है। इसलिए आप थोड़ा समय का ध्यान रखे।

श्री बनवारीलाल बैरवा : कट मोशन जो देते हैं उनका नाम तो होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने वह लिस्ट अलग बना रखी है। इसमें से जो कट मोशन वाले

Page No.175

(श्री अध्यक्ष)

हैं, कट मोशन की 54 लोगों की लिस्ट मेरे पास है (व्यवधान).... एक मिनट, उसमें जो अब बोल रहे हैं उनको मार्क करता जा रहा हूं और यदि इसमें से कोई बच गये तो उनको और एड कर दूंगा। कट मोशन जिन्होंने दिये हैं उनके नम्बर तो निश्चित आ ही जायेंगे। नाम मैं बराबर जोड़ दूंगा। अधिकांश के नाम तो आ चुके है अगर कोई रह भी गया तो उनका नाम जोड़ देंगे। आप तसल्ली से बैठिये, आराम से। थोड़ा समय का ध्यान रखें कि पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। श्री गोपीराम जाट।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा गया था उस समय आप उपस्थित नहीं थे। इसलिए अब आपका टर्न अंत में मौका मिलेगा तो आ जायेगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैं यहीं था। अब मुझे बोलने के लिए....

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं होगा, देखिये मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब आपका नाम पुकारा गया था आप उपस्थित नहीं थे।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, सुबह से बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं अन्दर बैठा भी सुन रहा था कि आपका नाम पुकारा गया था और आप यहां पर उपस्थित नहीं थे।

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य सचेतक महोदय से पूछा था, उन्होंने कहा था कि एण्ड में नाम है आपका।

श्री अध्यक्ष : But you have lost your chance. यह मेरे भाग्य की बात है। श्री गोपीचन्द गुर्जर।

अब इस लिस्ट में ऊपर नीचे, देखिये इसमें जो नहीं बोलने वाले होंगे उन्हीं का ऊपर नीचे करूंगा, जो अनुपस्थित होंगे अदरवाइज कोई ऊपर नीचे नहीं होगा जो है वही रहेगा श्री गोपीचन्द।

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय खेतसिंह जी और इन्होंने एक एडीशनल लिस्ट और दी है वह भी मैंने सब ले लिये। किसी को बाकी नहीं छोड़ा है। सभी का नाम है। आपका नाम भी पुकारूंगा।

श्री गोपीचन्द : राजस्थान के अन्दर जब पानी के बजट का सवाल आता है तो पूर्वी राजस्थान के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है आज तक। पश्चिमी राजस्थान में मानव और पशुधन दोनों के लिए बजट में पानी का प्रावधान होता है लेकिन पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर के लिए कभी भी पशुधन के लिए बजट में पानी के लिए कहीं कोई स्थान नहीं होता जबकि पिछले 15 साल से भरतपुर जिले की पानी के मामले में जितनी गम्भीर और विकट स्थिति है, मैं नहीं समझता कि पश्चिमी राजस्थान में भी इतनी विकट स्थिति होगी। भरतपुर जिले में पुरानी डेम व्यवस्था समाप्त हो

(श्री गोपीचन्द)

जाने की वजह से पानी इतना नीचे चला गया है और इतना खारा हो गया है, जिस पानी के अभाव की वजह से पूरा जिला आज संकट की स्थिति से गुजर रहा है।

भरतपुर जिले के साथ-साथ मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नगर विधान सभा क्षेत्र में रूपारेल बांध से सीकरी सिस्टम में पानी आता है वहां घाट खूटेडे पर उसकी देहड को ऊंचा कर दिया गया और आज सीकरी सिस्टम में पानी बिलकुल नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे सीकरी सिस्टम को सुधारा जाय और दलालिया नहर के मोरा के ऊपर कम से कम चार बारह इंची के बोर किये जाये। उस बोर के माध्यम से हमारे इलाके में सिंचाई की व्यवस्था करायी जाये। दूसरा, शाकी नहर, कूनी नहर और जितनी भी नहरें हैं, वह सब बिलकुल मिट्टी से बराबर भरी हुई पड़ी हैं। तीसरी गुड़गांवा कैनाल जो हमारे कामां तहसील के अन्दर हरियाणा से चल कर डीग तहसील को क्रोस करती हुई निकलती है, लाखों-करोड़ों रुपये उसके अन्दर अधिकारियों ने घपले में खत्म कर दिये और पिछले 15 साल से नहर के अन्दर काम चल रहा है लेकिन अभी तक वह नहर पूरी नहीं हो पायी। गुड़गांवा कैनाल के लिए इस बजट में भी कई प्रावधान नहीं किया गया है। गड़बड़ घोटाला अधिकारी करें, भ्रष्टाचार अधिकारी करें और उसका खमियाजा कामां तहसील या डीग उपखंड के नागरिकों को, इस बजट में में भी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की प्रक्रिया को लागू करने का तो सरकार का दायित्व है, सिंचाई मंत्री का दायित्व है कि अधिकारियों पर कंट्रोल करें। लेकिन वहां बजट दिया जाये। गुड़गांवा कैनाल को पूरा किया जाये, उसकी वितरिकाओं की व्यवस्था की जाये। भरतपुर जिले में जो पुरानी डेम व्यवस्था थी, पुराने टाइम में इतनी बढ़िया भरतपुर जिले के अन्दर बांध व्यवस्था थी, जब तक भरतपुर जिले की उस व्यवस्था को कायम नही किया जायेगा पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भरतपुर जिले के अन्दर खारे पानी को ठीक करने के लिए तालाब खुदाई का काम चलाया जाये। जब तक प्रत्येक गांव के अन्दर तालाबों की व्यवस्था नहीं होगी, बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक भरतपुर जिले की पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसी तरीके से वैर तहसील के अन्दर किरावली गांव, गोविन्दपुरा गांव में इतना जबरदस्त खार नहरें और गड्ढे हैं, वहां जब तक एनीकट की व्यवस्था नहीं की जायेगी उन गांवों की समस्या का भी समाधान नहीं होगा।

इसी तरीके से पी.एच.ई.डी. के अन्दर भी भरतपुर जिले में इस बार भी सबसे कम बजट दिया गया है जबकि भरतपुर जिला पानी की समस्या से पिछले पांच-दस सालों से कितने गम्भीर संकट से गुजर रहा है। चम्बल से लिफ्ट करके योजनाएं बनाने की चर्चा हो रही है। वह तो पता नहीं कितने समय में जाकर पूरी होगी लेकिन कम से कम कंटीजेंसी के अन्दर क्षेत्र से बजट बनाकर भेजा गया है डिपार्टमेंट के माध्यम

(श्री गोपीचन्द)

से उस पैसे को भी यहां स्वीकृत करके नहीं भेजा है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर की कंटीजेंसी के बजट के बारे में भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नगर कस्बा के लिए 6 लाख 19 हजार का कंटीजेंसी बजट भेजा गया जिसमें से मात्र 1 लाख 60 हजार के बजट को स्वीकृत करके भेजा गया है। गांवों की तरफ से 9 लाख 73 हजार का कंटीजेंसी बजट बनाकर भेजा गया उसमें कोई भी बजट स्वीकृत करके नहीं भेजा है। यदि इसी तरीके से कोई स्कीम स्वीकृत करके नहीं भेजी जायेगी तो हमारी तहसील की बहुत बुरी हालत हो जायेगी। और भरतपुर जिले के अन्दर जितने भी हैंड पम्प लगे हुए हैं, उसमें 80 फीसदी हैंड पम्प खराब पड़े हुए हैं, टूटे हुए पड़े हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं और 50 फीसदी हैण्ड पम्प तो खारे पानी के अन्दर लगाये हैं जबकि जहां पर मीठा पानी हो वहां हैण्ड पम्प लगाये जाने चाहिये, जहां खारे पानी हो वहां नहीं लगाने चाहिये। अधिकारियों और ठेकेदारों ने हैण्ड पम्प के माध्यम से धंधा करने का सिस्टम बना रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शिवनाथ सिंह [अनुपस्थित] श्री पराक्रम सिंह।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, पेयजल समस्या के ऊपर मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अभी से गांवों की ऐसी स्थिति हो गई जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मैं इन सारे नामों का जिक्र तो नहीं करूंगा क्योंकि समय आपने कम दिया है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि जहां हम हैण्ड पम्प के लिए मांग कर रहे हैं, पर अनेक गांव के अन्दर कुए हैं और उन कुओं के अन्दर मीठा पानी है। अगर सरकार दस-दस हजार रुपये भी उन कुओं को गहरा करने के लिए दे तो जिले को पानी तो कम से कम उपलब्ध हो जायेगा। इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी ग्रन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने कितने ही कुवे खोद रखे हैं, लावारिश पड़े हैं। पी.एच.ई.डी. वालों को हम कह कहकर थक गए। उन्होंने न तो इस तरफ कोई ध्यान दिया है। अगर पी.एच.ई.डी. वाले इन कुओं को लेकर पीने का पानी उपलब्ध करा सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव है कि इस विभाग के जो कार्य ठेकेदारों के मार्फत कराये जाते हैं, उसमें काफी देरी होती है, अगर कोई काम ठेकेदारों के मार्फत कराये जाने का जब तय किया जाये तो वह कलक्टर और विधायक की राय से किया जाये। डायरेक्ट पी.एच.ई.डी. उनसे कराने का तय करती है तो उनकी जो स्वीकृत राशि है उसमें से फिफ्टी पर्सेन्ट ही खर्च की जाती है, फिफ्टी पर्सेण्ट उनकी एडजस्टमेंट में चली जाती है। इस चीज को रोकने के लिए, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कलक्टर और विधायक की राय से टेंडर और ठेकेदारी पृथक होनी चाहिये। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शिवनाथ सिंह जी बोल रहे हैं?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): अध्यक्ष

(श्री शिवनाथ सिंह)

महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जहां तक मुझे तारीख याद है 30 दिसम्बर को मीटिंग बुलायी थी। कई जिलों वाले हम आये थे और एक इस प्रकार का इम्प्रेशन दिया गया था कि पानी की सब समस्याएं ठीक हो जायेंगी। इनके बड़े से बड़े अधिकारी यहां आये थे और हम यह समझ कर चल रहे थे कि पानी की कोई समस्या अब नहीं रहेगी। माननीय मंत्रीजी हमारे झुंझुनूं जिले से गये। कई जगह टंकियों का उद्घाटन किया और एक इस प्रकार का आदेश वहां देकर के आये कि एक महीने के अन्दर, यानि दो महीने, तीन महीने से अधिक मियाद नहीं ली सब टंकियों में पानी भर जायेगा। अध्यक्षजी, आज स्थिति यह है कि जो पानी जहां था, जो टंकियां खाली पड़ी थी वह वैसी की वैसी मौजूद हैं। हैण्ड पम्पस को ठीक करने का अभियान आपने चलाया, मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 388 हैंड पम्प थे। उनमें आधे से अधिक खराब हैं। रिपोर्ट उनके पास आती है कि ठीक हो गये लेकिन उनमें से आधे से अधिक खराब हैं। आधे इस प्रकार के हो गये हैं कि जिनको ठीक किया नहीं जा सकता, रीप्लेसमेंट यह कर नहीं सकते और डेढ़ हैंड पम्प आपने मुझे अपनी कांस्टीट्यूएंसी में बड़ी मेहरबानी से दिये हैं। उस आधे का मैं क्या करूं? कहां ले जाऊं? आज स्थिति इस प्रकार की है कि पानी के लिए लोग प्यासे हैं, तरस रहे हैं। मैंने प्रश्नों के द्वारा, माननीय मंत्रीजी को चिट्ठियों के द्वारा और इनके अधिकारियों को कई बार निवेदन कर चुका हूं। रीजनल स्कीम हमारी है। बांगोली की रीजनल स्कीम है। मंत्री महोदय से मैंने पर्सनली मिलकर रिकवेस्ट की, बिल्कुल बन्द पड़ी है। नेवली की रीजनल स्कीम है, बंद पड़ी हुई है और गांवों-गांवों में जो टंकियां हैं, उनमें इनके जो कर्मचारी लगे हुए हैं वह पानी उनमें भरते नहीं। बिजली संकट है लेकिन बिजली के संकट का नाम लेकर उनमें कोई काम नहीं करता है। कर्मचारी वहां रहते नहीं हैं। इस प्रकार की स्थिति पेयजल की आज हमारे जिले में है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति को यदि कायम रखा गया और यही रहा तो अगले आने वाले महीनों में भारी संकट हो जायेगा। हमारे जिले के लिए टंकियों की योजनाएं बनी थीं, उसका पता नहीं कहां क्या हुआ? शीशराम जी ने काफी विस्तार से उसके लिए बता दिया है, मैं उसमें अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी टंकियों की जो योजनाएं स्वीकार हो चुकी हैं, जिनका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, उनका निर्माण कार्य शुरू हो और जिनका निर्माण नजदीक है, उनको कनेक्शन दिये जायें। मैं अपनी कान्स्टीट्यूएंसी के लिए कहता हूं कम से कम साठ-सत्तर गांवों में पानी की टंकियां बनी हुई हैं। पंचायतों ने बनायी हैं। कहीं जे.आर.वाई. में बनी हैं उनमें एक में भी कनेक्शन नहीं हो रहा है।

यदि उनमें कनेक्शन हो जाये तो लोगों का पानी का संकट मिट सकता है। माननीय अध्यक्षजी कहीं पाइप नहीं जा रहे हैं, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है और जो पाइपों की मांग की जा रही है,

(श्री शिवनाथ सिंह)

यहां 30 तारीख की मीटिंग में, बड़े अफसर थे इन्होंने यह इम्प्रेशन दिया था, जहां कहीं मेटेरियल की आवश्यकता हो मुझे कहो और मेटेरियल की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो, तो मुझे दुबारा कहना। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अधिकारियों से कहें कि इस प्रकार का इम्प्रेशन दिया गया था उसमें किसी प्रकार का सुधार आज तक हुआ नहीं है।

मैं दो तीन गांवों की जो रीजनल स्कीमें हैं, जैसे सूपरासराय, हीरापुरा गांव की स्कीमें हैं, जाट झटवाणा बुड़ा की है, इन स्कीमों को दुरुस्त करवाएं। जहां पानी की पाइप आपकी डल चुकी है, टंकियां बन चुकी हैं और टाइम पर पानी नहीं पहुंच रहा है उनको ठीक करवाएं हैंड-पम्पों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा कोई साधन हमारे यहां हो नहीं सकता, इसलिए हैंड पम्पों की भी व्यवस्था आप करवाएं और आपका जो कंटीजेन्सी प्लान है, उसके अन्दर रुपया आप कहते हैं दिया है हमें लेकिन उसमें हमारे पास कोई रुपया पहुंचा नहीं है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे जिले की योजनाएं बनी हैं उनकी पूर्ति करवायें, कनेक्शन दीजिए और टंकी में पानी दिलवाइए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री कन्हैया लाल मीणा।

एक माननीय सदस्यः इधर-उधर के ले रहे हैं (व्यवधान) आज तीनों के तीनों....

श्री अध्यक्षः आज रामस्वरूपजी ने बहुत बड़ा त्याग किया है, अपना नाम कटवा करके।

श्रीमती कमलाः काटो मत साहब, बाद में बुलवाना.... (व्यवधान)....

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पेयजल समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र है, जो डार्क जोन से ग्रसित है, उसमें पेयजल की इतनी विकट समस्या है, हैंड-पम्प खूब लगाए गये हैं लेकिन जितने हैंड पम्प लगाये हैं, उनमें आधे से ज्यादा खराब हुए पड़े हैं पानी उनम आता है तो एक घण्टा या डेढ़ घण्टे का पानी है। अवेण्डन जो 117 हैंड पम्प हो गये हैं या तो उनकी जगह दूसरे हैंड पम्प लगाये जाएं, अन्यथा उनमें डोली की व्यवस्था विभाग की तरफ से करवायी जाकर के दो-दो पाइपों की अगर व्यवस्था करवा दी जाये तो उनमें कुछ पानी की व्यवस्था हो सकती है। जिस प्रकार गांव वालों ने परीक्षण बतौर एक दो हैंड पम्पों में वहां डोली हाथ से लगाकर के और अपने स्तर पर पाइप लगाये और वह हैंड पम्प दो साल से चल रहे हैं। पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से यह जो समस्या आ रही है इसको दूर करने के लिए डोली की व्यवस्था करवाकर के उन हैंड पम्पों को गहरा करवाया जाये या उनके स्थान पर दूसरे हैंड पम्प लगाया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 234 ऐसी ढाणियां हैं जिनके एक मिलीमीटर के आस पास कहीं भी कोई हैंड पम्प की व्यवस्था नहीं है। पानी के जो कुएं हैं वह सूख गए

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

हैं और जिनकी आबादी दो सौ से लेकर चार सो की है उन ढाणियों के अन्दर एक भी हैंड पम्प नहीं है इसलिए हैंड पम्प वहां स्वीकृत करवाए जायें। विधान सभा क्षेत्र में नांगल बोरा, पेड़पुरा, बाबूपुरा और दयालपुरा ऐसे गांव हैं जिनमें हर साल टेंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है और इस साल भी इनमें पानी इतनी विकट समस्या है कि उनको दौसा से जाकर पानी लाना पड़ता है। आज कोई शादी, विवाह जो भी कोई कार्यक्रम हो, तो उनको पानी के लिए दौसा जाकर के टंकियों से पानी लाकर पीते हैं। मेरा निवेदन है कि इन चारों गांवों में कम से कम टेंकर की व्यवस्था शीघ्र करवायी जाये जिससे इन गांव वालों के लिए पानी व्यवस्था हो सके। साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी जो पेयजल स्कीम बनी हुई थी, वह आज से करीबन तीन साल पहले बनाई गई थी, सर्वे कराया गया था लेकिन अब तक वह पेयजल स्कीम विभाग के अन्दर विचाराधीन पड़ी हुई है इसलिए उस पेयजल स्कीम मंजूर की जाकर इन गांवों की स्थायी पानी की व्यवस्था करवायी जाये।

इसके साथ ही हंस महल गांव है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिसमें सात किलोमीटर दूर से पानी आता है, करीब दस-पन्द्रह लाख की स्कीम पाइप लाइन डालकर के जी.एल.आर. बनाकर के दो साल से पड़ी हुई है। वह पेयजल स्कीम नहीं चालू होने की वजह से वहां भी बड़ी विकट समस्या है। मात्र एक जो एनीकट है उसके पास में एक हैंड पम्प तीन गांवों के मध्य चल रहा है न कुओं के अन्दर पानी है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जो हंसमहल की पेयजल स्कीम है उसको चालू करवाया जाये जिससे वहां के आसपास के जो 5-6 गांव हैं वह उससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पड़ासौली, गढ़ लालगढ़, बैनाड़ा, कूंधारा, रूपाहेड़ी, गढ़वासी, भिड़कयावास, धर्मपुरी, सामरिया, कानोता, गड़ौली और मानपुरा की पेयजल स्कीम विभाग के पास तीन साल से स्वीकृति हेतु पड़ी हुई हैं लेकिन आज तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से लोगों को पेयजल के सम्बन्ध में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, बेनाड़ा की पेयजल की जो स्कीम जो....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

टी.ए.एस. स्कीम के तहत चल रही थी, बैनाड़ा में श्रीजी का मन्दिर है वहां पर हर पन्द्रहवें दिन करीब दस हजार आदमी आते हैं और साल में दो बार बड़े मेले लगते हैं। वहां की पेयजल स्कीम विभाग द्वारा हाथ में नहीं लिए जाने के कारण आने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। और वहां पर तीन सौ टेंकर बाहर से मंगवाकर पंचायत द्वारा बड़ी मुश्किल से पानी की व्यवस्था करवायी जाती है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बैनाड़ा की जो पेयजल स्कीम है उसको विभाग में ली जाकर उसके द्वारा संचालित की जाये। साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

की जो समस्या है उसके समाधान के लिए सिंचाई विभाग और जलदाय विभाग दोनों का एक मिला जुला कार्यक्रम किया जाए तो कानोता बांध है जिसका निर्माण कार्य सिंचाई विभाग के द्वारा 86 में किया गया था तबसे लेकर के आज तक कानोता बांध का जो कार्य है अधूरा पड़ा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कानोता बांध का कार्य पूरा हो जाये तो बस्सी की आधी जो पेयजल सम्बन्धी समस्या है, समाधान हो सकता है कुओं में पानी आ सकता है और काफी हद तक संकट हल हो सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई मन्त्री जी को इसके लिए आगाह करें। मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कानोता बांध जो 1986 में स्वीकृत हुआ था, करीब चार करोड़ रुपये सरकार के खर्च हो चुके हैं, लेकिन वह अभी अधूरा पड़ा हुआ है उस और कोई ध्यान नहीं दिया गया है उस ओर ध्यान दें अगर कानोता बांध जो ढूंढ़ नदी पर बन रहा है वह बन जाता है तो जिस प्रकार से रामगढ़ बंधे से जयपुर को पानी मिलता है उसी प्रकार से इस बांध से जयपुर को भी काफी फायदा होने वाला है।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मेरा यह भी आपसे निवेदन है कि इस कानोता बांध को.... (व्यवधान) पूरा करवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामपाल उपाध्याय। (अनुपस्थित) श्री उदयलाल आंजना हैं क्या ? आप बोल लीजिए, उनकी जगह आप बोल लीजिए।....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका फैसला भी होने वाला है क्या, हमको लाभ मिलेगा क्या तब तो आप बोल लें और भंवरलालजी बोल लें, काम निपट जाए।....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : माननीय मदेरणा साहब का नाम नहीं....

श्री परसराम मदेरणा : सचेतक महोदय ने नाम तो मेरा नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय का निर्देश होगा और उनकी अनुमति होगी तो मैं पांच मिनिट के लिए....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, जरूर, जरूर....

श्री परसराम मदेरणा: कुछ सुझाव दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप चाहें तो बीच में बोलिए साहब।

एक माननीय सदस्य : अजी आपको निर्देश देने की जरूरत थोड़ी है हुकुम।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अकाल के वर्ष में सबसे बड़ी समस्या प्रदेश के सामने अगर कोई है तो पेयजल की समस्या है। पेयजल की समस्या के लिए हर रोज, इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा किसी न किसी रूप में प्रश्न उठाये जाते हैं चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे 295 हो, चाहे कट मोशन हो, चाहे ध्यानआकर्षण प्रस्ताव हो लेकिन इसके बावजूद भी सरकार एक कान से इस बात को सुनती है और दूसरे कान से इस बात को निकाल देती है। कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसके लिए मैं श्रीमान् एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र की हुडको कालोनी में जहां करीब एक हजार परिवार

(श्री उदय लाल आंजना)

रहते हैं, तीन वर्ष से वह रह रहे हैं लेकिन आज दिन तक वहां पानी की बहुत ज्यादा विकट समस्या बनी हुई है। इस सम्बन्ध में 5 जनवरी 1995 को जो माननीय मंत्री महोदय ने मीटिंग ली थी उसमें भी मैंने यह जानकारी दी थी। उसके बाद पुनः अतारांकित प्रश्न द्वारा एवं 295 के तहत यह बात उठायी लेकिन अभी भी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, कोई उस समस्या का समाधान नहीं किया गया है।

(20.00)

इससे कालोनी में पेयजल की भारी समस्या सामने आ गई है और टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है सरकार की वहां कोई किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं सोचता हूं कि निश्चित ही इस बार शायद सरकार ध्यान देगी, क्योंकि मंत्री महोदय बड़ी गौर से इस बात को सुन रहे हैं। साथ ही हमारे गांवों में एक कहावत है 'हींग घाटे साग बिगड़ जाये' वही की वही राजस्थान सरकार इस बात को चरितार्थ कर रही है क्योंकि गांवों में सभी जगह लगभग मेरे विधान सभा क्षेत्र में पनघट योजना के तहत करीब-करीब 15 टंकियां बना रखी हैं लेकिन टंकियां बनी हुई हैं, विद्युत कनेक्शन है ट्यूब वैल है लेकिन कहीं 500 फुट, कहीं 200 फुट, कहीं 400 फुट पाइप के अभाव में उनका लाभ गांव वालों को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं सोचता हूं कि उन टंकियों की तरफ निश्चित रूप से ध्यान देकर उनको जल्दी से जल्दी शुरू किया जायेगा, पाइप लाइन को जोड़ा जायेगा। साथ ही कोई व्यक्ति की व्यवस्था वहां नहीं है। पंचायतें अपनी जवाबदारी समझती नहीं हैं और न वाटर वर्क्स का कोई व्यक्ति रहता है। एक व्यक्ति के अभाव में जो लाभ जनता को मिलना चाहिये वह बिलकुल नहीं मिल रहा हैं और सरकार का लाखों रूपया बिलकुल ही बेकार किया हुआ है। इसी तरह से कारूंगा गांव जो निम्बाहेड़ा है उसमें ट्यूब-वैल लगा हुआ है टंकी है और डेढ़ किलो मीटर के एरिया में कोई पानी नहीं है। आज भी अभी एक अप्रैल से पुनः टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई किया जायेगा सरकार ने आदेश दिये हैं तो निश्चित ही अगर पाइप लाइन वहां दी जाये तो जल्दी से जल्दी उस गांव को लाभ मिलेगा। यही स्थिति केमुन्दा गांव की है, बाड़ी गांव की है, ओखलिया की है, लसरावन की है, चरलिया की है, रघुनाथपुरा की है। इसी प्रकार से 15 टंकियां बनी हुई हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही छोटी सादड़ी कस्बे के लिए जो पानी की समस्या है वह बहुत ज्यादा विकट बनी हुई है। पिछले कई बरसों से सिर्फ चार महीने बरसात के समय भले ही बंद रहता है बाकी प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान पत्रिका में न्यूज छपी थी कि 3 करोड़ 40 लाख की योजना वहां मन्जूर हो गई है और बडी मान सरोवर बांध से वहां पानी पहुंचाया जायेगा। तो निश्चित ही इसके लिए तो मैं सरकार की सराहना करता हूं लेकिन साथ ही यह निवेदन करता हूं कि आप तुरन्त से तुरन्त उस कार्य को शुरू कर दें ताकि यह गर्मी तो हम किसी न किसी प्रकार से निकाल देंगे लेकिन अगली गर्मियों में उसका लाभ मिल सके और साथ ही समय पर जल्दी योजना

(श्री उदय लाल आंजना)

होगी तो उसकी लागत और नहीं बढ़ेगी। एक साल और लेट हो गये तो अगली साल तक वह 5 करोड़ पर पहुंच जायेगी और इस सरकार के सामने और हमारे सामने समस्या खड़ी हो जायेगी। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) एक साथ में यह और निवेदन करना चाहता हूं कि हैंड पम्प वगैरह सब खराब हैं। केवल पाइपों के अभाव में काम नहीं हो रहा है। रिपेयरिंग वालों के पास पाइप नहीं है इसलिए काम शुरू नहीं हो रहा है इसलिए पाइप की व्यवस्था आप तुरन्त से तुरन्त शुरू कर दें। साथ ही यह भी निवेदन है कि पंचायत समिति निम्बाहेड़ा और सूरसाडी की सर्वे करा लें और कम से कम एक गांव में एक हैंड पम्प तो आप चालू रखवाने की मेहरबानी करें तो इस अकाल के समय में बड़ी राहत मिलेगी।

साथ ही एक निवेदन और है कि वाटर लेबल, सभी सदस्यों ने अपनी अलग अलग बात कही है ओर वाटर लेबल नीचे जा रहा है इसलिए हर गांव में....

श्री भंवर लाल शर्मा : हैड पम्प ठीक कराने के लिए दो व्यवस्थाएं हैं। एक ग्राम पंचायत है और एक हमारा विभाग है। तो सामान नहीं है यह आपको हमारे विभाग ने कहा या पंचायत ने कहा?

श्री उदय लाल आंजना : दोनों ने ही कहा। पंचायत समिति ने भी कहा और वाटर वर्क्स वाले काम कर रहे हैं वाटर वर्क्स वालों ने कहा कि हमारे पास पाइप की बहुत ज्यादा कमी है इसलिए हम यह सुधार नहीं कर सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा: यह कहा है आपको?

श्री उदय लाल आंजना: हां कहा है। साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हर गांव में छोटे-छोटे तलाइयां और तालाब हैं तो जवाहर रोजगार योजना के तहत वे भी काम तो। मेरे क्षेत्र में अकाल राहत कार्य नहीं हो रहे हैं वे भी शुरू किए जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट, आप बैठिये। धन्यवाद।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, आज पीने के पानी के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है। इसके लिए सबसे पहले मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे आमेर और अचरोल के अन्दर जो योजनाएं स्वीकृत पड़ी हैं। आमेर में 1 करोड़ 60 लाख की और अचरोल में 23 लाख की योजना स्वीकृत शुदा हैं। उनका कार्य अविलम्ब शुरू कराके गांव के लोगों को पीने के पानी की राहत दिलायें। उसी के साथ मेरे क्षेत्र में 4 जी.एल.आर. बन रहे हैं आलोकपुरा, जायसू, रामपुरा और जयरामपुरा में जी.एल.आर. बन रहे हैं उनके पानी के स्रोत इसके साथ ही साथ काम चालू कराके उन टंकियों का उपयोग किया जाये इसके लिए मेरा निवेदन है।

दूसरे जो काम के बदले अनाज योजना में टी० एस० एस० योजनाएं बन्द पड़ी हैं और पूरे जयपुर जिले में इस तरह की 55 टंकियां जिसके लिए पिछले तीन-चार साल से बराबर हम लोग आग्रह करते आ रहे हैं लेकिन उन टंकियों को पानी से भरने की कोई योजना नहीं बनायी गयी तो उन टंकियों को पानी से भरने की व्यवस्था

(श्री गोपीराम जाट)

करायें तो पूरे जिले के अन्दर करीब 55 गांवों में तो पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी के साथ-साथ हाथोज गांव के अन्दर पूरे क्षेत्र ही में जमीन में पत्थर आने के कारण जो लोकल व्यवस्थाएं थीं पीने के पानी की उनमें पानी सूख गया है। इसलिए अलग से योजना बनाकर करीब दस हजार की आबादी का यह क्षेत्र है इसमें पीने के पानी की व्यवस्था करायी जाना अतिआवश्यक है। हैंड पम्पों की रिपेयरिंग का जो अभियान चल रहा है जिस आशा के साथ हमने इसको शुरू किया था उतनी हमें सफलता नहीं मिली। इसमें हैंड पम्पों को ठीक करने के लिए जब जाते हैं तो उसके अन्दर बिना डोली चलाये और बिना गहरा किये उसकी कोई उपयोगिता साबित नहीं हो रही है। इसलिए उसको गहरा करके उसमें एक्स्ट्रा पाइप डालने की आवश्यकता है। इसी तरह से सिरसी एक गांव है जो नगर निगम-क्षेत्र में आ चुका है। वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था पंचायत द्वारा चलायी जाती थी। अब पंचायतें वहां से भंग कर दी गयी हैं और नगर निगम में आ जाने की वजह से कोई व्यवस्था उन पीने के पानी की योजनाओं को चलाने के लिए नहीं है। तो इस तरह की करीब 5-6 पंचायतें जैसे नीदड़ है, हरमाड़ा है माचड़ा है, सिरसी है और उसके साथ सिवार है ऐसी पंचायतें जहां पर पंचायतें नगर निगम में आ गयी हैं पानी की योजनाओं को विभाग द्वारा कोई योजना बनाकर उनको हाथ में लेना होगा वरना वहां पीने के पानी की जो समस्या है वह हम हल नहीं कर पायेंगे। इसी के साथ-साथ 3 योजनाएं विभाग के पास विचाराधीन हैं सेवापुरा, उदयपुरिया और चंदवाजी। नेशनल हाइवे पर चन्दवाजी ऐसा गांव है जहां गर्मी के दिनों में पीने के लिए दो रुपये में एक मटका पानी का मिलता है और मुझे जानकारी मिली है कि वहां की स्कीम तो मन्जूर हो गयी है लेकिन इस आने वाली गर्मी में और पानी की भयंकरता को देखते हुए उस योजना को तुरन्त चालू करवाकर वहां के लोगों को राहत दिलायी जा सकती है। इसी के साथ बेनाड़ एक ऐसा स्थान है जहां पर जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थस्थान है। वहां पानी की स्कीम तो बना दी गयी, ट्यूबवैल भी हो गया, पाइप लाइन भी डल चुकी है लेकिन अब पंचायत के अभाव में और पंचायत में धन का अभाव होने के नाते उस योजना को पिछले दो सालों से चालू नहीं किया गया। अतः मेरा आग्रह है कि उसको विभाग के द्वारा क्योंकि उसमें 5-6 लाख रुपया खर्च हो चुका है तो उस स्कीम को चालू कराके वहां पर जैन धर्मावलम्बियों का भी आना होता है उसके साथ-साथ में गांव में अनुसूचित जाति के लोग भी काफी मात्रा में हैं उन लोगों को भी पीने के पानी की राहत दिलायेंगे। इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल शर्मा।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता प्रकट की है विभाग भी चिन्तित है और मंत्री महोदय भी चिन्तित हैं। बारिश कम होने की वजह से वाटर लेवल नीचे चला गया है उसकी वजह से यह समस्या पैदा हुई है। ऐसी स्थिति में वह तो ठीक है ईश्वर के हाथ की बात है इसमें हम और

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

आप कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन मेरा तो तो आपसे यह निवेदन है कि जब तक आप सरफेस वाटर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे तब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। विशेषकर जहां पर कि सरफेस वाटर लेवल नहीं है वहां पर चाहे आप बांध बनायें, चाहे टैंक बनायें, चाहे तालाब बनायें, कुछ भी बनायें और पानी को रोककर वहां पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास करें पर प्रश्न तो यह उठता है मंत्री महोदय कि जहां पर हो सकता है पानी का लेवल नीचे चला गया है सरफेस वाटर आपको अवेलेबल नहीं है और वहां पर आपके सामने समस्या हो रही है वह तो मैं मानता हूं लेकिन धौलपुर जिले में जहां चम्बल नदी बहती है वहां पानी की कोई कमी नहीं है फिर भी उस जिले में समस्या है और खास तौर से धौलपुर में दो-तीन किलोमीटर पर जहां चम्बल बहती है और वहां पर अगर समस्या है तो यह मैं मानकर चलता हूं कि या तो सरकार ने या विभाग ने इसकी ओर गौर नहीं किया। वास्तव में बात क्या है कि बहुत से कस्बे, बहुत से गांव आपके उसमें कमिशण्ड हैं। धौलपुर की जो योजना बनायी थी। आज से 30 साल पहले बनायी थी। धौलपुर की आबादी उस समय शायद 25–30 हजार थी और आज करीब 25–30 साल हो गये 70–80 हजार की आबादी के करीब पहुंच गयी वही पाइप लाइन है वही पुराना टैंक है। ऐसी स्थिति में जहां पापुलेशन बढ़ रही है.... एरिया बढ़ रहा है तो समस्या निश्चित तौर पर बढ़ रही है। आपने सिटी के आग्मेन्टेशन में कभी पैसा दिया नहीं....

श्री भंवर लाल शर्मा : एक सैकण्ड, यह बतायें कि चम्बल से पानी लाने की योजना बनी थी ? या अलग बनी थी ?

श्री बनवारी लाल शर्मा : धौलपुर की योजना चम्बल से ही है।

श्री भंवर लाल शर्मा : बनी हुई है ?

श्री बनवारी लाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि चम्बल से बनी हुई है लेकिन 30 साल पहले बनी हुई थी। उस समय की पापुलेशन थी, उस समय की जो कैपेसिटी टैंक की कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी थी वह आज बहुत कम पड़ गयी है और इधर पापुलेशन बढ़ गयी है, एरिया बढ गया तो नैचुरल है कि वहां पर प्राब्लम बढ़ रही है। आग्मैण्टेशन में आपने पैसा दिया नहीं है, आग्मैण्टेशन में आप कुछ ध्यान रख नहीं रहे हो। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके सिटी की उसको रिवाइज करके, ज्यादा से ज्यादा पापुलेशन देखते हुए, बढ़ते हुए एरिया को देखते हुए इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें।

इसी प्रकार धौलपुर में बीहड़ हैं, हिली एरिया है या चम्बल के रेवाइंस हैं। उस इलाके में और हिली एरिया में हैण्ड पम्प की ज्यादा समस्या है। अब आपने एक योजना बनाकर भेज दी धौलपुर की जिसमें बूंदी को भी लिया है, सवाई माधोपुर को भी लिया है। और धौलपुर को भी लिया है उस योजना की पता नहीं आज क्या स्थिति है ? इसी प्रकार से धौलपुर और भरतपुर की आपने एक लम्बी योजना बनाकर भेज दी। आपने दो बड़े शहरों या 4–5 जिलों को मिलाकर जो योजना बनायी उसका अमाउण्ट बहुत ज्यादा

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

बढ़ जाता है, बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में वह मंजूर हो नहीं पाती है। खास तौर से धौलपुर की स्कीम, जहां चम्बल से ईजीली आप पानी दे सकते हैं डिपार्टमेण्ट अलग से क्यों नहीं बनाये और वहां के लोगों को राहत दे ?

इसके साथ-साथ हैण्ड पम्प के लिए पापुलेशन का आपका क्राइटेरिया है कि इतनी आबादी पर आप हैण्ड पम्प लगाएंगे। हैण्ड पम्प स्कीम, यह सही है कि इमीजिएट रिलीफ देने के लिए तो ठीक है लेकिन यह परमानेण्ट क्योर नहीं है। जिस समय इसको लगाते हैं उस समय तो लोग प्रसन्न होते हैं लेकिन जब यह खराब हो जाता है तो उससे ज्यादा नाराजगी होती है। जब लगाते हैं तो उससे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है, जितनी खराब होने पर उसकी नाराजगी होती है। खास तौर से हैण्ड पम्प आप लगाते हैं 250 की पापुलेशन पर। अब उन मजरों और ढाणियों का क्या होगा जहां वे रहते तो हैं लेकिन उनकी पापुलेशन उतनी है नहीं ? पानी की आवश्यकता तो उनको भी होती है निवेदन है कि मेहरबानी करके मजरों और ढाणियों को भी इसमें जोड़े।

अगर हैण्ड पम्प लगाते हैं तो सब चीजों को छोड़कर स्कूलों में जहां बच्चे पढ़ते हैं—किसी स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं किसी स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों को बहुत परेशानी आती है, तो स्कूल के बारे में तो आप अपना अलग से विचार बना लें कि जहां-जहां स्कूल हैं वहां पर हम हैण्ड पम्प लगायेंगे।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

धौलपुर जिले में एक हैण्ड पम्प पर करीब 35 हजार का खर्चा पड़ता है। आप कुओं की तरफ क्यों नहीं गौर करते हैं ? आपने कुए ज्यादा से ज्यादा बनवाये तो सोर्स ज्यादा होगा और लोगों को राहत ज्यादा मिलेगी बजाय हैण्ड पम्प के जो बार-बार खराब हो जाते हैं।

इसके अलावा जो रीजनल स्कीम्स हैं, टंकी बन गयी, सारा हो गया लेकिन पाइप की वैसे ही प्राब्लम है। पाइप हैं नहीं और गर्मी का मौसम आ रहा है। मेरा निवेदन है कि धौलपुर विधान सभा क्षेत्र की रीजनल स्कीम्स भंमरोली, कुरेनी, सरानीखेड़ा को आप जल्दी चालू करा सकें तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि विभाग के अधिकारियों को आप ऐसा आदेश दें कि जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी है, एक साल से उन के आश्रित लोग परेशान हो रहे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से यह तो ध्यान रखें। धौलपुर का महमूद पुत्र छुट्टन है, जिसकी 22. 5. 1993 को डैथ हुई। छुट्टन के तीन लड़के थे दो लड़कों की एक साथ डैथ हो गई। एक लड़का रह गया है, वह बुजुर्ग है और उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज्यादा परेशान है। इसी प्रकार से राजेश्वर श्रीवास्तव हैं, उनकी डैथ हो गयी। उनकी पत्नी बहुत परेशान है। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण से उनके आश्रितों को आप नौकरी दिलाएं।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह पुण्य का

(श्री भंवर लाल शर्मा)

काम तो जल्दी से करा लो आप। जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी उनके आश्रितों को नौकरी का काम तो पुण्य का काम है, इसको जल्दी करा लो आप। मुझे बताइये कौन–सा है।

श्री बनवारी लाल शर्मा: मैंने निवेदन किया न अभी।

श्री भंवर लाल शर्मा : नहीं, आप मुझे कागज दे दीजिए।

श्री बनवारी लाल शर्मा : लिखकर दे दूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

इसी प्रकार बरौदा में एक स्कीम है वहां पर कुएं में मोटर लगाकर आपने पानी दे दिया। लेकिन वहां सोर्स नहीं है। मेरा तो इतना निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : उसको पानी भी पिला रहे हैं रोटी भी खिला रहे हैं।

श्री बनवारी लाल शर्मा : बरौदा में सोर्स डवलप करें और वहां पर ज्यादा से ज्यादा राहत दें। माननीय अध्यक्षजी, धन्यवाद, मुझे आपने समय दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री मोती लाल।

श्री मोती लाल (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर तो पानी की समस्या कठिन है ही लेकिन भरतपुर में सबसे ज्यादा रूपवास क्षेत्र की समस्या, इतनी जटिल हो रही है कि रूपवास की जनता प्यासी मर रही है। रूपवास क्षेत्र में से बंध बरौठा और मोरोली स्कीम से पानी भरतपुर लाया जा रहा है। वहां की जनता की यह प्रार्थना है आपसे कि अगर आपने मई के महीने से पहले रूपवास क्षेत्र के लिए पानी का इन्तजाम नहीं किया तो, सारी जनता ने मिलकर प्रण कर लिया है, कि हम फर्स्ट तारीख को भरतपुर का पानी बन्द कर देंगे चाहे हमें पुलिस की गोली खानी पड़े, चाहे गोली से मर जाएं। वह अच्छा है। इसलिए मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि रूपवास तहसील के लिए जल्दी से जल्दी पानी का इन्तजाम कराएं।

मेरे क्षेत्र में 356 बरमे है, टोटल 356 बरमे खराब पड़े हैं, पानी निरन्तर नीचे होने से बरमों में पानी खत्म हो चुका है। एक-दो मीठे बरमे हमारे यहां पड़ौसी गांव में लगे हुए हैं जो भरतपुर तहसील में आते हैं, उनमें 360 मीटर नीचे पानी है। उससे पहले बरमे की स्कीम बेकार है। या तो तीन-चार गांवों के बीच में डीप बोर करा दी जाए जिससे पीने के लिए मीठा पानी मिल जाए। कुछ खारे कुएं हैं उनसे भी लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है, पर डाक्टरों ने मना कर रखा है कि मत पीओ वह पानी। 20–25 गांव ऐसे हैं जिनमें जबरदस्ती पानी पीना पड़ रहा है उनका। खारे पानी से बच्चे अपंग हो रहे हैं। अपनी बात को यहां समाप्त करके आपके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे बोलने का समय दिया। मन्त्री महोदय इस बात का ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी पानी का इन्तजाम कराएं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण डूडी।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पेयजल की मांग संख्या

(श्री रामनारायण डूडी)

27 की बाबत विचार-विमर्श हो रहा है। मैं आपकी मार्फत माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री जी से मेरे क्षेत्र की बाबत और अन्य निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो स्कीमें बनी हुई हैं उनमें अव्यवस्था के कारण हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। जो गांव हैण्डपम्प के अधीन कमीशण्ड थे, पानी नीचे जाने की वजह से उन गांवों के अन्दर पानी की भारी किल्लत पैदा हो गई है, ऐसे बीसियों गांव हैं जो हैण्ड पम्प स्कीम में थे।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, आज हमारे वहां 1000-1100 फीट पर पानी चल रहा है। प्राइवेट काश्तकारों ने 1100 फीट तक बोरिंग करा लिये हैं। ऐसी हालत के अन्दर है जोधपुर जिला और जोधपुर जिले की पंचायत समितियां चाहे वह भोपालगढ़ हो, ओसियां हो, बिलाड़ा हो, लूणी में तो पानी है ही नहीं, आपके पास मंत्री जी बिराजमान हैं। वहां तो जै राम जी की है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार गंगानगर, चूरू और झुंझुनूं की स्कीम बनाकर जर्मन सरकार की सहायता लेकर लिफ्ट कैनाल के द्वारा पानी मुहैया कराया जा रहा है वैसी स्कीम जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप लोगों को बनानी पड़ेगी। आज 1000 1100 फीट नीचे पानी चला गया और आपकी पूर्व की स्कीम 300-400 फीट पर बनी हुई हैं। जो पम्प, मोटर वहां लगी हुई हैं वे भी कम हैड़ की मोटर हैं, उनको भी आपको बदलना पड़ेगा। गांव के ट्रांसफार्मर के साथ जो पी. एच. ई. डी. के ट्रांसफार्मर लगाये हुये हैं उनकी भी अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए आपको समय रहते इन सभी योजनाओं का पुनर्गठन करना पड़ेगा।....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट लेना चाहता हूं।

दूसरा जो मेरा निवेदन है कि आप जोधपुर को जवाई कैनाल के जरिए पानी दे रहे हैं और जवाई कैनाल में जहां से पानी शुरू होता है वह करीब 100 क्यूसेक वहां से रवाना होता है और जोधपुर पहुंचते-पहुंचते वह पानी 20 या 30 क्यूसेक रह जाता है। 50 प्रतिशत पानी की छीजत होती हैं इसका कभी आपने मानीटरिंग करवाया। लोगों ने कैनाल के पास में कुएं खोद रखे हैं, ट्यूब वैल खोद रखे हैं और जो यह सारी अव्यवस्थाएं हो रही हैं यह अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है आपको उनका चैकअप करवाना चाहिये। आज जवाई कैनाल का काश्तकार मर रहा है, उनका कमाण्ड एरिया सूख रहा है और पानी जोधपुर के लिए, उसमें से बीच में चोरियां हो रही है यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपकी दोहरी व्यवस्था है। एक तो आप मीटर से पानी देते हैं और दूसरा आप फ्लेट रेट से पानी देते हैं, उसका किराया वसूल करते हैं पानी का रेवेन्यू लेते हैं तो जो फ्लेट रेट और इस रेट के अन्दर बहुत भारी गड़बड़ चलती है, लोगों को बहुत ही आगे पीछे घूमना पड़ता है अधिकारियों के। तो

(श्री रामनारायण डूडी)

आपको एक नीति अपनानी चाहिये अगर फ्लेट रेट से देते हैं तो फ्लेट रेट से दीजिये और मीटर से देनी है तो मीटर से....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हरिनारायण।

श्री रामनारायण डूडी : एक जहां आपके जी. एल. आर. बने हुये हैं, अध्यक्ष महोदय, जे. आर. वाई. के पैसे से जो पंचायत ने जी. एल. आर. वगैरह बनाये हैं उनको पूरे के पूरे को पाइप लाइन से जोड़े। लाखों करोड़ों रुपये जे. आर. वाई. के लगे हुये हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चौथ का बरवाड़ा हैं उसमें एक टंकी को फूटे हुये करीब 3–4 वर्ष हो गये हैं और उसको हर साल रिपेयर के लिए लाखों रुपये लगा देते हैं लेकिन उसकी रिपेयर नहीं हो रही है और इस बार पानी की वहां पर भारी समस्या है। मैं अधीक्षण अभियन्ता से मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमने नया प्रपोजल तैयार करके भेज दिया है और शीघ्र ही टंकी बनवा देंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उस टंकी के लिए जल्दी से जल्दी स्वीकृति दें। साथ ही बालेठ, बैरावडा कलां और कुरेड़ी में पनघट योजना की टंकियां बनकर के पड़ी हुई है बहुत दिनों से, लेकिन उनमें कनेक्शन नहीं दिये हैं, पाइपों की कमी बताई है इसलिए पाइप भिजवाकर के कनेक्शन दिये जायं। उलतला, बसाऊ कलां और बसाऊ खुर्द की स्वीकृति जो पनघट योजना और नल योजना है उनको चालू करवाया जाय। जितने भी हैण्ड पम्प खराब हैं, ये हैण्ड पम्प सुधारने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि दिनों दिन जल स्तर नीचे जा रहा है इसलिये यदि हैण्ड पम्प एक नया लगाने में 50 हजार रुपये खर्च करते हैं तो 50 हजार वहां के जो कुएं सूखे हैं उसमें लगाये जायं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और स्थायी समस्या का समाधान के लिए चम्बल से लिफ्ट द्वारा पानी जिला सवाई माधोपुर में पहुंचाकर स्थायी समस्या का हल करवाना चाहिये। साथ ही जहां-जहां भी नल योजनाएं हैं वहां पर एक शिकायत मिलती है कि हरिजन बस्तियां है जो अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं उनमें पानी नहीं पहुंचता। मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने भी बताया है कि हरिजन बस्तियों को पानी नही पहुंचता। इसके कारण का पता लगाया जाय कि हरिजन बस्तियों में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 6 मार्च के दिन 9 लोग नाव में बैठकर के चम्बल में से आ रहे थे मध्यप्रदेश के, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो लोग डूबकर मर गये उनकी जो विधवाएं हैं उनको नौकरी दी जाय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

संख्या 27 पेयजल पर लगभग 6 घण्टे से लगातार इस सदन में चर्चा हो रही है। किसी माननीय सदस्य की यह चिन्ता है कि उसके यहां पानी नीचे चला गया है, किसी माननीय सदस्य की यह चिन्ता है कि उसके यहां पानी नहीं है, किसी माननीय सदस्य की यह चिन्ता है कि बरसात होगी तो पानी आयेगा तब मिलेगा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं विभाग की अव्यवस्थाओं के बारे में। जहां सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और विभाग की अव्यवस्था के कारण वहां पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। बैठे हैं नदी किनारे फिर भी प्यासे हैं। यह हमारा हाल है। साइक्लोजी यह रहती है कि गंगानगर नहरों का इलाका है इसलिए मेरा नम्बर भी बहुत बाद में आया। जब बोलने के लिए कहते हैं पेयजल पर तो कहते हैं कि आपके यहां तो समस्या नहीं है लेकिन पानी होते हुये भी समस्या है और वह समस्या ऐसी है कि विभाग की लापरवाही की वजह से, विभाग की अव्यवस्था की वजह से और जो वाटर वर्क्स बने हुये हैं उनका रख-रखाव ठीक नहीं होने की वजह से। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3–3, 4–4 करोड़ रुपये लगाकर के वाटर वर्क्स बनकर तैयार हो, साल भर से वाटर वर्क्स बने पड़े हैं, चैनल बन गई, डिग्गियां बन गई, फिल्टर प्लांट लग गये और आज तक विभाग उसमें पानी डालने में असमर्थ रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि करोड़ों रुपये खर्च हो गये, व्यवस्था हो गई, पानी उपलब्ध है लेकिन विभाग पानी डालने में वहां पिछले तीन साल से असमर्थ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में जितने भी फिल्टर प्लांट लगाये हैं क्या उन्होंने कभी पूछताछ की है कि कितने फिल्टर प्लांट लगे और आज की तारीख में कितने फिल्टर प्लांट चालू है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि 95 प्रतिशत फिल्टर प्लांट बन्द पड़े हैं और लोग गन्दा पानी पी रहे हैं। फिल्टर पर करोड़ों रुपये खर्च हुये हैं वह वेस्टेज गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों की चिन्ता थी। लगभग 90 प्रतिशत माननीय सदस्यों ने हैण्ड पम्पों के बारे में बात की है। हैण्ड पम्पों का पानी खारा है और वहां खारे पानी की स्कीमें आज तक विभाग बनाकर भेज चुका हैं। तीन साल पहले जो स्कीमें बताकर के भेजी गई थी वे स्कीमें ही सरवाइव हो पाई है बाकी सब स्कीमें रद्दी की टोकरी में पड़ी हैं। तो जहां हैण्डपम्प खारे हो चुके हैं, रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है कि गांव को पानी दे दिया गया है लेकिन पानी है नहीं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हैण्ड पम्प लगे हैं उस इलाके को अबेंडड घोषित करके वहां खारे पानी की स्कीमें भेजी जाय ताकि लोगों को पानी मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां वाटर वर्क्स बन गये वहां पानी डालने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेण्ट से विभाग बैठकर बातचीत करे और एक स्टेंडिंग आर्डर होने चाहिये कि जहां वाटर वर्क्स तैयार हो गये हैं उसक स्वत ही पानी मिल जाय। उसकी फाइल जयपुर नहीं आये,

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

जयपुर आने के बाद 6–6 महीने पानी के चैनल लेने में लग जाते हैं तो आउट लैट नहीं मिल रहा है, मोगा नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहां तक कहें, जो चीज है उसकी रख-रखाव और उसकी व्यवस्था तक नहीं हो पाती है। पिछले जून महीने में, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के शासनकाल के दौरान में रेवेन्यू अभियान के दौरान गांवों में मुझे जाने का मौका मिला। मुझे ताज्जुब हुआ सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले गांव जहां एस. डी. एम. साहब भी थे, दूसरे अधिकारी भी थे और जल प्रदाय योजनाओं के अधिकारी भी थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल से डिग्गी बन गई है, चैनल बन गये हैं, डिग्गी पर घास उग आया है लेकिन पानी नहीं गया और आज तक पानी नहीं गया है इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं, चैनल खराब रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, उस चैनल को ठीक नहीं कर पाये। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं इस विभाग में बड़े-बड़े मेजर प्लांट्स की और क्या उम्मीद कर सकते हैं दूसरी स्कीमों की। जहां पानी उपलब्ध है, जहां पानी देना है। करतारसर की डिग्गी आज तीन साल से उसका चैनल टूटा पड़ा है बार-बार माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब भी जिला हैडक्वार्टर पर इसकी मीटिंग होती है तो बड़ी चिन्ता जाहिर की जाती है कि सुविधा होते हुये भी विभाग निष्क्रिय रहा है। माननीय मंत्री महोदय सिवाय सचिवालय के और जयपुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र के....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे ख्याल में पिछले तीन साल और इन चार महीने में भी निर्वाचन क्षेत्र दूसरा नही देखा है, क्योंकि इनको चिन्ता ही नहीं हैं ....(व्यवधान)....

कई माननीय सदस्य : देखे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : देखा हैं तो बता दीजिए कि गंगानगर के कितने प्रोग्राम्स हैं, कितने प्रोग्राम बनाये। आपने देखे हैं बहुत सारे, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिवालय में बैठकर, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को खुश कर के गंगानगर के लोगों को पानी इससे अच्छा नहीं मिल जाएगा। टंकियों में पानी सड़ रहा है, कबूतर गिर रहे हैं, बिल्लियां गिर रही हैं लेकिन विभाग ने कभी भी सफाई कराने का नाम नहीं लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी चिन्ता यह है कि सब संसाधन होते हुए भी, व्यवस्थाएं होते हुए भी, पैसा खर्च होने के बाद भी यदि जनमानस को अच्छा पानी नहीं मिलता है, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो प्लांट आज से 15 साल पहले बन चुके हैं वह आज सरवाइव नहीं हो रहे हैं, ओवर हैड टैंक बन चुके हैं, बन कर तैयार हो चुके हैं 3–3, 4–4 साल से लेकिन उसमें पानी भरा नहीं गया है, इसके क्या रीजन्स हैं? क्या विभाग की जिम्मेवारी नहीं है, क्या विभाग इतना

(श्री हीरालाल इन्दौरा)
पैसा खर्च करने के बाद उनमें पानी डाल कर लोगों को देना नही चाहता, तो अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्थाओं का सवाल है और व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी तो लोगों को पानी मिलेगा। इसलिए गंगानगर जैसे इलाके में जहां नहरों का जाल है, मैं मान सकता हूं कि और भागों में दिक्कत हो सकती हैं लेकिन गंगानगर के क्षेत्र में पांचों तहसीलों में

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नहरों जा जाल है, पानी उपलब्ध है, स्कीम्स है पर वाटर चैनल्स के लिए आदमी नहीं है, 600 लोगों की पोस्टें वेकेंट पड़ी हुई है, वाटर चैनल्स चलाने के लिए इनके पास आदमी नहीं है, किसी आपरेटर को उठाकर दूसरी स्कीम में भेज देते हैं तो फर्स्ट स्कीम बन्द हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं पहले से चालू हो रही है, जो व्यवस्थाएं कर चुके हैं उनके रख-रखाव के बारे में विभाग सोचे।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री हीरालाल इन्दौराः लाखों-करोड़ों रुपये जो खारे पानी के प्लांट हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट में वह खराब पड़े है उस बारे में विभाग को कोई चिन्ता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि विभाग इस ओर ध्यान दे। मेरा सुझाव के तौर पर निवेदन है कि घरेलू कनेक्शन के बारे में जहां दो हजार की आबादी पर घरेलू कनेक्शन की व्यवस्था है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि घरेलू कनेक्शन प्रत्येक गांव में दिये जायं चाहे आबादी कितनी भी हो। उससे आमदनी बढ़ेगी और आखिर जो जल प्रदाय योजनाओं पर खर्चा हो रहा है वह लोगों से आएगा। पब्लिक टैंक का पानी बिना टूंटी के चलता है उससे कीचड़ होता है, पानी वेस्टेज होता है वह नहीं होगा। इसलिए यह जो रेस्टिक्शन है दो हजार की आबादी की उसको हटाकर एक हजार की जाये।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। बैठिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी के बारे में पेयजल समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र फागी पूरी तहसील है और 14 पंचायतें हैं और चाकसू भी उसी में सम्मिलित है। मैं मंत्री महोदय को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि चाकसू तहसील की 14 पंचायतों की योजना आपने जो दिसम्बर माह में बैठक इस सम्बन्ध में बुलाई थी उसमें लिए गये निर्णय के अनुसार सारे कार्य चालू हो गए थे और पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए समस्याएं करीब करीब 50 प्रतिशत तक आपने चालू करवा दी है उसमें कृपाराम-पुरा की टंकी का कार्य है, जिसमें वाटर सोर्स नहीं था वह खुदवा कर पानी वहां पर उपलब्ध हो गया है, खेड़ालदान में आपने पानी पाइप लाइन डालकर सप्लाई चालू कर दी है, निमोरिया के अन्दर पाइप लाइन बिछा दी है। इस प्रकार से मेरे क्षेत्र में चहुंमुखी कार्य चालू है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय कि कार्य को आप थोड़ी गति दे दें, धीमी गति है और गति दे दें

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

तो मेरे क्षेत्र का कार्य सुचारु रूप से हो सकेगा और पेयजल समस्या समाप्त हो सकेगी।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। और कोई रह गया क्या?

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवाः साथ ही दूसरी तहसील है फागी, फागी तहसील में पानी खारा है। खारे पानी की समस्या वहां पर बहुत है। वहां पर लोगों को लगभग एक-एक, दो-दो किलोमीटर से पानी लेकर आना पड़ता है, पानी का कोई और सोर्स नहीं है, क्योंकि हैंड पम्पों से पानी खारा निकलता है, पानी खारा निकलता है इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि उनको ठीक नहीं कराया जाय, किसी तरह से नहीं चलाया जाय, क्योंकि वह खारा पानी जानवर पीते हैं; कपड़े धोने व स्नान के काम में तो आ जाता है लेकिन खारा पानी पी नहीं सकते हैं इसलिए मीठे पानी के लिए सुझाव देना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्षः आपने सरकार को बहुत धन्यवाद दिया है इसलिए मांग करिये आप।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवाः हमारे क्षेत्र में दो नदियां बहती हैं बाण्डी नदी और मासी नदी यहां पर ओपन वैल बनाकर टंकियां बनाई जाकर, पाइप लाइन डालकर पेयजल की व्यवस्था की जाय तो वहां मीठा पानी भी उपलब्ध होगा और एक तरह से समस्या का समाधान होगा। क्षेत्र में जो हैंड पम्प हैं उनको सुचारु रूप से ठीक करवाया जाये, इनकी मानीटरिंग की जाये। एक दफा ठीक करने के बाद दुबारा ठीक नहीं हो सकते हैं उसकी टाइमली देख-रेख की जाये तो यह दिक्कत हमारे यहां नहीं आएगी।

तीसरा, सार्वजनिक कुए, बावड़ी आदि जो भी बने हुए हैं उनके लिए सरकार की तरफ अनुदान राशि दी जाये जिनसे गांव वालों के लिए परमानेन्ट सोर्स आफ वाटर तैयार हो सके और पानी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी पालिसी के अन्दर ढाई सौ व्यक्ति जहां पर निवास करते हैं वहां पर एक हैंड पम्प लगाने की सुविधा है पर मैं इसमें यह एड करना चाहता हूं कि आदमियों के अलावा जहां प्राइमरी या मिडल स्कूल हैं, बच्चे पढ़ते हैं वहां एक हैंड पम्प लगाकर जोड़ दिया जाय, क्योंकि स्कूलों के अन्दर बच्चों को ज्यादा वहां पर पानी की आवश्यकता होती है इसलिए स्कूलों के लिए यह प्रोविजन हटाकर स्कूल में ही हैंड पम्प लगाने की व्यवस्था कर दी जाय।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर अनुसूचित जाति, जन जाति के लोग बसते हैं। गवर्नमेंट चाहे कितने ही कानून बना दे, कितना ही उनको प्रोटेक्शन दे दे, परन्तु वहां पर छुआछूत की परम्परा गांवों में वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इसलिए गांवों में जहां हरिजन बसते हैं उनके लिए अलग से एक हैंड पम्प लगाने की व्यवस्था का प्रावधान किया जाये, चाहे जनसंख्या कितनी ही हो।

गांवों में पी.एच.ई.डी. वाले टैंक बना

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

देते हैं उसमें पानी का सोर्स लगा देते हैं किन्तु बिजली का कनेक्शन नहीं होने की वजह से 1-2-3 साल तक उस टंकी वैसी की वैसी पड़ी रहती है और जो उद्देश्य होता है वह प्राप्त नहीं कर पाते है। इसलिए इस पर भी अंकुश लगाया जाये कि टंकी बनने के बाद एक महीने में या दो महीने में बिजली का कनेक्शन हो जाएगा और पानी की सप्लाई चालू हो जाएगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा(निवाई): माननीय अध्यक्षजी, पिछले सत्र में भी माननीय मंत्रीजी हम लोगों को बुलाकर हमारी समस्याओं से अवगत होना चाहा। हम उनसे उम्मीद भी यही करते थे कि इतने संजीदा आदमी हैं कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी तो समस्या के समाधान की ऐवज में कुछ इजाफा और हो गया है। आज मैंने आपकी किताब के अन्दर पढ़ा था, यह आपके महकमें की किताब है उसमें यह लिखा है कि -" अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ नसीराबाद, केकड़ी व सरवाड़ नगरों को नियमित रूप से पेयजल सुलभ कराने हेतु 153.00 करोड़ रुपये की संवर्धन योजना स्वीकृत की गई है। जिसके अन्तर्गत बनास नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा बीसलपुर ग्राम के पास बनवाये जा रहे बांध से उपरोक्त नगरों को 'पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रभावित है।"

माननीय अध्यक्षजी, जो मूल योजना थी, जिसका उद्घाटन हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने किया था और उसके बाद में उसमें जो संशोधन करके जो कटौती की जा रही है उसके बारे में सुबह भी आपको निवेदन किया था कि पानी लेने से बहुत ज्यादा लाभ होगा भी नहीं। क्योंकि बनास नदी 12 महीने बहने वाली नदी भी नहीं है उसमें तो 6-7 महीने कुल पानी बहता है लेकिन कुछ नदियां आपके पास ऐसी हैं जो 12 महीने बह रही हैं, जिनका पानी बहकर जा रहा है, चम्बल का पानी बह कर जा रहा है, पार्वती का जा रहा है, काली सिंध का जा रहा है उनको कहीं रोकिए। आपने तो उसका सर्वे करवाया है। इसरदा के ऊपर रोकिए, आप उस पानी को रोकने के लिए उसमें बांध बांध कर जयपुर को दीजिए, आस-पड़ौस में और भी इलाकों में आप दीजिए हमें कोई एतराज नहीं है। मगर आप बीसलपुर से ही लेने की बात करेंगे। आपने वहां से मान तो लिया लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इस बात के लिए वहां का किसान वजीद है इस बात के लिए कि हमारा पानी हम नहीं जाने देंगे और इसमें झगड़े की बुनियाद खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि आप दूसरी योजनाओं पर विचार करें व्यवस्था बैठाएं और जयपुर को उससे पानी उपलब्ध करवायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बात अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। निवाई क्षेत्र के अन्दर सन् 1972 में टंकी बनी थी 40,000 लीटर की, उसके बाद दूसरी कोई टंकी वहां पर बनाई नहीं गई है। पिछले दिनों मासी डेम का पानी निवाई के लिए दिया गया लेकिन वह पानी

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

पर्याप्त नहीं था। सन् 1972 के अन्दर 40,000 लीटर की टंकी बनाई गई थी, उस समय वहां 15,000 की आबादी थी, आज वह आबादी बढ़कर 40,000 हो गयी आज वहां पर जरूरत हो गयी इस बात की कि दो लाख लीटर की तीन टंकियां बनें। एक शिवाजी कालोनी में और दूसरी भगत सिंह कालोनी में बनाइये और 60,000 लीटर की टंकी नगर निवाई के अन्दर बनाइये, यह बहुत आवश्यक है और इससे कम में वहां पर कोई काम चलने वाला नहीं है। इसके साथ ही मान्यवर, यह बात कहना चाहता था कि बिडोली बांध से पहले वनस्थली विद्यापीठ को पानी दिया जाता था, बिडोली बांध गत साल टूट गया और उसके कारण उसमें पानी शेष नहीं रहा, उसको बंधवाइये और बंधवाकर आस पास के जो गांव हैं उनकी रीजनल स्कीम बनाकर उनको दिया जाय, पानी नीचे बहुत खारा हो गया। राहौली से लेकर खरेड़ा में पानी की बहुत दिक्कत है और बहुत किल्लत है तो लिहाजा एक तो आप इसको दिखवाइये, दूसरा, बनास नदी के किनारे के जो गांव हैं उनके अन्दर इतना खारा पानी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पीना तो मुश्किल, मुझे तो पिछले दिनों कहने लगे कि हमारे यहां तो शादी-ब्याह का संकट हो गया। लोग कहते हैं, हम तो अपनी लड़की आपके गांव के लोगों को नहीं देंगे और उसका कारण यहां डेढ़ मील से इस नदी में से पानी लेकर आना पड़ता है। मान्यवर, वहां से जो स्कीम बनकर आई है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उन स्कीम्मो को आप मंजूर करवाकर भिजवाइये। मैं टौंक के बारे में एक बात कहना चाहता था, गत वर्ष वहां पर चार टंकियां बनकर तैयार हुई और जब बनकर तैयार हो गई। मैंने पूछा कि ये टंकी बन तो गयी, फिर ये तुर-तुर पानी आ रहा है, सब जगहों पर पानी की बहुत परेशानी है, माजरा क्या है, उससे पानी सप्लाई नहीं हो रहा है क्या? बताया गया कि वहां पर जो पाइप डाली गयी है, ज्योंही उसमें पानी छोड़ते हैं वे पाइप टूट जाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। आप मालूम करवा लें इस बात को, भगवान करें, यह बात गलत हो और ये पाइप सही साबित हो जाये लेकिन एक्चुअली बात है कि वे पाइप सही साबित नहीं हो रहे हैं। मुझे बताया गया कि वे तो रिजेक्टेड पाइप थे जो दे दिये गये और उनको डाल दिया गया। जब उनमें पानी छोड़ते हैं तो वे टूट जाते है, यह बहुत बड़ी समस्या

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

है, उस समस्या का आप निदान करें। मैं मुख्य मन्त्री जी को....

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्रीमती मीना अग्रवाल। तीन मिनट मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः हां, एक बात कह दीजिये आप। मुख्य मन्त्री जी को नहीं, मंत्रीजी को कहिये। (व्यवधान) बैठिये बैठिये। एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा :.... आपका

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

ध्यान हरिजनों की जो समस्या है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। वैसे तो व्यवस्था है इस देश की इसके लिए तो हम क्या करें, किसको हम कहें, लेकिन कुछ लोग दूसरों के सिर पर मैला ढुलवाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मान्यवर, वैसे तो यह बहुत घृणित काम है कि कोई दूसरे का मैला अपने सिर पर आदमी खुद ढोये, यह तो उसके लिए बहुत दुखद बात है लेकिन जो ढुलवाते हैं उनके लिए भी पाप की बात है मुख्य मन्त्री जी ने कहा था, अब की बार कुछ ऐसी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि जो पाखाने हैं उसकी जगह सैफ्टी टैंक या फ्लश की व्यवस्था करें। मैं उसके लिए लिए कुछ सुझाव देता हूं कि निवाई और टौंक दोनों ऐसे कस्बे हैं, वहां पर बहुत गन्दगी है और वह इसी कारण है। अगर सीवरेज हो तो हम गंदगी से मुक्ति पा जाय वरना तो इससे बहुत परेशानी रहेगी मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अलवर की जनता मंत्रीजी को धन्यवाद देती है कि अलवर में एस.ई. आफिस इन्होंने कुछ दिन पहले ही खोला है। मैं उम्मीद करती हूं कि अलवर की महिलाओं को इस गर्मी में मटके फोड़ने की नौबत नहीं आयेगी कुछ साल पहले अलवर में नासीपुर गांव है, वहां पर वाटर वर्क्स वालों ने सर्वे किया था कि वहां पर पानी काफी है, मगर नासीपुर में ट्यूब वैल अभी तक लगा नहीं है जबकि तीन ट्यूब वैल की मशीन के लिए पैसा भी जमा करा दिया गया है, वह मशीन अभी तक गांव में नहीं भेजी गई है तो मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगी कि वह मशीन जल्दी से जल्दी गांव में भिजवायें।

दूसरा, मैंने 30 ट्यूब वैल और 65 हैण्ड पम्पों की पाइप लाइन के लिए इनको दिसम्बर, 1993 में लिस्ट दी हुई है उनको जल्दी से जल्दी मंजूर करवा दें।

तीसरी बात यह कहना चाहूंगी कि हमारे अलवर में नगर परिषद के जरिये पब्लिक नल लगे हुए थे, चूंकि यह मंत्रीजी से सम्बन्धित है, पब्लिक नल को नगर परिषद ने कटवा दिया है। हर मौहल्ले में लगे हुए थे। कटवाने के बाद वहां पर जनता में रोष पैदा हो गया तो नगर परिषद को मंत्रीजी कहें कि वे नल वापस लगाये जायं, नगर परिषद का यह कहना था कि ये नल इसलिए कटवाये गये कि पानी नहीं आता था, बिल आता है। इसलिए उन्होंने नल कटवा दिये तो इनसे मैं निवेदन करूंगी कि वे नल जल्दी से जल्दी लगवा दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अमरा राम।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के "राजस्थान पत्रिका" में प्रथम पेज पर आया है कि "बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्मी है" और इस गर्मी के कारण लोगों को जब पीने का पानी नहीं मिलता है तो यह कितनी भयंकर समस्या है। वैसे एक समय था, इस वीरान रेगिस्तान में, इस अथाह रेगिस्तान में....

श्री अध्यक्ष : जल्दी-जल्दी बोलिये

(श्री अध्यक्ष)

वरना चार वाक्य बोल पायेंगे आप । टाइम खत्म हो जायेगा । 5 मिनट का टाइम है ।

श्री अमराराम चौधरी : जहां पर दो प्रेमी है, अपने क्षेत्र में थोंपी-थोंपी करते अपने प्राणों को त्याग दिया "जल थोड़ो मे घणो लाग्या प्रीत रा बाण, थोंपी-थोंपी करतां तज्या दोनूं प्राण" ऐसे पिछड़े रेगिस्तान में हमारी पूर्व की सरकारों ने हिमालय का पानी मोहनगढ़ तक लाये और अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस इन्दिरा गांधी नहर का पानी बालोतरा तक लाने की कृपा करें । बालोतरा में लूणी नदी जरूर है और लूणी नदी के कारण हमारे बिटूजा के अन्दर ट्यूब वैल हैं और आप पचपदरा से बूस्ट करके हमारे गांवों में आप पानी भेजते हैं लेकिन पचपदरा के अन्दर ऐसी व्यवस्था है कि एक-एक बूंद पानी के लिए जनता तरस रही है, वहां पानी का तालाब भरा हुआ है । यह मैं 4-5 साल से देख रहा हूं कि जितने हौज बने हुए हैं, वे हौज ओवरफ्लो हो जाते हैं । यहां बिजली बन्द हो जाती है, बिटूजा में बिजली बन्द होती नहीं है, जिसके लिए टेलीफोन से व्यवस्था नहीं कर सकते । आज 4-5 सालों से लाखों रुपयों का पानी, एक गैलन पानी की साढ़े चार रुपया कोस्ट आती है तो कितने ही हजारों गैलन पानी हमारी जमीन में ढुल रहा है जो घी से भी महंगा पानी है । यह की यह हालत उण्डु कुंपलिया लाइन की है, हीरा की ढाणी में, वहां महीने में 10 हजार गैलन पानी जमीन में बिखरता है, हमारे कुम्पलिया के अन्दर जब आपने 4.1.94 को मीटिंग ली, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक्स.ईएन. को निर्देश दिये कि मेरे साथ चले । कुम्पलिया के अन्दर 10 सालों से पानी नहीं जा रहा था....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां 8 दिन से लगातार होज भरा गया । पानी तो पहुंच सकता है, व्यवस्था की कमी है और मैंने मीटिंग के अन्दर यह भी निवेदन किया था, जो जनरेटर लगे हुए थे हमारे रोडवां कलां में, ओजनवीरा पर, दूदवा के आगे खट्टू पानी पहुंचाने के लिए जनरेटर लगे हुए थे, उनको हटा दिया गया । उन जनरेटर को लगाने के लिए मीटिंग में निर्देश दिये थे, आपने आश्वासन दिया था, वह आश्वासन आपके विभाग ने पूरा नहीं किया । इस भयंकर अकाल के अन्दर जहां पानी होते हुए भी हम प्यासे हैं, पानी जमीन में ढुल रहा है, इसके लिए आप व्यवस्था करावें । मेरा बालोतरा शहर जहां 20,000 की जनसंख्या थी पहले, उसमें जो पाइप लाइन लगी हुई है और अब 60,000 की या 50,000 की आबादी हो चुकी है बालोतरा की, उन पाइप लाइनों का पुनर्गठन कराना बहुत ही जरूरी हो गया है । एक ओवर हैड टैंक बना हुआ है जिससे 20,000 लोगों को पानी मिलता था, आज हमारी 60,000 की जनसंख्या हो गयी उसके लिए हमने एक योजना तैयार करवायी है और आपके यहां भेजी होगी । इसके ओवर हैड टैंक और पाइप लाइन का आप पुनर्गठन करेंगे तो शहर में जो चार दिन से पानी मिल रहा है, लोगों को रात के एक बजे पानी मिलता है, पानी होते हुए भी भयंकर समस्या बनी हुई है उससे राहत मिलेगी । इसको आप पूरा करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर ।

श्री अमराराम चौधरी : दूसरी जो स्कीम है खड़तू के लिए, सिलानाडी के लिए, मूल की ढाणी के लिए, तरणी के लिए जो टेल के गांव हैं उनके लिए भी दो स्कीम आपके पास आयी होंगी, उनको भी आप स्वीकृत करायें । इसके अलावा सरूरी दायमों की ढाणी, बाट का बाड़ा में पानी नहीं जा रहा है । जो स्कीम बनती है, पानी हमारे यहां रूणी नदी के पास बहुत है । इन योजनाओं को आप जल्दी स्वीकृत करायें ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल पर आज यहां चर्चा हो रही है । मैं भी अपने क्षेत्र की और भिनाय विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में अपने सुझाव देना चाहूंगा । जनता को स्वच्छ पेयजल सुलभ कराना जलदाय विभाग का प्रथम दायित्व है और इस दायित्व के सम्बन्ध में पिछले शासनकाल में और वर्तमान शासन में माननीय जलदाय मंत्रीजी ने बहुत ही संवेदनशीलता और गम्भीरता के साथ अपने प्रयास किये हैं और सतत् प्रयत्नशील हैं । कई महती योजनाएं प्रारम्भ की, बहुत सी लम्बित योजनाओं को पूर्ण कराया और बहुत सी योजनाएं प्रगति पर हैं । हमारे अजमेर जिले के लिए जो ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, भिनाय क्षेत्र को जल प्रदान करेंगी पेयजल योजना बहुत ही द्रुत गति से प्रारम्भ की और अगले सितम्बर माह तक अजमेर व ब्यावर के नगरवासियों को इस योजना से लाभ मिलेगा ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे केकड़ी और भिनाय विधान सभा क्षेत्र के करीब 200-250 गांव ऐसे हैं जो फ्लोराइड युक्त पानी से ग्रसित हैं । पिछले शासनकाल में हमने निवेदन किया था मैं जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि प्रथम योजना में 94 गांवों को आपने सम्मिलित किया है । यह 18.5 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार से मंजूर हुई है और अब राजस्थान सरकार में आपके विभाग के विचाराधीन है । 18.5 करोड़ की महती योजना जिससे 94 गांव लाभान्वित होंगे और वे ग्रामवासी फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे थे, कुबड़े हो रहे थे, कई बीमारियों से ग्रसित थे । फ्लोराइड की पीड़ा से सभी माननीय सदस्य चिंतित हैं । मैं जलदाय मंत्रीजी का इसके लिए बार-बार धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा लेकिन जो शेष गांव रह गये है इन गांवों को द्वितीय चरण में फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति दिलायें ।

इसके साथ ही भिनाय विधान सभा क्षेत्र की कई योजनाएं दो साल से लम्बित हैं आपके विभाग में और बिजली के कनेक्शन की वजह से लोग पेयजल के लिए महरूम हो रहे हैं । इसलिए भिनाय क्षेत्र के गांवों की इन योजनाओं को जल्दी स्वीकृत कराने की कृपा करें ।

इसके साथ ही जो पिछले शासनकाल में आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र के अरणिया, ताजपुरा, मियां भगवानपुरा की 45 लाख की योजना मंजूर की थी उसमें एक नोट डाल दिया था कि पहले सोर्स डवलप कराये जायं । सोर्स डवलप किये जा चुके हैं परन्तु पी. पी. सी. से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद मंजूरी करेंगे । तो जो गांव फ्लोराइड

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

युक्त पानी पी रहे हैं उनको शुद्ध पेयजल मुहैया होगा। धौलाई शंभूनगर की योजना उन पाइप लाइन से अधूरी रह गई है। ददारा, गुरगांव, साकरिया योजना मंजूर है लेकिन विभाग के अधिकारियों ने टेंडर लेने के बाद भी वहां कार्य चालू नहीं किया है। पाइप लाइन विस्तार योजना में मेरे क्षेत्र की खवास योजना से सेतपुरा गांव को जोड़ना प्रस्तावित है। खालीतलाई, खेड़ा की योजना से गणेशपुरा को जोड़ना प्रस्तावित है। नेरू कलां से नया गांव मालियान का पाइप लाइन विस्तार योजना से जोड़ना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जब आप बीसलपुर प्रवास के दौरान बनास पाइप लाइन से बिलकुल निकट मेरे गांव मुलकिया को स्वीकृति प्रदान की थी लेकिन उस गांव को अभी तक कनेक्शन नहीं हुए हैं। इसलिए बनास पाइप लाइन के नजदीक ही मोलकिया, टूपला और डोरई गांव को आप पाइप लाइन से जोड़ने की महती कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : और बोल लें, मैं लास्ट में बोल लूंगा।

श्री विष्णु मोदी : केन यू एकोमोडेट मी।

श्री अध्यक्ष : वे तो सचेतक हैं उनका लास्ट में आयेगा नाम। सचेतक पहले नहीं बोल सकते। खेतसिंहजी ने तो नाम ही नहीं दिया। आपका नाम है।

कुछ माननीय सदस्य : हमारा भी नाम है क्या?

श्री अध्यक्ष : जितने बैठे हैं सबका नाम है। अब आप कहें तो मैं सुना दूं। बचे तो और जोड़ दूंगा। श्री रामनारायण जी के बाद श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री रूपाराम, श्री परसादीलाल मीणा, श्री भीमराज भाटी, श्री नारायण सिंह चौधरी, श्री सुरेन्द्र गोयल, श्री हरिसिंह (महुआ), श्री प्रभुराम ग्रासिया, श्री हरिसिंह (कुम्हेर), श्री रामेश्वर भारद्वाज, श्री एमामुद्दीन, श्री महावीर भगोरा, श्री भरतसिंह, श्री माधवसिंह दीवान, श्री रामस्वरूप, श्री विष्णु मोदी।

श्री परसराम मदेरणा : श्री नारायण सिंह बोल चुके हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा नाम है इसमें?

श्री अध्यक्ष : हां, आपका नाम है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा एडजस्टमेंट कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैं कर देता हूं।

श्री विष्णु मोदी : मैं दो मिनट का ही समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : देखिए, आज धनखड़ साहब ने बिना मेरे से पूछे दूसरों की प्रायोरिटी ले ली।

श्री विष्णु मोदी : मैंने श्री रामनारायण जी से रिक्वेस्ट की है।

श्री अध्यक्ष : आपका हमेशा एडजेस्ट करता हूं लेकिन आज नहीं करूंगा। आज जो बहुत देर से बैठे हैं। आपका नाम बोला गया है और अन्त में परसराम जी बोलने वाले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य श्री हीरालाल विश्नोई का नाम भी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने लिख लिया। श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। यहां पर माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। पानी का एक्सप्लोयटेशन, अण्डर ग्राउण्ड वाटर को चार्ज करने के लिए एक्सपर्टस, इण्टर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट्स का संतुलन आदि जो बातें कही गयी हैं, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा के अन्दर जो पानी की समस्या है वहीं तक अपने आपको सीमित रखूंगा। मैंने तीन कटौती प्रस्ताव दिए हैं जो अपने आप में स्पष्ट हैं। एक नम्बर का मेरा कटौती प्रस्ताव है, हमारे झुन्झुनूं जिले में 96 गांव खारे पानी के हैं अब उनकी संख्या 140 हो गयी है। 1983 के अन्दर तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय श्री शिवचरण जी साहब को मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ले गया था और वे मेरे साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरते हुए चूरू, तारानगर, बाउण्ड्री से हम गुजर रहे थे तो मैंने वहां 10 मिनट के लिए रोककर कहा कि इस साइड में दाहिनी तरफ चूरू डिस्ट्रिक्ट और तारानगर है, यहां मण्डावा क्षेत्र में खड़े हैं यहां साहवा गंधेली से पानी आ रहा है और यह गांव हमारे 100 खारे पानी के हैं। इन गांवों में जब इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी आयेगा,

(21.00)

तो हमारे लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी ? तो बोले, क्या होना चाहिए ? यह पानी इधर आ सकता है लिफ्ट से तो हमारे इस इलाके में भी क्यों नहीं आ सकता। सवाल है निश्चय का और धन खर्च करने का। उनके दिमाग में वह बात जंच गयी, तो उन्होंने कहा, क्या करना चाहिए ? आप आदेश दीजिए, स्कीम बनवाइये। वह आ गये, आकर के उन्होंने आदेश दिया कि इन गांवों को देखा जाये। तो वह स्कीम बन गयी। स्कीम बनने के बाद 1995 में वह भी नहीं रहे और मुझे भी इस सदन में आने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ सका था, श्री हरिदेवजी जोशी मुख्य मंत्री बने, उनके ध्यान में मैं यह बात लाया, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी प्रेस कान्फ्रेन्स में। इस सारी स्कीम को देखा, स्कीम तब तक बन गयी थी, उन्होंने घोषणा करके उनको और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने इसको झुन्झुनूं कर दिया, झुन्झुनूं शहर भी इस स्कीम में हम जोड़ेंगे और उधर मान्यवर सीकर तक कर दिया, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और सीकर, यह प्रेस कान्फ्रेन्स है चीफ मिनिस्टर की 1985 की। माननीय मंत्री महोदय, आप देख लीजिये कि चीफ मिनिस्टर की कान्फ्रेन्स का रिकार्ड रहता है, यह दोनों उन्होंने की। उसके बाद वह भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, यह स्कीम बन तो गयी थी और बनाने के बाद, मान्यवर, क्या हुआ कि यह सैकण्ड फैज में तो पहले ही थी क्योंकि फर्स्ट फैज

(श्री रामनारायण चौधरी)

में साहबा गंधेली वाला पानी आ गया था, वह तो फर्स्ट फेज था और दूसरे फेज के अन्दर तारानगर के कुछ गांव आने वाले थे और हमारे यहां वह दूसरे फेज का था। अब वह कहां फेजिंग और रीफेजिंग के चक्कर में हमारे 96 गांवों में, प्लस एक नगर पालिका, इसको ऐसा गोल-मटोल कर दिया कि कहीं भी उसमें नजर नहीं आती कि 10 वर्ष में, 20 वर्ष में कोई पानी, नाम तो सैकण्ड फेज का आपने ही फरमा दिया कि आपका तो सैकण्ड फेज में है, तो मान्यवर, सैकण्ड फेज का थर्ड फेज का कोई ठिकाना नहीं रहा, यह कैसे हो गया? मान्यवर, सैकण्ड फेज का ठिकाना नहीं रहा....

श्री अध्यक्ष : रतनगढ़ भी सैकिण्ड फेज में है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो समर्थ हो, आपका तो फर्स्ट में हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सैकिण्ड फेज रतनगढ़ होगा तो आपका भी हो जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, तो आपके साथ जुड़ गये। इसलिए मुझे तो लग रहा है, हमारे यहां आने का सवाल ही नहीं है अभी। यह कैसे और कहां हुआ, यह मैंने मंत्री महोदय को कहा। मैं मंत्री महोदय की आलोचना-प्रत्यालोचना नहीं करता, वह हमदर्द हैं मेरी स्कीम के बारे में और उनकी दिलचस्पी भी है, लेकिन वह कहते हैं क्या करें? आप ही सोचो रास्ता, क्या करें? हमें तो मान्यवर, इन्दिरा गांधी नहर का पानी चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

दूसरा, मेरी कान्स्टीट्यूएंसी में सात रीजनल स्कीम्स हैं, सात रीजनल स्कीम्स में एक स्कीम में 40 गांव हैं, वह इसके अन्दर लिखा हुआ है, उनको मन्त्री महोदय आप नियमित कर दीजिये। जितने गांवों के लिए बनी हैं, उनको नियमित रूप से पानी मिल जाये यह मैं आपसे आश्वासन नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि उनकी आप पानी की सप्लाई नियमित कर दें। एक

(9.05)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

बड़ी स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करने से तारानगर के गांवों के साथ-साथ ही हमारे झुन्झुनू जिले के गांवों को भी पानी मिले; इसमें हमें आपकी सहानुभूति सहयोग, हमदर्दी चाहते हैं। आप इनको उस तरह से मत उलझाओं की सैकण्ड फेज, थर्ड फेज तारानगर वाले गांव जुड़े, उसके साथ ही हमारे गांव भी जुड़ने चाहिये। इतने ही शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री भंवर लाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपसे मेरी बातचीत भी हुई है, आप एक बार देख लें कि इस स्कीम में आपके गांव अगर आ सकते हैं, तो मैं पूरी सहानुभूति ही नहीं, प्रयत्न करूंगा कि वहां पर, पर आप समझा दो कि आ सकते हैं क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो नहीं समझा सकता, मैं तो इतना ही निवेदन

(श्री रामनारायण चौधरी)

करूंगा कि ग्रापकी जगह अगर मैं होता ग्रौर मेरी जगह ग्राप होते ग्रौर जितनी ग्राप हमदर्दी मुझे दिखा रहे हैं, उतनी हमदर्दी मेरे दिल में होती तो मुझे कुछ भी करना पड़ता, मैं चीफ मिनिस्टर को राजी करता, किसी को भी राजी करता, मैं ग्रापका यह काम करके देता। मैं तो ग्रापको यही कहता हूं कि मैं करके देता, चाहे मुझे चीफ मिनिस्टर की खुशामद करनी पड़ती, कुछ भी करनी पड़ती, मैं तो यह कहता कि श्री भंवर लाल जी का गांव हैं, जोड़िये, चाहे कुछ भी हो।

श्री भंवर लाल शर्मा : धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (अनुपस्थित) श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में ग्रादमी की जरूरत की पहली चीज पर चर्चा की जा रही है। वैसे ग्रादमी की जरूरत की पहली चीज हवा भी है, लेकिन ग्रभी इसका कोई मंत्रालय नहीं है। हवा ईश्वर की तरफ से, प्रभु की तरफ से प्रकृति की तरफ से ग्रभी फ्री मिलती है। पर्यावरण में हम केवल दूषित ही करते हैं हवा को। हवा को ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है, उसकी ग्राज्ञा के बिना, इजाजत के बिना हम हवा ले सकें या नही ले सकें। हवा के बाद दूसरा नम्बर पानी का है, लेकिन सरकार द्वारा हमें जो सुविधा दी जा रही है, करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने, सब जगह एक ही बात बतायी है। किसी के टंकी है, तो पानी नहीं, किसी के नल नहीं, किसी के हैण्ड पम्प खराब हैं। मैं समय को मध्य नजर रखते हुए इन सभी समस्याग्रों को माननीय मंत्री जी को बता रहा हूं। मेरे क्षेत्र में भी ठीक यही हाल है टंकियां कई सालों से बनी हैं, पाइप नहीं है ग्रौर मैं तो मेरे कुछ जो निजी सुझाव हैं वह ग्रापको बता रहा हूं। राजस्थान मेहमानवाजी में, ग्रतिथि सत्कार में सबसे ग्रागे है ग्रौर माननीय मंत्रीजी यदि कभी ग्राप हमारे घर पधारेंगे ग्रौर हम ग्रापकी सबसे पहली सेवा जो पानी की सेवा है, वह नहीं भी कर सकेंगे, तो रहीमदास जी ने जो कहा था—

रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
पानी गये न उबरे, मोती मानस चून।।

जब हमारे यहां पानी ही नहीं बचेगा, उस समय रहीमदास जी को शायद ही यह पता नहीं था कि इस दोहे के ग्रनुसार हम जब चलें तो इसमें सहयोग ग्रापका जरूरी होगा। माननीय मंत्री महोदय, का सहयोग ग्रगर हमें नहीं मिलेगा तो हम इस दोहे के ग्रनुसार जीवन यापन करने में समक्ष नहीं रहेंगे। एक बात बीच में मैंने अभी देखी है। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्रीजी कोई भी कार्य करने में तत्पर हैं, सजग हैं, लेकिन मंत्रीजी की हालत, उनकी हालत मुझे वही लग रही है जैसी एक विश्व प्रसिद्धकार रेसर की है, वह रेस तो जीतना चाहता है, लेकिन उस कार में टायर गाड़िया लुहार की गाडी के डाल दिये गये हैं, जो ग्रापके विभाग के कर्मचारी समझों या ग्रधिकारी समझों ग्रौर जब ग्रापमें ग्रौर ग्रापके विभाग में तालमेल ठीक इसी तरह रहेगा, जिस तरह गाड़िया लुहार की तो छगड़ी के टायर ग्रौर ग्रापकी मर्सिडीज कार के, तो उसमें तालमेल नहीं रहेगा। माननीय मंत्री महोदय, ग्राप उस रेस को या आप इस पानी की समस्या

(श्री रूपाराम)

मिटाने वाली रेस को कभी नहीं जीत सकेंगे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब मकराना की एक दो समस्या बता दूं । मकराना में अभी मैंने पांच दिन पहले एक आदमी से पूछा, एक कर्मचारी आया, उसने कहा भाई साहब पानी आया, मैंने कहा आया । मैंने कहा खारा आया । फिर तो ठीक है, बहुत अच्छा है । खारा पानी अच्छा कैसे ? मैं खारे पानी की टंकी में रहता हूं, मेरी ड्यूटी पूरी हुई । यानि पहले हमारे 15-20 मिनट खारा आता है या कभी बीच में खारा पानी, बीच में मीठा पानी, एक ही नल की यह योजनाएं हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमें खारे और मिठे पानी की पहचान में, कम से कम एक आदमी को मकराना में रोज खारा पानी पीना पड़ता है, टूंटी के नीचे बैठता है, अभी खारा आ रहा है, भाई साहब रूक जाओ, यानि हमारे परिवार का एक मेम्बर बैठा देंगे, मीठा आते ही बोल देना, मटकी लगा देंगे, तो या तो पानी में, मीठे और खारे पानी के कलर में कुछ परिवर्तन किया जाएं । एक तो थोड़ा हल्का लाल दे दिया जाये, ज्योंही हरा आयेगा तो मीठा आ गया, मीठा आ गया । हमारे बंधभेरा, मकराना की एक स्कीम है, जिसमें गुलजारपुरा शामिल है, भाकरों की ढाणी जिसमें मैं वहां रहता हूं, वह भी शामिल है । यह भी एक आश्चर्य है कि एक ही नल में दो तरह से पानी आता है, एक तो माननीय मंत्रीजी आप इसका कुछ समाधान करें । (व्यवधान)....

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने समय सीमा तय की हुई है । बोलिये आप ।

श्री रूपाराम : दूसरी बात यही है मेरी तरफ से तो, गांवों में भी शहरों की तरह लोगों की पानी की समस्या की तरफ ध्यान दिया जाये, प्रतिशत के हिसाब से, जैसे यहां करोड़ों लगते हैं तो वहां कुछ लाख तो लगने ही चाहिये, जो ढाणियों में रहते हैं । ठीक इसी तरह– सितारों से बढ़ कर जहां और भी है. बड़े शहरों से हटकर इन्सां और भी है । आपने समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद ।. नमस्कार ।

श्री सभापति : श्री परसादी लालजी मीणा ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, आज पेयजल की मांगों पर विचार हो रहा है....

एक माननीय सदस्य : मेरा भी नम्बर है ।

श्री सभापति : नम्बर सब का आयेगा, नम्बर सब का ही आने वाला है, आपका भी आयेगा ।

श्री शिवनाथ सिंह : यह प्रकृति का नियम है ।

श्री सभापति : प्रकृति का नियम है ।

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय मंत्रीजी ने पेयजल के लिए जो यह प्रगति–विवरणिका पेश की है उसके पेज नं. दस पर नगरीय पेयजल, प्रस्तावित वार्षिक योजना 1994–95....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : कितने लोग रह गये ?

श्री परसादी लाल मीणा : आपको जाना है तो जाइये कालीचरणजी, मांग पास हो जायेगी, आप नहीं रहोंगे जब भी, जाइये आप ।

श्री सभापति : आसन प्रश्नों का जवाब कभी नहीं देता । माननीय सदस्य, आसन से प्रश्नोत्तर नहीं किया करें । आप बिराजिए ।

श्री परसादी लाल मीणा : तो पेज नं. दस पर प्रस्तावित वार्षिक योजना 1994-95 नगरीय पेयजल योजनाएं---130.59 करोड़ रुपये, ग्रामीण पेयजल योजनाएं—72.65 करोड़ रुपये । सभापति महोदय, मंत्रीजी को गांव कहीं नजर ही नहीं आते । इनको केवल शहर नजर आते हैं, सरकार ढिंढोरा पीटती है और बजट भाषण के पेज नं. 32 पर इन्होंने कहा है कि "ग्रामीण क्षेत्र में बड़े व्यापक पैमाने पर हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे ।" सभापति महोदय, बजट में शहर और गांव के बीच आधा फर्क है, कैसे गांवों में हैण्ड पम्प लगेंगे । ग्यारह बजे से मैं यह कागज देख रहा हूं, मेरे को बड़ा तरस आ रहा है कि मंत्रीजी गांवों की ओर देखना ही नहीं चाहते । इनको गांवों की संख्या का भी पता नहीं क्योंकि यह तो नगरपालिकाओं के जो कस्बे हैं इनकी या जयपुर शहर है इनकी गिनती करते हैं । गांवों की संख्या 33889 है जिनमें जनसंख्या तीन करोड़ 39 लाख है । 222 कस्बों की संख्या, संख्या में जनसंख्या है एक करोड़ । अब आप देख लीजिये, नहीं तो फिर आप कहेंगे हम गांवों के लिए 62 प्रतिशत बजट दे रहे हैं । मैं कह रहा हूं कि आप आधा ही दे रहे हैं । मंत्रीजी, आप विचार करिये । आप यह घोषणा कर दीजिए कि एक विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं राजस्थान में, जहां पर पेयजल का संकट न हो, जहां पर पेयजल की आज समस्या न हो । आप हमारे साथ चलिये क्षेत्रों में । किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइये । आप जयपुर के नजदीक चौमूं चले जाइये, जमुआरामगढ़ चले जाइये, लालसोट चले जाइये, दौसा चले जाइये, आपको एक ही मांग गांवों में मिलेगी कि पानी की समस्या है, हमारी ढाणी में पानी नहीं है । आपने हैण्ड पम्प लगा दिये, आज उन हैण्ड पम्पों की हालत देखिये । आपने यह भी इस बजट में या इस योजना में नहीं रखा कि जो हैण्ड पम्प खराब हो जायेंगे, अबेंडेड हो जायेंगे उनको आप ठीक कैसे करायेंगे । यदि एक गांव में पांच के पांच हैण्ड पम्प खराब हो गये तो आपका कोई बजट प्रोविजन नहीं है कि आप वहां हैण्ड पम्प लगा देंगे 91 में आपने बजट सेशन के समय यहां एम. एल. एज. की मीटिंग बुलाई थी तो मंत्रीजी, मैंने आपको कहा था कि फलां दो-तीन गांवों में एक भी हैण्ड पम्प ठीक नहीं है । फिर आपने अधिकारियों से जांच करवायी और आपने यह कहा था कि अधिकारियों ने मेरे को सूचना यह दी है कि वहां हैण्ड पम्प ठीक है । अगर उनकी सूचना गलत निकली तो मैं कार्यवाही करूंगा । अधिकारी आपके गये, आपके एडीशनल चीफ जो यहां बैठे हैं, ओ. पी. गोयल वहां गये । वहां एक भी हैण्ड पम्प ठीक नहीं मिला गांव में । आज यह गांवों की हालत है । आपके अधिकारीगण गांवों में जाते नहीं । आपने सफेद हाथी, एक एस. ई. को यहां बैठा रखा है, हिलना-डुलना ही उसके बस का रोग नहीं, वह जाय कैसे गांव में । एक्स. ईएन. को

(श्री परसादी लाल मीणा)

आपने पावर नहीं दे रखी है कि वह हैण्ड पम्प स्वीकृत कर दे। आखिर करेगा कौन ? तो यह जो खराब हैण्ड पम्प गांवों में हो गये, आप उनको कैसे पानी सुलभ करायेंगे। आप कह रहे हैं हमारे इतने गांव लाभान्वित हो गये, इतने गांवों में इस साल कर देंगे, 1450 को और सारा राजस्थान इस साल लाभान्वित हो जायेगा। मंत्री महोदय, आप शहर में रहते हैं और आप यहां के मंत्री हैं, आपको जयपुर से बाहर जाने का मौका बहुत कम मिलता है। आप राजस्थान के मंत्री हैं, मैं नहीं मानता।

श्री सभापति : श्री परसादी लालजी, नहीं-नहीं। मंत्रीजी का गांव है त्याली।

श्री परसादी लाल मीणा : गांवों में जाने का आपको मौका नहीं मिलता। आप एक दिन गांव में घूमिये। आपको हैण्ड पम्प और पानी की समस्या के अलावा गांव में कोई समस्या नहीं मिलेगी। जो आपने योजनाएं बनवायी।

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल मीणा : और उन योजनाओं की क्रियान्विति आज तक नहीं हुई। योजना का नाम है, एक तो खेड़ला खुर्द महारिया, खुर्री किशोरपुरा। आपने अभी पिछले सत्र के समय हमारी जिलेवार मीटिंग बुलायी, आपने कहा था कि यह सारे काम हो जायेंगे बजट सेशन से पहले। माननीय मंत्रीजी, आपने जो कहा, आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिए, आप बताइये कि उनमें से कितने काम हो गये। आप अधिकारियों के सामने और हमारे सामने अधिकारियों से ऐसे कहते हैं जैसे हम यह सोचते हैं कि यह काम तो पन्द्रह-बीस रोज में हो जायेगा और आज दो महीने हो गये, एक भी काम एक भी योजना पूरी नहीं हुई। जो ओबजेक्शन्स इन्होंने लगाये थे, आज तक इन्होंने स्वीकृत नहीं किये। आखिर पानी कैसे पिलायेंगे, आखिर होगी कैसे गांवों की व्यवस्था और आप कहते हैं कि हम इतना बजट दे रहे हैं। आपने जो बजट हमारे गांवों के लिए रखा वह तो मैंने आपको बता ही दिया। आपकी जो योजनाएं है उनका कोई धणी-धोरी नहीं है आज। अगर मोटर जल गयी....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, मैं दो मिनट का टाइम और लूंगा, मेहरबानी करें आप।

आज गांवों की योजनाओं का कोई धणी-धोरी नहीं, आज उनको कोई समय पर नहीं चलाता। अगर बिजली आ जाये तो गांव वाले चला दें, पानी आ जाय, नहीं तो मोटर खराब हो गयी, दस दिन तक पड़ी रहती है, डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं रहता। मैंने सुना है, जैसा मुझे मालूम हुआ है, मंत्री महोदय, जो गांवों की योजनाएं हैं उनको भी ठेके पर चलाना चाह रहे हैं। कौन चलायेगा ? ठेकेदार चला देगा अच्छी तरह उनको। सरकार की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उनकी मोटर जल गयी तो दो महीने तक ठेकेदार नहीं बंधायेगा तो क्या गांव वाले उसके पीछे-पीछे घूमेंगे। आप मेहरबानी

(श्री परसादी लाल मीणा)

करके, मेरा निवेदन है कि चाहे आप गांव में कनेक्शन दे दीजिए, आपका जो आदमी रहेगा, आपका बिजली का खर्चा, आप दस रुपये, पन्द्रह रुपये कनेक्शन, जितने भी हो सके, जो नियम है उससे बांध दीजिए, वहां कनेक्शन देकर उन योजनाओं की सही क्रियान्विति करायें। कहीं पर नल तोड़ दिया, आपके आदमी ही नहीं है तो देखेगा कौन उनको। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारी लालसोट की योजनाएं हैं वहां एक भी योजना पर आदमी नहीं है। न आपके नीजणना है, न बगड़ी है, न बिलोना है, न शिवसिंहपुरा है, न गुरतपुरा है, कहीं एक भी जगह विभाग का आदमी नहीं है। आखिर उन योजनाओं को कौन चला रहा है। भगवान भरोसे योजनाएं चल रही है। आज लालसोट में देख लें, मण्डावरी में देख लें, रामगढ़ में देख लें, डीडवाना में देख लें, सारी योजनाओं में अगर दो दिन तक बिजली नहीं आये तो मन्त्री महोदय, वहां गांव वालों को पानी नहीं मिलेगा। आज क्या साधन है आपके पास ? किसी कुएं में पानी नहीं, आपने कहीं वह साधन बनाये नहीं, सारे कुएं जो ग्राम पंचायतों ने कुएं बनाये थे शत-प्रतिशत कुएं आपके ड्राई हो गए। आप मेहरबानी करके उन कुओं को गहरा कराइये। मेरा एक सुझाव और है। मेरे एक ओदायली गांव था। वहां पर चार हैण्ड पम्प अबेन्डेंड हो गये। आपके डिपार्टमेंट ने चारों को ड्राई घोषित कर दिया, गांव वालों ने मिलकर जन सहयोग से उन चारों हैण्ड पम्पों को बीस-बीस फीट बोरिंग करके स्वयं के खर्चे से, आपके डिपार्टमेंट ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और आज वह चारों हैण्ड पम्प आज चालू हैं।

मेरा सुझाव है सरकार से कि जो हैंड पम्प ड्राई हो गये हैं, आप उसमें दो हजार, तीन हजार बजट मंजूर कीजिए और उन सबको गहरा कराइये। एक हैण्ड पम्प की लागत पच्चीस और तीस हजार के बीच है। दो तीन हजार के लिए आप उन हैण्ड पम्पों को ड्राई करते हैं। उनके सामान को आपके इंजीनियर ले जाते हैं खोलकर। इंजीनियर्स के एक और इन्टरेस्ट रहता है, नये हैण्ड पम्प लगाने में उनको पांच हजार दस हजार रुपये के बीच कमीशन मिल जाता है इसलिए वह पुराने हैण्ड पम्पों को क्यों ठीक कराये। दो हजार, तीन हजार में तो उनको कितना कमीशन मिलेगा। आप कह दीजिए अपने विभाग को, कि जितने हैण्ड पम्प ड्राई हो गये हैं, दो से पांच हजार तक खर्चे में सारे हैण्ड पम्प आपके चालू हो सकते हैं। आपके डिपार्टमेंट की ओर इंजीनियर्स की यह इच्छा नहीं है कि हम इन हैण्ड पम्पों को ठीक करायें। नये हैण्ड पम्प लगेंगे तो एक हैण्ड पम्प पर जो हमको कमीशन मिलेगा, हमारा अच्छा गुजारा होगा। इस तरह अगर आप इन ड्राई हैण्ड पम्पों को ठीक करायें, चाहे आपको फेमिन में से पैसा देना पड़े, आप अकाल राहत मंत्रीजी से पैसा लीजिए, आपका जो कन्टीजेन्सी प्लान है आज तक वह नहीं बना है, आप कब उसको चालू करेंगे ? अगर आपने इस महीने में, अप्रैल और मई में, अपने प्लान को एक्जीक्यूट नहीं किया तो फिर अगस्त और जुलाई में करके क्या करेंगे मन्त्री महोदय। आप अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि जितने भी ट्यूब वैल बनने है, अप्रैल माह में बना लीजिए। उनको पाबंद करिये कि अप्रैल में

(श्री परसादी लाल मीणा)

बन जाने चाहिए, उन पर कनेक्शन हो जाने चाहिए, वह चालू हो जाने चाहिए। हमारे वहां लालसोट में देख लीजिए, आपकी जो स्कीम पड़ी है वह हुडको से आयी है, आज तक भी चालू करने का कोई काम नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री परसादी लाल मीणा: आज लालसोट की ढाणियों में एक भी हैण्ड पम्प नहीं है। आज वहां पर बीस-बीस किलोमीटर तक पानी का साधन नहीं है, 95 प्रतिशत कुएं हमारे लालसोट क्षेत्र के, दौसा क्षेत्र के ड्राई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो अबेन्डेन्ड हैंड पम्प हैं उनकी तरफ ध्यान देने के लिए कहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गांवों में पीने के पानी की समस्या की ओर तो क्या बात करूं, मेरा तो जन्म स्थान है पाली उस पाली शहर में भी करीब 25-30 हजार की ऐसी बस्ती है, राजेन्द्र नगर है, रायको की ढाणी है, बादियों की सोसायटी है, अम्बेडकर नगर है, शिव कालोनी है, गरीब नवाज कालोनी है, राम रहीम नगर है, हैदर कालोनी है। कम से कम ऐसी 25-30 हजार मजदूरों की और शिड्यूल्ड कास्ट की बस्ती है जहां पाली शहर में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और सालों से वह बस्तियां बसी हुई हैं लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उन औरतों, बच्चों और मजदूर लोगों को साइकिल पर दो-दो, ढाई-ढाई किलो मीटर रेलवे के कुएं से या महाराजा उम्मेद मिल के अन्दर जाकर पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, मैं मन्त्री महोदय आपकी एफिसियेंसी की दाद देता हूं, आपके सचिव महोदय की एफिसियेंसी की दाद देता हूं। लेकिन मुझे दुख है कि आपने बाली, फालना और रानी के लिए 7 करोड़ 35 लाख का कोई कार्यक्रम मंजूर करके बाली, फालना और रानी के लोगों को पीने के पानी की सुविधा नजदीक में ही उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लेकिन मन्त्री महोदय, आपके सचिव महोदय ने अपनी जिन्दगी के सुनहरे दिन पाली में ही गुजारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब वो पाली बिराज रहे थे अपने जीवन के सुनहरे काल में उस जमाने में जो पानी की वाटर सप्लाई की स्कीम और पाइप लाइन डाली गयी थी उस पाइप लाइप के बाद जब बीस-बाइस हजार की बस्ती होगी करीब पाली शहर में आज की तारीख में एक लाख बीस हजार की बस्ती है, एक लाख बीस हजार की वस्ती के बाद भी पाली की जो वाटर सप्लाई की पाइप लाइन है वो की वो पाइप लाइन है। वह राउरकेला के 12 ईंच के पुराने पाइप हैं। उसके आगमेंटेशन की आपके पास स्कीम आ चुकी है। पाली का फिल्टर हाउस जो था, हमारे रामसुख जी गुप्ता चेयरमेन हुआ करते थे, उनका स्वर्गवास भी हो चुका, वह जमाना लद चुका लेकिन उस फिल्टर हाउस की आज भी वही केपेसिटी है। शायद आपके सचिव भण्डारी साहब को पता होगा कि पाली में कितना सुन्दर तालाब हुआ करता था और वह तालाब पाली का मेन पानी का स्रोत है। उस तालाब में से ही पानी खींचकर फिल्टर हाउस में डाला जाता है। लेकिन आज उस तालाब की यह

(श्री भीमराज भाटी)

स्थिति है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी ज्यादा उस तालाब में गन्दगी है और वह पाली शहर का मेन पानी का स्रोत है। उस तालाब के किनारे जो बेरे वगैरहा का पानी था वह पानी स्वास्थ्यवर्द्धक माना जाता था। उन बेरो की हालत उस तालाब में गन्दगी की वजह से यह हो गयी कि उसका कुछ नहीं हो रहा।

मैं कहता हूं कि जब आप सात करोड़ की एक योजना पाली जिले के कुछ हिस्से के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए इतनी त्वरित गति से, इतनी एफिशियेन्सी दिखाकर मंजूर कर सकते हैं तो फिर पाली शहर की जो आगमेंटेशन की आपके पास सालों से स्कीम पड़ी हुई है उसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया। फिल्टर हाउस के एक्सपान्शन की जो स्कीम आपके पास पड़ी है उसकी तरफ क्यों नहीं गया। क्यों नहीं आपका ध्यान मेरे उस चौराई क्षेत्र में गया? मैं हैण्ड पम्प वगैरहा की बात नहीं करता। मेरे यहां तो पीने का पानी ही खारा है। हमारे तो कुएं भी खराब हो चुके हैं उस प्रदूषण की वजह से मेरे उस इलाके की तीन करोड़ 21 लाख की योजना आपके पास पेंडिग पड़ी है। आप जब सात करोड़ की योजना 15-20 दिन में चुटकियों में मंजूर करके भेज सकते हैं तो वह तीन करोड़ इक्कीस लाख की योजना आपके पास पड़ी है। उसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया।

मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वायदा और सिराणा का एक कंटीजेंसी प्लान आपके पास बहुत लम्बे समय से पेंडिग पड़ा है उसकी मन्जूरी आपके यहां से क्यों नहीं आई। जब आप सात-सात करोड़ की योजना चुटकियों में बना देते हैं, एक मीटिंग में ही, एक ही सिटिंग में बना देते हैं और एक ही झटके में उसको मन्जूर कर देते हैं तो यह भेदभाव नहीं तो और क्या है तो क्या पाली जिले के एक साइड में इन्सान नहीं रहते हैं और एक साइड में कोई विशेष लोग रहते हैं तो इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो आपके पास स्कीमें पेण्डिग पड़ी हैं उन पर ध्यान देकर तुरन्त मन्जूर करवायें।

मन्त्री महोदय, मैं आपसे कई बार मिल चुका हूं। तीन चार बार मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी निवेदन किया है कि अगर जवाई नहर से हमारे चौराई क्षेत्र के तालाब नहीं भराये गये तो मैं कहता हूं कि अगले 15–20 दिन में आपको इतनी भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वहां आंधियां भी आनी शुरू हो गयी हैं, बिजली की लाइनें भी हमेशा डिस्टर्ब होती हैं, 15-15 दिन तक वह बिजली की लाइनें ठीक नहीं होती हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर 15-20 दिन में हमारी उस चौराई क्षेत्र के तालाबों को अगर आपने जवाई नहर से भरने की व्यवस्था नहीं की तो मेरे पास सील साते का एक दिन है तो उस सील साते के दूसरे दिन से मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। मैं सरकार से पैसा मांगता नहीं, सरकार से कोई बात मांगता नहीं। सरकार से सिर्फ पानी मांग रहा हूं और पानी भी एक दया की भीख के रूप में मांग रहा हूं। अगर आपने जवाई नहर से हमारे तालाबों को नहीं भरवाया तो माननीय मन्त्री जी मुझे सील साते के दूसरे दिन से भूख हड़ताल करनी पड़ेगी।

Page No.209

(श्री जीवनराज भाटी)

जो ढाणियां है, माननीय राज्य मन्त्री बिराजमान हैं, उनको पता है कि ढाणियों में पीने के पानी की कितनी तकलीफ है। वहां आप चाहे हैण्ड पम्प खुदायें तो भी पानी खारा है। वहां पानी अवेलेबल नहीं है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर अवेलेबल ही नहीं है। उन ढाणी वालों को 7-8 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, 110 ढाणियां हैं उसमें से कुछ तो आपने मन्जूर की है लेकिन उनमें से आपको जो परचेजिंग का सिस्टम है पाइप खुदवाने और पाइप डिलीवरी वाला कहता है कि मेरे पास पाइप नहीं है, मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है। इसलिए आपकी प्रोसीजरल फार्मेलिटी में दिन गुजरते जा रहे हैं और वह दिन दिन परेशान होते जा रहे हैं। उन ढाणी वालों की तरफ विशेष ध्यान देकर उनकी तरफ भी कुछ कार्यवाही करवाने की मेहरबानी करें।

मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाता हूं सील साते के दूसरे दिन अगले पन्द्रह दिनों में तालाब नहीं भरे गये तो मेरे पास कोई जरिया नहीं है, मैं उनको कोई बात नहीं बता सकता। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : बाली फालना, खेमेल और रानी यह सन् 77 की योजना है। सन् 77 से ही इसके पीछे लगे हुए थे वह योजना अब चालू हुई है ।

श्री सभापति श्री सुरेन्द्र गोयल ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : सभापति महोदय, आज सुबह से ही पेयजल की चर्चा हो रही है और सभी माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हैं। कहीं हैण्ड पम्प खराब पड़े है और कहीं पर स्कीम स्वीकृत है पर पाइप नहीं है कहीं पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से पानी मुहैया नहीं हो रहा है तो मैं निवेदन करता हूं कि जबसे सृष्टि की रचना हुई है तब से जिस समय प्राणी ने जन्म लिया है तब से हवा, पानी सूरज की किरणें भोजन की व्यवस्था प्रकृति ने की है। परन्तु पिछले पांच-सात सालों में जो यह पेयजल का संकट राजस्थान में इतना गहराया है इसके कारणों की जांच करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन हैं कि पेयजल का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या की वृद्धि है। अगर अपन एक टंकी 500 आदमियों के लिए बनाते हैं तो जनसंख्या पांच-सात साल में दुगुनी हो जाती है।....

श्री सभापति: सुरेन्द्र जी यह प्रजापति की कृपा है।

श्री सुरेन्द्र गोयल: इसलिए मेरा निवेदन है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए कानून बनाना पड़ेगा और इस पर रोक लगानी पड़ेगी। दूसरा, सभापति महोदय, इन्सान बहुत विलासी हो गया है। पहले गांव का एक आदमी लोटा लेकर लैट्रिन जाता था और बाल्टी लेकर स्नान करके वापस घर आ जाता था। आज जब तक टंकियों का पानी पूरा खत्म नहीं हो तब तक वह अपना फव्वारा बन्द नहीं करता है और पानी बहता रहता है। इस सम्बन्ध में भी अपने को कुछ सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय, जो अधिकारी योजना बनाते हैं, भविष्य को मद्य नजर रखते हुए जब तक योजना नहीं बनायेंगे आने वाले समय में इस पानी का जल स्तर कितना नीचे जायेगा यह पानी की कमी कैसे आयेगी, कम से कम योजना बनाते वक्त 15-20 साल आगे की सोच

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

समझ कर योजना को क्रियान्वित करेंगे तो आगे जाकर पानी का संकट नहीं होगा।

सभापति महोदय, आज एक चीफ इन्जीनियर का ट्रांसफर करने में मन्त्री जी को कोई तकलीफ नहीं होती है पर वहां जो हैल्पर लगे हुये है उनकी यूनियन बनी हुई है, वह हैल्पर वहां 15–20–30 साल से वहां बैठे हैं और जब हम अफसरों को कहते हैं कि वहां हैल्पर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, रात को घर चला जाता है, तो ए. ई एन. और एक्स. ई. एन. कहते हैं कि साहब क्या करें इनकी यूनियन बनी हुई है, कल हड़ताल कर देंगे। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिदे कि इस प्रकार के जो दो–तीन साल से कर्मचारी लगे हुए हैं उनको वहां से हटाकर के अन्यत्र स्थापित करने की व्यवस्था की जाये तो आधा संकट इससे साल्व हो सकता है।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक और निवेदन करता हूं कि मेरे एरिये जैतारण में मन्त्री महोदय को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहले शासन में मेरे यहां की स्कीमें स्वीकृत कर दीं.... अब स्वीकृत तो स्कीमें हो गयी। परन्तु पहले तो जोइंट नहीं थे, पाइप नहीं थे, अब महीने-डेढ़ महीने से पाइप भी आये हैं। मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं और पाइप आ गये हैं तो ठेकेदार नहीं है। जहां एक किलोमीटर में लाख, डेढ़ लाख का खर्चा आता है वह डेढ़ लाख रुपये तो सरकार को मिल जाते हैं परन्तु उस ठेकेदार के एक हजार या पांच हजार रुपये खुदाई के लगते हैं उसका ठेका देते हैं और तीन-तीन साल तक वह हजारों जगहों ठेका ले लेता हैं और वह पाइप लगाना नहीं चाहता है। तो मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से आपके मार्फत कि अगर पाइप आ जाते हैं, कुआं खुद जाता है और बिजली का कनेक्शन हो जाता है तो कम से कम ठेकेदार जो लापरवाही करते हैं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वहां का विधायक, वहां का सरपंच, वहां का ए. ईएन., एक्स. ईएन. चार जने बैठ कर के जिस हिसाब से ठेका मिला है उस हिसाब से कोई गांव का व्यक्ति, मजदूर खुदवाने को तैयार है तो आप यह पैसा उनको दे दो और वह खुदवा ले तो कम से कम पानी की राहत तो समय पर मिल जाये। मैं मेरे एरिये की बात निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : अब आपने पांच मिनट तो सारी सृष्टि की बात पर लगा दिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल : सभापति महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं और दो मिनट ही हुये हैं। मेरे एरिये में जैसे, दयालपुरा, सेवरिया, टुकड़ा, आसरलाइ, बांजाकुड़ी में आधे कुएं खुदे हुये है कम से कम तीन साल हो गये, कनेक्शन उनके अन्दर हो गये, पाइप लाइन भी आ गयी पर वह ठेकेदार नहीं खोद रहा है, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। पिछले साल–डेढ़ साल से प्रक्रिया चल रही है। मैं उनसे पूछता हूं कैसे उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब दुबारा टेण्डर करेंगे। गांव वाले चार साल से पानी के लिए मोहताज है। गवर्नमेंट का पूरा पैसा लग गया है जबकि थोड़े से पैसों में कम से कम 10–20 हजार रुपये खर्चे के अन्दर कुआं चालू

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

होकर गांव को पानी मुहैया हो जाता है। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाय कि इन कुओं को वापस चालू कराया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मेरे एरिया में निम्बोल, फालका, बैंडकला, आगेवा, लितरिया, बलूपुरा में ट्यूब वैल खुदे हुये हैं। इतने दिन तो पानी था उसके अन्दर पता नहीं कोई कचरा आ गया है मैंने कई बार निवेदन किया कि साहब कम्प्रेसर मशीन ला करके उनकी सफाई की जावे या थोड़ा बहुत उसको गहरा किया जावे। एक-एक गांव के ऊपर एक-एक स्कीम के अन्तर्गत 15–15, 20–20 गांवों में लगे हुये हैं। अब उनमें पानी बिल्कुल सूख गया है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि तुरन्त प्राथमिकता से जो बीस-बीस हजार आदमी, जो पेयजल का स्रोत है.... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, निम्बाज व जैतारण नगर-पालिकायें हैं और....

श्री सभापति : बिराजिये मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यह समस्या कई, जगह आती है। आखिर में कुछ काम डिपार्टमेंट करता है कुछ ठेके पर करने पड़ते हैं। तो ठेकेदार कभी-कभी इस परिस्थिति में आ जाता है कि वह काम नहीं कर पाता और उसका ठेका भी कैन्सिल नहीं होता उसके कारण प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि जिस रेट पर ठेकेदार को हमने काम दिया है यदि उसी रेट पर कोई दूसरा व्यक्ति काम करने के लिये तैयार हो तो आप कर ले हम उसको अनुमति दे देंगे।

श्री सभापति : एकदम में समाधान हो गया आपका।

श्री सुरेन्द्र गोयल : इसके अलावा मैं निवेदन कर रहा था। जैतारण नगर पालिका हैं आप आज ही पता कर लीजिये 5–5, 7–7 दिन से पानी आता है। और एक हुडको की स्कीम मन्जूर हो रखी है ढाई करोड़ की। तो कम से कम जल्दी से जल्दी ट्यूब वैल खुदवा करके पाइप लाइन डलवा कर पानी मुहैया करावें। आज निम्बाज गांव है 15 हजार की पापुलेशन है। वहां पर फिर एक कुआं लेकर के पानी मुहैया करवाया जा रहा है दो-दो, तीन-तीन दिन से। तो मेरा निवेदन है कि निम्बाज गांव में एक ट्यूब वैल खोदी जावे और ट्यूब वैल खोद करके जल्दी से जल्दी पानी मुहैया करावें। इसके अलावा बलूपुरा, अमरपुरा में पुराने स्रोत हैं, कुयें खुदे हुये हैं और गांव वाले राजी हैं कि हमारे यहां बिजली का कनेक्शन लगा दिया जाये तो कम से कम बिजली का कनेक्शन वहां लगा दें तो पांच-पांच, दस-दस दिन से पानी नहीं मिल रहा है तो कम से कम पानी मुहैया हो। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या

(श्री हीरालाल विश्नोई)

27 की प्रक्रिया के तहत आज सुबह से ही छह-सात घन्टे से पेयजल की चर्चा चल रही है। वैसे ही हमारा जिला जालौर राजधानी से सात–आठ सौ किलोमीटर की दूरी पर है और आज मेरे को बोलने का मौका भी लास्ट में ही मिला है। और समस्यायें भी हमारे वहां अनेक हैं। ऐसी समस्या भयंकर बनी हुई है पिछले तीन चार साल से। 1990 की बाढ़ जब आयी थी उस टाइम बाढ़ के अन्दर जो भी हमारे 30–40 पंचायतें बाढ़ग्रस्त इलाके में जो पाइप लाइन टूटी थी पिछले दो, तीन साल से अभी तक कई-कई गांवों में कई-कई पंचायत हैड क्वाटर्स पर भी पानी नहीं पहुंचा है। पिछले 1987–88 में जवाहर रोजगार के तहत टांके, टंकियां बनायी गयी थी उनको भी अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया हैं। तहसील हैड क्वार्टर पर भी पानी की बड़ी भयंकर समस्या है। पिछली छुट्टियों में तहसील हैड क्वार्टर पर मैं गया था तो वहां के लोग इकट्ठा हो करके मेरा घेराव करने लगे। बोले आपके जीतते ही हमारे पानी की समस्या आ गयी। मैंने कहा मैं जीत तो जरुर गया मगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा हम तो आपका ही घेराव करेंगे। यहां कई जयपुर के सदस्य: कई बाहर के सदस्य बोले कि हम यहां मटका फोड़ेंगे और मेरा एरिया तो इतना लम्बा है वहां मटके से मेर सरा भी फोड़ देंगे तो यहां की सरकार देखने वाली नहीं है। पानी खारा है, खारे पानीपन से हमारे वहां भयंकर बीमारी फैली हुई है। पेट की बीमारी, कुबड़ापन की बीमारी, तरह-तरह की बीमारियां फैली हुई है। और कई इलाकों में आने-जाने का रास्ता ही नहीं हैं।

सभापति महोदय, अब सरकार बनने के बाद हमारे पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री महोदय दो बार वहां पर पधार करके आये हैं। पिछली सरकार के टाइम में भी मंत्री महोदय वहां गये थे नदी के बाहर से, गांव से बाहर सड़कें टूटी हुई थी तो कहा सहाव यहां एक यह बना दी जाये। सड़क बना दी जाये तो हमारा जो जहाप जो बड़ा कस्बा है वह जुड़ जायेगा। तो कहा एक महीने के अन्दर-अन्दर आर्डर दे देंगे। यह मंत्री महोदय ने कहा था और अबकी बार जब मंत्री महोदय वहां पधारे 132 के. वी. सब स्टेशन का उद्घाटन किया तो हमारे वहां के पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारीगण ने कहा और उन्होंने भाषण में कहा कि जो चतुर्वेदी जी कह देते हैं वह करके दिखाते हैं। शाम को डाक बंगले में उसी अधिकारी ने कहा कि चतुर्वेदी जी साहब मंत्री जी आपने कहा था और पिछली आपकी घोषणा बाकी है वह तो आप करवा ही दो। दूसरे ही दिन उसका ट्रांसफर हो गया। ऐसे हमारे सरकार के मंत्री जी हैं। जो बात उनको याद दिला देते हैं तभी उनका वहां से ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसी सरकार को सभी वहां के पक्ष के माननीय सदस्य ने सभी ने धन्यवाद दिया। मैं भी मंत्री महोदय को धन्यवाद दूं कि मेरे यहां पिछले 4–5 साल में कोई काम नहीं हुआ उसी का धन्यवाद तो दे दूं; अध्यक्ष महोदय जी ने भी कहा था माननीय सदस्य बोल रहे

(श्री हीरालाल विश्नोई)

थे तो आपने धन्यवाद दिया सरकार का इसलिये बोलने का टाइम ज्यादा दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरी समस्या अनेक हैं मुझे दो मिनट का मौका बड़ी मुश्किल से मिला है और ऐसा ही मेरा एक प्रश्न था माननीय जलदाय मंत्री जी ने मुझे जवाब भेजा है उस जवाब में लिखा है, मैंने कुओं के बारे में पूछा था कि आपने वहां कितने कुयें बनाये हुये हैं पी. एच. ई. डी. के तहत ? माननीय मंत्री जी ने मुझे जवाब में लिखा है 42 कुयें खोदे गये हैं 19 कुओं में विद्युतीकरण नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जब कुयें बनाये थे, टांके बने हुये हैं तो विद्युतीकरण अगर नहीं करेंगे तो उन कुओं का क्या होगा ? मगर कर्मचारियों की और अधिकारियों की भी मिलीभगत हैं सरकार के साथ या तो सरकार करना नहीं चाहती या उनको कुछ अनियमितता करने से कोई पाबन्दी नहीं है। उसमें सरकार का खर्चा बताया है 38 लाख 40 हजार 42 कुओं पर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मंत्री जी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे वहां कुयें बनाने के अन्दर 25–30 हजार से ज्यादा कभी भी कोई कितना भी ट्यूब वैल खोद दें तो भी खर्चा नहीं आ सकता और मैं यह लिख कर आपको देता हूं कि आपका जो भी ठेकेदार जिसको भी आपने ठेका दिया है वह सभी उन्हीं अधिकारियों के घर काम करने वाले हैं कोई ठेकेदार नहीं।....

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, मेरी दो-चार समस्याएं हैं, पूरी करने दीजिये।

श्री सभापति : मैं आपको तीन दिन से लगातार सुन रहा हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : तो, मंत्री महोदय जी, ऐसे-ऐसे अधिकारी वहां बिराजमान हैं। 38 लाख रुपये का खर्चा करने के बाद भी अभी भी 19 कुएं बाकी पड़े हैं और अभी तक मेरे यहां एक चोहरा और अरनाय गांव के अन्दर तीन कुएं बनाये। उन तीनों कुओं के अन्दर अभी पाइप लाइन नहीं है, कुएं बनाएं हुए हैं विद्युतीकृत नहीं हुए फिर भी सोर्स के लिए नये कुएं जरुर बनाये जाते हैं। अभी अरनाय गांव में एक कुआं ऐसा बनाया पहले ही अरनाय गांव के नाम से चोहरा में एक और बनाया था अब फिर एक और बना दिया। हमारे माननीय मंत्री जी बिराजमान हैं हमारे जिले के और गृह मंत्री जी भी हमारे जिले से एम. पी. रहे हैं, वहां की स्थिति जानते हैं, लोगों ने इनको इसलिए वोट दिया था कि....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, कई गांव मेरे ऐसे पड़े हैं।

श्री सभापति : सूची दे दें आप।

श्री हीरालाल विश्नोई : सूची दे देंगे। सभापति महोदय, मगर कई गांव

(श्री हीरालाल विश्नोई)

ऐसे पड़े हैं वहां चार-चार साल से खारा पानी है और टांके बने हुए हैं, स्कीम बनी हुई है और वहां पानी नहीं पहुंच रहा है ।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल विश्नोई : जैसा कि गांव का नाम ही पंचायत हैड क्वार्टर का खारा है और पानी भी खारा है । चार साल से स्कीम बनी हुई पड़ी है और वहां पानी बिल्कुल नहीं पहुंचा है । जो भी एस.सी., एस.टी. की बस्ती हमारे सूराचन, सूथड़ी, रीड़का, भीमगुड़ा, खेजड़िवाली पंचायत, जियाल....

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ । श्री प्रभूराम ग्रासिया ।

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदय, दो मिनट, मेरी....(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं क्षमा चाहूंगा, हां नहीं करूंगा ।

श्री हीरालाल विश्नोई : ढाणी सियाल, टांका, सुथारा की ढाणी, हनुमान चौकी, माणियों की ढाणी, रतनपुर मेघवालों की ढाणी, निम्बाऊ मेघवालों की बस्ती....

श्री सभापति : भाषण समाप्त हुआ । श्री प्रभूराम ग्रासिया । माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री हीरालाल विश्नोई : चितलवाना, मैसाड़िया नाडी, पमाणा नाडी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर लूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा । जितने भी हमारे अधूरे काम पड़े है, माननीय मंत्री महोदय, यदि कुछ आश्वासन देंगे कि यह जल्द से जल्द पूरा करायेंगे और जो भी अनियमितता हो रही है उसके बारे में भी वह ध्यान देंगे । जयहिन्द, धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री प्रभूराम ग्रासिया ।

श्री प्रभूराम ग्रासिया (पिण्डवाड़ा) : सभापति महोदय, मेरे आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र में पिंडवाड़ा तहसील के सागवाड़ा में पानी की इतनी समस्या है कि औरतें बेचारी पांच-पांच किलोमीटर की दूरी से पूरे दिन पानी का काम करती हैं, घर का दूसरा काम नहीं कर सकती हैं । वहां हैण्ड पम्प खोदे थे किन्तु उसमें भी खारा पानी निकला और अभी भी जो हैण्ड पम्प हैं वह खराब हैं । सांगवाड़ा, बाटेरा और बारजा, वीरवाड़ा, वीरोली गांव हैं जहां पानी की इतनी भयंकर समस्या है जो हद से बाहर है और गर्मियों में तो कभी-कभी वहां टैंकर लगाये जाते हैं । इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी आपसे निवेदन करूंगा कि सांगवाड़ा, बाटेरा, वीरोल और वीरवाड़ा की समस्या को मध्यनजर रखते हुए सेंक्शन दिलायें जिससे इस गर्मी में उनको पानी की राहत मिले । आबू रोड में आधा घण्टे पानी मिलता है । आबू रोड बड़ी तहसील है वहां आधा घण्टा ही पानी मिलता है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर आपने जो स्कीम बनायी है उससे आबू रोड को

(श्री प्रभूराम ग्रासिया)

ज्यादा से ज्यादा पानी मिले ग्रौर जहां शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स इलाकों में अभी तक पाइप लाइनें नहीं लगायी हैं वहां लगायी जाय। जैसे स्वरूपगंज में एक इंच की पाइप लगी हुई है वह पुरानी है और कनेक्शन ज्यादा। इसलिए मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि वहां पाइप लाइन सेंक्शन करवा कर उनको पानी दिया जाय।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर भारद्वाज।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : सभापति महोदय, पेयजल की चर्चा सदन में हो रही है, जयपुर में बाहर से पानी लाने की बीसलपुर की योजना पर सुबह चर्चा हुई थी।

श्री सभापति : आप जयपुर के बारे में बोल चुके हैं, माननीय सदस्य, आप ग्रपनी समस्या के बारे में बता दें।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। जो ग्रभी कच्ची बस्तियों के लिए सरकार की ग्रोर से एक निर्णय हुआ है कि उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाय। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं जो मेरे क्षेत्र में बहुत सारी कच्ची वस्तियां हैं....

श्री सभापति : मंत्रीजी ग्रापके बगल में ही रहते हैं।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : उनमें कई सारी बस्तियों में ऐसी समस्या है जहां पाइप लाइन नहीं जा सकती तो उस बस्ती में जो योजना बनी है उसके तहत उस पर काम शीघ्र शुरू करवाया जाए। वहां टकी बना कर जो पानी देने की योजना बनायी है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन उसमें तत्काल काम शुरू करवाये जाय। कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिनका मैं जिक्र करना आवश्यक समझता हूं, जो सोसायटी के द्वारा बनी हुई हैं। उन बस्तियों का निश्चित रूप से ध्यान रखा जाय ग्रन्यथा गर्मी शुरू हो गयी ग्रौर पानी की समस्या ग्रभी से खड़ी हुई है। तो जो सोसायटीज द्वारा बसायी गयी बस्तियां हैं उनकी जो प्राइवेट पाइप लाइन ग्रौर उनके कुएं हैं उनको सरकार ग्रपने हाथ में लें, उनमें व्यवस्थित रूप से पानी देने की कोई योजना तत्काल हाथ में लें। इसी तरह से बस्तियों में सीवरेज लाइन नहीं है जिसके कारण जयपुर में गंदा पानी ग्राता है, शास्त्री नगर क्षेत्र में अनेक बस्तियां जिनमें विश्वकर्मा कालोनी है, शिवाजी नगर है, व्यास कालोनी है, बेरिया बस्तियां हैं, बलाई बस्ती है इन बस्तियों में भी सीवरेज लाइन शुरू करवाई जाय तो मैं समझता हूं उचित होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री माधवसिंह दीवान। (ग्रनुपस्थित)। श्री भरत सिंह (ग्रनुपस्थित)। श्री हरिसिंह कुम्हेर (ग्रनुपस्थित)। श्री हरिसिंह महुग्रा।

श्री टीकमचन्द कान्त : ग्रगला नाम बोलिये, सभापति महोदय।

श्री सभापति : हां, नहीं बोलना चाहते ?.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं थोड़ी सी तो ग्रर्ज कर दूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दें इनको दो मिनट ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं-नहीं, इतनी-सी अर्ज कर रहा हूं, सभापति महोदय....

श्री सभापति : आपने हाथ किया था इसलिए मैंने पुकारा ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जहां बेदर्द हाकीम हो वहां फरियाद क्या करना, बस इतना ही कहना है ।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री एमामुद्दीन जी (अनुपस्थित) । श्री महावीर भगोरा ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, मैं हरिसिंह जी को एक मुक्तक पेश कर रहा हूं ।

श्री सभापति : हां ।

श्री महावीर भगोरा : "जल जोहरी, जल हीरा, जल मोतियन की खान, निगाह उठा कर देखिये, जल बिन जग कंगाल" । पानी की स्थिति, जल की स्थिति यह है कि इतना महत्व है उसका परन्तु आजादी के इतने वर्षों बाद, 46 वर्षों बाद तक जिस किसी पार्टी का शासन रहा है हमारे आदिवासी क्षेत्रों की क्या स्थिति है, यह थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं । सभापति महोदय, कोटड़ा पंचायत समिति में 304 गांव हैं और हमारे यहां ढाणियां नहीं बोलते फले बोलते हैं । फले वगैरह मिला कर 12 सौ बस्तियां हैं इनमें सिर्फ एक स्कीम जलप्रदाय की कोटड़ा मुख्यालय पर है इसके अलावा किसी भी गांव में नहीं हैं । यही हाल गोगुन्दा तहसील का है । गोगुन्दा में 148 गांव हैं, 148 में सिर्फ 9 गांव में जलप्रदाय स्कीम है । यह तो भला हो यूनीसेफ और विश्व के अन्य संगठनों का जिनके माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वरना वहां का आदिवासी, भीखा भाई जी बैठे हुए हैं, नारू के रोग से जिस तरह की इनकी स्थिति हो गयी है ऐसी हजारों आदिवासियों की स्थिति हो चुकी है....(व्यवधान).... हंसने की बात नहीं है, श्रीमान्, आज भी वहां का आदिवासी, मैं बता रहा हूं 12 सौ बस्ती में मे सिर्फ एक जगह योजना है और इधर 148 गांव में 9 जगह । मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहता हूं कि जन जाति क्षेत्रों में आबादी इतनी बिखरी हुई पहाड़ी क्षेत्रों में है कि वहां आपके हैण्ड पम्प और जलप्रदाय योजना की स्कीम बनाने के जो नार्म्स हैं उनमें कृपया शिथिलता बरतते हुए 50 से 100 की आबादी में एक हैण्ड पम्प और हजार की आबादी में जलप्रदाय योजना चाहे पी.एन.टी. से हो, चाहे टी.एस.एस. स्कीम से हो, जो भी स्कीम हो उसमें करवाने की कृपा करें ।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, सुनने की कृपा करें । हमारे क्षेत्र में ऐसे गांव और बस्तियां हैं जो अपना गांव अपना काम योजना में इस जलप्रदाय स्कीम को भी लेना चाहते हैं । क्या सरकार ऐसी योजनाओं को मंजूरी देना चाहती है ? इस पर भी मैं थोड़ा सा जानता हूं । साथ ही, वर्तमान में जो स्थिति है, अभी जो हैण्ड पम्प हमारे यहां स्वच्छ परियोजनाओं के द्वारा, नारू परियोजनाओं के द्वारा स्वीकृत

(श्री महावीर मगोरा)

किये गये हैं परन्तु आज की तारीख तक रिगें उन पाइंट्स तक नहीं पहुंची हैं। वर्षा के दिनों में यह रिग्स वहा नहीं जायेंगी तो जल्दी से जल्दी आप निर्देश जारी करावें कि वे रिग्ज तुरन्त सिलेक्टेड पाइंट्स पर चली जायं और हैण्ड पम्प खोदें।

इसी तरह से, एक निवेदन कर रहा हूं कि विभागों में समन्वय नहीं है। हमारे यहां चार विभागों के द्वारा या परियोजनाओं के द्वारा हैण्ड पम्प खोदे गये हैं चाहे कासा स्कीम में हों, स्वच्छ परियोजनाओं में हों, नारू उन्मूलन में हों या वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा हो इनमें आपस में समन्वय नहीं होने से हैण्ड पम्प्स की रिपेयरिंग नहीं हो रही है। इसी तरह से पंचायत समिति जब हैण्ड पम्प रिपेयर करती है और वाटर वर्क्स खोदता है तो इसमें भी यह स्पष्ट नहीं है कौन इसको रिपेयर करेगा तो इसी पर भी समन्वय की कृपा करें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री महावीर मगोरा : दूसरी तरह से, टी.एस.एस. स्कीम में कुआ वगैरह खोदने के काम तो पी.एच.ई.डी. करता है परन्तु बिजली का कनेक्शन बिजली विभाग करता है और महीनों तक कनेक्शन नहीं होता। तो इनमें भी समन्वय कराने की कृपा करें।

साथ ही मेरा एक निवेदन और है कि इन डिपार्टमेंट्स में जिस जगह पर जिन अधिकारियों की पोस्टिंग्स की गयी हैं, वह हैड क्वार्टर पर नहीं रहते हैं और कई अधिकारियों को डेप्युटेशन पर लगा रखा है। मेहरबानी करके उनको हैड क्वार्टर पर रखने के निर्देश जारी करावें। यह मेरा निवेदन है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री शैलेन्द्र जोशी (अनुपस्थित)। श्री रामगोपाल बैरवा (अनुपस्थित)। श्री रामस्वरूप मीणा। आज बोलने दें माननीय सदस्य उनको।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आपसे सबसे पहला मेरा करबद्ध निवेदन है कि आज मैंने शान्ति का दान दिया है, दिन भर इंतजार कर रहा हूं। कृपया जब तक मैं बोलूं, मुझे बोलने दें और पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल मात्र पांच मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोलें लेकिन आपने शान्ति का दान दे दिया वह इधर आ गयी, अब तो मुश्किल हो जायेगी इसलिए आप अपनी समय सीमा में बोलें।....(व्यवधान).... सुनें आप उनको।

श्री रामस्वरूप मीणा : आदरणीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कृपया मेरा सहयोग करें यह जन समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस सदन को इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि यह पानी के लिए पैसा दान कर लोग प्याऊ लगाते हैं, पुण्य करते हैं, पानी पिलाते हैं यह हमारी परम्परा रही है, हमारा इतिहास रहा है, हमारा यह धर्म रहा है। आदरणीय हमारे मंत्री महोदय बिराजमान हैं, आपका भाग्य है कि आपको सारे राजस्थान को पानी पिलाने का धर्म का काम

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मिला है। इसलिए मैं तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो धर्म का पैसा आपने दिया है। मेरे क्षेत्र में धर्म के पैसे से रात-दिन दारू के दौर चल रहे हैं।....(व्यवधान).... आप कृपया मेरी सुन लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया सुन लें।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह बड़ा दुःख का मामला है, मैं मेरे दुःख को प्रकट कर रहा हूं। आप कृपया हंसें नहीं इसमें।

श्री सभापति : कृपया सुनें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में हैण्ड पम्पों में कुछ घोटाले हुए हैं माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूं, बस थोड़ा ही है ज्यादा नहीं है। हैण्ड पम्पों में घोटाला हुआ है ठेकेदारों की मिलीभगत से। एक ही ठेकेदार को ढाई सौ हैण्ड पम्पों का ठेका दिया गया है। यह भी एक बहुत बड़ी मिलीभगत थी मेरे डिवीजन के अन्दर और उस ठेकेदार ने हैण्ड पम्पों में क्या किया यह निवेदन कर रहा हूं। विभाग के मापदण्ड के अनुसार 60 मीटर गहरा हैण्ड पम्प, प्रति हैण्डपम्प 26,840 रुपये की लागत बनती है आपके डिपार्टमेंट की। वैसे पूरा विवरण है किस-किस तरह से खर्चा आता है लेकिन कुल मिला कर 26,840 रुपये लागत बनती है लेकिन विभाग द्वारा, माननीय सभापति महोदय, जो भुगतान किया गया है वैरीफिकेशन करके माप पुस्तिका में दर्ज करके 60 मीटर गहरा प्रति हैण्ड पम्प 49,720 रुपये का भुगतान हुआ है। एक 60 मीटर गहरे हैण्ड पम्प का 49,720 रुपये। अब इसमें कितना घोटाला हुआ है, 34,580 रुपये प्रति हैण्ड पम्प, माननीय मंत्री महोदय। 34 हजार का मेरे पास पूरा रिकार्ड है मापदण्ड का, वह मैं आपके समक्ष पूरा पेश कर दूंगा।

दूसरा मेरा निवेदन है, यह तो 34 हजार रुपये प्रति हैण्ड पम्प का हुआ है : एक ही ठेकेदार को जब ढाई सौ हैण्ड पम्प दिये गये हैं तो टेण्डर नोटिसों को निरस्त कर दिया वहां के अधिकारियों ने और निरस्त करके एक ही वहां के ठेकेदार को ढाई सौ दे दिये गये। इतना बड़ा घोटाला हुआ है इसका भी मैं निवेदन करता हूं। नलों में पानी की हालत खराब। इसमें दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां भी 4 जो हैण्ड पम्प लगे हैं 1993 में, सांकरवाड़ा, होल्डा, भोपर, खादरपुर, कंजोली, पालड़ा, बजेरा, मल्डेलू हैण्ड पम्प लगाये। बी-क्लास की जगह एक्स्ट्रा लाइट पाइप लगाये। इनका 9 टन मात्र 40 किलोग्राम वजन, भुगतान 75 किलोग्राम माप प्रस्ताव में भी हैण्ड पम्प में से 1। इंच भरा है। पाइप 19 किलोमीटर बी-क्लास की जगह एक्स्ट्रा लाइट पाइप लगाये हैं भुगतान बी-क्लास का इस प्रकार से 9 लाख रुपये का घोटाला इसके अन्दर हुआ है। मेरे यहां पर क्यारदा, बाचना, करई कन्टीजेंसी के कार्य अगस्त में कराये हैं और उनका सारा पैसा जुलाई में ही एडवांस में दे दिया गया है। यह इतना पैसा जो एडवांस में दिया गया है इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? एक महीने पहले पूरा पैसा एडवांस में दे दिया गया है।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दूसरा, मोल्डा गांव के अन्दर एक ट्यूब वैल आपने बनवाया था जिसकी 75 हजार रुपये लागत आयी थी आज तक वह कुआ सूखा पड़ा है, मौका आकर देख लें माननीय मंत्री महोदय । इस प्रकार के मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने पेश किये हैं । एक-एक हैण्ड पम्प में जब 34-34 हजार का घोटाला हो तो मेरे यहां कितने हैण्ड पम्प लगे होंगे, राजस्थान में कितने हैंण्ड पम्प माननीय सभापति महोदय, लगे होंगे, उन सारे हैण्ड पम्पों की आप जांच करावें और यह पता लगावें कि क्या इन हैण्ड पम्पों में इतना पैसा लगा है क्या ? ये हैण्ड पम्प आज मौजूद हैं या नहीं ?

(21.55)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन ।)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है आज जो हैण्ड पम्प आपने मेरे यहां लगवाये हैं 50 पर्सेण्ट आपको हैण्ड पम्प नहीं मिलेंगे, दूसरी जगह मिलेंगे, जहां लगने चाहिए वहां नहीं मिलेंगे। उन हैण्ड पम्पों को दूसरी जगह लगा दिया है, जहां उनकी आवश्यकता नहीं है वहां पर उनको लगाया गया है । कई घोटालों की आपसे पहले शिकायत की गई है इसलिए मैं तो उन पर क्या शिकायत करूं । मैंने मेरे क्षेत्र की योजनाओं के बारे में पहले ही निवेदन कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय आपने मुझसे यह कहा था, सदन के अन्दर वायदा किया था कि मैं टोडाभीम चलूंगा, आपकी जितनी भी योजनायें अधूरी पड़ी हुयी हैं, आपकी जो टंकियां खाली पड़ी हैं, आज तक नहीं भरी गयी हैं बनने के बाद में, 10-10, 12-12 साल से उन सब की मैं इन्क्वायरी कराऊंगा और मौके पर ही आपके कामों को करके आऊंगा । मैं तो आपके इस वायदे से बंधा हुआ हूं माननीय मंत्री महोदय लेकिन मेरे जो घोटाले हुए हैं, मेरे यहां जो दुष्ट अफसर आपने लगा रखे हैं । मेरा यहां के ए.ई.एन., जे.ई.एन. जनता की खून पसीने की कमाई को रात-दिन दारू पीकर खर्च कर रहे हैं । आज यह सदन यहां बैठा हुआ है दिन भर से हम यहां बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं । इस समय किसी को भी भेज दो अगर दारू के दौर नहीं चल रहे हों आपके विभाग में तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । रात भर दौर चलते हैं उनके, ये लाखों के घोटाले करने वाला आपका नादौती में बैठने वाला ए.ई.एन. दिन-रात दारू पीता है । मैं सत्य कहता हूं इस सदन के सामने माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी रक्षा करना आप । ये मेरी नहीं सुनते हैं । ये सारे भम्भे ही भम्भे हो गए । आदरणीय श्री भंवर लाल जी भम्भा, आदरणीय भण्डारी जी भम्भा और आदरणीय भार्गव जी भम्भा बैठे हुए हैं । ये भम्भा ही भम्भा आप बैठे हो मत सुनो मेरे यहां के भम्भो, मेरा ऊपर वाला भम्भा सुन लेगा, भगवान ।

चार साल हो गये उस ए.ई.एन. को. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी हृदय की पुकार आपके सामने निवेदन कर रहा हूं । ये सारे भम्भे नहीं सुनेंगे, तो मेरा अध्यक्ष महोदय भम्भा बैठा हुआ है ये ही सुन लेंगे मेरी तो । आप भी भम्भे हो भम्भे ही भम्भे मौजूद हों और फिर भी प्यासा ही रहे मेरा क्षेत्र में....(व्यवधान....

श्री अध्यक्षः राजस्थान के सब भम्भे

(श्री अध्यक्ष)

[redacted]

नाराज हो जायेंगे आपसे। ये सोच लो आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से समस्त माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे है। मेरे क्षेत्र के अन्दर जिस ए.ई.एन. को लगा रखा है, दो बार ट्रान्सफर हुआ, दोनों बार कैंसिल करा कर ले गया। आपको मैं ईमानदार मानता था लेकिन वह कहता है मैं तो पैसा देकर कैंसिल करा लाता हूं, गण्डारी जी आप भी सुन लेना। मेरे ए.ई.एन. का दो बार ट्रान्सफर हुआ चार साल में और वापस वहीं चला गया टोडामीम में और दावे के साथ कहता है मेरा ट्रान्सफर कराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर उसमें गुण हो, तो आप मत करिये, मर्जी आये जिसको मेरे क्षेत्र में लगा दो, हटाओ उसको कराओ इन्क्वायरी जो भी क्षेत्र में घोटाले किये हैं। यही मांग है इस सदन से वरना मेरा इस सदन में आना ही बेकार है अगर इस पर कुछ नहीं हुआ तो इसलिए पुनः आपने जो मुझे समय दिया और मेरे दुख को सुना मुझे विश्वास है है मेरे इस सदन में बैठने वाले सभी मेरी पुकार सुनेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आपने आज अभी कहा था शांति का दान नहीं, अशांति का दान किया और शांति रखी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री कासनिया।

(22.00)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। (व्यवधान) मेरी राशि तुला है, इसलिए बता रहा हूं वह घोटाला क्या हुआ ? सन् 1988-89 से पहले जो भी स्कीमें बनी थीं उन स्कीमों के बारे में इस सदन में मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि वह सारी की सारी 70 प्रतिशत जो योजनाएं हैं, वह अधूरी हैं। किसी का चैनल टूटा हुआ है, किसी डिक्की का छल्ला टूटा हुआ है, कहीं पर फिल्टर चालू नहीं है। स्वच्छ-जल का तो खाली नाम है। यह तो अध्यक्ष महोदय, वह हुआ "बंदोरा पोती खाव, फेरा दादी ले ले"। मंत्री महोदय, यह बंदोरे तो कांग्रेस वाले खा गये। अब यह फेरे तो आपको लेने पड़ेंगे। उन स्कीमों पर अब आप मेहरबानी करके....

श्री अध्यक्ष : बंदोरे वाले को तो क्या मिला, मिलेगा फेरे वाले को ही।

श्री रामप्रताप कासनियां : मेरे क्षेत्र में पुरानी जो स्कीमें बनी हुई हैं और एक बाढ़ और आयी मेरे क्षेत्र में। कम से कम 1980-90 ऐसे गांव हैं, जिनमें हैण्ड पम्प लगे हैं। हैण्ड पम्प किस तरह से लगे ? जिस तरह से कांग्रेस सरकार के जमाने में अकाल राहत कार्य हुआ करते थे, उसी तरह से हैण्ड पम्प बड़ी तेज गति के साथ लगा दिये। यह नहीं देखा इन गांवों में पानी खारा है कि मीठा है।

श्री रामनारायण चौधरी : लगा तो दिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : लगा दिये, यह बात सही है। जहां 60 फीट पाइप कागजों में दिखा रही है, वहां 35 फीट ही नहीं मिलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप खारे

Page No.221

(श्री रामनारायण चौधरी)

में लगाकर तो दिखाओ।

श्री रामप्रताप कासनियां : जहां 40 फीट पाइप दिखा रखी है, वहां 10 फीट पाइप नहीं मिलेगी। जहां 5 फीट का फिल्टर दिखा रखा है, वहां 2 फीट फिल्टर नहीं मिलेगा। आप भी उन हैण्ड पम्पों को कटवा कर देख लीजियेगा कितना कागजों में पाइप दिखाया है फिल्टर दिखाया है, उसकी लम्बाई आपको नहीं मिलेगी। मेरा यह चार्ज है कि पूर्व में 70 प्रतिशत स्कीम में, सदन में बार-बार चार्ज लगा चुका हूं, परन्तु मंत्री महोदय उन स्कीमों पर आप कुछ तो रहम कीजिये, कुछ तो खर्चा कीजिये, ताकि ग्रामवासियों को उन स्कीमों से कुछ लाभ पहुंच सके और पीने के लिए पानी मिल सके। हमारे वहां कहने को तो नहरी इलाका है। हालात यह है कि पहले पीने के पानी के जो स्रोत थे, वह सारे के सारे खत्म हो गए। गांवों में कच्चे तालाब थे, वह तालाब तो सारे नष्ट हो गए और ना ही कोई और दूसरी व्यवस्था रही है। हालात यह है कि जिन गांवों में स्कीम चालू है और गांव में पाइप लाइन बिछी हुई है, घरों में कनेक्शन हैं, उन घरों में दो-दो मटके हैं। जब किसान शाम को खेत से घर आता है और घरवाली को कहता है पानी लाओ नहाने के लिए तो वह यह जवाब देती है कि फलां गांव से पहले पानी लाने की व्यवस्था करो फिर कोई बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कई बार तो घर में झगड़ा हो जाता है, इस बात को लेकर। अब माननीय सदस्यों का मन नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब आप जो मंत्रीजी का फेरा करोगे तो ढूंढ लो पहले, नहीं तो वैसे ही बैठे रहोगे। श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : मैं सबसे पहले माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि जब पिछली बार आप बेगूं क्षेत्र पधारे थे, श्रीनगर में पेयजल पनघट योजना का उद्घाटन किया था उसके बाद एक योजना और हमारे यहां पाचना में लग गयी है और दोनों योजनाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। साथ ही मुझे खेरपुरा और रायता दो पनघट योजनाओं का आश्वासन विभाग की ओर से मिला है और मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय उन पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

मेरा हैण्ड पम्पों की समस्या के बारे में कुछ सुझाव यह है कि जल स्तर ऊपर बढ़ाने के लिऐ तालाब-तलैया, एनीकट जो भी सम्भव हो, प्रत्येक गांव में ये निर्मित किये जायें। दूसरा, जो गांव वाले सहयोग कर रहे हैं, मान लीजिए वह ट्यूब वैल खुद खोदना स्वीकार करते हैं, मेरे इलाके में कुछ ऐसे गांव भी हैं तो उनको कनेक्शन और पाइप की सुविधा अगर सरकार दे दे तो उनकी हमेशा-हमेशा के लिए समस्या हल हो सकती है और हैण्ड पम्प की बीमारी से छुटकारा उनको मिल सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपका प्रस्ताव मंजूर है।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : धन्यवाद साहब, बहुत-बहुत।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। गुर्जर साहब मिल गया, बहुत लोग तो प्यासे ही

(श्री अध्यक्ष)

जायेंगे । बैठिये–बैठिये हो गया ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : एक-आध बात और....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका काम । मेरे पास जो कटौती प्रस्तावों की सूचना आयी थी मैं समझता हूं उसमें लगभग सब बोल चुके हैं यदि भूल से कोई, जिसने कटौती प्रस्ताव दिया है और वो बैठे हैं, बोलना चाहें तो बोलें ।

कई माननीय सदस्य : सब हो गये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसराम जी मदेरणा ।

श्री परसराम मदेरणा(नेता, प्रतिपक्ष) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 द्वारा कई माननीय सदस्यों ने पेयजल की जो विषम और विकट समस्या राजस्थान में खड़ी हो गयी है, उसके निराकरण और समाधान के लिए कई प्रकार के सुझाव दिये हैं । अध्यक्ष महोदय, इस साल राजस्थान में त्रिकाल है अनाज का भी अकाल है, चारे का अकाल है । और पानी का अकाल है । पानी की समस्या आने वाले दिनों में ग्रीष्मकाल में और भी विकट होने की सम्भावना है । इस ओर सरकार का ध्यान माननीय सदस्यों ने आकर्षित किया । मैं यह मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जब बिजली के अन्दर डिमाण्ड और सप्लाई पर करीब 49 पर्सेन्ट का और 50 पर्सेन्ट का गैप है और आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि बिजली को जनरेशन के हम प्रोजेक्ट्स समय पर प्रारम्भ नहीं कर सके । जस्टेशन पीरियड पांच वर्ष का है । मैं ऐसा मानता हूं मंत्री महोदय कि राजस्थान जो पूरे देश का जीओग्राफीकली 10 फीसदी इलाका है और पानी एक फीसदी है । पानी एक फीसदी होने के अलावा जो पिछले सात-आठ वर्षों से उसके कई कारण हैं अध्यक्ष महोदय, एक कारण नहीं है कि पानी का जल स्तर नीचे ही नहीं जा रहा है लेकिन पानी के स्रोत सूख गये हैं और इसलिए आने वाले समय के अन्दर पानी की डिमाण्ड और सप्लाई के बीच जलपूर्ति और जल की मांग के बीच में 500 पर्सेण्ट का गैप रहेगा । इसका मुख्य कारण, अध्यक्ष महोदय, यह है कि बढ़ती हुई आबादी, जनता के रहन-सहन के स्टेण्डर्ड की वजह से पेयजल की मांग, राजस्व के ग्रामों के अंदर आपके सामने समस्या यह है कि राजस्व के नये ग्राम बनने की वजह से 2500 गांवों की बढ़ोतरी, 18000 ढाणियों का जिक्र जो आपने अपने प्रगति विवरण में किया है, वह भी एक समस्या है अपने आप में, जबकि इस साल आप करीबन-करीबन केवल 500 ढाणियों को लेने जा रहे हैं । अब इस पेस आगे जा रहे हैं और कितने वर्षों तक इस समस्या का समाधान कर सकेंगे, यह सरकार के आगे दूरगामी क्या दृष्टिकोण हैं, उन पर मुनस्सर रहेगा । औद्योगिकरण के कारण जल का प्रदूषण हुआ है । क्वालिटी डिटोरियट हुई है पानी की, इसकी वजह से चार हजार गांवों में फ्लोराइड है और उसी प्रकार करीबन तीन साढ़े तीन हजार गांवों के अंदर ब्रेकिश वाटर है । भरतपुर का एरिया, गंगानगर का एरिया, आपके बाड़मेर एरिया जोधपुर की लूणी तहसील, आपके पाली की अरोहर तहसील, बाड़मेर की बालोतरा तहसील, इसमें नीचे का पानी बिलकुल

(श्री परसराम मदेरणा)

अंकिश है, खारा पानी है। उसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, कई प्रकार के जीओफिजिकल चैन्जेज हो रहे हैं और उसकी वजह से जो गांव आज नोन प्रोब्लैमैटिक हैं, वह कल प्रोब्लैमैटिक बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां 24 हजार गांवों को प्रोब्लैमैटिक समझ रहे थे आज हम 34 हजार को समझ चुके हैं। अब यह सोचते हैं कि उससे ज्यादा समस्या और आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। उसके साथ ही साथ नीचे का आज बीओफिजिक्स है, एक बाड़मेर का उदाहरण देना चाहता हूं आपको बाड़मेर शहर को पानी आप बोदिया भाड़ता से दे रहे हैं। मैं वहां पर था, अध्यक्ष महोदय, अभी वहां पर जो पानी आ रहा है, उस पानी में गर्मियों के दिनों में गीजर के अंदर रस्ट लगने से सब गीजर टूट रहे हैं, पाइप लाइन फट रही है।

मैंने पूछा इसका कारण क्या है तो मुझे यह बताया गया कि उधर नीचे जमीन के अन्दर जीओफिजिक्स है इस एरिया की उसमें कार्बन मोनो आक्साइड और कार्बन डाइ आक्साइड की मात्रा आक्सीडेशन ज्यादा है और इसकी वजह से कैमिकल रिएक्शन से एसिडिक नेचर की वजह से पाइप लाइन और पम्पस में रस्ट लग जाती है और केसिंग पाइप तीन साल के अन्दर खराब हो जाती है। एक केसिंग पाइप का ट्यूब वैल बनाने के अन्दर आपको चार लाख रुपये है, यह लोंगेविटी है उसकी चार-साढ़े चार लाख रुपये के ट्यूब वैल बनाने के बाद में आज उस ओर आपका ध्यान गया कि नहीं गया, मैंने आज मालूम किया था इस स्कीम को सैंक्शन करते वक्त यह प्राब्लम आपके डिपार्टमेंट के ध्यान में है और मैं समझता हूं कि इसका समाधान किया जा सकता है अगर उसके अन्दर अन्य प्रकार के मैटीरिअल इस्तेमाल किये जाएं तो। साथ ही आज सोच तो यह रहे थे कि मिनिमम सर्विस ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लोगों को, कन्ज्यूमर्स को देंगे, जो 18 गैलन के आस पास बनती है लेकिन बढ़ती हुई आबादी की वजह से शहरों और गांवों के अन्दर, गांवों का प्रश्न नहीं है जो आपने रीजनल पाइप बनायी है टेल एण्ड वह मिसनोमर है और टेल एण्ड इसलिए मिसनोमर है कि आपने जो योजना बनायी है उसमें ह्यूमन पापुलेशन नहीं बढ़ी है, जनसंख्या आपकी बो बाइन पापुलेशन की बढ़ रही है उसका परिणाम यह हुआ कि आपके टेल एण्ड गांवों के अन्दर ह्यूमन पापुलेशन को एक लीटर पानी पीने को नहीं मिल रहा है, यह आज समस्या है। और यह समस्या आज की नहीं है। इसी वजह से रेगिस्तानी 10 जिलों के अन्दर किसी स्कीम को बनाते वक्त मिनिमम पानी सप्लाई की जो सर्विस रखनी है वह 70 लीटर रखनी है इसलिए किया गया था। लेकिन 70 लीटर रखने के बाद में उन स्कीम्स को अगर आप रिआर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं तो वह अपने आप में प्राब्लम है। और आप खुद इस प्रोब्लम को समझते हैं और प्रोब्लम को समझते हुए भी आज ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर, अभी लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने प्रावधान कैपिटल हैड के नीचे 236 करोड़ रुपये के आसपास रखा है, कुछ आपके सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम का यह ट्रान्सफर होगा, 41 करोड़ और कुछ लाख के आस पास....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : 42 करोड़ है।

श्री परसराम मदेरणा : 42 वह आपको गलत बताया है। 41 करोड़ और 83 लाख है। आप हैड देख लीजिये। अगर आप हैड चाहते हैं तो मैं हैड बता देता हूं आपको। खैर, आप देख लीजिए। 41 करोड़ 83 लाख आपके वोल्यूम तीन के अन्दर पेज 205 के ऊपर है। वोल्यूम तीन आय-व्ययक का है उसमें 205 के ऊपर देख लीजिए। 41 करोड़ इतने लाख हैं, 42 समझिये उसका कोई मतलब नहीं, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप 42 करोड़ की बात कर रहे हैं लेकिन साढे चार करोड़ की राजस्थान की जनसंख्या में से साढ़े तीन करोड़ तो ग्रामीण जनसंख्या है और एक करोड़ शहर की जनसंख्या है। इसके अन्दर बीच के अन्दर जो आपने पेरिटि रखी है वह पेरिटि गांव के लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन है जब कि वहां प्रोब्लम बहुत ज्यादा विकट और विकराल है, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमने 62 पर्सेण्ट पूरे प्लान का उधर ट्रांसफर कर दिया है। यह भी कई दफे मैं यहां कह चुका हूं कि सब आइटम को आपको बताना चाहिये कि किस-किस सेक्टर के अन्दर कौन सी योजनाओं में उसका पूरा बेनिफिट रूरल एरिया को मिलेगा इस सम्बन्ध में सरकार चुप्पी साध लेती है। 62 पर्सेण्ट का एक बड़ा आंकड़ा हमारे पास में रख देती हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि अभी यहां टेन्थ फाइनेंस कमीशन आया था और टेन्थ फाइनेंस कमीशन के सामने सरकार ने पेयजल की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों की रखी थी वह अपने आप में इस हाउस का ज्ञान-वर्द्धन करेगी कि गवर्नमेण्ट का मेमोरेण्डम इस प्रकार का है "On account of recurring droughts resulting in receding water table assures source of drinking water supply in most areas of the State is eluding a solution. The past investment made in tubewells the handpumps and pipes water supply scheme have become infractuous. On account of the receding water table for augumenting the existing water sources and providing a minimum service level of water supply. In the rural areas alone an investment of Rs 7 thousand crores at current prices would be required on conservative basis. The details in this regard shall be submitted to the Commission separately." वह तैयार हो रहे हैं, आपने देखे होंगे। जब सात हजार करोड़ आज की प्राइसेज के ऊपर एक मिनिमम सर्विस देने के लिए रूरल एरिया के अन्दर आपको चाहिए और आप डिमाण्ड संख्या 200 है, 27 से केवल आप ग्राण्ट करना चाहते हैं 74 करोड़ और कुछ लाख रुपये इसमें से आधे से ज्यादा आपका नान प्लान एक्सपेण्डीचर है। इस स्नेल पेस से जाकर आप यह समझते हैं कि राजस्थान की समस्या का समाधान कर सकेंगे और इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय,....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 हजार करोड़ की जो योजना है वह तो भारत सरकार को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भेजी है वह तो किसी कर्जे से या लोन से या उससे होगी तो वह रेग्युलर डिमाण्ड में कहां से आयेगी। जब यह सैंक्शन होगी तब रेग्युलर डिमाण्ड में आयेगी।

श्री परसराम मदेरणा : प्रोब्लम कितनी माइरेड है उसकी ओर मैं हाउस का ध्यान दिला रहा था। इस सात हजार करोड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि सात हजार करोड़ जब आप कह रहे हैं मैं तो इनकी प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग की बात कर रहा था और जब प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग की बात कर रहे थे उस पर ही आना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस सम्बन्ध में, यह विभाग मेरे पास में रहा है और जब विभाग मेरे पास में रहा है तो मैंने यह सोचा है, मैंने गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया के सामने यह बात रखी थी कि रीजनल पाइप लाइन बिल्कुल किसी काम की नहीं है, टेलएण्ड पर कभी पानी नहीं पहुंचना है, एक बात। मैंने यह बात भी उसमें कही है मैं वह स्पीच रख दूंगा अभी सदन की टेबल पर, पढ़ने के लायक है। मैंने यह बात भी कही कि विलेज़ को कवर करने की बात कही वह एक वाटर पाइंट से मिसनोमर है और उससे केवल कवरेज होता है वह 20 पर्सेंट पापुलेशन का होता है, 80 पर्सेण्ट पापुलेशन का कोई कवरेज नहीं है, उनको ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध नहीं हो रहा है और उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहां पर पूछ रहे थे कि कौन से सजेशन आने चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर सजेशन भी यहां पर दिये हैं और मै यह निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि एक एक बूंद पानी की बचाये बिना और ट्रेडीशनल पानी सोर्सेज है उनको वापस रेस्टोर किये बिना हम इस पानी की समस्या को और गहरा सकते हैं।

इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि 1974 में प्लानिंग कमीशन के मेम्बर बने थे मिस्टर मैनन और साइंस एण्ड टेक्नोलोजी मिनिस्टरी के जो एडवायजर भी रहे हैं उन्होंने जोधपुर में कन्वोकेशन एड्रेस करते वक्त 1974 में एक बात कही थी और एक वार्निंग दी थी कि राजस्थान में आने वाले समय में पानी का ड्रोवल इस लेवल पर अगर होता रहा तो राजस्थान के सामने 20 साल के बाद में कोई विकल्प नहीं रहेगा और आपकी पापुलेशन को माइग्रेट करना पड़ेगा और मैं उस समय वहां, था उस वक्त मैं बाई चान्स जोधपुर में था, मैंने कहा आज कन्वोकेशन एड्रेस में इन्विटेशन आया है मुझे जाना चाहिए और उसकी कापी मैं लाया था, बाद में जाकर के जब मैं सिंडीकेट का मेम्बर था तब वह पी. एच. ई. डी. को दी थी कि यह वार्निंग है यह आपके लिए इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज हम स्टेण्डर्ड की बात नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की कमी हैं लेकिन मंत्री जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त जोधपुर में मैने हैण्ड खुदवाये थे और इस बात के ऊपर यहां पर बहुत जोरदार चर्चा हुई थी कि आप एक्सेस नाइट्रेट वाला पानी हैण्ड पम्प के जरिये जो लोगों को दे रहे हैं और उस वक्त बी. जे. पी. का एक शिष्टमण्डल श्री

(श्री परसराम मदेरणा)

गिरधारीलाल भार्गव और श्रीमती उजला जी के नेतृत्व में करीबन 10–15 लोग मेरे पास में आये थे। मैंने कहा अगर आप लिख कर दे दीजिये कि आप इसमें एतराज नहीं करेंगे। रेड प्लेट लगा दूंगा कि सिर्फ लोण्ड्री के काम में, कपड़े धोने के काम में, बर्तन धोने के काम लेंगे लेकिन इस बात को जब आपके नेता हाउस में यह कह रहे हैं कि नाइट्रेट ज्यादा होने की वजह से मैथनियोग्लोबीनिमिया हो जाता है, इन्फेंटाइल बीमारी हो जाती है, मतलब डेढ़ साल का बच्चा अगर वह पानी पी लेता है उसके अन्दर नाइट्रेट एम. जी. 20 तक भी हैं तो वह नीला पड़ जाता है। इसलिए जयपुर के 20 लाख के शहर के अन्दर चाइल्ड मार्टलिटी है, इन्फेंट मार्टलिटी, यह ट्यूब वैल आपके शहर के अन्दर लगे हुए हैं इनके सब की केमिकल जांच हो चुकी है उस पानी की आपकी लेबोरेटरी में और उसका देख लीजिये पर्सेण्टेज। कोई भी ट्यूब वैल में 100 एम. जी. से कम नहीं हैं। जबकि फोर्टी आखिरी लिमिट है। बाहर के फेराफेरी के काम ठीक हैं। उनमें प्रेसक्राइब पेरामीटर के अन्दर स्टेन्डर्ड केमिकल उसके नीचे है तो आप बाहर वालों की योजना बना कर गांवों में दीजिये। इन लोगों को आप जहर क्यों पिला रहे हैं। जहर पिला कर आप इन छोटे-छोटे बच्चों को नीला बना रहे हैं। यहां पर अभी किसी ने कहा, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, उन्होंने एक बहुत अच्छा दोहा कहा मंत्री जी के बारे में "रहिमन पानी राखिये"। उस पानी का मतलब चूने में, आटे में डालने वाला पानी नहीं है, पानी चाहिये मिनिस्टर के अन्दर। वह ग्रिट और मेंटल आपके अन्दर है क्या? वह पॉलिटिकल विल पावर हैं क्या? क्योंकि आज डिपार्टमेण्ट के अन्दर एक इमरजेंसी है, कंटीजेंसी प्लान आपके पास आये। सात करोड़ रुपये आपको फेमिन के अन्दर दिये। हमसे जो डिमाण्ड पास करायी है आपने यहां पर। वोट आन अकाउण्ट होता है तो पूरी डिमाण्ड कभी पास नहीं होती लेकिन चुपके-चुपके करा ली। हमने सोचा कि शायद क्यों करा लें इसलिए मुझे ऐतराज रहा थोड़ा सा। बता देते आपकी हम पूरी की पूरी इसको करवायेंगे, बाकी छह महीने का ले रहे हैं। ....(व्यवधान) नहीं वह स्थिति जो थी पूरी डिमाण्ड उसमें भी नहीं होती। लेकिन अभी सात करोड़ रुपये केलेमिटीज रिलीफ फण्ड आपको दिये हैं। डिमाण्ड नम्बर 34 को मैं देख रहा था डिटेल में, जब उसके पौथे देखे मैंने तो मालूम पड़ा कि केलेमिटी रिलीफ फण्ड के अन्दर जो अभी 216 करोड़ सेविंग है, 1994–95 में 124 करोड़ रुपये एड हो जायेंगे, तो कुल मिलाकर आपके पास में 340 करोड़ 18 लाख रुपये हैं। इस राशि के अगेनस्ट में पानी की इतनी भीषण समस्या राजस्थान में है और उसके निराकरण के लिए सरकार ने सात करोड़ रुपये आपको दिये और कंटीजेंसी प्लान आपने मंगाया। आप क्यों करेंगे यहां पर? और रखा क्या है? आप कह रहे हैं वह हमने टोटल रख दिया है। मैं चौमू से आने वाले माननीय सदस्य को कह रहा हूं कि 340 करोड़ 18 लाख में से 54 करोड़ रुपये रखे हैं आपने सिर्फ फेमिन के ऊपर जिसमें पानी भी शामिल

(श्री परसराम मदेरणा)

है, 17-17 करोड़ भी आस पास में इन तीनों को पानी, चारा और रिलीफ में बांट दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि आज आपके पास में वह अमाउण्ट है। यह एक बहुत बड़ी केलेमिटी ड्रिंकिंग वाटर की हो गयी है राजस्थान के अन्दर फेमिन की वजह से और आपके पास में फण्ड्स हैं तो आपको इमीजिएटली इस पानी की समस्या का समाधान के लिए क्योंकि लोग अभी यहां पर कह रहे थे कि आपने एक-एक जिले में दस-दस, बारह-बारह हैण्डपम्प दिये हैं, हैण्ड पम्प देने के बाद में जहां पर पानी नीचे हैं अगर पानी का स्तर गिरा हुआ नहीं है और हैण्ड पम्प खुद सकते हैं तो वार फुटिंग के ऊपर खुदाना चाहिये। वार फुटिंग में खुदाने के अन्दर मंत्री महोदय कुछ लोग यहां आफिसरों की तारीफ कर रहे थे, मैं समझता हूं कि आफिसर कुछ नहीं है मिनिस्टर अगर ग्रिट वाला है और उसमें वह मैंटल है तो आप कैबिनेट में बैठ कर कम से कम सौ करोड़ रुपये 340 करोड़ में से रखिये पानी के लिए, 15 दिन के अन्दर आपके हैण्ड पम्प खुद सकते हैं और हजारों खुद सकते हैं, जहां पानी है। अबंडन्ड वहां पर खुद सकते हैं जहां नीचे पानी है। रिपेयर्स का काम है तो वह भी वार फुटिंग में लीजिए। वार फुटिंग के ऊपर लेने पर मैं एक सजेशन दूंगा कि इनको मोनिटरिंग के लिए यहां अफसरों की चिलम भरने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको इनकी ड्यूटी लगानी चाहिये कि नाइट होल्ड यह तीस दिन में से बीस दिन बाहर गांवों में करेंगे और वहां कांसटेंटली टास्क पर रहेंगे। अगर इस तरह की पाबन्दी नहीं करते हैं और आप सख्ती से इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो लोग पानी के लिए तरसते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक परम्परा है और आप यहां पर काफी उल्लेख भी करते हैं राजस्थान की स्वस्थ परम्परा की। यहां परम्परा यह है कि छह महीने बाद दुबारा असेम्बली मीट होती है तब तक लोग प्यासे मर जाएंगे।

मैंने दो-तीन सजेशन दिये है और एक सजेशन यह भी देना चाहता हूं कि लोंग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर आप 7 हजार करोड़ की स्कीम की दूसरी बात करते हैं, जोधपुर की लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम के सम्बन्ध में कुछ प्रावधान आपने करीबन तीस करोड़ के आस पास में रखा है, 34 करोड़ के आस पास। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह जोधपुर का प्रश्न नहीं है, पूरे के पूरे उत्तरी राजस्थान के अन्दर पानी की समस्या के सम्बन्ध में रतनगढ़ और मंडावा की बात भी हो रही थी, जब तक आप राजस्थान कैनाल से लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं नहीं बनायेंगे तब तक रूरल एरिया का पर्मानेन्ट सोल्यूशन होना असंभव है। मैं आपसे फोर कास्ट कर सकता हूं मैं ज्योतिषी नहीं हूं और इसलिए मैंने.... (व्यवधान) आप सुनिये। एक पैरा पढ़ाना चाहूंगा। सदन का समय नहीं लेना चाहता, बहुत ज्यादा समय हो गया है और मैं बोलना भी नहीं चाहता था, मैं बैठता हूं तो सुनता रहता हूं। मैं एब्सेन्ट माइंडेड कभी हाउस में नहीं बैठता, इसलिए आपने जो कहा है। 28 जुलाई, 1974 को। पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर कांफ्रेंस में मैंने क्या कहा है Though Rajasthan areawise is

(श्री परसराम मदेरणा)

the second largest State in India having 10 per cent of total geographycal area. We have hardly 1 per cent of total country's surface water resources. The only silver lining in this bleak picture is the Rajasthan Canal. बाद में नाम बदला था इसका इन्दिरा गांधी कैनाल। in true sense another Ganga coming from Himalayas after travelling 1200 Kms. The area on the right bank of the Canal would be irrigated by gravity flow. However, the vast areas on the left bank also deserve covering atleast for the drinking water by lift Canals the total cost of such scheme is due to its magnitude may have to be spilled over several plans' period. But start has to be made in the next plan मैं सिक्सथ प्लान पर बोल रहा था और इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि आप एट्थ प्लान के अन्दर दो साल के इस रूलिंग प्लान के बाद में एट्थ प्लान का तीसरा साल है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पांच या छह स्कीम की सर्वे की हुई है। मैंने एम. ई. और उनके साथ में तीन एक्स. ई. एन. लगा कर इस तरह की पांच-छह योजनाएं बनायी थीं और यह सोच कर बनायी थी कि आने वाले समय में पानी का कोई पर्मानेन्ट सोल्यूशन नहीं है। आप पैसा लगाते जाईये। आपने आज बहुत लम्बा चौड़ा विवरण भेजा है। एक बात तो मैं कहूंगा कि आपका एक अचीवमैण्ट जरुर है निश्चित तौर पर कि आप गिनी वार्म को इरेडिकेट करने में काफी सफल हुये हैं और बहुत सी स्कीम आपने भेजी हैं भारत सरकार के पास, जर्मनी के पास, यूरोपियन कम्युनिटी के पास, सभी जगह, काफी जगह स्कीम भेजी हैं। वह बहुत थोड़ी हैं। मैंने देख ली है कुल मिला कर एक हजार करोड़, जो सात हजार करोड़ की आप बनाने की सोच रहे थे, वह जल्दी बनाकर भेजिये, स्वीकृत कराइये। नहीं तो आने वाले समय के अन्दर आपने केवल बजट तो शिक्षा को सुपुर्द कर दिया। पानी तो नहीं वहां पढ़ेगा कौन? सबसे बड़ी प्रोब्लम आज डेजर्ट एरिये में आ रही है कि जहां आपने प्राइमरी स्कूल बनाई हैं वहां बच्चे खुद साथ में पानी लेकर आते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि बहुत बड़े-बड़े टांके बनाइये छोटे-छोटे टांके बना रहे हैं आठ-आठ, नौ-नौ हजार के, कोई मतलब नहीं है। मेरे फादर ने अपनी जिन्दगी में एक काम किया था उन्होंने टांका बनवाया। जो करीबन 60-70 फीट चौड़ा 40 फीट गहरा है और उसमें कम से कम 15-20 मवेशियों के लिए और एक फैमिली के लिए बारह महीने तक पानी आ जाता है कैचमैण्ट एरिया में।

श्री अध्यक्ष : कुआं ही बनाया है पूरा।

श्री परसराम मदेरणा : हां, बहुत बड़ा है। अभी तक मैं समझता हूं कि इतना बड़ा कोई टांका होगा ही नहीं कई जिलों के अंदर उन्होंने अपनी जिन्दगी में एक काम किया वह टांका बनाया। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था मंत्री महोदय कि आपके गिनी

(श्री परसराम मदेरणा)

वार्म वाले जो गांव बचे हुए हैं। वह 6776 गांव थे उनमें से सिर्फ 957 गांव बचे हैं और व्यक्ति जो प्रभावित थे 15210, वह रह गये हैं करीबन 792, इसका मतलब यह है कि इनमें आपके एक सौ और कुछ गांव ऐसे हो गये हैं जिनमें आपके अभी गिनी वार्म का पानी तो गड़बड़ है लेकिन वहां कोई गिनी वार्म किसी को नहीं है। जो बच गये वह 792 ही हैं और गांव 957 हैं। गांव अफेक्टेड कैसे हैं फिर उस पानी पीने से किसी को गिनी वार्म ही नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ? मेरे को समझ में नहीं आया। आप कृपया इसको एक्सप्लेन कीजिए। मैं यह कहूंगा कि बड़े-बड़े शहरों में भी, पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कि जोधपुर के अन्दर गुलाबसागर, फतेहसागर, उनमें जो मीठा पानी आता था और बहुत जो आस-पास की नहरें थीं उस पर लोगों ने ट्रेस पास कर दिया है। आप शहरों के अन्दर जब तक हमारे रेन वाटर में एडिशनल सोर्सेज हैं उनको वापस रेस्टोर नहीं करेंगे जगह-जगह एनीकट हैं एनीकट बनाने के बाद में अपने आप स्वतः ही वाटर लेवल कुओं का ऊंचा उठ जाएगा इसलिए आप एनीकट बनाने की योजना इसके साथ में डोवटेलिंग कीजिए ड्रिंकिंग वाटर के साथ में फेमिन के अन्दर जो आगे जाकर आप काम खोल रहे हैं नदियों के ऊपर। मैं यह नहीं कहता बड़े बांध बनाइये, बड़े बंधे उल्टे नुकसान करते हैं। लेकिन आप छोटे एनीकट बना रहे हैं वह निश्चित तौर पर आगे जाकर पानी की समस्या के समाधान के लिए हमारे लिए वरदान सिद्ध होंगे। इसके साथ ही आप जो ग्राण्ट हमसे स्वीकार करवा रहे हैं। रूरल एरिया के साथ में आपका डिस्क्रिमिनेशन है जो आपको नहीं रखना चाहिए। इस डिस्क्रिमिनेशन को, जो आपके पास हैड 34 के नीचे जो केलेमिटी रिलीफ फण्ड है उसमें से अमाउण्ट लेकर इस इम्बैलेन्स को मिटाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस समस्या पर हम विचार कर रहे हैं वह वास्तव में बहुत गम्भीर है। माननीय सदस्यों ने बहुत ही उपयोगी सुझाव अपनी चर्चा में दिये हैं और मैं तो यह कहता हूं यह एक ही समस्या ऐसी है, कई बार ऐसे प्रसंग सदन में आते हैं जब हम एकमत होते हैं, विपक्ष और प्रतिपक्ष आज का विषय भी ऐसा ही है। जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, सबकी वाणी एक, सबकी शिकायत एक, सबकी पीड़ा एक, सबके सुझाव एक। ऐसा विषय है जिसमें सारा सदन एक है और इसलिए मुझे बड़ी हिम्मत आयी है जब सारा सदन एक साथ मिल कर यह काम करेगा तो जो भी समस्या आज हमारे सामने है उससे संघर्ष करने के लिये हम निश्चित रूप से सफल होंगे। समस्याओं से संघर्ष करना पड़ेगा और आपको सहयोग करना पड़ेगा। संघर्ष और सहयोग दोनों ही इस समस्या से हमको पार करेंगे। वह पानी की समस्या कोई मनुष्य की क्रिएट की हुई नहीं है। जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय सदस्यों ने कहा और हम सब भी जानते हैं कि आज कुओं का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, किसकी ताकत है उसको रोके, कौनसा फार्मूला हो सकता

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है जिससे उसको रोका जाय, कौन सरकार इसमें मदद कर सकती है, कौनसा कानून अध्यादेश ऐसा हो सकता है कि इस काम को रोक देगा। मैंने शुरू में कहा था कि मेहनत पूरी करेंगे सब शक्ति लगायेंगे और फिर भगवान में भरोसा करो। माननीय सदस्यों ने कहा कि क्या राम भरोसे रहोगे? उसका भरोसा रखिये और परिश्रम करिये, मेहनत करिये। अपनी एक-एक पसीने की बूंद बहा कर के भी पानी पैदा करना, पानी लोगों को देना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा ध्येय है। उसमें भगवान की मदद मिलेगी। बरसात भी खूब होगी, हम निराशावादी नहीं हैं। हमारे रामस्वरूप जी....

श्री परसराम मदेरणा : संतोषी सदा सुखी, चूंकि यह जो फिलोसफी है। चाहे भले कोई भी तकलीफ हो लेकिन सदा सुखी रहना चाहिए। Woods are lovely dark and deep, I have promises to keep and, Miles to go before I sleep and, Miles to go before I sleep. You should have some destination इसलिये मैंने यह डेस्टीनेशन बताया था। आप कहेंगे कि भगवान आ जायेंगे तो ऊपर से तो भगवान नहीं आ जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं आप के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं। आप उस वक्त बिराज नहीं रहे थे, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। परिश्रम करना मनुष्य का काम है, हां, परिश्रम करने में कहां कमी है, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं है और आपको लगेगा, अभी भी लगना चाहिए इस समस्या के मामले में सरकार बड़ी संवेदनशील है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो पिक्चर किया है माइग्रेशन का उसमें जनता को तसल्ली दिला रहे हैं कि भगवान मदद करेगा। माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : और आज माननीय रामस्वरूपजी कह रहे थे।....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने यह जो कहा है, थोड़ी देर में आप देखेंगे, कहेंगे कि हम करेंगे, करके दिखायेंगे और करके रहेंगे। इस स्प्रीट से बोलेंगे माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा विनम्र निवेदन यह है कि सरकार इसके लिए निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है, निश्चय किया हुआ है और जो सुझाव आपने दिये हैं, जिस समस्या का वर्णन आपने किया है, मेरा ऐसा विश्वास है कि सरकार इस समस्या के समाधान में निश्चित रूप से सफल होगी। समस्या बड़ी जटिल है और इसके कुछ पहलू हैं जिनके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। माननीय सदस्यों ने अधिकांश एक बात पर जोर दिया कि राजस्थान में पानी के लिये जो साधन हैं उनमें हमारा हैण्ड पम्प एक बहुत बड़ा साधन हैं। मैं इस बात को मानता हूं लेकिन यह साधन कोई परमानेंट नहीं है। हम हैण्ड पम्प के आधार पर बहुत समय तक इस समस्या से लड़ सकें इसकी सम्भावना तो कम है इसके लिए तो जो फ्लो वाटर है या बरसात से जो पानी आता है उसकी एक-एक बूंद को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हम बचा कर कैसे लोगों के काम में ला सकते हैं इस पर विचार करना होगा, इस पर कार्यवाही करनी होगी लेकिन अभी वर्तमान में जो हैण्ड पम्प हैं, उन हैण्ड पम्पों की स्थिति के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह काम पंचायत के जिम्मे है लेकिन पंचायत के पास कोई बहुत बड़े साधन ऐसे नहीं हैं....

श्री परसराम मदेरणा : ग्रामसेवक के पास है....

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी, ग्राम-सेवक के पास हैं लेकिन इस भयंकर समस्या को देख कर, वैसे भी विभाग इन दिनों में हैण्ड पम्प रिपेयर का काम अपने जिम्मे लेता है और जब तक बरसात न आ जाए तब तक हैण्ड पम्प रिपेयर का काम डिपार्टमेंट करता है, इस बार भी करेगा। हमने 27 जनवरी से इस अभियान को चालू किया था और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री हीरालाल इन्दौरा : अभियान चालू कर रखा है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : अभियान चालू कर रखा है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, अभियान चलाया है, 27 जनवरी से अभियान चलाया है, चल रहा है न अभी, चल रहा है और जब तक बरसात नहीं आती है, स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक यह काम चलेगा। लेकिन इसमें सामान्य यह शिकायत आती है हैण्ड पम्प ठीक नहीं किया, हैण्ड पम्प ठीक करने वाले जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। वह क्षेत्र में जाते भी नहीं हैं। इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं। सरकार ने यह तय किया है कि यह काम केवल हैण्ड पम्प ठीक करने वाले अधिकारियों के जिम्मे नहीं छोड़ा जाए। उसमें जनता की भागीदारी हो। मेरा मतलब भागीदारी मे यह है कि उसमें नियंत्रण हो और इसलिये सरकार ने यह तय किया है कि हैण्ड पम्प रिपेयर के मामले में जिस गांव में, जिस पंचायत समिति में वह हैण्ड पम्प ठीक होगा वहां का पटवारी, वहां के हैड मास्टर और विधान सभा क्षेत्र के विधायक महोदय, तीन व्यक्तियों को नोमीनेट करेंगे। यह 5 लोग इस सारे काम को देखेंगे इसकी मोनिटरिंग करेंगे और हैण्ड पम्प ठीक हो रहा है या नहीं इसका पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : पीपुल्स कमेटी, आपको रेस्पोन्सिबिलिटी, पी.एच.ई.डी. के अधिकारियों और जे.ईएन. पर फिक्स करनी चाहिए और फिक्स करने के अन्दर अगर इनको टार्गेट देवें, वह पूरा नहीं करें तो उनको आप पनिश कीजिए। रेस्पान्सीबिलिटी उनके ऊपर फिक्स नहीं करेंगे और टार्गेट नहीं देंगे तो 3 आदमी क्या करेंगे ? इनके हाथ में क्या है ? मिनिस्टर जाते हैं या हैड आफ दी डिपार्टमेंट जाता है तो जाते ही उस जे.ईएन. को सस्पेंड कर देंगे, उनके ऊपर भय होना चाहिए। बिना भय के आप समझते हैं कि इस शार्ट पीरियड में इतने ट्यूब वैल की रिपेयर कर सकेंगे ? रिपेयर वाले पहले भी अभियान चले थे और वह सब फ्लाप हुए थे। इसमें बहुत

(श्री परसराम मदेरणा)

डिफिकल्ट प्रोब्लम है। ग्रेपल करना हो तो रेस्पान्सीबिलिटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर डालिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह विनम्र निवेदन है माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय कि काम तो वही करेंगे। यह कुछ नहीं करेंगे। काम तो डिपार्टमेंट करेगा ही। पर वह काम ठीक कर रहे हैं या नहीं इसकी मानीटरिंग और उसकी सूचना....

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास में इतने काम्पीटेन्ट सैक्रेटरी हैं कि फोर्जरी के डाकुमेन्ट कहीं पर भी पकड़ सकते हैं। आप लगाओ सैक्रेटरी को इनके ऊपर ताकि जहां फोर्जरी हो रही है, ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है उसकी निगरानी रहनी चाहिए। उसका सुपरवीजन रहना चाहिए पूरे राजस्थान के अन्दर। उस सैक्रेटरी के ऊपर आपका सुपरवीजन रहना चाहिए and you should be constantly on wheels.

श्री भंवरलाल शर्मा : I will....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कहूंगा कि आपको अच्छी गाड़ी लेनी चाहिए ताकि आप भाग सको, दौड़ सको। टायर सही हो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इस पर पुनः विचार कर लें....

एक माननीय सदस्य : आप रामस्वरूप के लिए कुछ कह रहे थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : रामस्वरूप जी के बाद वह बोले इस डिपार्टमेन्ट में "भ" ही 'भ' हैं। वह कुछ 'भ' 'भ' कर रहे थे। मुझे कह रहे थे भवरलाल 'भ', 'भम्मा' 'भम्मा' कर रहे थे।

श्री रामस्वरूप मीणा : आदरणीय भंवरलाल जी साहब, आदरणीय भण्डारी साहब, आदरणीय भार्गव साहब और हमारे परम सम्माननीय श्री भामड़ा साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : और उस पर आदरणीय भगवान।

श्री अध्यक्ष : जब मेरा नाम लेते हैं तो भगवान का भी लो ताकि दूसरा नम्बर तो रहे भगवान से।

एक माननीय सदस्य : वह तो इन्होंने कह दिया कि भगवान नहीं सुनेंगे तो आप तो सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भगवान के पास नहीं जाने दूंगा। मैं ही सुन लूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अभियान है इस अभियान में यदि जनता की भागीदारी इस बात के लिए रहती है कि वह केवल सुपरवीजन करेंगे। वह हमें सूचना देते रहेंगे कि काम ठीक हुआ कि नहीं। मैं समझता हूं कि इससे निश्चित रूप से इस काम में गति आएगी और जगह-जगह शिकायत आती है कि हमारा काम नहीं हुआ, हैण्ड पम्प ठीक नहीं किया आदि-आदि यह इसमें से निकल जाएगी। मैं समझता हूं कि यह योजना ठीक रहेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : इनका कोआर्डीनेशन नहीं रहेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें कोग्रार्डीनेशन की क्या जरूरत है। यह कोई मेहनत थोड़े ही करेंगे। न हैण्ड पम्प लगायेंगे यह, न मरम्मत करेंगे। वह तो विभाग करेगा। हमारे डिपार्टमेन्ट का जो सम्बन्धित ग्रधिकारी है, सहायक अभियन्ता या कनिष्ठ ग्रभियन्ता वह करेगा। यह काम हुआ या नहीं इसकी जांच करेगा एम.एल.ए.।

श्री शीशराम ग्रोला : एम.एल.ए. को कहां बैठाओगे ? एम.एल.ए. को बहुत नीचे मत लाग्रो ग्रौर ग्राप काम तो ग्रपने विभाग के अधिकारियों को ही दे दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यही निवेदन करता हूं कि मेरी बात पूरी....

श्री परसराम मदेरणा : जनता पार्टी की सरकार थी और वर्तमान मुख्य मंत्रीजी उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री थे तो एम. एल.ए. को रोडवेज की बसों को चैक करने के लिए एक ग्रधिकार दिया था ग्रौर ग्रधिकार देकर एक नोटबुक भी पकड़ायी थी। मैं तो ग्रापको बताऊं कि मैंने तो उसी दिन वह नोटबुक रिटर्न कर दी थी कि यह काम हमारा एम. एल. ए. का नहीं है लेकिन एक श्री मालाराम जी एम.एल.ए. थे जो बिलकुल मेरे एडजाइनिंग ही रहते थे ग्रौर उनको रोडवेज की बस को चैक करने पर ड्राइवरों ने पिटाई कर दी। ग्राप एम एल. ए. को वहां कहां भेज रहे हैं ? वह पिटेंगे बाद में। वह मेरे पास में आये और उनके लगी हुई थी। मेरे इम्मीडियेट पड़ौसी थे। मैंने पूछा कि क्या हुग्रा तो कहा कि मैं चैक करना चाहता था, मेरी थोड़ी बहुत तो उससे बोलचाल हुई ग्रौर उसके बाद में मेरी पिटाई कर दी। मैंने कहा कि यह पोथा जो तुम्हारे पास में इन्सपैक्शन का है इसको फाड़ दिया। मैंने कहा कि फाड़ा हुग्रा भी मुख्य मंत्रीजी के पास में भेज दो। एम.एल. ए. वहां जाकर हैण्ड पम्प संभालेगा ग्रौर संभालेगा तो ग्रभी परबतसर से ग्राने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह हैंडल हाथ में ही ग्रा जायेगा। हमारा यह काम नहीं है। हम जाकर किस को पकड़ें वहां ? ग्राप मेहरबानी करके रेस्पान्सीबिलिटी डिपार्टमेन्ट पर डालिये। **fix the responsibilities on Officers of your department. They are answerable to you and you are answerable to this sovereing House.**

श्री भंवरलाल शर्मा : दैट इज करेक्ट। लेकिन ग्राप मेरी बात तो सुनो।

श्री परसराम मदेरणा : ग्राप वायरलैस रखिये। मैं इत्तला मंगा लूंगा, यह नहीं आपकी गाड़ी के पीछे वायरलैस आप को इन्फार्मेशन ग्राफिसर्स **Wherever you are on tour of the State of Rajasthan.** ग्रापको इन्फार्मेशन वायरलैस से भेजेगा यह। इतना कम्युनिकेशन बढ़ गया है। **The world has become, with the advancement of science and technology, a global village now.**

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ग्रापको सुनने में शायद भूल हुई है। मैंने एम. एल. ए. के लिये नहीं कहा है। यह तो श्री शीशराम जी बोले एम.एल.ए. के लिये तो। मैंने नहीं कहा। मैंने यह कहा कि स्थानीय विधायक होंगे, वह 3 ग्रादमियों को ग्रपनी तरफ से ग्रौर लगा देंगे। उनकी पांच की

(श्री भंवरलाल शर्मा)

टीम बनेगी। एम. एल. ए. नहीं जायेंगे वहां।

श्री शिवनाथ सिंह : उस कमेटी की क्या गत होगी कि एम. एल. ए. शिकायत कर रहे हैं कि हैण्ड पम्प ठीक नहीं हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एम.एल.ए. नहीं जायेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : 5 आदमियों की कमेटी होगी उसकी क्या गत होगी? यह कह रहा हूं आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : गति कुछ नहीं होगी। माननीय सदस्य....

श्री परसराम मदेरणा : गत-वत कुछ नहीं होगी। रामनाम सत्य है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह केवल उनके ऊपर एक मानीटरिंग कमेटी होगी जो हम को सूचित करती रहेगी कि हैण्ड पम्प ठीक हो गया या नहीं हो गया। ऐसे ही शहरों में भी....

श्री हीरालाल इन्दौरा : इसके लिये पैसा कितना रखा है? जब आपके अधिकारियों से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है हैण्ड पम्प को ठीक करने के लिये और न सामान है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर यह बात कोई भी अधिकारी कहे....

श्री हीरालाल इन्दौरा : कब कहे? आगे जब कहें तब? पिछले वाले छोड़ दें?

श्री भंवरलाल शर्मा : पिछली बार का तो पता नहीं, अभी कहता हूं मैं तो....

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी जब जागे तभी सवेरा। क्या बिगड़ रहा है, अच्छा ही है कल से भी यदि आपको यह शिकायत हो तो तुरन्त दूर हो गयी; यह अच्छा ही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसमें भी आप जो पंचायत के अधिकारी हैं उनको नहीं कहें। पी.एच.ई.डी. के अफसरों को कहें तब आपको उत्तर मिलेगा कि सामान सब है।

दूसरा सवाल यह है कि गांवों में कुएं होते हैं पंचायतों में तो हमने यह तय किया है कि जो ग्राम का कुआं होगा उसका बोर हम करायेंगे, उस पर पंचायत मोटर लगायेगी, उसका खर्चा बिजली का हम देंगे और उसकी रिपेयर भी हम करायेंगे। उनको यह भी अधिकार होगा कि यदि वह चाहें तो पाइप लाइन डाल दें और उससे रेवेन्यू भी इकट्ठी कर लें, कनेक्शन दे उनकी मर्जी नहीं दे तो उनकी मर्जी लेकिन बिजली का खर्चा हमारा, कुएं की बोरिंग हमारी और बिजली की रिपेयर हमारी....

श्री शिवनाथ सिंह : और मोटर आपकी? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मोटर उनकी। जो भी उसके चलाने के लिये बिजली का खर्चा होगा वह हम देंगे। वह भी यदि चाहें तो उससे अपने गांव में पाइप लाइन डाल सकते हैं और पाइप लाइन डालने के अन्दर जो पैसा कमायेंगे वह भी उनका ही होगा।

Page No.235

श्री हीरालाल इन्दोरा : इस स्कीम का नाम क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसका नाम होगा जनता जल योजना । जनता चलाएगी जनता करेगी ।

श्री शीशराम ओला : वह तो मोटर भी सरकार की हो, विभाग की हो और मोटर जाये तो भी रिपेयर सरकार कराये ।

श्री शिवनाथ सिंह : मन्त्री महोदय इतनी उदारता और दिखाओ कि मोटर भी आप देंगे ।

एक माननीय सदस्य : पंचायत जे.आर. वाई. से सहायता ले सकती है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस सुझाव पर विचार कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मेरी समझ में एक बार इस डिपार्टमेंट ने अकाल के सम्बन्ध में जो तात्कालिक स्कीम्स बनायी हैं वे सुन लीजिए। फिर आपको लगे कि इसमें कोई सुझाव देने हैं तो दीजिये । नहीं तो अन्त नहीं होगा । पहले एक बार टोटल सुन लीजिए कि कौन कौन-सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनायी हैं, फिर आपको कोई लैकूना दिखे तो आप उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर दीजिए । उसको भी वे कन्सिडर कर लेंगे, क्या दिक्कत है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी माननीय सदस्य यह चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि राजस्थान में ऐसे कई स्थान हैं जहां का पानी पीने से कूबड़े होते हैं या कोई डिफारमिटी आती है, कई प्रकार के रोग उन में आ जाते हैं । तो हमने यह तय किया है कि हम उन स्थानों पर टांके बनायेंगे । टांके बनाकर आसपास के इलाके के लोगों को पानी उससे मिल सके, इसकी व्यवस्था करेंगे ताकि बरसात का पानी उसमें एकत्र हो और साल भर कम से कम पीने के लिए वह मिल जाए जिससे वे बीमारी से बच सकें । इस प्रकार की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं । मैं यह समझता हूं कि इसमें भी आप लोगों को अपने अपने इलाके में सहयोग करके बनवाने चाहिए ।

श्री रामनारायण चौधरी : सिर्फ फ्लोराइड में बनायेंगे या खारे पानी में भी ?

श्री भंवरलाल शर्मा : खारे पानी में भी बना देंगे । जहां भी आप चाहेंगे वहां बनायेंगे इसको । लेकिन प्रायोरिटी उनको होगी जहां फ्लोराइड है और जिसको पीने से लोग बीमार होते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : इस फ्लोराइड से मरते तो नहीं हैं, खारे पानी से तो मरते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसमें कोई डिस्प्युट नहीं है । हम इस स्कीम को एनकरेज करना चाहते हैं । अगर सक्सेस बनती है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : खारे पानी के लिए इसलिए बनायेंगे कि नहाने-धोने में काम में ले लो आप, पीने के लिए नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, उसमें तो बरसात का पानी होगा, बरसात का पानी आयेगा ।

साथ ही विभाग ने यह भी तय किया है कि जो पुराने ट्रेडीशनल स्रोत हैं, जिनका पानी लेने से सीपेज होता है, रीचार्ज होता है और आज वे हमारे काम में आ रहे हैं,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उनको मेण्टेन करने का काम, उनकी मरम्मत का काम, उनमें पानी आता रहे इसमें आने वाले व्यवधानों को हटाने का काम हमारा डिपार्टमैण्ट करेगा ताकि रीचार्ज होता रहे पानी और दिक्कत नहीं आये।

अभी लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने कहा तो यह था कि हम बजट का बहुत सारा भाग-62 प्रतिशत गांवों में देते हैं पर आपकी प्रगति विवरणिका में पेज 10 पर ग्रामीण पेयजल योजना (एम.एन.पी.) में 72 करोड़ 65 लाख हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एम.एन.पी. में तो हमने इतना दिया ही है बाकी सेण्टर की जो स्कीम है ए.आर. डब्ल्यू.एस.पी. उसमें आपको 42 करोड़ रुपया और मिलेगा गांवों के लिए और इससे यह 114 हो जाएगा।

श्री परसादीलाल मीणा : फिर भी कम रहा यह शहर से।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह 130 है यह 114 हो गया, क्या कम है ?

श्री परसादीलाल मीणा : संख्या कितनी है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : संख्या कह देंगे इसमें अब।

श्री परसराम मदेरणा : टोटल आपके पास 236 करोड़ और कुछ लाख है प्लान में, उसके अन्दर यह जुड़ा हुआ है 41 करोड़ और कुछ लाख। 130 के साथ जब जोड़ते हैं तो वह 236 से ऊपर बढ़ जाती है। और प्लान अकाउण्ट में 245 करोड़ हो नहीं सकता, 236 करोड़ कुछ लाख रहना चाहिए, इसका मतलब यह है कि 41 करोड़ और 73 या 72 लाख है वह टोटल रूरल एरिया में नहीं जा रहा है सेण्ट्रल स्पांसर्ड।

श्री भंवरलाल शर्मा : वही होगा।

श्री परसराम मदेरणा : एब्राड से जो फाइनेन्शल एड आ रही है उसका कुछ पर्सेण्टेज अरबन एरिया में भी जाएगा। 41 करोड़ यह नहीं है। इसमें चाहे आठ करोड़ हो या नौ करोड़ हो, यह अरबन एरिया में जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : थोड़ा-सा जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : हां, थोड़ा-सा जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बीसलपुर पर जो खर्चा हो रहा है वह कहां जायेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारी कई पेयजल की जो योजनाएं हैं उनको स्वीकार करने में कई वार तो इसलिए कठिनाई होती थी कि हमारे अधिकारियों को अधिकार नहीं थे सैंक्शन करने के। वे केन्द्रित हो रहे थे। अब हमने यह तय किया है कि सभी योजनाएं जो पी.पी.सी. में आती थीं अब पी.पी.सी. में हरेक के आने की जरूरत नहीं है। पांच लाख तक की जो योजना रहेगी उसको मुख्य अभियन्ता ही पास कर देंगे।

श्री हरि सिंह (महुआ) पहले से ही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, यह नहीं था

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो लाख तक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की है अभी।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसको पांच लाख कर दिया। 20 लाख तक की स्वीकृति हमारी वित्तीय समिति पास कर देगी और इससे कोई बड़ी होगी तब पी.पी.सी. में आयेगी वर्ना इसका निपटारा नीचे हो जाएगा। जो आप यह कह रहे थे कि कई महीनों तक आपकी स्कीम पास होने में पड़ी रहती हैं, चक्कर खाती हैं, अब वे....

श्री परसराम मदेरणा : 20 लाख तक की किसको दे रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वित्त समिति है हमारी उसको। इसलिए जो देर हुआ करती थी वह देर अब नहीं होगी।

श्री शिवनाथ सिंह : एम.ई. एक्स.ईएन. लेवल पर दे रहे हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो है ही आलरेडी उनको। वह तो जो है वह है।

श्री अध्यक्ष : पांच लाख तक की योजनाओं पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ? जितनी होंगी सब पास हो जाएगी ?

श्री भंवर लाल शर्मा : हां, सब पास होंगी वह तो। पांच लाख तक की जितनी भी होंगी।

श्री रमाकांत शर्मा : पहले दो लाख की सीमा थी कितनी पास होती थीं ? अब पांच लाख में भी पांच लाख से सवा पांच लाख करके सरका देंगे आगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा काहे के लिए करेंगे ?

श्री रमाकांत शर्मा : पहले दो लाख में क्यों किया करते थे ऐसा ? पहले दो लाख की थी नहीं करते थे, दो लाख को सवा दो लाख करके ऊपर खिसका देते थे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कुओं पर....

श्री अध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना, अभी समाप्त तो कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी चर्चा में यह बात आयी कि हैण्ड पम्प जो स्वीकृत किये गये हैं उनकी संख्या कम है। मुझको भी ऐसा लगता था। किसी क्षेत्र में, किसी जिले में अगर 13 हैण्ड पम्प हैं या 15 हैं, या 30 भी हैं तो भी संकट था। इसलिए अब यह तय किया है कि इस संख्या को, जो 900 के करीब थी, बढ़ाकर अब दो हजार कर देंगे दो हजार हैण्डपम्प राजस्थान में लेंगे।

श्री शीशराम ओला : दो हजार से क्या होगा, मंत्री महोदय ?

श्री अध्यक्ष : कुछ बढ़ी ही है। डबल हो गयी। घटी थोड़े ही है, डबल हुई है।

एक माननीय सदस्य : एक विधान सभा क्षेत्र में 15 करो आप।

श्री रमाकान्त शर्मा : एक विधान सभा क्षेत्र में पहले 10 थे अब बीस हो जायेंगे, क्या होने वाला है इससे ? इतने-से.... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : एस.सी., एस. टी. के लिए 50 हैण्ड पम्प तो लग ही

(श्री परसादी लाल मीणा)

रहे हैं कौनसा अहसान कर रहे हैं? दो हजार तक बढ़ाकर कौनसा अहसान कर रहे हैं, वह तो बजट में ही है।

श्री भंवर लाल शर्मा : वह तो सम्भव नहीं होगा, एक साथ तो सम्भव नहीं होगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : वहां तो प्यास से मरेंगे लोग।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सुनिये। सुनिये, मंत्री जी को।

श्री परसादी लाल मीणा : यह सरकार गांव की जनता का भला नहीं कर सकती।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप भला कर गये होते न। भला नहीं कर सकते, बार बार में काहे को मांग रहे हो फिर?

श्री अध्यक्ष : कन्हैया लाल जी, बैठो। बैठो आप।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह कर जाते तो संकट ही नहीं आता। इसलिए उन बातों में मत जाइये। जो हमारे फाइनेंसेज हैं उसका भी ध्यान रखिये आप।

श्री अध्यक्ष : देखिये, तारीख बदलने में एक घण्टा बचा है।

श्री भंवर लाल शर्मा : तो, जैसी माननीय सदस्यों की चिन्ता है, दो हजार की बजाय तीन हजार हैण्ड पम्प राजस्थान में लगाएंगे।....(व्यवधान)....इसमे ज्यादा तो और क्या हो सकता है?

(23.00)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि जिलाधीश और हमारे एस.ई. भी जो विधायक हैं उनकी सलाह से यह कर लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके एस.ई., कलक्टर और एम.एल.ए.....(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : जिलाधीश का क्या काम है इसमें?

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर कौन करेगा?

श्री शिवनाथ सिंह : एक्स.ई.एन.को कीजिये। जिले का एक्स.ई.एन.जो है....

श्री भंवरलाल शर्मा : कलक्टर को जोड़ने का मतलब यह है कि कलक्टर के पास और भी फण्ड होता है।

श्री शिवनाथ सिंह : कलक्टर को जोड़े लेकिन एक्स.ई.एन. को भी जोड़ें। एम.एल.ए. हो, कलक्टर हो और एक्स.ई.एन. हो।

श्री शीशराम ओला : एक्स.ई.एन. का रहना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : जहां एस. ई. जायेगा वहां एक्स. ई.एन. अपने आप आ जाएगा।....(व्यवधान) वह तो जब मंत्री महोदय जाएंगे तो सारा स्टाफ रहेगा या नहीं रहेगा वहां?

श्री शिवनाथ सिंह : एक्स. ई.एन. को रख दो। जिले में रहता है। एस. ई. तीन-तीन जिलों का ....(व्यवधान).... इसलिए एक्स. ई.एन. हो जाए, कलक्टर हो जाय, एम. एल. ए. हो जाए।....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कच्ची बस्तियों और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

गरीब मौहल्लों का भी जिक्र आया कि उनके यहां पानी की व्यवस्था नहीं होती है, इनको कनेक्शन नहीं मिलते थे। माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि पिछली बार ही हमने यह आदेश प्रसारित कर दिये थे कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी कालोनी में रहता हो, वह रेगुलर हो, इर्रेगुलर हो इसका कोई वास्ता नहीं? जो भी पानी का कनेक्शन मांगेगा उसको दिया जाएगा कोई रुकावट नहीं होगी। कुछ वे कालोनीज भी होंगी....

श्री अध्यक्ष : यह दे दिये कि आपके आदेश पहुंच जायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वे तो पहुंच गये। उसमें जो काम, थोड़ी दिक्कत आयी है वह नगर पालिकाओं को भी आदेश आज मिलने चाहिए थे, वे बाद में मिले हैं इसलिए अब दिक्कत नहीं आएगी।

श्री रामनारायण चौधरी : कलक्टर ने रोक लगा रखी है उसको हटा दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब कलक्टर का सवाल ही नहीं है, अगर वह लगा रखी है तो उसको भी निर्देश दे देंगे। क्यों लगाऐंगे वे। वह तो हमारा डिपार्टमेंट हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : गांवों के बारे में क्या कह रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : हैण्ड पम्प है ना। वे दे रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल इन्दौरा : नहीं, उसको रिलेक्स कर रहे हैं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : दूसरा, कुछ कालोनीज ऐसी हैं....(व्यवधान)....

श्री कन्हैया लाल मीणा : गांव जो तीन हजार की आबादी वाले हैं....(व्यवधान).... उसको विभाग अपने अण्डर में लेकर चलायें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हरेक गांव में डोमेस्टिक कनेक्शन मिले।

श्री भंवरलाल शर्मा : कुछ कालोनियां ऐसी हैं जो अभी नियमित नहीं हुई वह नियमित नहीं हुई लेकिन अभी आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों में ही सरकार ने एक आदेश निकाला है जिसमें कोई कृषि भूमि पर भी मकान बनाया है, या कोई और अनियमितता करके भी मकान बना लिया हैं तो उसको नियमित करने का एक आदेश निकल गया है। उसमें वह कालोनी पूरी 25 रुपया विकास शुल्क देकर और जो उसकी राशि देने के बाद वह पूरी कालोनी नियमित होगी। उसके बाद उसको भी सुविधाएं हम दे देंगे।....

श्री शीशराम ओला : 25 रुपया प्रति हार्स और प्रति बीघा?

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रति गज....

श्री शीशराम ओला : कहां से लायेगा वह प्रति मीटर, वह पानी के लिए तो मकान.... उनको पानी दें....(व्यवधान).... मंत्रीजी यह फरमा रहे हैं कि हमारे ये आदेश.... मेरी अर्ज सुनिये एक मिनट....

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रति गज। माननीय सदस्य, फिर आप समझे नहीं। पूरी कालोनी को नियमित करने की फीस है, यह पानी के लिए नहीं है।

श्री शीशराम ओला : हमको तो पानी ही चाहिये और करते रहो रेगुलर आप ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो आप समझे 25 रुपये पानी की फीस थोड़े ले रहे हैं, वह तो विकास शुल्क अलग से तय किया है उसके अन्तर्गत सब हो जायेगा । अभी जो....

श्री परसराम मदेरणा : वह बात ठीक है लेकिन यह जो विकास शुल्क, जो डवलपमेण्ट चार्जेज है यह 25 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है ?

श्री अध्यक्ष : यार्ड है ।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये आप कन्वर्जन चार्जेज के, जो अनआथोराइज्ड थे, जिनके 10 टाइम्स वगैरह, वह अभी शर्तें नहीं रख रहे हैं आप....

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं वह सब साथ हैं उसके ।

श्री परसराम मदेरणा : जब साथ है तो एक आदमी को देने पड़ेंगे 60 हजार रुपये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नियमित तो करनी ही पड़ेगी पूरी कालोनी को, उसमें पाइप लाइन डालने की बात करता हूं । आज भी उनमें पाइप लाइप नहीं है ।

श्री शीशराम ओला : वह एक प्रकार का सारे स्टेट में है अथवा अलग-अलग शहरों का अलग-अलग है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसकी अलग-अलग रेट्स है.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : सब पूछ रहे हैं तो आप क्यों पूछ रहे हैं । अच्छा तो यह होता कि यह अपनी बात पूरी कर लें । वरना आज यह भाषण समाप्त नहीं होगा । ..हर कदम पर आप पूछोगे और फिर बाद में और पूछोगे तो इसमें डुप्लीकेशन हो जाएगा । इसलिए पूरा कर लें, सब स्कीम समझ लीजिए । तब आपको कहीं सजेशन देना हो, शंका करनी हो करिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा . समर कंटिजेंसी के बारे में माननीय सदस्यों की यह शिकायत थी कि वह 7 करोड़ रुपया दिया गया है । अप्रैल से जून तक कांटिजेंसी के प्लान में हमने 20 करोड़ 89 लाख, यह तो ग्रामीण इलाकों को दिया है और 6 करोड़ 55 लाख यह शहरों के लिए दिया है । मैं समझता हूं कि इस अमाउण्ट से आने वाली गर्मी में हमारी जो भी योजनाएं हैं उन्हें पूरी कर सकेंगे और जो 7 करोड़ की बात आप कह रहे थे, उस 7 करोड़ के बजाय इतना पैसा हमने जिलों को बांट दिया है । हमने यह आदेश भी निकाल दिया है और काम शुरू कर दिया है ।

श्री सुन्दरलाल : हम हरियाणा से पानी लाते हैं उसका क्या करोगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां तक हरियाणा से पानी लाने की आप बात कहते हैं, मैंने अभी यह चर्चा की है, आप अपनी इच्छा से जाओगे तो हम रोकेंगे नहीं लेकिन मजबूर होकर पानी लेने जाओगे तो हम पानी की व्यवस्था कर देंगे ।

श्री सुन्दरलाल : हमें पानी ही चाहिये ।

Page No.241

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर मान लीजिये आपकी इच्छा हो तो रोकेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपको हरियाणा का पानी ज्यादा मीठा लगे तो....

श्री भंवरलाल शर्मा : चले जायेंगे आप वरना आपको....

श्री अध्यक्ष : कई बार होता है मीठा पानी होता है तो लोग वह लाते हैं, खारा पानी नहीं पीते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको तो हरियाणा जाने नहीं देंगे, यही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : वह तो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पानी मुंह लगा हुआ हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर की मानसी वाकल योजना के बारे में भी प्रश्न आया था। यह बात सही है कि यह योजना बहुत पहले बनी थी और बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिये थी लेकिन वह नहीं हो पायी। वह भी बढ़ गयी और जो समझौता था उदयपुर की उस फर्म से, जिसका नाम हिन्दुस्तान जिंक है उनके कोलेबोरेशन से साझेदारी से यह स्कीम बननी थी लेकिन वह पूरी नहीं हुयी। उस जमीन को एक्वायर करनी थी लेकिन अब उसकी जो लेटेस्ट स्थिति यह है कि करीब-करीब जमीन एक्वायर हो गयी, उसका कम्पनसेशन ए. डी. एम. साहब के पास जमा करा दिया। अभी कुछ लोग उसको एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस विधान सभा के सत्र के बाद या तो मैं या हमारे बड़े अधिकारी कोई भी जाकर उसको सैटल करेंगे और लगता यही है, विश्वास यही है कि हम उसको पूरी करके चला सकेंगे। पूरी हो जायेगी, आपका सहयोग भी लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप मेहरबानी करके 12 तो बजने ही मत दो नहीं तो सब गड़-बड़ हो जायेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इतना ही अब निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार का निश्चय है और मैं विश्वास दिलाता हूं....

श्री शीशराम ओला : मैं आपके हाथ से नहीं बैठने वाला महावीर जी। आप बैठकर सुनिये। आपने झुन्झुनूं की जनरल सब बात कह दी। आपने जनरल सब बात कह दी हमने सुन ली। झुन्झुनूं के लिये आपने कोई चर्चा नहीं की। चार बजट, पांच बजट उसके बाद आपने पास कर दिये। क्या कहना चाहते हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को जानते हैं कि जब आप जलदाय विभाग के मंत्री थे तब यह आपने पी. पी. सी. से स्कीम मंजूर करवाई तो आपने सारे राजस्थान को छोड़कर अपनी कान्स्टीट्यूएंसी के लिये यह स्कीम पास की और वह भी क्या किया आपने कि चुनाव के आस-पास थी शायद, टंकियां तो बना दी, क्योंकि वह दिखती थी, अगर मान लीजिये पाइप लाइन डालते तो अन्दर ढलती वह दिखती नहीं, वह आपने बनवा दी और पानी की व्यवस्था आपने की नहीं....

Page No.242

श्री शीशराम ओला : आप गलत चार्ज लगा रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : चार्ज नहीं लगा रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिये यह तो आपकी सफलता है ।

श्री शीशराम ओला : पूरे जिले के लिये है, पी. पी. सी. की मीटिंग में मंजूरी हुई, भारत सरकार से मंजूरी है, डिपार्टमेण्ट के पास स्कीमें भेजी, यह 70 लीटर किया गया, 40 से 70 पूरे जिले के लिये....

श्री भंवरलाल शर्मा : वही कह रहा हूं मैं आपको ।

श्री शीशराम ओला : सुनिये आप मेरी बात, आप यों कह कर टालिये मत ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं टाल नहीं रहा हूं । आगे कह रहा हूं ।

श्री शीशराम ओला : मैं जानता हूं आप सुनिये दो मिनट लिये । (व्यवधान) उसका उत्तर नहीं दूं । तिवाड़ीजी आप भी । भाई, एक बात बड़ी गंभीर कह दी । सुनिये दो मिनट के लिये । यह जो स्कीम है । मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी सुनिये जरा ....(व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके बावजूद भी वह दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपने सोर्स नहीं ढूंढा, और सोर्स नहीं है तो पानी उसमें कैसे जायेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टंकी बनवा दी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : टंकी बन गई वह तो ठीक है, एक काम पूरा कर गये, एक काम तो पूरा कर दिया बाकी का काम तो हमको पूरा करना है और वह हम पूरा करेंगे लेकिन थोड़ा धैर्य रखिये ।

श्री शीशराम ओला : मेरा निवेदन यह है कि अगर आप सही जानकारी नहीं रख सकते हैं तो कृपया उत्तर न देते सोर्स आफ वाटर इज देयर, **Tube wells are there every things are there, who says no source of water ?**

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर आपने किया क्यों नहीं, फिर आपने जोड़े क्यों नहीं ?

श्री शीशराम ओला : सबके ट्यूब वैल बने पड़े हैं, पानी है, कुएं हैं, मीठा है, सब कुछ है, उनको जोड़ना है, पाइप लाइन से जोड़ना है.... (व्यवधान).... भाई कहने दो मुझे, देखिये, मुझे बोलने दीजिए मेहरबानी करके....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य....

श्री शीशराम ओला : न तो मैं अकेला लाया, मैं पूरे डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए राजस्थान के लिये दिल्ली से स्कीम क्लियर करवायी थी, पहले 5 हजार की आबादी पर ही ओवर हैड टैंक बनता था मैंने दो हजार की आबादी पर बनाने की मंजूरी दी और विधान सभा में दी किसी का अहसान नहीं है। मैंने कायदे से किया है, भारत सरकार की मंजूरी से कार्य किया है, विधिवत कार्य हुए हैं पिछली बार भी यह बात कह कर टाल दिया गया और

(श्री शीशराम ओला)

आज भी वही बात कह रहे हैं। आप मेहरबानी से गलत बयानी नहीं करें। वस्तु स्थिति की आप सही जानकारी हमको दें। पानी है, कुएं है, कई जगह ट्यूब वैल हैं, कई जगह दूसरे कुएं हैं....

श्री अध्यक्ष : इन्हें आप ऐसा बता दीजिये कि कब तक कर देंगे? हो गया है वह तो ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर आपने जोड़े क्यों नहीं सब थे तो?

श्री शीशराम ओला : मैं कहां से जोड़ता मैं तो चला गया था। मैं कौन था जोड़ने वाला। मैं होता तो राजस्थान की पीने के पानी की यह दशा होती क्या?

श्री अध्यक्ष : देखिए लोगों ने इन्हीं को तोड़ दिया तो जोड़ेंगे कहां से?

श्री भंवरलाल शर्मा : यहां जरुरी नहीं है कि जो जोड़ेगा वह चले जाएंगे कहीं जो जोड़ेगा चले जायेगा ऐसा तो नहीं है कहीं।

श्री शीशराम ओला : आप जाओ या नहीं जाओ....(व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : यह बात हो नहीं सकती एक्सिलेरेटेड रुरल वाटर सप्लाई में ओवर हैड टैंक बना दो आप और उस डिपार्टमेण्ट के इंजीनियर को मरना है क्या कि उसने सोर्स तैयार ही नहीं किया है, सोर्स अगर ट्यूब वैल है, ट्यूब वैल नहीं है तो ओपन वैल वहां पर है और उसमें वाटर अबेंडेंट में है, कनेक्शन का मामला है और कनेक्शन के मामले में यह आरोप लगाना....

श्री भंवरलाल शर्मा : आरोप नहीं लगा रहा हूं....

श्री परसराम मदेरणा : कि उस वक्त ये बड़े-बड़े ओवर हैड टैंक बना दिये और अपनी कन्स्टीट्यूएंसी में बना दिये। मैं गया था, अध्यक्ष महोदय, वहां पर....

श्री भंवरलाल शर्मा : आरोप नहीं है साहब, आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं खुद गया था उस क्षेत्र में, जनवरी, 1993 में उस क्षेत्र में गया था....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब तो सवाल यह है कि वहां पर पानी का प्रबन्ध कब तक पहुंचा देंगे?

श्री परसराम मदेरणा : इनके क्षेत्र में ही नहीं हैं ऐसे ओवर हैड टैंक्स आपके वहां भी बने हैं इसलिये....

श्री अध्यक्ष : जो हुआ है ठीक है लेकिन आप पानी कब तक पहुंचा देंगे?

श्री परसराम मदेरणा : कनेक्शन देना है और कनेक्शन नहीं करने में कहीं आधा किलोमीटर है, कहीं एक किलोमीटर है, कहीं 400 गज है, कहीं 500 गज है आप उसको कीजिये। ऐसी क्या बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा कर दीजिये मंत्री महोदय, यह गलती उस जमाने, में सैंक्शन तो मिनिस्टर ने की है यह जिम्मेदारी उनकी तो नहीं है, यह जिम्मेदारी तो विभाग की है। जिस अधि-

(श्री रामनारायण चौधरी)

कारी ने बिना सोर्स के टंकी बना दी उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री रामनारायण जी साहब श्री शीशराम जी अपनी बात कहने में सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष : पानी पिला रहे हैं घूंट-घूंट पिलाएंगे आपको। एक साथ नहीं घूंट-घूट।

श्री भंवरलाल शर्मा : चूरू, गंगानगर और झुन्झुनूं के 11 कस्बों के 956 ग्राम समस्याग्रस्त हैं इनके लिये 502 करोड़ रुपये की स्कीम जर्मन सहयोग से पूरा करने के लिये (व्यवधान).... 956

श्री शीशराम ओला : मण्डवा के अकेले के 96 गांव हैं, मंत्री जी आप क्यों टाइम ले रहे हैं हाउस का आपको सही जानकारी नहीं है। मुझे तो पता है कि गांवों का क्या हाल है।

श्री भंवरलाल शर्मा : 956 कुल बता रहा हूं ना....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : 956 जिसमें चूरू, गंगानगर आपका झुन्झुनूं ये शामिल हैं, तीनों जिलों के शामिल हैं गांव।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस योजना के प्रथम चरण में.... (व्यवधान) आ रहा हूं आपके लिये गंगानगर के नोहर तहसील के 113 गांव, चूरू जिले के 212 गांव तथा दो कस्बों के लिये 253 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार और जर्मन सरकार के बीच समझौते के हस्ताक्षर हो गये हैं और इसकी क्रियान्विति जल्दी होगी, ऐसी हमको आशा है।

श्री शीशराम ओला : झुन्झुनूं को पीछे क्यों ?

श्री हीरालाल इन्दोरा : टोटल 325 हो गया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : 11 अलग

श्री शीशराम ओला : 96 गांव तो अकेले झुन्झुनूं के हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मंत्रीजी अभी आपने जर्मनी का नाम लिया ना, बजट में प्रावधान कितना रखा है ? 10 लाख रुपये, 1994-95 में।

श्री भंवरलाल शर्मा : टोकन है।

श्री अध्यक्ष : जर्मनी देगा तब।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब आयेगी तब लगायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : वह स्वीकृत हुई ? अभी हुई नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : दस्तखत हो गये हैं।....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : बजट में सैंक्शन की बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक जो समस्या आती है वह आती है कि आजकल दोहन अधिक मात्रा में हो रहा है और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा विभाग सारी खोज-बीन के बाद ट्यूब वैल बनाता है और काश्तकार को पता लगता है या किसी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

व्यक्ति को पता लगता है कि यह यहां सफल हो गया तो उसके पास ही अपना ट्यूब वैल बना लेते हैं इसलिये हमारे ट्यूब वैल्स असफल हो जाते हैं। इसलिये हम सोच रहे हैं कि इस बारे में भी कोई कानून बनाया जाय कि इस प्रकार के कुएं खोदने पर किसी से पर्मिशन ली जाएं और कोई भी अधिकारी या कोई संस्था देखे कि उनको पर्मिशन दी जाए या नहीं दी जाए और उस परमिशन के देने से कहीं योजना तो असफल नहीं होगी। उसके बाद ही वह पर्मिशन देकर खोदा जाय। इस पर भी हम विचार कर रहे हैं ताकि ये रोज की समस्या है यह इससे खतम हो जायेगी।

इसके बाद तकनीकी मिशन के अन्तर्गत कई मशीनें थीं उसमें यह योजना थी कि 3 वर्ष तक केन्द्र सरकार और एक संस्था के बीच में समझौता था कि 3 साल तक वह चला कर देंगे और 3 साल बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी आ जायेगी और राज्य सरकार उनको चलायेगी। अब वह समय पूरा हो गया लेकिन कुछ मशीनें ऐसी हैं जो अभी ठीक नहीं है। जिम्मेदारी यह थी कि ठीक करने के बाद ही डिपार्टमेण्ट सम्भालेगा। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बात-चीत चल रही है और इतनी भी तैयारी है कि यदि मान लो विभाग को भी कुछ खर्चा करके यदि इनको चलाना पड़े तो चला दे और कुछ के लिये तो हमने निविदा आमन्त्रित कर ली हैं और शीघ्र ही वह खुलने वाली है इसके बाद राज्य सरकार का विभाग उनको चलायेगा। आपकी समस्या यह थी कि प्लांट लग तो रहे हैं लेकिन काम नहीं आ रहे हैं, बन्द पड़े हैं। इनकी समस्या का समाधान हो जायेगा और जिन इलाकों में ये लगी हुई है वह ठीक रूप से, निश्चित रूप से पानी देना शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर जो समस्याएं हमारे सामने हैं उनके समाधान हमने ढूंढे हैं.... (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : कुल मिलाकर इस टैक्निकल मिशन का इवेल्युएशन किया है क्या ?

एक माननीय सदस्य : टोटल फ्लाप गया है।

श्री परसराम मदेरणा : टैक्निकल मिशन जो है यह फ्लाप गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब तो प्लांट और प्लाण्ट्स हैं उनके लिये क्या करें ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं उनके लिये नहीं कह रहा हूं, तब तक तो उपयोग करना पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी उनकी भी बात करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी उनको चालू हालत में लाइये आप और इसका इवेल्युएशन कर लीजिये....(व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : आगे की स्कीम के लिए विचार करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : टैक्निकल मिशन में 3 जिले थे,....(व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह राजीव गांधी मिशन है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, देखिये फ्लाफ इसलिए हुये हैं कि उनको ठीक ढंग से नहीं चलाया गया। फ्लाप नहीं हुआ है जहां पर चालू रहे हैं वहां पर खारा पानी होने के बावजूद भी लोगों को उस पानी से बड़ा सहारा मिला है, परन्तु उसकी मेन्टीनेंस नहीं की गयी, प्रापर देख-भाल नहीं की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत खर्चीला है।

श्री अध्यक्ष : खर्चीला है, यह दूसरी बात है। लेकिन पहले जब खर्चीला था तो कान्ट्रेक्ट गुजरात की फर्म से हुआ था। तो खर्चीला था या नहीं था आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उस समय भी उस फर्म ने भी जहां ध्यान नहीं दिया वहां फ्लाप हुआ है और जहां फर्म ने बराबर काम किया है, मेरे क्षेत्र में भी ऐसे थे. कोई फ्लाप नहीं हुआ। जब तक काम किया सब प्लांट ने काम किया और लोगों को पानी का भारी सहारा मिला था। अब सवाल यह है कि उसका प्रोपर मेंटीनेंस नहीं हो तो दिक्कत है:....

श्री शीशराम ओला : मैंने नम्बर बताये थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : कुछ माननीय सदस्यों ने.... ऐसे तो पूरा ही नहीं होगा मेरा तो....

श्री अध्यक्ष : अब ये बैठ जायेंगे, फिर आप बोलिये। अब आप समाप्त करिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे ध्यान में करप्शन की बात लायी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आप जो करप्शन बता रहे हैं, ये मुझे आप दे दें, निश्चित रूप से इनकी जांच करायेंगे और इसमें जो दोषी पाये जायेंगे उनको दण्डित भी किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये मंत्री महोदय, मेरा एक निवेदन है, अब आप कुछ भी समझ लीजिये इसे, अधिक से अधिक पाइपों की व्यवस्था करिये यदि आप अपनी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। उसमें मेक्सीमस पैसा खर्च करिये। आपकी बहुत स्कीमें केवल कनेक्शन के लिये पड़ी हुई हैं Everything is there, source is there टंकी है, सब कुछ है, कनेक्शन नहीं हुआ है। पूरे राजस्थान में ऐसी बहुत टंकियां बनी हुई हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कई ऐसी हैं जो बिजली के कनेक्शन के अभाव में पड़ी हुई है, पूरी कम्प्लीट है, केवल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, वह ठीक है। We are alert for that, कर रहे हैं उसके लिये भी, जैसे ही सरकार आयी थी, जैसा आपको ध्यान है, मैंने सारे एम. एल. एज. को, विधान सभा भी चल रही थी, इसीलिये बुलाया था कि जो कुछ काम हम

ी भंवरलाल शर्मा)

करना है, वह एक बार जानकारी में जाए, क्योंकि एक वर्ष....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मुझे मालूम है, नहीं किया। क्योंकि एक वर्ष तक.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में नहीं बोलें। सुन तो लें पूरी बात।

श्री भंवरलाल शर्मा : ....क्या प्रगति डिपार्टमेंट में हुई, क्या काम रुके रह गये, क्या काम नहीं हुए, यह जानकारी हमको नहीं थी इसलिये सबसे पहले मौके पर ही आप लोगों को इसीलिये बुलाया कि आप लोगों से फीड बैंक मिले तो यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी, इस समस्या के प्रति हम पहले से ही जागरूक थे और आपसे जानकारी करने के बाद, यह बात सही है कि पाइप नहीं थे जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था लेकिन जानकारी एकत्र करने के बाद, पाइप के टेण्डर जनवरी-फरवरी में हुए हमारे आने के बाद हमने टेण्डर फाइनल किये और पाइप इतनी जल्दी नहीं खरीदे जा सकते। अब वे खरीद लिये गये हैं और इसीलिये जो आपकी शिकायत थी कि वे काम पूरे नहीं हुए, उसमें यह बहुत बड़ा व्यवधान था। अब पाइप भी है, हैण्ड पम्प के पाइप सारे हैं, ये भी हैं और जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, यह पाइप हमारी सबसे बड़ी चिन्ता का समाधान है और वे हमारे पास उपलब्ध हो गये।

अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि बरसात का पानी जो बह कर जाता है, अभी इसका न तो कोई प्लान है न अध्ययन है। इसके लिये कुछ एक्सपर्ट्स को कुछ पुराने लोगों को जो इसकी जानकारी रखते हैं, उनकी एक समिति बना कर, उनका सहयोग लेकर राजस्थान के बरसात में बह कर जाने वाले पानी को रोकने के लिये क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या योजना हो सकती है, क्या योजना हो सकती है उसको हम करेंगे और तभी इस समस्या का समाधान हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। एक-एक, वन बाई वन, एक साथ नहीं, आप बैठिये। एक-एक बोलिये, हां, एक-एक बोलिये। मैं इधर से ही शुरू करता हूं। एक-एक बोलिये। आप बोलिये। शीशराम जी शुरू करेंगे, ऐसे सब बोलते जाइये।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सोर्स आफ वाटर, नेचुरल सोर्स को डवलप करने की बात कहते हैं पर वो तो लोगों ने एनक्रोचमेन्ट कर लिया। करो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। आप करोगे अच्छी बात है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप जनवरी में टेण्डर करने की बात फरमा रहे हैं पाइप और दूसरे सामान के लिये, आप तो 1990 से यहां टेण्डर लेते आ रहे हैं। 4 साल में पाइप और दूसरा सामान नहीं पहुंचा। एक साल की बात नहीं, 4 साल की बात है,

(श्री शीशराम ग्रोला)

उसका उत्तर आपने नहीं दिया। पाइप हमारे यहां नहीं पहुंचे, आपने हमको उत्तर नहीं फरमाया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब पहुंचा देंगे आपके यहां.... (व्यवधान)....

श्री शीशराम ग्रोला : देखिये महावीर जी, यह ग्रच्छी बात है क्या ? मेरी बात सुनिये जो मैं बात कह रहा हूं। ग्रापका दोष है कि मेरा है। आप सरकारी चीफ व्हिप हैं। ग्राप बी.जे.पी. वालों को कह दो। मेरा निवेदन है, मुझे ग्रर्ज करने दो....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो बोला ही नहीं।

श्री शीशराम ग्रोला : मेरा निवेदन है, मैंने ग्रापसे विनम्र निवेदन किया है कि 16 यंत्र खारे पानी को मीठे में परिवर्तित करने के लिये ग्राये उसमें से एक गोखरी में काम कर रहा है, एक ने काम किया, ग्रौर लगाये ही नहीं, वहां पर पड़े हैं। या तो उनको मंगा लो, क्यों रखे हुए हैं वहां। आपने फ्लोराइड वाटर को शुद्ध करने के लगाये, उनमें से एक ही की चर्चा है। वहां खारा पानी है नहीं, फ्लोराइड है नहीं। वह ग्राप ने एक बता रखा है तो उनकी ग्रापने चर्चा ही नहीं की। वेग बात कह दी, मैंने वेग बात नहीं कही। मैंने आपको नम्बर बताये कि इतने यह हैं, इतने यह हैं।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि 180 टंकियों का क्या हुग्रा ? उनको कब तक जोड़ देंगे ? गांवों को पानी कब तक मिल जायेगा ? वहां खारा पानी, फ्लोरा पानी पीते-पीते लोग कुबड़े हो गये। हमा यहां के लोग ग्रार्मी में जाते हैं और पान अच्छा नहीं मिलता तो आर्मी के लिये फि नहीं रहते, फौज में जाने के लिये, उनको दो नुकसान हुआ। एक तो उनको रोजगार नहीं मिला ग्रौर ग्रार्मी को अच्छे रिक्रूट नहीं मिले। इस बात को महत्व दीजिये, इसकी ग्रहमियत को समझिये ग्रौर जो 4-5 साल पहले विभाग के पैसे खर्च हो गये उनको कब पूरा कर देंगे, उनको पानी कब तक दे देंगे ?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री भीमसेन जी।

श्री भीमसेन चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे खाजूवाला एरिया में सी.ए.डी. की तरफ से जितनी भी डिग्गियां बनी हुई हैं, उन डिग्गियों की वाटर चैनल की मरम्मत एवं उनकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वह व्यवस्था करायी जाय, वहां बहुत बड़ी समस्या है।

श्री ग्रध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा निवेदन है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी जांच कर ली जायेगी। जो ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ आप जांच कर रहे हैं क्या उनको हटा कर निष्पक्ष जांच करायेंगे, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)....मैंने दो बार ट्रांसफर कराया था, ग्रापने दोनों ही बार कैंसिल किया है। मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि ग्राप उनके खिलाफ कार्यवाही करके उनको हटा कर निष्पक्ष जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका निवेदन। ...लिये। हां आप बोलिये।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प की योजना जिन गांवों के अन्दर थी, उनका पानी नीचे चला गया है और वहां पानी नहीं है 300-400 फीट पर, उन गांवों के लिये आपकी क्या योजना है और कब तक उन गांवों को, जो आलरेडी हैण्ड पम्प स्कीम के अन्दर थे और हैण्ड पम्प अबंडंड हो गये, उनको कब तक जोड़ देंगे ? मेरे ओसियां क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार....

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री रामनारायण डूडी : ....अध्यक्ष महोदय, दूसरा मामला, आपने....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप इतनी शान्ति से बैठे हैं। थोड़ी देर और बैठ जाइये।.... (व्यवधान).... हां आपका हो गया। इनको बोलने दीजिये।

श्री रामनारायण डूडी : ....ओसियां पंचायत समिति की स्कीम एप्रूव्ड बाई डी. आर. डी. ए., जे. आर. वाई., लिफ्ट नम्बर डब्ल्यू, 6015/15/92 दि. 14.1.1991 को हमारी सारी स्कीम्स आगमेन्टेशन में पास हुई हैं, उनमें से 7 स्कीमों पर काम हुआ है, 88 में से 7 तीन साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनका कब तक काम करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : वे सब अधूरी को पूरी कर रहे हैं। हां बोलिये। अमरा राम जी बोल रहे हैं पहले।

श्री अमराराम चौधरी : ऐसे संयंत्र जो खारे पानी को मीठा कर रहे हैं, आज एक भी चालू नहीं है। आप कब तक इनको चालू करवा देंगे, या दूसरी जगह जहां बिजली है इनको ट्रांसफर कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये, भाटी साहब बोलिये।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत मंत्री महोदय से तालाबों में पानी के लिये निवेदन है कि वहां पानी का कोई सोर्स नहीं है। न अण्डर ग्राउण्ड वाटर अवेलेबल है और न कुछ भी है। मेरे इलाके में बहुत बड़ी तकलीफ हो जायेगी पानी की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलिये। (व्यवधान) ये सब नोट करते रहिये आप।

श्री बाबूलाल : ....जो स्कीम होती हैं उसका काम आप कब तक शुरू करवा देंगे ? कृपया यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : हां, भंवरसिंह जी बोलिये।

श्री भंवरसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को धन्यवाद कि पी.पी.सी. वाला को साइड-विद किया लेकिन पी. पी. सी. में जो केसेज आयेंगे उनमें टेक्नीकल और फाइनेंशल सेंक्शन साथ दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, यह मेरा प्रश्न है।.... (व्यवधान).... राजस्थान कैनाल को अगर स्वीडिश गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला नागौर जिले को....

श्री अध्यक्ष : हां वह ठीक है। हो गया बिराजिये। अब तो खाली सजेशन दीजिये ताकि वे नोट कर लें।

श्री भंवरसिंह चौधरी : अभी बता दें, फाइनेंशल सोर्स हैं, वे बता दें।

श्री अध्यक्ष : हां तो ये दे दीजिये कि पी.पी.सी. में साथ मिल जाय। हो गया सजेशन आपका। श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कैनाल एरिया में जहां वाटर वर्क्स बन कर तैयार हो गये हैं, उन वाटर वर्क्स में पानी नहीं डल रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट पानी नहीं दे रहा है। पी.एच.ई.डी. के अधिकारी से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पानी की फाइल जयपुर भेज रखी है, ये इतना लम्बा प्रोसीजर है 8-9 महीने से। सीधा सा काम है पानी लेकर डालना है, उसमें कोई बजट की बात नहीं। फाइनेंस की बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, जे. आर. वाई में गांव-गांव में टंकियां बनी हैं, कुएं भी हैं। क्या मंत्रीजी उनको भी जोड़ने की स्कीम रखेंगे? जे.आर.वाई. की टंकियां बनी हुई हैं, गांव वालों ने बनाई हैं। गांव वालों का कुआं बना हुआ है। उनका कनेक्शन हो जाय तो काम चल जाय।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बाद में मंत्रीजी से पूछ लें। बाद में मंत्रीजी से मिल लें। आप लोग बाद में मंत्रीजी से मिल लेना। आप बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कटमोशन दिये हैं वे भी मेरे पास हैं....

श्री परसराम मदेरणा : मैं एक स्पष्टीकरण मांग रहा था। आपने अभी एक घोषणा की और सदन को सूचित किया कि आपने कंटीनजेंसी प्लान्स की स्कीम्स को एक्जीक्यूट करने के लिये रूरल एरिया में 20 करोड़ और अरबन एरिया में 7 करोड़ रुपया दिया है। यह आपने सी.आर.एफ. में से दिया है या प्लान में से दिया है?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह फेमिन में से दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : इसका मतलब है कि फेमिन में अगले साल के लिए आपने मांग संख्या 34 जो 54 करोड़ की थी उसे पास कराया था। इसमें से आधा 27 करोड़ तो उसमें गया....

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी तो आप कह रहे थे कि यह देओ, वह....

श्री परसराम मदेरणा : सप्लीमेंटरी कब ला रहे हो, सप्लीमेंटरी ग्रान्ट कब ला रहे हो?

श्री अध्यक्ष : ले आयेंगे बीच में।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिये हैं वे मेरे पास हैं, जो सुझाव आपने दिये वे भी मेरे पास हैं।.... (व्यवधान)....अब आपकी टंकी कब जोड़ दी जायेगी, यह कोई सवाल-जवाब हो सकता है क्या? यह कोई सवाल है क्या?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो एक ही डिपार्टमेंट से पानी दिलवाना है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का और आपके बीच में कोर्डिनेशन होना चाहिये। दूसरा, जो पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रोयट

(श्री परसराम मदेरणा)

की थी। आप हर साल तालाबों को ड्रिंकिंग वाटर देते रहते हैं लेकिन इस वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो मांग की है उस पर यह विचार करना पड़ेगा कि इनको पानी देने में कहीं और व्यवधान तो नहीं आयेगा। यह दोनों विचार करना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : पहले क्यों दे रहे थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले ज्यादा होगा पानी।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपकी बात छोड़ो।

श्री परसराम मदेरणा : वह पानी कड़ुवा है। आपकी रीजनल स्कीम है, कैनाल जा रही है, जवाई बांध में पानी बहुत है। पानी नहीं होता तो अलग बात थी। अब इरिगेशन नहीं हो रहा है। पानी बच गया है। पानी ईयर मार्क व रिजर्व किया हुआ है ड्रिंकिंग वाटर के लिए और एक घर में नहीं दे रहे कई घरों में दे रहे हो। हमेशा देते आये हो आप।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय, जो-जो भी इन्होंने अपने व्यक्तिगत क्षेत्र की समस्याएं रखी हैं, आप सारे राजस्थान की तो सोचेंगे ही मगर इनको प्रायोरटी से सोचें ताकि जल्दी से जल्दी इनको रिलीफ मिल जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं और सदन और सदन के मार्फत राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी भयंकर परिस्थिति हमारे सामने आ रही होगी लेकिन राजस्थान के किसी व्यक्ति को भी चाहे हमको ट्रांसपोर्ट से या किसी तरह से भी पानी ले जाकर पिलाना पड़ेगा, पिलायेंगे। किसी को प्यासा नहीं मरने देंगे।

मांग संख्या 27 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27–पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 5,78,92,40,-000/– (पांच अरब, अठत्तर करोड़, बानवे लाख, चालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही दिनांक 21.3.94 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.35 बजे सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)